रजिस्ट्री सं० डी एल (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. DL (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 01—मई 07, 2005, शनिवार/वैशाख 11—वैशाख 17, 1927
No. 19] NEW DELHI, MAY 01—MAY 07, 2005, SATURDAY/VAISAKHA 11—VAISAKHA 17, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2005

का.आ. 1654.—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार राज्य सरकार के गृह (पुलिस) विभाग की दिनांक 05-11-2004 की अधिसूचना संख्या-1/सी.बी.आई.-80-30-2003 एच(पी.) 11911 द्वारा प्राप्त सहमति से दिनांक 26-3-2002 को पुलिस थाना गर्दनीबाग (सचिवालय), पटना में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-ख के तहत दर्ज मामला संख्या-204/2002 का अन्वेषण और उसी संव्यवहार के क्रम में अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत उपर्युक्त अपराधों के संबंध में अथवा उनसे संपृक्त किए गए किसी अन्य अपराध (अपराधों), दुष्प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों का अन्वेषण करने के लिए एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य के सम्बन्ध में करती है।

[सं. 228/86/2004-ए.वी.डी.-II]
चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th April, 2005

S. O. 1654.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of State Government of Bihar vide Department of Home (Police), Notification No. 1/CBI-80-30-2003 H (P) 11911 dated 5-11-2004 hereby extends the powers and

jusrisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for the investigation of the case No. 204/2002 registered on 26-3-2002 with Police Station Gardanibagh (Secretariat), Patna under Section 409, 420, 467, 468, 471, 120-B of the Indian Penal Code and any other offence (s), attempts, abetments and conspiracy in relation to or in connection with the said offences committed during the course of same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/86/2004-AVD.-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

स्टाम्प

का.आ. 1655.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, मुम्बई को मात्र दो करोड़ नब्बे लाख चौसठ हजार एक सौ बत्तीस रुपए का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है, जो उक्त बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र सात सौ पचहत्तर करोड़ चार लाख पैंतीस हजार रुपए के समग्र मुल्य के ऋण पत्रों के स्वरूप वाले 1550087 असुरक्षित विमोच्य बन्ध पत्रों (जनवरी, 2005 को जारी) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 12/2005-स्टाम्प/फा. सं. 33/14/2005-बि.क.]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st April, 2005

STAMPS

S. O. 1655.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits ICICI Bank Limited, Mumbai to pay consolidated stamp duty of rupees two crore ninety lakh sixty four thousand one hundred thirty two only chargeable on account of the stamp duty on 1550087 unsecured redeemable Bonds (January, 2005 Issue) in the nature of debentures aggregating to rupees seven hundred seventy five crore four lakh thirty five thousand only, to be issued by the said Bank.

[No. 12/2005-STAMP/F. No. 33/14/2005-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1656.—सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्था' की श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक 1-4-2005 से दिनांक 31-3-2008 तक की अवधि के लिए शन्मुध आर्ट्स, साइंस, टेक्नालॉजी एंड रिसर्च एकादमी (एस ए एस टी आर ए) "लक्ष्मी निवास" सं. 5, मेन रोड, डॉ. सुब्बारायन नगर, कोडाम्बक्कम, चेन्नई-600024, जो अंशत: अनुसंधान कार्य-कलापों में कार्यरत है, (और न कि अनुसंधान के लिए एक मात्र मौजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' के रूप में है), को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) अनुमोदित संगठन अपने अनुसंधान कार्य-कलापों के लिए अलग खाते रखेगा।

(ii) वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए जिसके लिए यह अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है, अनुमोदित संगठन अनुसंधान कार्य-कलापों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की एक प्रति इसके क्षेत्राधिकार वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) को आय कर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को अथवा उससे पहले अथवा इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के अन्दर, जो भी बाद में समाप्त हो, प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iii) यह संगठन उपर्युक्त पैरा (ii) में संदर्भित आय एवं व्यय खाते के साथ लेखा परीक्षक से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा :—

(क) जिसमें संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त की गई उस राशि का उल्लेख किया गया हो, जिसके लिए दानकर्ता धारा 35(1) (ii) के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

(ख) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किया गया व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही था।

[अधिसूचना सं. 130/2005/फा. सं. 203/80/2004-आयकर नि.-II]

निधि सिंह, अवर सचिव

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 15th April, 2005

(INCOME-TAX)

S. O. 1656.—It is hereby notified for general information that the organization **Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SASTRA) "Lakshmi Nivas", No. 5, Main Road, Dr. Subbarayan Nagar, Kodambakkam, Chennai-600024** has been approved by the Central Government for the purposes of clause (ii) of Sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961, read with rule 6 of the Income Tax Rules, 1962 for the period from **1-4-2005 to 31-3-2008** under the category, university, college or other Institution', partly engaged in research activities (and not as a 'Scientific Research Association' existing solely for research) subject to the following conditions :—

(i) The approved organization shall maintain separate accounts for its research activities.

(ii) For each of the financial years for which the approval is being given, the approved organization shall submit a copy of its audited Income.

(iii) and Expenditure account in respect of the research activities for which it has been approved under Sub-section (1) of Section 35 of Income Tax Act, 1961 to the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction, on or before the due date of filing of return of income or within 90 days from the date of this notification, whichever expires later.

(iv) The approved organization shall also enclose with the Income and Expenditure account referred to in paragraph (ii) above, a certificate from the auditor :—

(a) specifying the amount received by the organization for scientific research in respect of which the donors are eligible to claim deduction under clause (ii) of Sub-section (1) of Section 35.

(b) certifying that the expenditure incurred was for scientific research.

[Notification No. 130/2005/F. No. 203/80/2004-ITA-II]

NIDHI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2005

का.आ. 1657.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार ने उद्यम/उपक्रम कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड, पी. उब्ल्यू डी ऑफिसेस एनेक्सी, तृतीय तल, के. आर. सर्कल, बैंगलौर-560001, को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 छ) के प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी (उच्च कृष्णा परियोजना) पर सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दिनांक 01-04-2004 से 31-03-2007 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया है।

2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/उपक्रम :—

(क) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 छ) के उपबंधों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका अनुपालन नहीं करेगा ;

(ख) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 ङ के स्पष्टीकरण (ख) में यथा परिभाषित पात्र कारोबार को जारी रखना बंद कर देता है ;

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ङ के उपनियम (6) द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा नहीं कराता है ;

(घ) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ङ के उप नियम (6) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क (4) (i) (ग) के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करने के बाद उसका प्रचालन और अनुरक्षण शुरू नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 136/2005/फा. सं. 205/67/98-आ.क.नि.-II(खंड-III)]

निधि सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th April, 2005

S. O. 1657.—It is notified for general information that the enterprise/undertaking, **Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd, PWD Offices Annexe, 3rd Floor, K. R. Circle, Bangalore-560001,** has been approved by the Central Government for the purpose of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962 **for execution of Irrigation Projects on Krishna River (Upper Krishna Project) in the State of Karnataka,** for the period of 3 years from **01-04-2004 to 31-03-2007.**

2. The Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/undertaking :

(a) ceases to conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with the 2E of the Income-tax Rules, 1962 ;

(b) ceases to carry on the eligible business as defined in Explanation (b) to Rule 2E of I.T. Rules, 1962 ;

(c) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (6) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962 ;

(d) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (6) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

(e) fails to start operating and maintaining the infrastructure facility after developing it in terms of Section 80 IA(4)(i)(c) of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 136/2005/F. No. 205/67/98-ITA-II-(Vol. III)]

NIDHI SINGH, Under Secy.

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय)

पुणे, 28 अप्रैल, 2005

सं. 01/2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नॉन टॅरिफ)

का.आ. 1658.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 01-07-1994 की अधिसूचना संख्या 33/94-सीमा शुल्क (नॉन टॅरिफ) के अधीन मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रभाकर निगम, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे। आयुक्तालय, पुणे, एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के, पुणे जिले के, तालुका मावल, तलेगाव, के अंबी तथा नवलाख उंबरे गॉव को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन वेअर हाउसिंग स्टेशन घोषित कर रहा हूँ। इसे निजी बॉडेड वेअर हाउस के रूप में स्थापित किया गया है।

[फा. सं. वीजीएन(19)/56/शत प्रतिशत निर्यात लक्ष्यी यूनिट/2005]

प्रभाकर निगम, आयुक्त

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE)

Pune, the 28th April, 2005

No. 01/2005-C.E. (NT)

S. O. 1658.—In exercise of the powers conferred on me by the Notification No. 33/94-CUS (NT) dated 01-7-1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue New Delhi, I, Prabhakar Nigam, Commissioner of Central Excise Pune-I Commissionerate, Pune, hereby declare **Village Ambi, and Navlakh Umbre, Tal-Maval, Talegaon, Dist Pune, in the State of Maharashtra to be Warehousing Station** under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for setting up of Private Bonded warehouse.

[F. No. VGN (19)/56/100%EOU/2005]

PRABHAKAR NIGAM, Commissioner

(कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क)

भोपाल, 21 अप्रैल, 2005

सं. 01/2005

का.आ. 1659.—श्री वाई० के० गुप्ता, अधीक्षक, समूह 'ख', केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय भोपाल, का देहावसान दिनॉक 03-04-2005 को हो गया है।

[फा. सं. II(25)/01/2000/स्था.I]

बी. डी. बोरकर, संयुक्त आयुक्त (का./स.)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

Bhopal, the 21st April, 2005

No. 01/2005

S. O. 1659.—Shri Y. K. Gupta, Superintendent, Group 'B' Central Excise and Customs, Bhopal Commissionerate has passed away on 03-04-2005.

[F. No. II(25)/01/2000/Et-I]

B. D. BORKAR, Jt. Commissioner (P&V)

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2005

का.आ. 1660.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के मुख्य महाप्रबंधक, श्री चन्दन सिन्हा को भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सिवाली चौधरी के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, इलाहाबाद बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं. 9/18/2000-बीओ-I]

जी. बी. सिंह, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 27th April, 2005

S. O. 1660.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, hereby nominates Shri Chandan Sinha, Chief General Manager,

Reserve Bank of India, Guwahati as a Director of Allahabad Bank with immediate effect and until further orders *vice* Smt. Sewali Chowdhary, Chief General Manager, Reserve Bank of India, Kolkata.

[F. No. 9/18/2000-BO.I]

G. B. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2005

का.आ. 1661.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा (6) की उप-धारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को 25 अप्रैल, 2005 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है :—

1. श्री के. चेरियन वर्गीज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक आफ इंडिया	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1) (ङ) (iii) के अनुसरण में
2. श्री एस.जी. ओसवाल, अध्यक्ष, सी आई आई टैक्सटाइल कमेटी एंड वर्धमान ग्रुप	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1) (ङ) (iii) के अनुसरण में
3. श्रीमती किरन मजूमदार शॉ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बायोकोन इंडिया लि.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1) (ङ) (iii) के अनुसरण में
4. श्री अरूणाचलम वेल्लायन, उपाध्यक्ष, ईआईडी पैरी इंडिया लि.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6(1) (ङ) (ii) के अनुसरण में

[फा. सं. 24/27/2002-आई एफ-I(i)]

अतुल कुमार राय, निदेशक

New Delhi, the 28th April, 2005

S. O. 1661.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (1) of Section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates the following persons as part-time non-official directors on the Board of Directors of Export Import Bank of India (EXIM Bank) for a period of three years with effect from 28 April, 2005 :—

1. Sh. K. Cherian Varghese, Chairman and Managing Director, Union Bank of India	In pursuance of Section 6(1)(e)(ii) of Export-Import Bank of India Act, 1981
2. Shri S.P. Oswal, Chairman, CII Textile Committee and Verdhman Group	In pursuance of Section 6(1)(e)(iii) of Export-Import Bank of India Act, 1981
3. Smt. Kiran Majumdar Shaw, Chairman and Managing Director, Biocon India Ltd.	In pursuance of Section 6(1)(e)(iii) of Export-Import Bank of India Act, 1981
4. Sh. Arunachalam Vellayan, Vice Chairman, EID Parry India Ltd.	—do—

[F. No. 24/27/2002-I.F.I. (i)]

ATUL KUMAR RAI, Director

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2005

का.आ. 1662.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा (6) की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री विनयशील गौतम, डालमिया चेयर प्रोफेसर ऑफ प्रबंधन, आईआईटी, दिल्ली को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक बोर्ड में 30-4-2007 तक, अर्थात् छः वर्ष की सीमा तक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नामित करती है।

[फा. सं. 24/27/2002-आई एफ-I(ii)]

अतुल कुमार राय, निदेशक

New Delhi, the 28th April, 2005

S. O. 1662.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (e) of Sub-section (1) of Section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby re-nominates Shri Vinayshil Gautam, Dalmia Chair Professor of Management at IIT, Delhi as part-time non-official director on the Board of Directors of Export-Import Bank of India (EXIM Bank) upto 30-4-2007, *i.e.* till limit of six years.

[F. No. 24/27/2002-I.F.I. (ii)]

ATUL KUMAR RAI, Director

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2005

का.आ. 1663.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड (9) के उप-खंड (1) और (2)(क) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी संघ के सचिव (दक्षिण अंचल) श्री टी.के. बालसुब्रमणियन को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30-6-2007 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता

की तारीख तक की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी को नामित किए जाने तक अथवा जब तक वे बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 9/28/2004-बी.ओ.-I]

जी.बी. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2005

S. O. 1663.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (1) and (2)(a) of clause (9) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri T.K. Balasubramanian, Secretary (South Zone) of the All India Bank of Baroda Officers' Association as a Director on the Board of Directors of Bank of Baroda for a period from the date of notification and upto 30-6-2007, *i.e.* the date of his superannuation or until his successor has been nominated or until he ceases to be an officer of Bank of Baroda, whichever is earlier.

[F. No. 9/28/2004-BO-I]

G.B. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2005

का.आ. 1664.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री के.एन. पृथ्वीराज, जो वर्तमान में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मार्च, 2007 तक अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/65/2004-बी.ओ.-I]

जी.बी. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th April, 2005

S. O. 1664.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clasue 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K.N. Prithviraj presently Executive Director, United Bank of India as Chairman and Managing Director, Oriental Bank of Commerce from the date of his taking charge of the post and upto 31-3-2007, *i.e.* date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/65/2004-BO-I]

G.B. SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2005

का.आ. 1665.—सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री.पी.के. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक 1 मई, 2005 से अथवा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, अपने कार्यों के साथ-साथ युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

[फा. सं. 9/31/2004-बी.ओ.-I]

जी.बी. सिंह, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 2005

S. O. 1665.—Government have decided that Shri P.K. Gupta, Chairman and Managing Director, National Housing Bank, will hold additional charge of the post of Chairman and Managing Director, United Bank of India, in addition to his own duties with effect from 1st May, 2005 or until appointment of regular Chairman and Managing Director in United Bank of India, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/31/2004-BO-I]

G. B. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2005

का.आ. 1666.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 3 के उप-खंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री एस.सी. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31-5-2007 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की आयु तक या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो,

पंजाब नैशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/63/2004-बी.ओ.-I]

जी.बी. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2005

S. O. 1666.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clasue 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri S. C. Gupta, Chairman and Managing Director, Indian Overseas Bank as Chairman and Managing Director, Punjab National Bank from the date of his taking charge of the post and upto 31-5-2007, i.e. the date of his superannuation, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/63/2004-BO-I]

G. B. SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1667.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रो. ए. राजशेखरन को डॉ. लिवतार सिंह चावला के स्थान पर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और का.आ. 3049, दिनांक 2-11-1996 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

6. प्रो. ए. राजशेखरन
'अर्जुन'
सं. 70, फर्स्ट एवेन्यू,
इंदिरा नगर,
चेन्नई-600020.

[सं. वी-11013/5/2001-एम ई (नीति-I)]

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 13th April, 2005

S. O. 1667.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government hereby appoints Prof. A. Rajasekaran to be a member of the Post-Graduate Medical Education Committee in place of Dr. Livtar Singh Chawla and makes the following further amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare published vide S.O. 3049 dated 2-11-1996 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated by the Central Government" for seral number 6 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

6. Prof. A. Rajsekaran,
'ARJUNA'
No. 70, First Avenue,
Indira Nagar,
Chennai-600 020.

[No. V-11013/5/2001-ME (Policy-I)

ARVIND KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2005

का.आ. 1668.—स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खंड (छ) के अनुसरण में राज्य सभा की सदस्य श्रीमती अंबिका सोनी को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में सेवा के लिए राज्य सभा द्वारा तारीख 9 मार्च, 2005 को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है।

[सं. वी-17011/1/1999-एमई(पीजी)/एमई डैस्क-2]

डा. विनायक एम. प्रसाद, निदेशक

New Delhi, the 25th April, 2005

S. O. 1668.—In pursuance of clause (g) of Section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966) Smt. Ambika Soni, Member, Rajya Sabha has been duly

elected on 9th March, 2005 by the Rajya Sabha to serve as Member of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh subject to the fulfilment of the provisions of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act 1996.

[No. V-17011/1/1999-ME(PG)/ME Desk-II]

Dr. VINAYAK M. PRASAD, Director

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1669.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्र. सं.	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की सख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 15544:2004/ आई ई सी 61080 (1991) क्वार्ट्ज क्रिस्टल युनिटों के समतुल्य वैद्युत प्राचलों के मापन की मार्गदर्शिका	—	दिसंबर 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरूवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एल टी डी/जी-75/केपुवि/13:2]

डी. के. नैय्यर, प्रमुख (एलआईटीडी)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 21st April, 2005

S. O. 1669 .—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
1	2	3	4
1.	IS 15544 : 2005 /IEC 61080 (1991) Guide to the Measurement of Equivalent Electrical Parameters of Quartz Crystal Units	—	December 2004

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : LTD/G-75/CMD/13:2]

D.K. NAYYAR, Head (LITD)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

का.आ. 1670.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जय इन्स्ट्रूमेंट्स एंड सिसटम्स प्रा. लि., सी-64 टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, टुरभे, जिला-थाणे, नवीं मुंबई-400075 द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-II) वाले ''जिनी'' शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांण्ड का नाम ''जय-पान'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/425 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

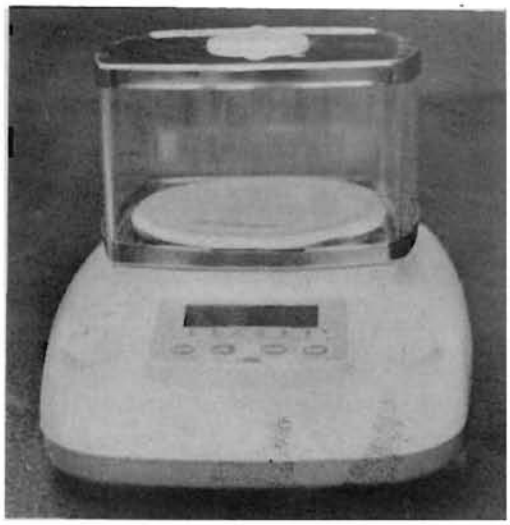

उक्त मॉडल एक विकृत (स्ट्रेन) गेज प्रकार का भार सेल आधारित (टेबल टाप प्रकार का) अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 मि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 मि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक के ''ई'' मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो घनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(274)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 15th April, 2005

S.O. 1670.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "JINNEE" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "JAY-PAN" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Jay Instruments & Systems Pvt. Ltd., C-64, TTC Industrial Area, Turbhe, Distt. Thane, Navi Mumbai-400075 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/425;

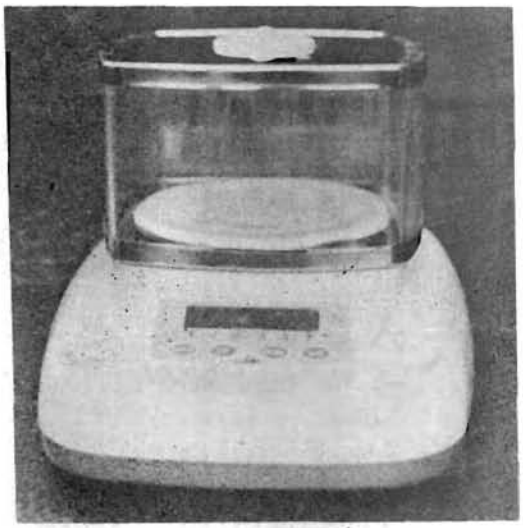

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 300g. and minimum capacity of 200mg. The verification scale interval (e) is 10mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 50mg and with verification scale intervel (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(274)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1671.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेगास्केन इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. ग्राउण्ड फ्लोर, राजमेंसन, प्लाट-59, वृन्दावन कालोनी, डा. ए एस राव नगर, ई सी आई एल पोस्ट, हैदराबाद-500 062 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "डब्ल्यू एम-500" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "वे मास्टर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/461 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

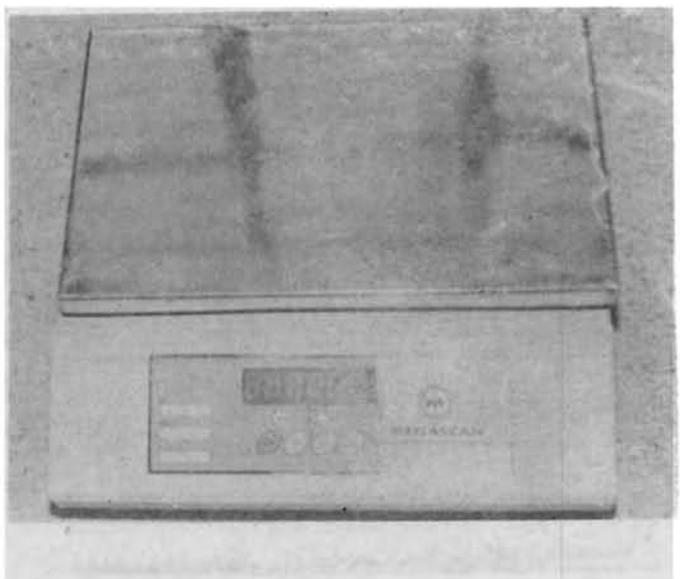

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(41)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1671.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "WM-500" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "WEIGH-MASTER" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Megascan Electronics & Communications Pvt Ltd., Ground Floor, Raj Mansion, Plot No. 59, Brindavan Colony, Dr. A. S. Rao Nagar, ECIL Post, Hyderabad-500062, Andhra Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/461;

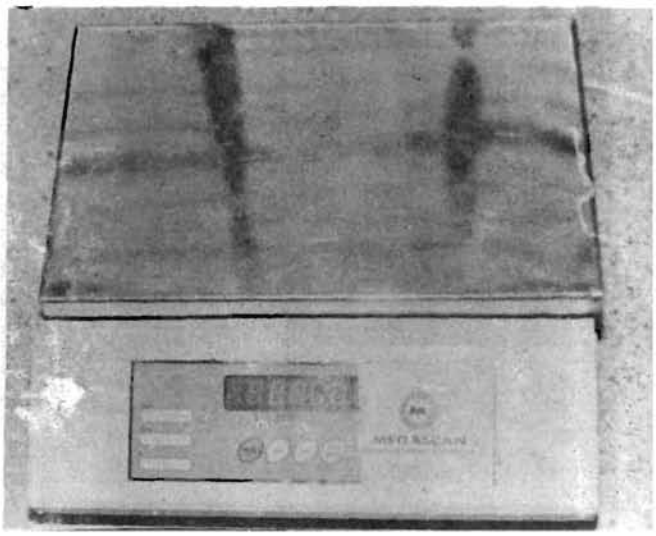

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg to 2g.and with verification scale intervel (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1672.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेगास्केन इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि., ग्राउण्ड फ्लोर, राजमेंसन, प्लाट-59, वृन्दावन कालोनी, डा. ए एस राव नगर, ई सी आई एल पोस्ट, हैदराबाद-500 062 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "डब्ल्यू एम-2000" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "वे मास्टर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/462 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

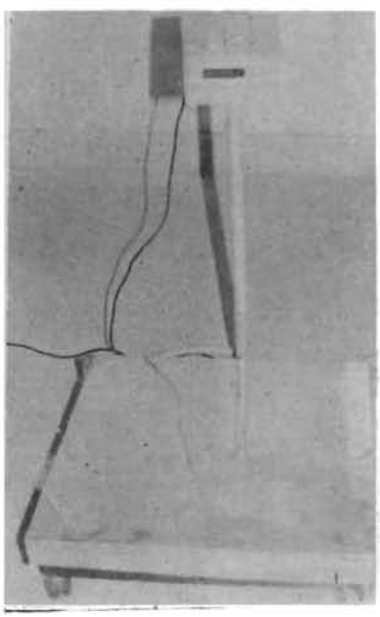

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 600 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2.5 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 50,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(41)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1672.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "WM-2000" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "WEIGH-MASTER" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Megascan Electronics & Communications Pvt. Ltd., Ground Floor, Raj Mansion, Plot No. 59, Brindavan Colony, Dr. A. S. Rao Nagar, ECIL Post, Hyderabad-500062, Andhra Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/462;

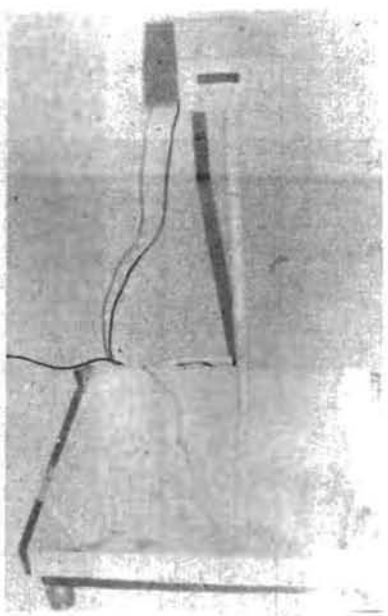

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 600kg. and minimum capacity of 2.5kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts , 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 1000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 50,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1673.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेगास्केन इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. ग्राउण्ड फ्लोर, राजमेंसन, प्लाट-59, वृन्दावन कालोनी, डा. ए एस राव नगर, ई सी आई एल पोस्ट, हैदराबाद-500 062 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "डब्ल्यू एम-1000" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "वे मास्टर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/463 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

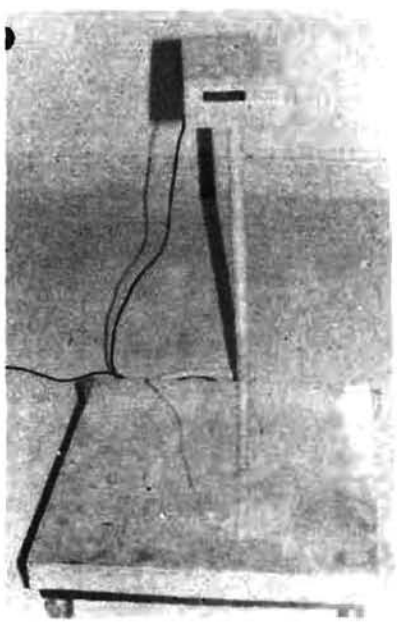

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(41)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1673.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "WM-1000" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "WEIGH-MASTER" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Megascan Electronics & Communications Pvt Ltd., Ground Floor, Raj Mansion, Plot No. 59, Brindavan Colony, Dr. A. S. Rao Nagar, ECIL Post, Hyderabad-500062, Andhra Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/463;

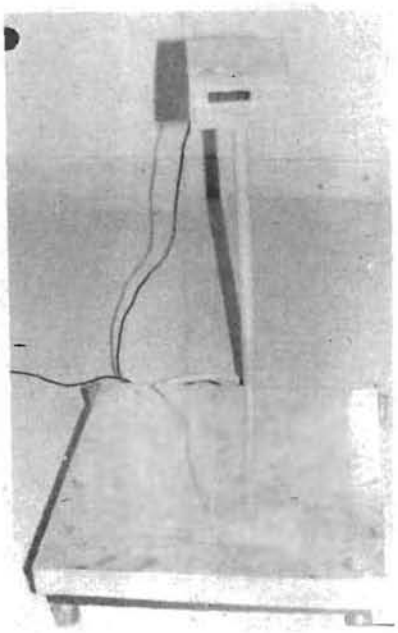

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000kg. and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1674.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेगास्केन इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. ग्राउण्ड फ्लोर, राजमेंसन, प्लाट-59, वृन्दावन कालोनी, डा. ए. एस. राव नगर, ई सी आई एल पोस्ट, हैदराबाद-500 062 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "डब्ल्यू एम-600" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "वे मास्टर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/460 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

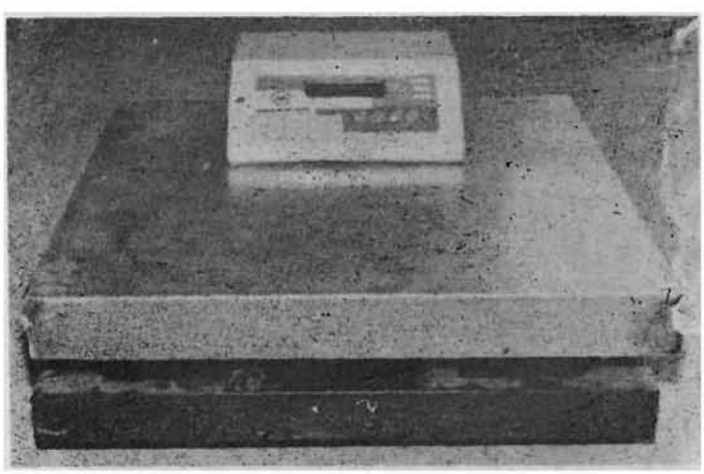

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(41)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1674.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "WM-600" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "WEIGH-MASTER" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Megascan Electronics and Communications Pvt. Ltd., Ground Floor, Raj Mansion, Plot No. 59, Brindavan Colony, Dr. A. S. Rao Nagar, ECIL Post, Hyderabad-500062, Andhra Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/460;

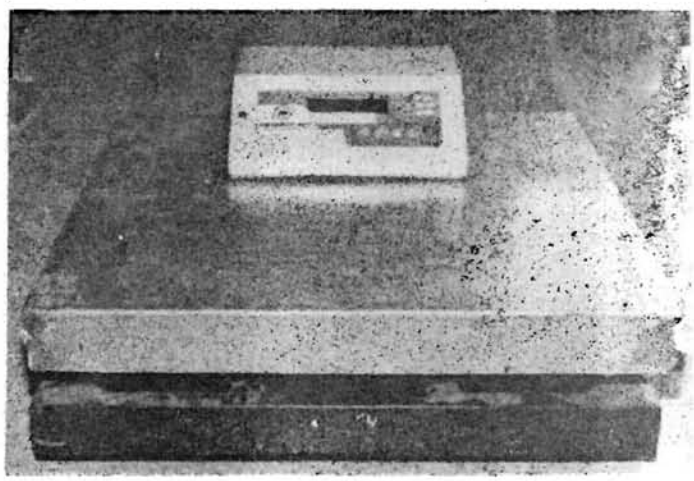

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100 g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval(n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg. to 50 mg. and with verification scale intervel (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 10 mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(41)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1675.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कैस वेईंग इंडिया प्रा. लि., 568, उद्योग विहार, फेज-V, गुड़गांव-122016 (हरियाणा) द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "एम डब्ल्यू" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "सी ए एस" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/316 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखे) एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 300 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 मि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 मि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकिन करने के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 5000 की रेंज में सत्यापन मानमाप अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(156)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1675.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "MW-II" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "CAS" (herein after referred to as the said Model), manufactured by M/s CAS Weighing India Pvt. Ltd., 568, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122 016 (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/316;

The said model (see the figure given below) is strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 300g. and minimum capacity of 200mg. The verification scale interval (e) is 10mg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg. to 50 mg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, K being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design accuracy and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(156)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1676.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कैस वेईंग इंडिया प्रा. लि., 568 उद्योग विहार फेस-V, गुड़गांव-122016 (हरियाणा) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले "ई पी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, स्वत: सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सी ए एस" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/317 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आँधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकित के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा.तक के "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^{\text{क}}$, $2 \times 10^{\text{क}}$ या $5 \times 10^{\text{क}}$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(156)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1676.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "EP" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "CAS" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. CAS Weighing India Pvt. Ltd., 568, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122 016 (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/517;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg. to 2g. or with verification scale interval(n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same material with which the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(156)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1677.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अत्रि इलक्ट्रो-वेग, 4-5, सुमेरु पार्क, हरभोलेनाथ पार्क के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, उद्धव रोड, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले "ए टी टी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "अत्रि" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/434 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. से 2 ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमन अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(187)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1677.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "ATT" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "ATARI" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Atari Electro-Weigh, 4-5, Sumeru Park, Opp. Harbholenath Park, National Highway No. 8, Odhav Road, Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/434;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg to 2g or with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(187)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1678.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स अत्रि इलक्ट्रो-वेग, 4-5, सुमेरु पार्क, हरभोलेनाथ पार्क के सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, उद्धव रोड, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-II) वाले "ए पी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "अत्रि" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/435 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

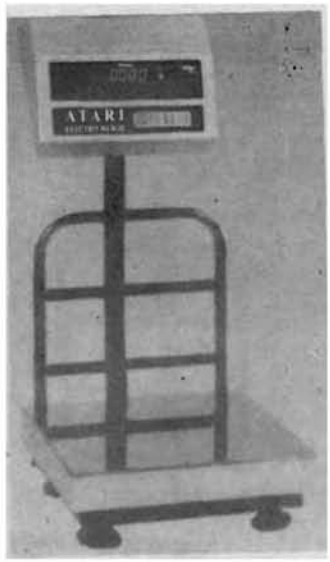

उक्त मॉडल एक विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1100 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट के मुद्राकंन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(187)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1678.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic (Plateform type) weighing instrument with digital indication of "AP" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "ATARI" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Atari Electro-Weigh, 4-5, Sumeru Park, Opp. Harbholenath Park, National Highway No. 8, Odhav Road, Ahmedabad, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/435;

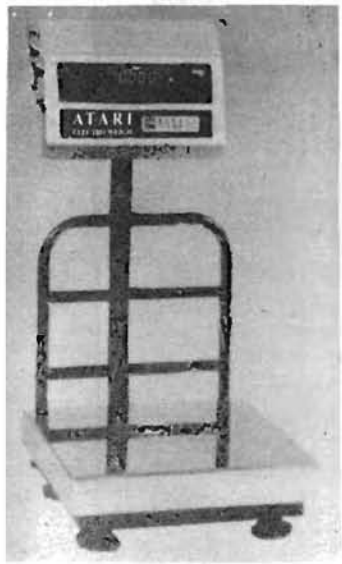

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1100 kg and minimum capacity of 5kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100g or more and with 'e' value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, and with the same materials with which the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(187)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1679.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टिआ टेक्नोलोजी, 16 कलाथुर लेआउट, गंगामां सर्किल, बंगलोर द्वारा विनिर्मित स्वचालित गुरुत्वमापी भरण उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एसीसी एफआईएल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2003/501 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

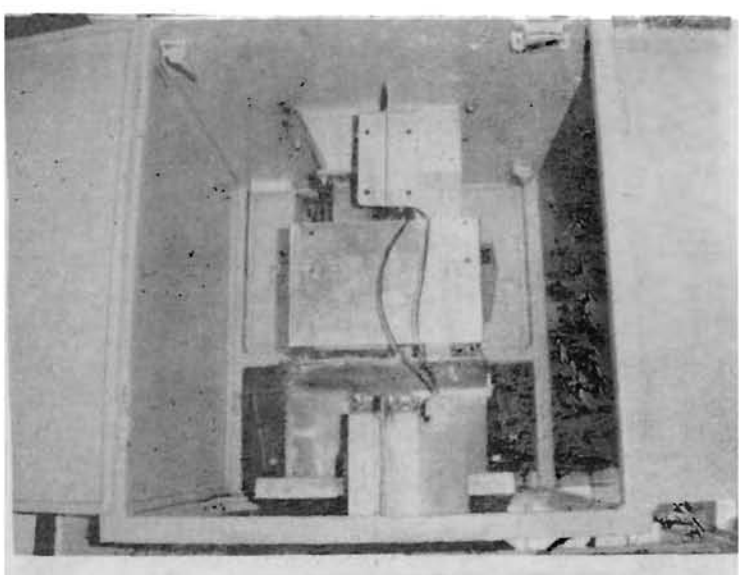

उक्त मॉडल विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार का भार सेल आधारित गुरुत्वमापी भरण उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है। इसकी अधिकतम क्षमता 25 पाउच प्रति मिनट है। यह मशीन मुक्त प्रवाह उत्पादों जैसे चाय, चीनी, चावल, बीज, कन्फैक्शनरी, बिस्कुट, आलू चिप्स, दालें आदि को भरने के लिए डिजाइन की गई है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 2 ग्रा. से 5 कि. ग्रा. की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21(337)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1679.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of automatic gravimetric filling instrument of 'HSF-505' series with brand name "ACCFIL" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Tia Technology, 16, Kalathur Layout, Gangamma Circle, Bangalore-560 013 and which is assigned the approval mark IND/09/2003/501;

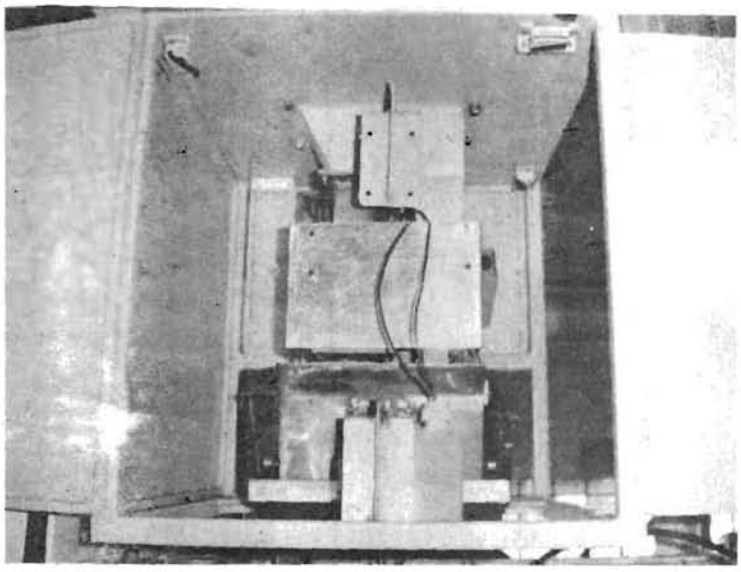

The said Model is a strain gauge type load cell based automatic gravimetric filling instrument. Its maximum capacity is 2kg. It has a maximum fill rate of 25 pouches per minute. The Machine is designed for filling free flowing products like tea, sugar, rice, seeds, confectionery, biscuits, potato chips, pulses and the like.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the Automatic filling machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 2g to 5kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same materials with which the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(337)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1680.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी नीदरलैंड मीटिंस्टीटूएट (एन एम आई) नीदरलैंड में इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित निकाय द्वारा उसे पैटर्न मूल्यांकन रिपोर्ट और परीक्षण परिणाम सहित प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स येनेन इंजीनियरिंग, सेमसेटिंग गुनाल्टा कैड.110/3, 81070 सुअदिए इस्तांबुल, टर्की और भारत में बैंजाज इंजीनियर्स लि., 85/1 पाउड रोड, कोथारुड, पुणे-411038 द्वारा विपणित "वी ए एन ए जेड" श्रृंखला के आटोमोबाइल के एलपीजी वितरक (जल से भिन्न अन्य द्रवों के लिए मीटर) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "वी ए एन ए जेड" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/315 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

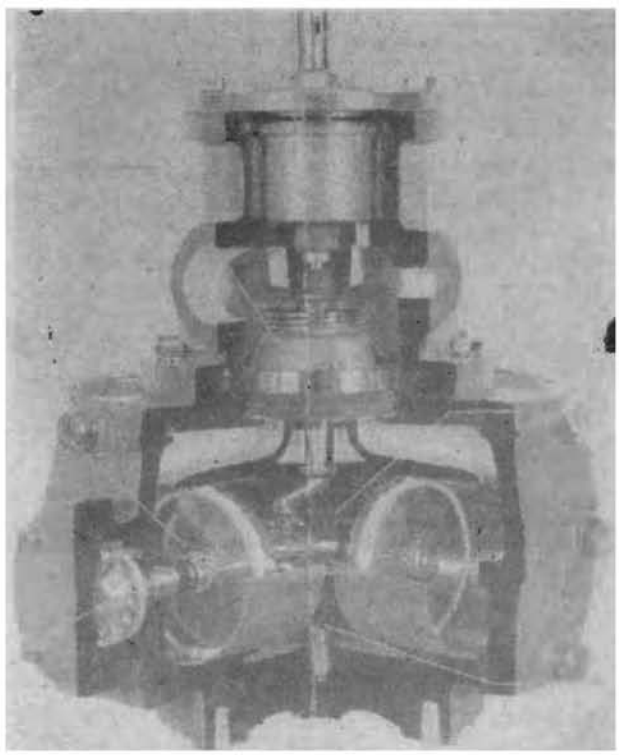

उक्त मॉडल एक धनात्मक विस्थापन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक लीटर में ईंधन के आयतन को नापने के लिए मोटर यान के लिए एल पी जी वितरक है। इसका अधिकतम प्रवाह दर 60 ली./मि. है और 6 ली./मि. की न्यूनतम दर है। इसकी न्यूनतम नापी गई मात्रा 5 लीटर है। इसकी अधिकतम प्रचालन दाब 25 बार और न्यूनतम प्रचालन दाब 1 दाब है। इसकी यथार्थता वर्ग 1.0 है और पर्यावरणीय वर्ग "ग" है। यह मोटर यान में एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन भरने के लिए प्रयुक्त होती है और 24 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रवाह पर कार्य करता है। चक्रीय आयतन 0.5 लीटर और स्पन्द दर 50 स्पन्द/चक्र है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21(109)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1680.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it along with the pattern evaluation port and test result granted and approved by the prescribed authority, a notified body for the purpose in the Netherlands, Netherlands, Meetinstituut (NMI) is satisfied that the models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (3) and sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby approves, issues and publishes the certificate of approval of model of LPG Dispensers for automobiles (Meter for liquids-other than water) of "YGM" series (hereinafter referred to as said model) with brand name "VANAZ" manufactured by M/s Yenen Engineering, Semsetting Gunalta Cad. 110/3, 81070 Suadiye Istanbul, Turkey and marketed in India by M/s Vanaz Engineers Limited, 85/1 Paud Road, Kothrud, Pune 411038 and which is assigned the approval mark IND/13/04/315;

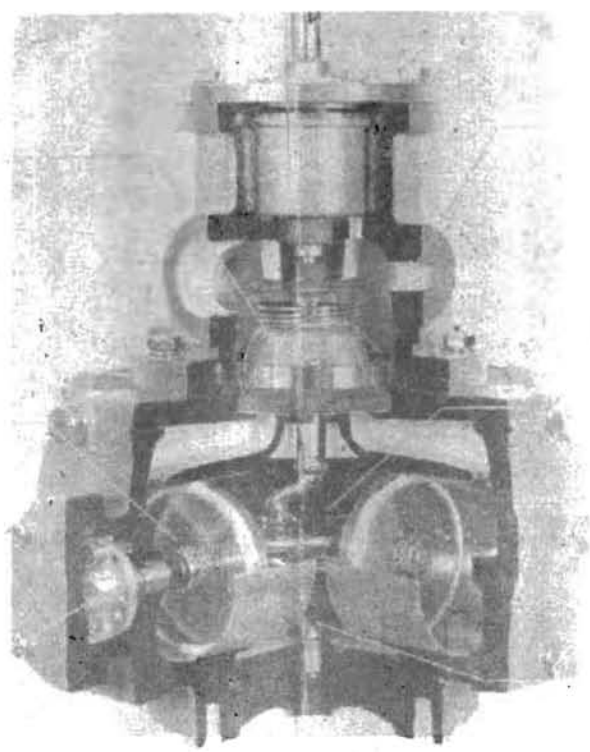

The said model is a LPG dispenser for motor vehicle measuring the volume of fuel in litre using positive displacement principle. Its maximum flow rate is 60 litre/min and minimum flow rate is 6 litre/min. The minimum measured quantity is 5 litre. The maximum operating pressure is 25 bar and minimum operating pressure is 1 bar. Its accuracy class is 1.0 and environmental class is "C". It is used for filling LPG, Propane and Butane in motor vehicles and it operates on 24 Volts DC power supply. The cyclic volume is 0.5 litre and number of pulses/rotation is 50.

[F. No. WM-21(109)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1681.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स ग्लेक्सी स्केल कं., शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515, गुजरात द्वारा विनिर्मित गणक मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/383 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक गणक मशीन है जो दण्ड के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है। इसके ब्राण्ड का नाम "राजा" है।

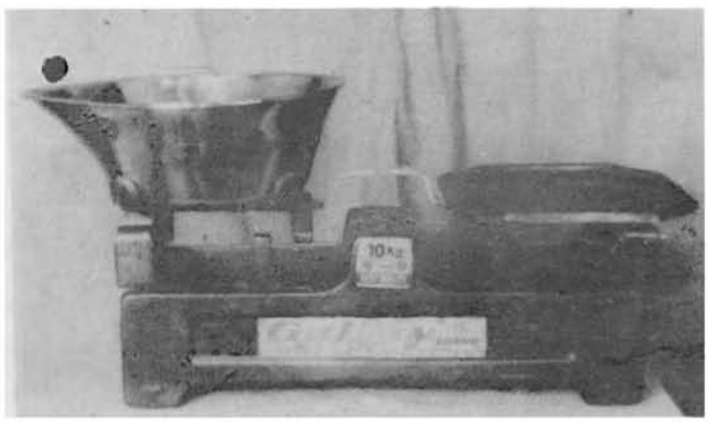

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की गणक मशीन भी होंगी जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. तक की है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21(231)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1681.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Galaxy Scale Co., Shivaji Nagar, Savarkundla-364515, Gujrat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/383;

The said model (see the figure given below) is a counter machine working on the principle of beam with maximum capacity of 10kg with brand name "RAJA".

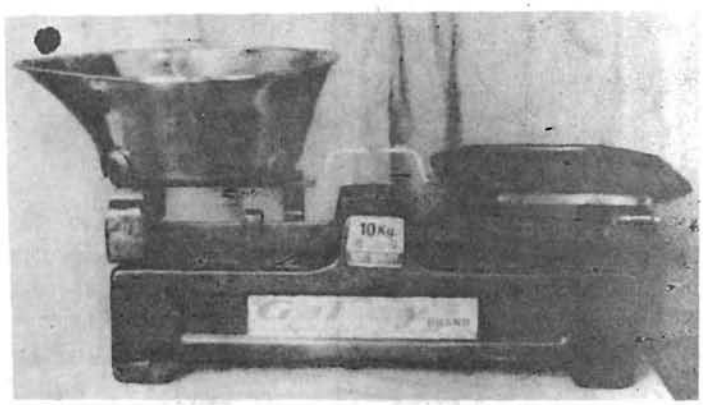

In addition to sealing the stamping plate, Machine shall be sealed to prevent its opening for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the counter machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity from 500g up to 50kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same material with which the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(231)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1682.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स केनफ्लैक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 1919, सी-8/3, इंडस्ट्रियल एस्टेट, संथ नगर, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित "केनन-जी" श्रृंखला के स्वचालित भरण मशीन (कप फिलर) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "केनन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/415 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

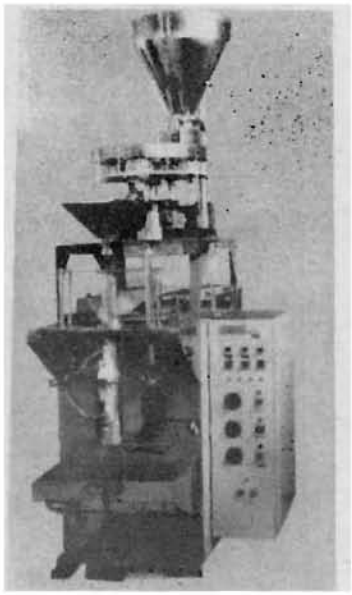

उक्त मॉडल एक स्वत: भरण मशीन (कप फिलर) है। इसकी क्षमता 100 ग्रा. से 5 कि.ग्रा. तक की या समतुल्य मात्रा की रेंज में है। मशीन को मसाले, चीनी, चावल, नमक, सूजी, डिटर्जेंट, चाय, बीज और कृषि उत्पादों जैसे मुक्त वहाव वाले उत्पादों के लिए डिजाइन किया है। यह 10 से 40 भरण प्रति मिनट कर सकती है और यह 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21(303)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1682.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of automatic filling machine (Cup Filler) of 'CANNON-G' series with brand name "CANNON" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Canflex Engineering Private Limited, Post Box No. 1919, C-8/3, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad and which is assigned the approval mark IND/09/2004/415;

The said Model is an automatic filling machine (Cup Filler). Its capacity is in the range of 100g to 5kg or equivalent volume. The machine is designed for filling free flowing products such as spices, sugar, rice, salt, soji, detergent, tea, seeds and agricultural products. It can fill 10 to 40 fills per minute and It operates on 230 Volts and 50 Hz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(303)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1683.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स केनफ्लैक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 1919, सी-8/3, इंडस्ट्रियल एस्टेट, संथ नगर, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित "केनन-पी पी" शृंखला के स्वचालित भरण मशीन (औगर फिलर) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "केनन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/416 समनुदेशित किया गया है, अनमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है:

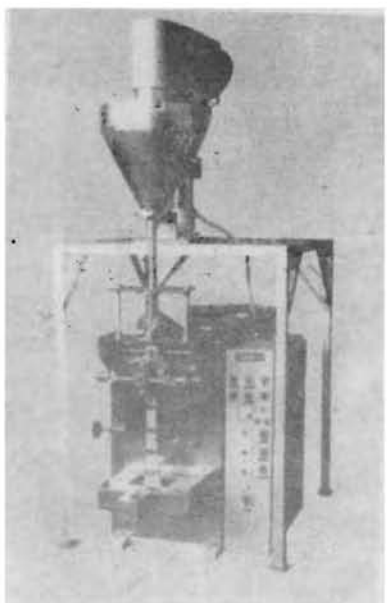

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन (आगर फिलर) है। इसकी क्षमता 10 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की या समतुल्य मात्रा की रेंज में है। मशीन को दुग्ध पाउडर, काफी पावडर गेहूं का आटा, पिसे मसाले, औषधीय चूर्ण, टूथ पाउडर और रसायनों जैसे मुक्त बहाव वाले उत्पादों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 60 थैली प्रति मिनट तक भर सकती है और 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(303)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1683.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of automatic filling machine (Auger Filler) of "CANNON-PP" series with brand name "CANNON" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Canflex Engineering Private Limited, Post Box No. 1919, C-8/3, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad, and which is assigned the approval mark IND/09/2004/416;

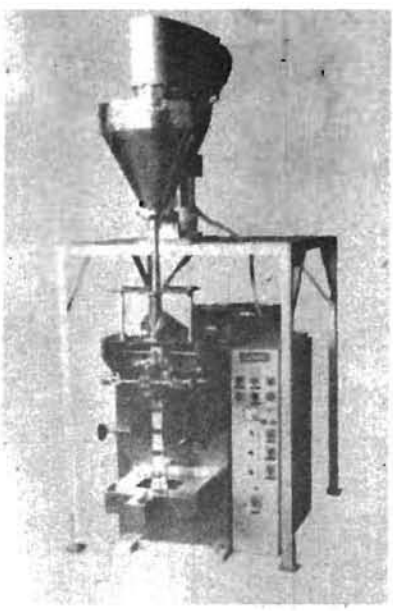

The said Model is an automatic filling machine (Auger Filler). Its capacity is in the range of 10g to 1000g or equivalent volume.The machine is designed for filling free flowing products such as milk powder, coffe powder, wheat flour, ground spices, pharmaceutical powder, tooh powder and chemicals. It can fill up to 60 pouches per minute and it operates on 230 Volts and 50Hertz alternative current power supply.

[F. No. WM-21(303)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1684.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स केनफ्लैक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 1919, सी-8/3, इंडस्ट्रियल एस्टेट, संथ नगर, अहमदाबाद द्वारा विनिर्मित "केनन-एल" शृंखला के स्वचालित भरण मशीन (ग्रविटी फिलर) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "केनन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/417 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है·

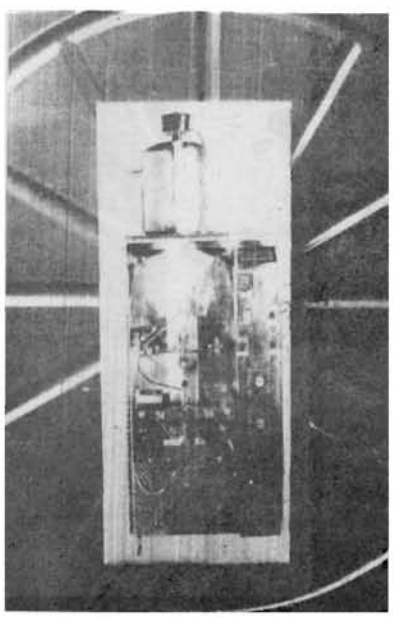

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन (ग्रविटी फिलर) है। इसकी क्षमता 10 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की या समतुल्य मात्रा की रेंज में है। मशीन को दुग्ध मम्खन, कपड़े को सफेद करने वाला, नील, ताड़ी, मिनरल वाटर जैसे मुक्त बहाव वाले अविकास द्रव उत्पादों को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 10 से 35 भरण प्रति मिनट तक भर सकती है और यह 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(303)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1684.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of automatic filling machine (Gravity Filler) of "CANNON-L" series with brand name "CANNON" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s Canflex Engineering Private Limited, Post Box No. 1919, C-8/3, Industrial Estate, Sanath Nagar, Hyderabad, and which is assigned the approval mark IND/09/2004/417;

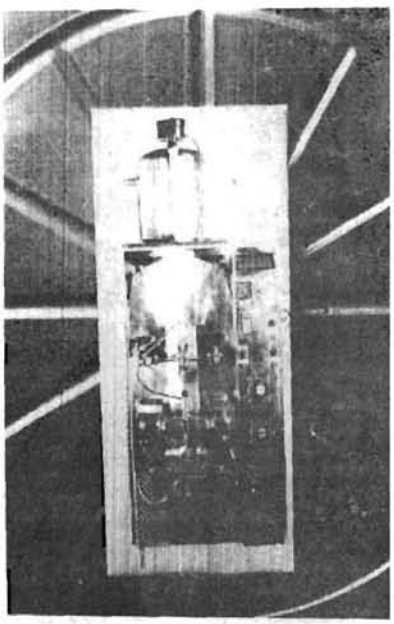

The said Model is an automatic filling machine (Gravity Filler). Its capacity is in the range of 10g to 1000g or equivalent volume. The machine is designed for filling free flowing non-viscous liquid products like milk butter milk, fabric whitener, blue, arrak, mineral water. It can fill up 10 to 35fills per minute and it operates on 230V, and 50Hertz alternatie current power supply

[F. No. WM-21(303)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1685—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स आदिनाथ स्केल एण्ड सिस्टम्स, 4227, गली बारान, बारा टूटी, सदर बाजार, दिल्ली-110006 द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "ए टी टी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "एडीआईटीएच" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/487 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 12 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अंतराल (एन) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(107)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1685.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "ATT" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "ADITH" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Adinath Scales & Systems, 4227, Gali Barana, Baratooti, Sadar Bazar, Delhi-110006 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/487;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 12 kg. and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg to 50 mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100 mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(107)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1686.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स आदिनाथ स्केल एण्ड सिस्टम्स, 4227, गली बारान, बारा टूटी, सदर बाजार, दिल्ली-110006 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "ए टी पी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "एडीआईटीएच" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/488 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

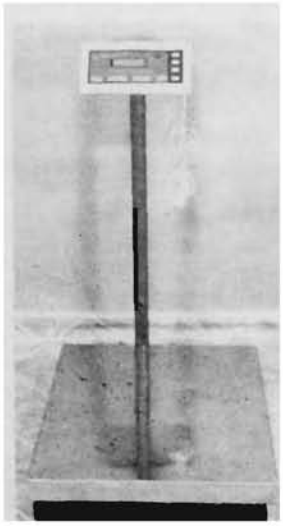

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(107)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1686.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "ATP" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "ADITH" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Adinath Scales and Systems, 4227, Gali Barana, Baratooti, Sadar Bazar, Delhi-110006 and which is assigned the approved mark IND/09/2004/488;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 kg. and minimum capacity of 1 kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50 Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and upto 1000 kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(107)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1687.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स शुभम फ्लेक्सिबिल पैकेजिंग, एम/सी एस (प्रा.) लि., प्लाट सं. 61, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा विनिर्मित "ए वी एफ एफ एस/8 एल वर 1" श्रृंखला के स्वत:सूचक, स्वचालित द्रव भरण मशीन (पिस्टन फिलर) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "शुभम फ्लेक्सिबिल पैकिजिंग" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/400 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) 1 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक या समतुल्य आयतन की रेंज की क्षमता के साथ एक स्वचालित भरण मशीन (पिस्टन फिलर) है। इसमें पैकेटों को भरने और शैम्पू, केश तेल, खाद्य तेल, 2 टी सेल, क्रीम, इंजन तेल और अन्य मुक्त प्रवाह वाले द्रवों जैसे द्रव को भरने के लिए सीलबंद युक्ति के लिए बहु पथी प्रणाली है। यह 30 थैली/मिनट से 70 थैली मिनट भरण करता है।

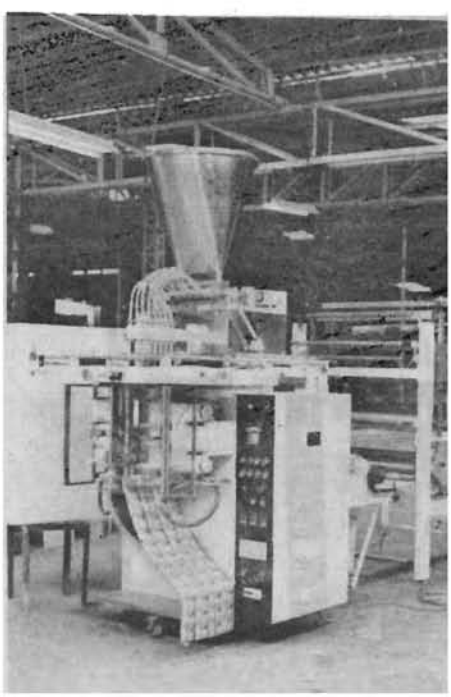

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन यथार्थता के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के 1 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की रेंज में क्षमता के साथ यथार्थता उपकरण भी होंगे।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(160)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1687.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of self indicating, Automatic Liquid Filling Machine (Piston Filler) of "AVFFS/8L ver.1" series with brand name "Shubham Flexible" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Shubham Flexible Packaging, M/Cs (P) Ltd., Plot No. 61, Sector-6, Faridabad, Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/400;

The said Model is an automatic filling machine (Piston Filler) with a capacity range of 1g to 1000g or equivalent volume. It has multi-track system for filling the packets and sealing device used for filling of liquid products like shampoo, hair oil, edible oil, 2T oil, cream, engine oil, and other free flowing liquids. It fills 30 pouches/minute to 70 pouches minute.

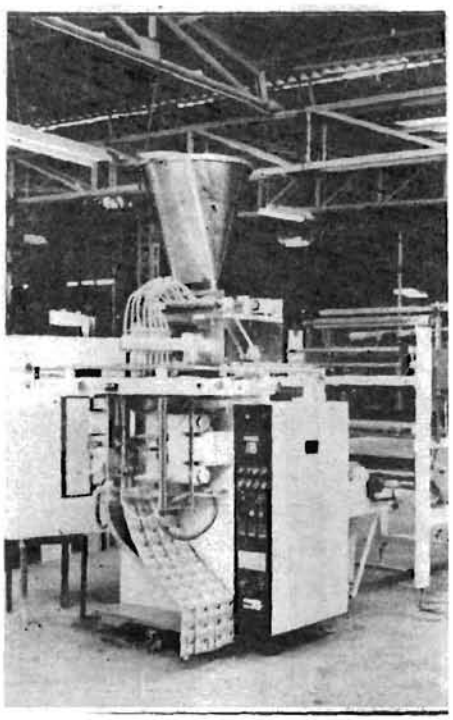

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, and performance of same series with maximum capacity in the range 1g to 1000g or equivalent volume manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design acuracy and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(160)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1688.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स शुभम फ्लेक्सिबिल पैकेजिंग, एम/सी एस (प्रा.) लि., प्लाट सं. 61, सेक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा विनिर्मित "ए वी एफ एफ एस/8 एल वर 1" शृंखला के स्वत:सूचक, स्वचालित भरण मशीन (कप फिलर) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "शुभम फ्लेक्सिबिल पैकेजिंग" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/401 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) 1 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की रेंज की क्षमता के साथ एक स्वचालित भरण मशीन (कप फिलर) है। इसका प्रयोग मुक्त प्रवाह वाले उत्पाद जैसे दुग्ध चूर्ण मसाले, काफी चूर्ण, चाय चूर्ण, डिटरजेंट चूर्ण, ग्लूकोज चूर्ण, सूजी, नमक आदि को भरने में किया जाता है। यह 60 से 240 थैली प्रति मिनट तक भरण करती है और यह 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

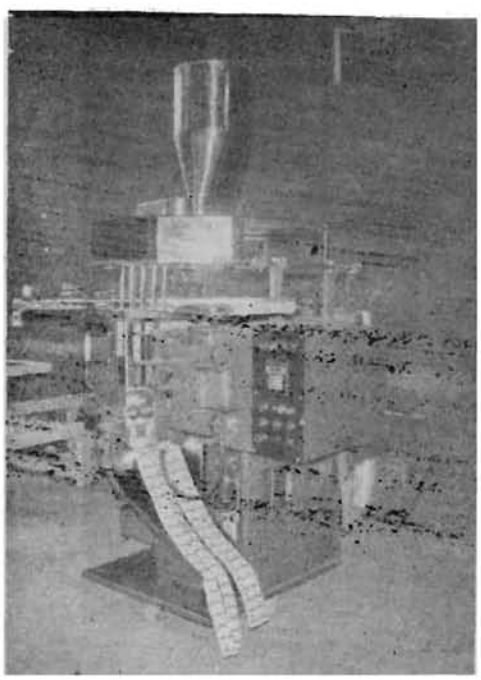

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबंद करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन यथार्थता के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, कार्यपालन के 1 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की रेंज की क्षमता के साथ यथार्थता उपकरण भी होंगे।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(160)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1688.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of self indicating, Automatic Filling Machine (Cup Filler) of "AVFFS/8L ver.1" series with brand name "Shubham Flexible Packaging" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Shubham Flexible Packaging, M/Cs (P) Ltd., Plot No. 61, Sector-6, Faridabad, Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/401;

The said Model (see the figure given below) is an automatic filling machine (Cup Filler) with a capacity range of 1g to 1000g. It is used for filling the free flowing products like milk powder, spices, coffee, powder, tea powder, detergent powder, glucose powder, suzi, salt etc. It fills 60 to 240 pouches per minute. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

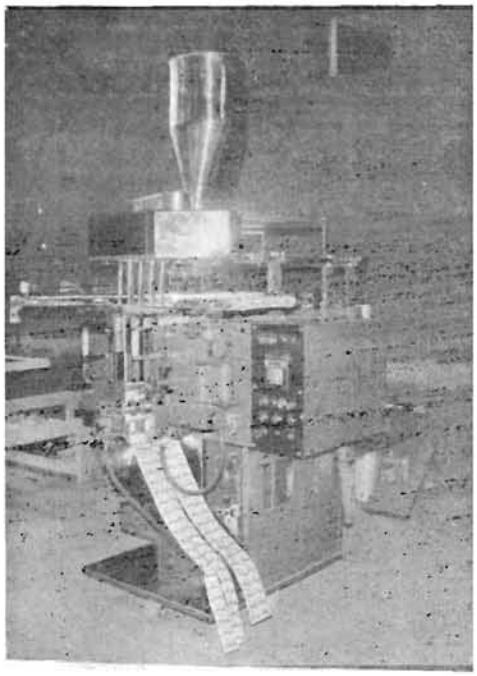

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make and performance of same series with capacity in the range 1g to 1000g manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design accuracy and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(1[illegible]02]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal M[illegible]ology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1689 .—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लागॉक वेट्रॉनिक्स, 11/558, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 (राजस्थान) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''एल टी'' शृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''लागॉक'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/228 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक विकृत (स्ट्रेन) गेज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) का उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

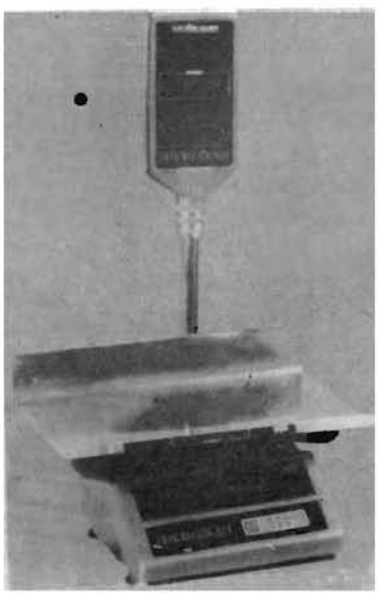

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो और 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक ''ई'' मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(177)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1689.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "LT" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "LAGOC" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Lagoc Weightronics, 11/558, Chopasni Housing Board, Jodhpur-342008 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/228;

The said model (See the figure given below) is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

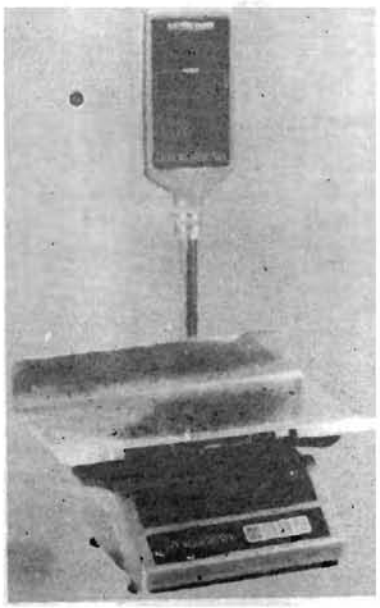

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg. to 2g. and with verification scale intervel (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(177)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1690.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लागॉक वेट्रॉनिक्स, 11/558, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 (राजस्थान) द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-II) वाले ''एल पी'' शृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''लागॉक'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/229 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक विकृत (स्ट्रेन) गैज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वाचालित (प्लेटफार्म प्रकार) का उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1100 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो और 100 मि. ग्रा. या उसे अधिक के ''ई'' मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से ऊपर और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(177)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1690.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "LT" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "LAGOC" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Lagoc Weightronics, 11/558, Chopasni Housing Board, Jodhpur-342008 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/229;

The said model (See the figure given below) is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1100kg. and minimum capacity of 5. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, and performance of same series with maximum capacity ranging above 50 kg. to 5000 kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(177)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1691.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स आर एस टैक्नोलोजिस एल आई जी बी-63, डा. ए एस राव नगर, ई सी आई आई पोस्ट हैदराबाद-500062 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''आर एस टी-पी डब्ल्यू'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मशीन-सिक्का प्रचालित प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''ग्राम'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/365 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार भार सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 200 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 50 ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि.ग्रा. से 250 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(87)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1691.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of model of the non-automatic weighing instrument with digital indication (Person weighing machine-coin operated) of medium accuracy (Accuracy class-III) belonging to 'RST-PW' series with brand name "GRAMS" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s R.S. Technologies LIG B-63, Dr. A.S. Rao Nagar, E.C.I.I. Post Hyderabad-500062 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/365;

The said model (See the figure given) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with the maximum capacity of 200kg. and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. The Display is of Light Emiting Diode (LED) Type. It operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, Machine shall be sealed to prevent its opening for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 250kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 50g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(87)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1692.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जय इंस्ट्रूमेंट्स एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सी-64, टी.टी.सी इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला थाणे, नवी मुंबई-400 705 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''फ्लैक्सी-वे-एफ डब्ल्यू'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''जयपान'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/385 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

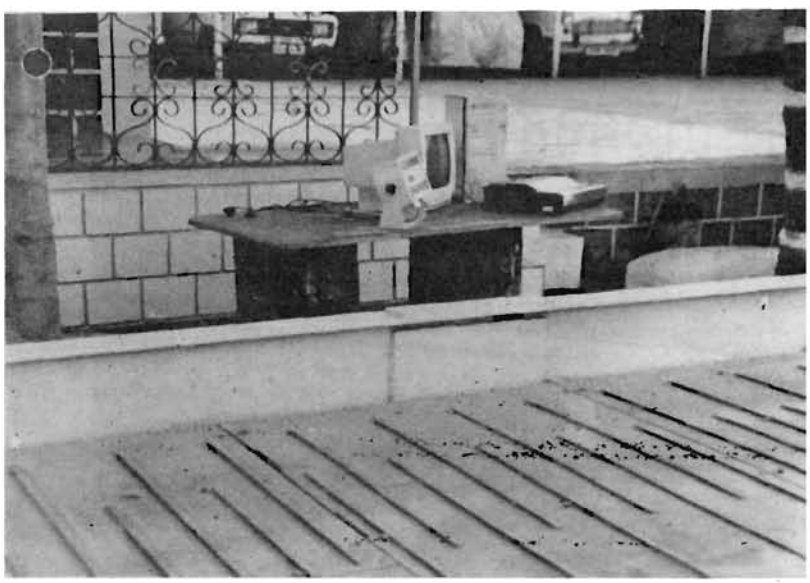

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 40 टन और न्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 कि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि. ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 5 टन से अधिक और 100 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(144)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1692.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Weighbridge type) with digital indication of "FLEXI-WEIGHT-FW" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "JAYPAN" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Jay Instruments and Systems Private Limited, C-64, TTC Industrial Area, District-Thane, Navi Mumbai-400 705 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/385;

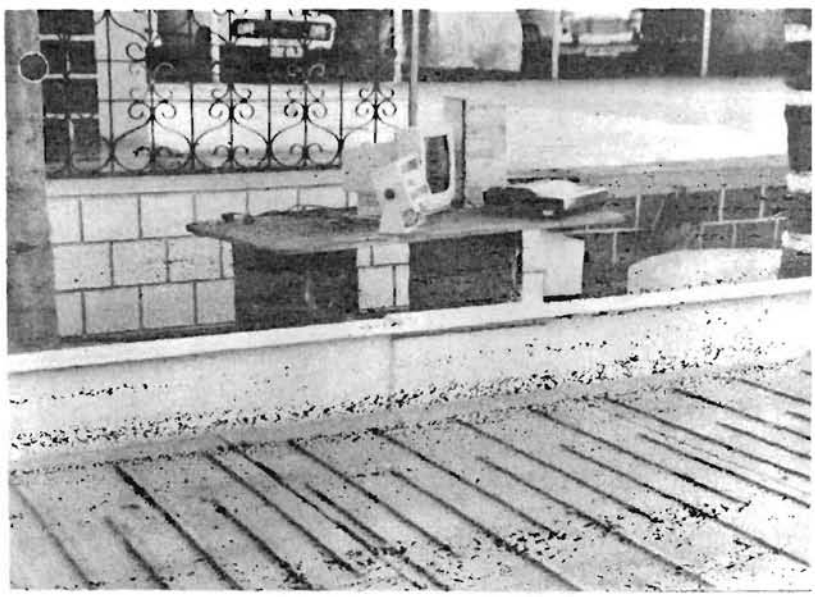

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Weighbridge type) with a maximum capacity of 40 tonnes and minimum capacity of 200kg. The verification scale interval (e) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 100 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(144)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1693.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रिलाईंस स्केल ट्रेडर्स, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला, 364515 गुजरात द्वारा विनिर्मित गणक मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/371 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक गणक मशीन है जो दण्ड के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। इसके ब्राण्ड का नाम बंशी है।

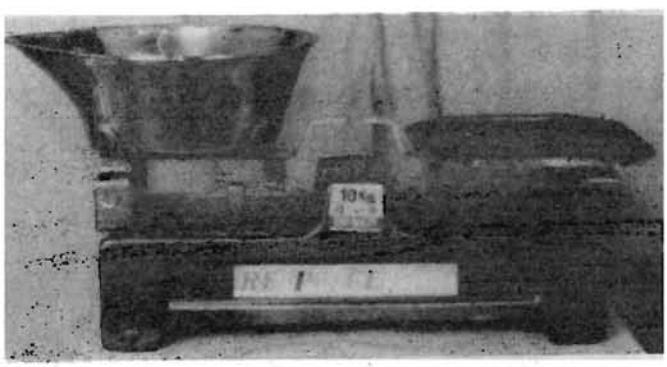

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की गणक मशीन भी होंगी जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्रा. तक की है।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(232)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1693.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein reffered to as the said model), manufactured by M/s Reliance Scale Traders, Shivaji Nagar, Savarkundla-364 515, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/371;

The said model (see the figure given below) is counter machine working on the principle of beam with maximum capacity of 10kg with brand name "BANSI".

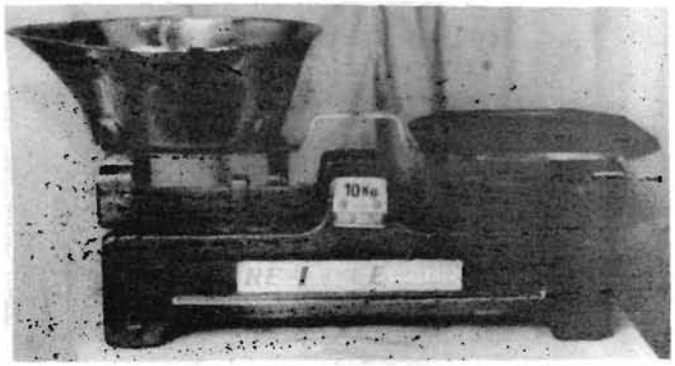

In addition to sealing the stamping plate, machine shall be sealed to prevent its opening for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the counter machine of semilar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(232)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1694.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्पार्क सिस्टम्स, 811, IV ब्लाक, बी ई एल लेआउट, विधारानपुरा, बंगलौर-560 097 द्वारा विनिर्मित उच्च यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "एस एस-जेपी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "स्पार्क" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/451 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 15 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान के अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(63)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. **1694.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "SS-JP" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "SPARK" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Spark Systems, 811, IV Block, BEL Layout, Vidyaranpura, Bangalore-560 097 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/451;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 15 kg and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1 mg to 50mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(63)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1695.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्पार्क सिस्टम्स, 811, IV ब्लाक, बी ई एल लेआउट, विधारानपुरा, बंगलौर-560 097 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "एस एस-टी बी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "स्पार्क" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/452 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 15 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(63)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1695.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "SS-TB" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "SPARK" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s Spark Systems, 811, IV Block, BEL Layout, Vidyaranpura, Bangalore-560 097 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/452;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100 mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principles, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(63)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1696.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स स्पार्क सिस्टम्स, 811, IV ब्लाक, बी ई एल लेआउट, विधारानपुरा, बंगलौर-560 097 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''एस एस-पी टी'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''स्पार्क'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/453 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

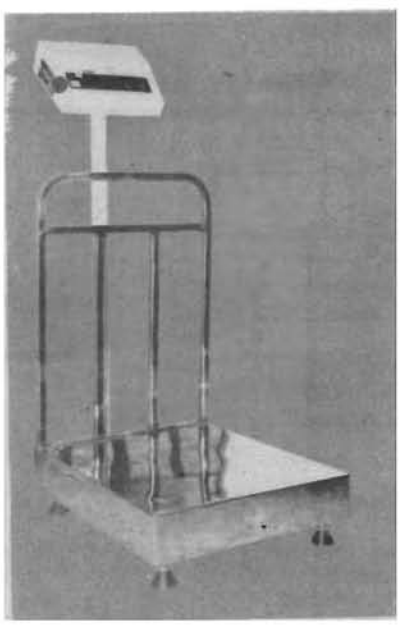

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(63)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1696.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "SS-PT" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "SPARK" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s Spark Systems, 811, IV Block, BEL Layout, Vidyaranpura, Bangalore-560 097 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/453;

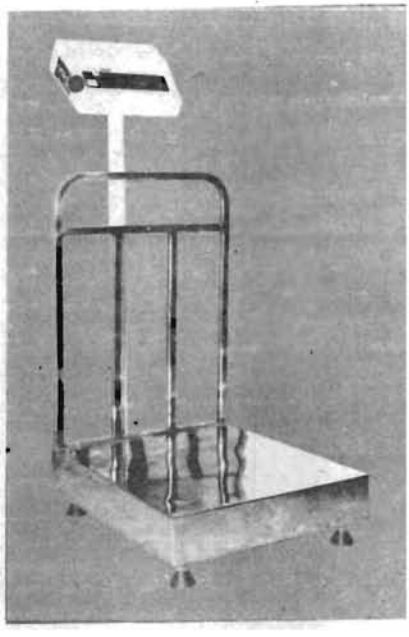

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 kg and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg and up to 1000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(63)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का.आ. 1697.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बी. एस. इंजीनियरिंग वर्क्स, 433, भोपा रोड, नई मंडी, मुजफ्फरनगर-251 001 (उ. प्र.) द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''बी एस ई'' श्रृंखला के सदृश सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु-विषम भुज तुला प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''धीमान'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/386 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

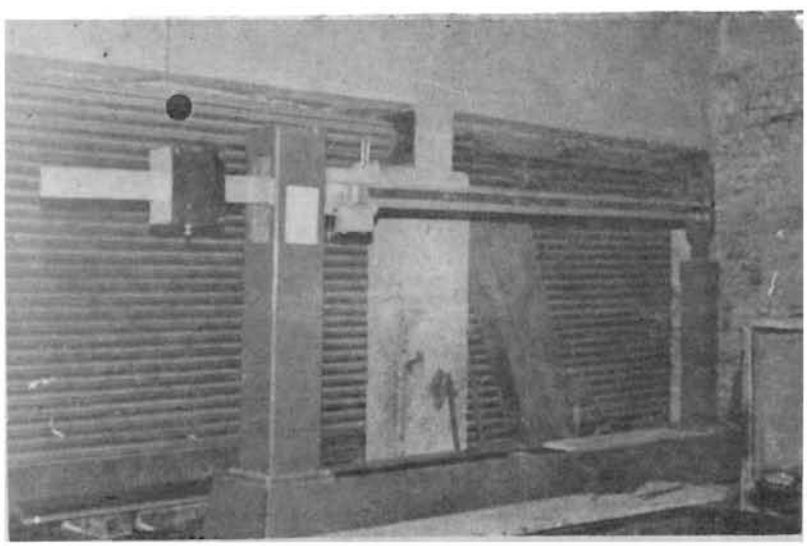

उक्त मॉडल यांत्रिक लीवर आधारित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) सदृश सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु-विषम भुज तुला प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 40 टन और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 कि. ग्रा. है।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि. ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 टन से अधिक और 100 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(94)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1697.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of Model of non-automatic weighing instrument (Weighbridge-Steel yard type) with analogue indication (hereinafter referred to as the said model) belonging to medium accuracy class (Accuracy class-III) and "BSE" series with brand name "Dhiman", manufactured by M/s B. S. Engineering Works, 453, Bhopa Road, New Mandi, Muzaffar Nagar-251 001 (U.P.) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/386;

The said model is a mechanical lever based non-automatic weighing instrument (Weighbridge-Steelyard type) with analogue indication of maximum capacity 40 tonne, minimum capacity 100kg and belonging to medium accuracy class (Accuracy class-III). The value of verification scale interval 'e' is 5kg.

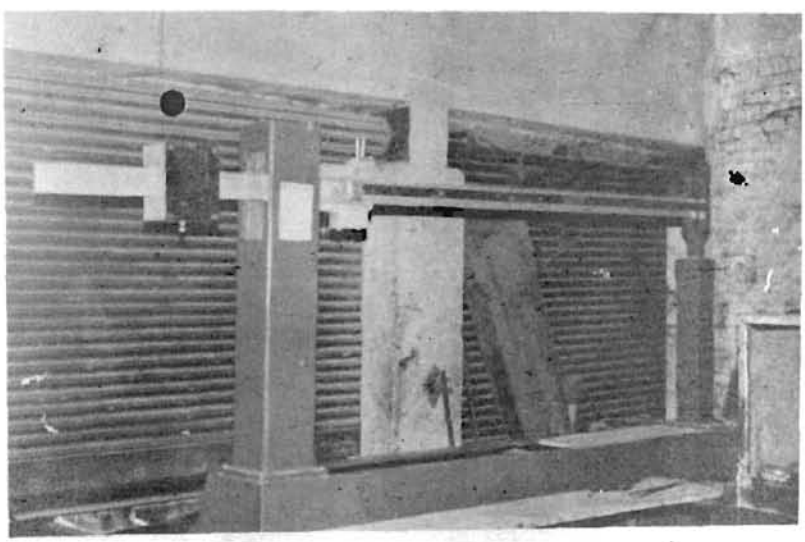

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 100 tonne and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5kg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(94)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का०आ० 1698.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स साईसन इंजीनियर्स, 26, अजंता काम्पलेक्स, कनाट प्लेस, एन-5, सिडको, औरंगाबाद-431003 (एम एस) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले ''जी टी एस'' श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''जीसिकी'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/238 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक विकृत (स्ट्रेन) गेज प्रकार का लोड सेल आधारित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) का एक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रदर्श इकाई प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकार की है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को सीलबन्द करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाती है।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक ''ई'' मान के लिए 100 से 5,0000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) के लिए और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 5,000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k}, या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(91)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1698.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication (herein referred to as the Model) belonging to high accuracy class (accuracy class-II) and "GTS" series with brand name "JISIKI", manufactured by M/s. Saisun Engineers, 26 Ajanta Complex, Cannought Place, N-5, Cidco, Aurangabad-431 003 (M.S.) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/238;

The said Model (see the figure given) is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of maximum capacity 22 kg. minimum capacity 100g and belonging to high accuracy class (accuracy class-II). The value of verification scale interval 'e' is 2g. The display unit of light emitting diode type. The instruments operates on 230 V, 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate sealing is also done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50 kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1 mg. to 50 mg. and with the number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 50,000 for 'e' value of 100 mg. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(91)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का०आ० 1699.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स साईसन इंजीनियर्स, तुलसा, सं. एन-7, जी-3-46, सिडको, औरंगाबाद-431003 महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "एस पी एस" श्रृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "जीसिकी" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/340 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक विकृत (स्ट्रेन) गेज प्रकार लोड सैल आधारित (प्लेटफार्म प्रकार) का अवस्चालक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 600 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2500 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) अंतराल सहित 50 कि..ग्रा. से ऊपर और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k}, या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(91)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1699.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Plateform type) with digital indication of "SPS" series of high accuracy(Accuracy class-II) and with brand name "JISIKI", (herein referred to as the Model) manufactured by M/s Saisun Engineers, Tulsa, No. N-7, G-3-46, CIDCO, Aurangabad-431 003 Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/2004/340;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Plateform type) with a maximum capacity of 600 kg. and minimum capacity of 2500g.The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

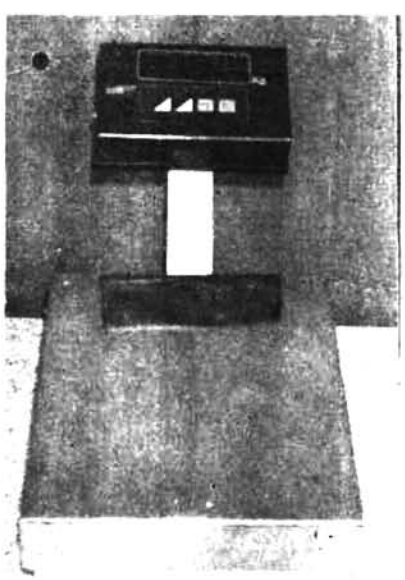

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government herby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. to 1000kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100 mg. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(91)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1700.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कास वेईंग इंडिया प्रा. लि., 568 उद्योग विहार फेस-V, गुड़गांव-122016 (हरियाणा) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले "बी डब्ल्यू" शृंखला के स्वत:सूचक, अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "कास" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/292 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक विकृत (स्ट्रेन) गेज प्रकार का लोड सैल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

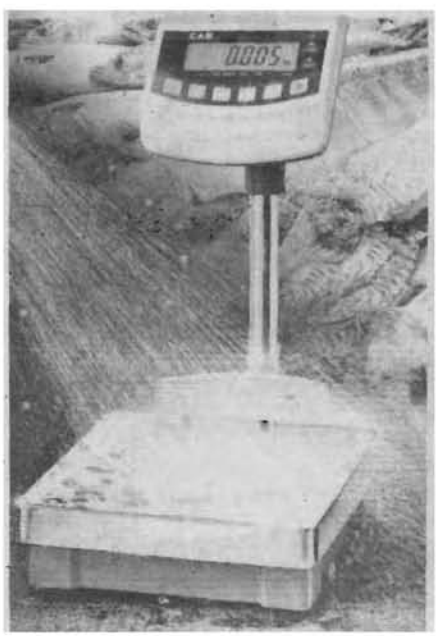

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल भी विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से लेकर और 500 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{क}, 2×10^{क} या 5×10^{क}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(31)/2000]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1700.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of the self indicating, non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "BW" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "CAS" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. CAS Weighing India Pvt. Ltd., 568, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122 016 (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/292;

The said Model (see the figure given below) is a strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 150kg. and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50Hertz alternative current power supply.

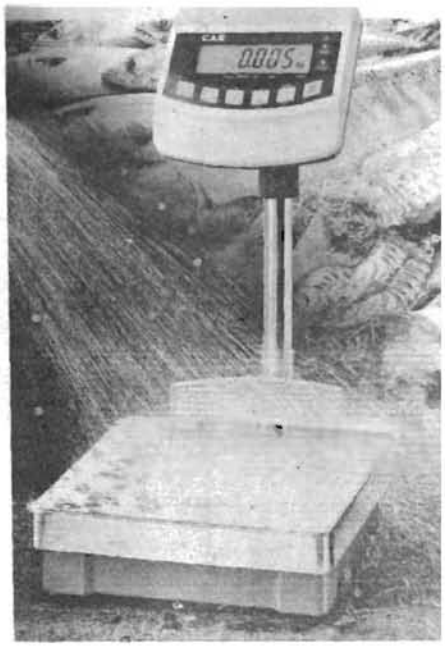

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 500kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same material with which, the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(31)/2000]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1701.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सी ए एस वेईंग इंडिया लिमिटेड, 568 उद्योग विहार फेस-V, गुड़गांव (हरियाणा)-122016 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "पी ओ स्केल" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सी ए एस" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/471 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{क}, 2×10^{क} या 5×10^{क}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(233)/2004]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1701.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic weighing instrument with digital indication of "POScale" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "CAS" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. CAS Weighing India Ltd., 568, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon (Haryana)-122 016 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/471;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The liquid crystal display (LCD) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with "e" value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same material with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(233)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1702.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स उदयन स्केल्स कं., म्यूनिसिपल शापिंग कांप्लेक्स, सं. 12, कुमारन रोड, तिरुपुरा-641601 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''यू एस-टी बी'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम ''सनराइज'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/409 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

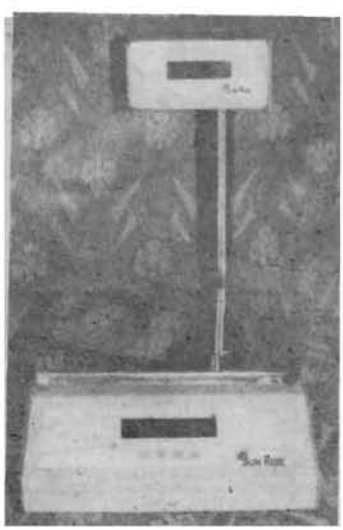

उक्त माडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान $1 \times 10^{\text{के}}$, $2 \times 10^{\text{के}}$ या $5 \times 10^{\text{के}}$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(61)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. **1702.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Table Top type) with digital indication of "US-TB" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "SUNRISE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. The Udyan Scales Co,. Municipal Shopping Complex, No. 12, Kumaran Road, Tirupur-641601 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/409;

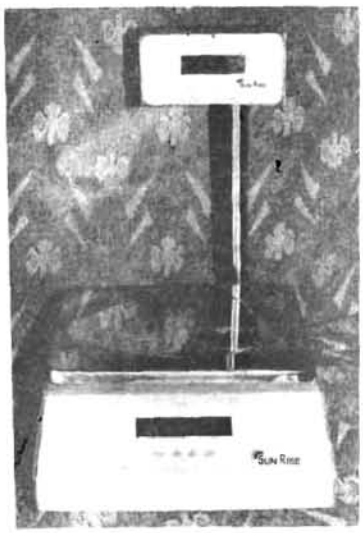

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table Top type) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 100mg or more and with "e" value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(61)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1703.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स उदयन स्केल्स कं., म्यूनिसिपल शापिंग कांप्लेक्स, सं. 12, कुमारन रोड, तिरुपुरा-641601 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "यू एस-पी एफ" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सनराइज" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2004/410 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

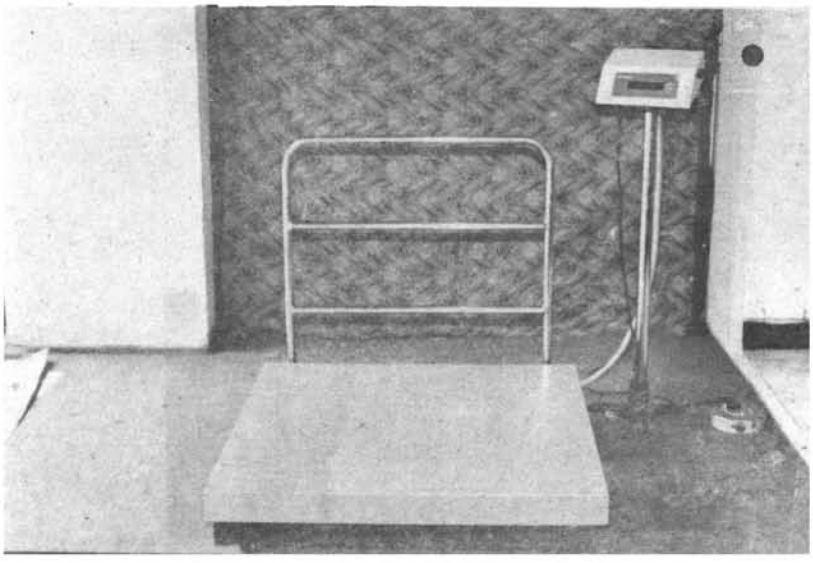

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(61)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1703.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "US-PF" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "SUNRISE" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. The Udyan Scales Co,. Municipal Shopping Complex, No. 12, Kumaran Road, Tirupur-641601 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/410;

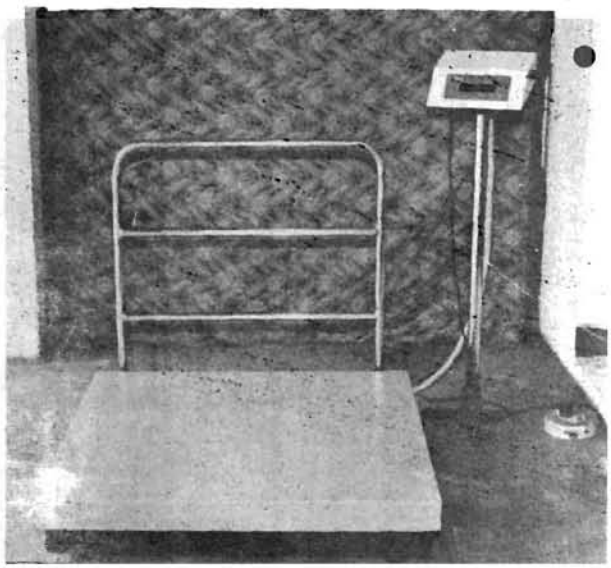

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000kg and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and up to 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(61)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2005

का. आ. 1704.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स जेन इंस्ट्रूमेंट्स, सी-19/4 जयश्री टेनामेंट्स, अरबुध नगर, क्रास रोड, भाग्यलक्ष्मी डेयरी के ऊपर उद्धव, अहमदाबाद, गुजरात-382415, द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "एम एस" श्रृंखला के स्वत:सूचक, अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "मटीज" है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई एन डी/09/2003/138 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति (स्ट्रेन) गेज प्रकार का भार सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 11 कि.ग्रा. है। इसकी न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान (ई) अन्तराल 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी मुद्रांकित किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है, विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(67)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 21st April, 2005

S.O. 1704.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of self-indicating, non-automatic (Table type) weighing instrument with digital indication of "MS" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "MATIZE" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Zen Instruments, C-19/4, Jayashree Tenaments, Arbudh Nagar, Cross Road, Above Bhagyalakshmi Dairy, Odhav, Ahmedabad, Gujarat-382415 and which is assigned the approval mark IND/09/2003/138;

The said Model (See the figure given) is a strain gauge load cell based type weighing instrument with a maximum capacity of 11kg and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, and 50Hertz alternate current power supply.

Sealing : In addition to sealing the stamping plate, sealing is done to prevent the opening the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg to 50mg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5,000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with "e" value of $1x10^k$, $2x10^k$ or $5x10^k$, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(67)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई, 2005

का. आ. 1705.—केन्दीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में मांगल्या (इन्दौर) संस्थापन से हरयाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्दीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियॉ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमे उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री दीपक नन्दी, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई–मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बी–105, इन्द्र विहार, तलवंडी, कोटा – 324005 (राजस्थान) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : पिड़ावा जिला : झालावाड़ राज्य : राजस्थान

क्र0	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4
1	सरखेड़ी	977	0.0648
		952	0.1224
		953	0.0072
		976	0.2232
		975	0.2376
		973	0.1944
		966	0.1584
		669	0.1368
		667	0.0792
		555	0.0216
		556	0.2664
		559	0.0720
		560	0.1008
		561	0.1440
		563	0.0864
		564	0.0360
		591	0.0144
		592	0.0648
		593	0.1224
		511	0.0288
		508	0.0020
		510	0.1440
		470	0.2376
		452	0.2016
		441	0.1944
		442	0.0360
		443	0.0936
		444	0.1440
		445	0.2592
		446	0.0040
		432	0.0576
2	रामपुरिया	672	0.0288
		671	0.0504
		670	0.0072
		679	0.0432
		681	0.2232
		683	0.1440
		686	0.1440
		687	0.0072
		689	0.3672
		669	0.0360
		690	0.0432
		691	0.0072

1	2	3	4
2	रामपुरिया (जारी.....)	668	0.0360
		667	0.0216
		666	0.1512
		646	0.1800
		644	0.1152
		643	0.1224
		641	0.2088
		597	0.0144
		542	0.2232
		544	0.0144
		545	0.0576
		547	0.0360
		548	0.0288
		549	0.0072
		550	0.0504
		551	0.0432
		552	0.0504
		573	0.0648
		190	0.0288
		179	0.0144
		185	0.1440
		189	0.1080
		187	0.1224
		227	0.0360
		221	0.0072
		228	0.1080
		229	0.1728
		230	0.0040
		231	0.0288
		232	0.0792
		245	0.2232
		247	0.1800
		248	0.1440
		121	0.0720
		120	0.0504
		119	0.3528
		118	0.0720
		115	0.2808
		111	0.1008
		110	0.0288
		81	0.0720
		85	0.1440
		82	0.1008
		84	0.0040
		83	0.0288
3	रामटी	172	0.0504
		173	0.1224
		171	0.2880
		169	0.0144
		147	0.2880
		142/540	0.0072
		140	0.2520
		139	0.1080
		138	0.0360
		137	0.1440
		134	0.1440
		135	0.0144
		130	0.0144
		93	0.1080
		96	0.1440
		97	0.2016
		98	0.0648
		99	0.1512
		76	0.0360
		73	0.0144
		51	0.1584
		67	0.5472
		64	0.0216

1	2	3	4
3	रामटी (जारी.....)	59	0.2880
4	शेरपुर	653	0.0288
		652	0.1944
		626	0.0072
		627	0.2592
		628	0.2016
		629	0.2016
		621	0.2304
		620	0.0216
		604	0.2592
		603	0.0864
		602	0.2232
		601	0.0720
		594	0.0432
		594	0.0144
		338	1.6832
		337	0.0288
		336	0.2664
		332	0.0648
		331	0.1584
5	दौलतपुरा	349	0.0432
		342	0.0720
		348	0.1080
		347	0.1296
		349	0.6552
		350	0.0040
		384	0.0072
		354	0.2376
		357	0.3312
		360	0.0144
		304	0.2376
		527/302	0.1224
		524/302	0.2376
		521/301	0.0864
		522/301	0.2160
		525/301	0.2520
		268	0.2448
		267	0.0040
		266	0.0144
		264	0.1872
		263	0.1008
		260	0.1440
		258	0.2376
		257	0.1440
		256	0.1512
6	धरोनिया	1717	0.8208
		1718	0.3744
		1734	0.0216
		1790/1945	0.1728
		1790/2009	0.0216
		1791	0.0864
		1789	0.0216
		1773	0.1440
		1776	0.0864
		1777	0.1080
		1779	0.1440
		1780	0.1440
		1781	0.0072
		1782	0.0864
		1783	0.1656
		1784	0.0216
		1767	0.0144
		1807	0.0216
		1809	0.1872
		1856	0.0072
		1820	0.0936
		1819	0.0040
		1821	0.0864

1	2	3	4
6	धरोनिया (जारी.....)	1822	0.0864
		1847	0.0864
		1846	0.0040
		1848	0.0576
		1872	0.0792
		1839	0.1224
		1838	0.0936
		1837	0.0792
		1835	0.1368
		1833	0.0360
7	निमाहेडा	166	0.1296
		167	0.0504
		168	0.0432
		186	0.2088
		185	0.0720
		187	0.2304
		196	0.0432
		195	0.0792
		194	0.1440
		199	0.0216
		199/245	0.0864
		193	0.0288
		200	0.1224
		201	0.0720
		447	0.0720
		448/561	0.0576
		448/562	0.0504
		448/563	0.0504
		448/564	0.0720
		545	0.0144
		542	0.2160
		543	0.0040
		452	0.0144
		526	1.5192
8	कचरा खेडी	661/700	0.0936
		661/701	0.0288
		661/705	0.0288
		661	0.6120
		654	0.0360
		650	0.0792
		649	0.0288
		645	0.1368
		644	0.0504
		642	0.1584
		638	0.0864
		639	0.0216
		437	0.1080
		630	0.1512
		631	0.0216
		629	0.0144
		521	0.0036
		522	0.0072
		523	0.0576
		520	0.0072
		524	0.0864
		525	0.1080
		526	0.0072
		528	0.0720
		529	0.0144
		533	0.0792
		538	0.1512
		536	0.0144
		537	0.0144
		539	0.0360
		603	0.0648
		604	0.0936
		601	0.0792
		600	0.0648

1	2	3	4
8	जबरा खेड़ी (जारी.....)	599	0.0792
		599/729	0.1080
		598	0.0216
		604	0.0288
		597	0.2664
9	फतेहगढ़	581/1109	0.0216
		581	0.0576
		580	0.0216
		525/1082	0.1584
		515	0.0288
		517	0.0792
		518	0.1008
		519	0.2304
		524	0.0720
		521	0.1224
		522	0.0144
		523/1107	0.0360
		545	0.1368
		523/1108	0.0360
		523	0.0216
		506	0.1368
		546	0.0288
		547	0.0288
		497/1173	0.0072
		497	0.0576
		490/1104	0.0020
		490	0.0288
		489	0.0648
		488	0.0288
		487	0.0072
		486	0.0720
		485	0.0020
		481	0.0288
		478	0.0936
		479	0.0144
		475	0.0288
		474	0.0504
		473	0.0216
		472	0.0144
		470	0.0576
		471	0.0144
		468	0.0144
		463	0.0144
		466	0.0072
		465	0.0288
		459	0.0576
		455/1172	0.1728
		454/1171	0.0432
		446	0.0216
		757	0.0576
		758	0.1008
		422	0.0144
		759	0.0216
		444	0.0020
		428	0.0720
		427	0.0936
		422/1105	0.0144
		424	0.0648
		423	0.0288
		421	0.0648
		420	0.0360
		419	0.0360
		417	0.0432
		418	0.0072
		413	0.0216
		411	0.0020
		412	0.0432
		409	0.0216

1	2	3	4
9	फतेहगढ (जारी.....)	408	0.0288
		405/1100	0.0040
		405	0.0288
		404	0.1080
		400	0.0288
		399	0.0432
		403	0.0072
		385	0.0360
		384	0.1872
		383	0.0144
		380	0.0792
		379	0.0504
		823/1122	0.1224
		823	0.1584
		824	0.0072
		825	0.1080
		927	0.3816
		926	0.1368
		923	0.2664
		922	0.0360
		921	0.0864
		920	0.0792
		901	0.1440
		902	0.1512
		912	0.0288
10	खिजरपुर	6	0.1800
		7	0.0720
		9	0.2664
		28	0.0864
		29	0.1008
		30	0.0936
		31	0.1944
		33	0.0792
		35	0.2592
		36	0.0576
		79	0.0576
		99	0.0072
		102	0.2736
		78	0.1296
		115	0.1080
		116	0.0936
		125	0.0648
		128	0.0216
		129	0.1296
		124	0.0072
		123	0.0040
		144	0.1296
		145	0.0288
		159	0.0144
		158	0.0792
		160	0.0288
		186	0.0144
		187	0.0432
		185	0.0040
		179	0.0040
		190	0.0864
		192	0.0360
		193	0.0144
		194	0.0020
		196	0.0504
		195	0.0144
		199	0.0576
		200	0.0432
		396	0.0936
		395	0.1152
		397	0.0864
		394	0.1152
		458	0.0144

1	2	3	4
10	खिजरपुर (जारी.....)	398	0.3096
		455	0.0020
		399	0.0020
		401	0.0216
		402	0.0360
		421	0.0576
		422	0.0432
		427	0.1944
		428	0.0432
		429	0.0144
		430	0.0040
		197	0.0288
11	बानोर	927	0.0144
		917	0.1296
		918	0.0144
		919	0.0360
		920	0.0144
		921	0.2160
		943	0.0216
		942	0.1584
		941	0.1080
		940	0.1152
		939	0.0936
		946	0.0360
		950	0.1296
		949	0.0648
		956	0.1296
		957	0.0144
		959	0.0288
		958	0.0072
		984	0.1008
		955	0.1440
		960	0.1224
		983	0.0648
		982	0.0040
12	आसॉदिया	2	0.2376
		3	0.0144
		4	0.0216
		5	0.1440
		5/407	0.0864
		13/409	0.1944
		36	0.1440
		35	0.0144
		34	0.0864
		37	0.0144
		33	0.0864
		15	0.0144
		20	0.4104
		96	0.0144
		99	0.1800
		102	0.1296
		101	0.0792
		103	0.1728
		106	0.0936
		108	0.0936
		107	0.0072
		121	0.0216
		120	0.0020
		122	0.1584
		131	0.1152
		130	0.3024
		129	0.0072
		128	0.0576
		161	0.0216
13	कोटडी खुर्द	13	0.0216
		15	0.0288
		14	0.0360
		18	0.1080

1	2	3	4
13	कोटडी खुर्द (जारी.....)	19	0.0072
		26	0.1944
		25	0.1368
		27	0.0072
		32	0.1944
		33	0.1944
		37	0.0144
		93	0.1872
		98	0.0504
		99	0.1008
		103	0.2592
		89	0.1152
		88	0.0144
		87	0.2808
		82	0.2304
		81	0.2448
		71	0.0216
		70	0.2736
14	सेमली भवानी	251	0.0216
		253	0.2232
		259	0.1152
		258	0.0504
		257	0.0648
		260	0.0020
		256	0.2088
		247	0.1008
		246	0.0432
		243	0.0020
		266	0.0288
		305	0.0720
		306	0.1656
		319	0.1368
		320	0.2448
		323	0.0020
		322	0.1512
		321	0.0072
		324	0.0144
		422	0.2736
		419	0.0216
		420	0.3528
		421	0.0576
		407	0.4104
		456	0.1080
		455/474	0.0072
		406	0.0144
		396	0.0216
		395	0.2088
		393	0.0576
		397	0.1368
15	बोरबंद	361	0.0144
		362	0.1368
		373	0.0144
16	दीवल खेडा	301	0.0072
		302	0.1008
		303	0.0792
		317	0.2664
		318	0.1368
		320	0.0144
		369	0.0144
		368	0.0144
		370	0.2160
		371	0.1728
		388	0.1080
		390	0.1728
		391	0.0216
		389	0.0072
		395	0.2520
		396	0.0144

1	2	3	4
16	दीवल खेडा (जारी.....)	343	0.0040
		399	0.1728
		495	0.0072
		546	0.1368
		566	0.1080
		564	0.2016
		569	0.0072
		570	0.1440
		700	0.0216
		870	0.2808
		869	0.2088
		861	0.0144
		864	0.1224
		863	0.1584
17	मुंडला	856	0.0720
		855	0.1296
		858	0.0072
		859	0.1008
		865	0.1152
		861	0.0040
		864	0.0936
		866	0.1224
		867	0.0936
		795	0.2304
		803	0.2016
		789	0.0040
		792	0.0020
		791	0.1368
		790	0.1368
		771	0.2880
		772	0.1584
		774	0.0504
		775	0.0072
		770	0.0216
		649	0.0144
		651	0.4608
		650	0.0020
		653	0.0216
		654	0.0720
		656	0.1728
		657	0.0216
		658	0.0792
		759	0.0072
		760	0.0144
		661	0.0040
		176	0.0576
		667	0.0288
		668	0.0288
		669	0.0566
		670	0.1728
		671	0.0144
		537	0.0040
		535	0.1008
		542	0.0020
		534	0.0720
		523	0.0144
		533	0.1512
		531	0.1440
		528	0.0040
		529	0.0040
		530	0.0072
		312	0.0144
		313	0.0144
		314	0.0144
		315	0.0504
		316	0.0216
		317	0.0288
		319	0.0288

1	2	3	4
17	मुंडला (जारी....)	320	0.0288
		321	0.0144
		322	0.0144
		323	0.0936
		324	0.0288
		340	0.1296
		300	0.0020
		339	0.0040
		341	0.0720
		359	0.0216
		358	0.0648
		360	0.0144
		357	0.0360
		354	0.0020
		368	0.0792
		367	0.0144
		371	0.0576
		370	0.0144
		372	0.0720
		378	0.0072
		377	0.1080
		376	0.0360
		375	0.0216
		389	0.1512
		393	0.0072
		388	0.0144
18	कल्याणपुरा	36	0.0648
		35	0.0936
		37/89	0.1008
		44	0.0216
		77	0.4032
		76	0.1296
		75	0.0288
		74	0.1152
		48	0.0020
		49	0.0072
		57	0.1512
		51	0.0216
		52	0.0216
		53	0.0504
		54	0.0576
		55	0.0040
		56	0.0576
		28	0.0648
		59	0.1080
		60	0.0864
		43	0.0288
19	बजरंगपुरा	59	0.0360
		57	0.0576
		58	0.2160
		56	0.0504
		54	0.1152
		6	0.0216
		7	0.0504
		8	0.0360
		9	0.1224
		10	0.0576
		11	0.0576
		12	0.0792
		45	0.2160
		44	0.0360
		43	0.1800
		42	0.0288
		22	0.0144
		29	0.1008
		28	0.0504
20	रघुनाथपुरा	246	0.0072
		247	0.0288

1	2	3	4
20	रघुनाथपुरा (जारी....)	248	0.0144
		249	0.1296
		250	0.0072
		251	0.1296
		234	0.1152
		230	0.1656
		231	0.0040
		232	0.2160
		289	0.0792
		233	0.0864
		192	0.2088
		193	0.1656
		191	0.0144
		189	0.0144
		239	0.0216
		184	0.0040
		127	0.1368
		126	0.0288
		125	0.1368
		129	0.0144
		131	0.0040
		130	0.0040
		150	0.1440
		149	0.2232
		146	0.1368
		147	0.0792
		145	0.0288
		144	0.0144
		361	0.0216
		363	0.0504
		364	0.0936
		367	0.0040
		365	0.0288
		366	0.1368
		354	0.0576
		369	0.0864
		370	0.1584
		387	0.1440
		386	0.0072
		388	0.1296
		389	0.1728
		392	0.2304
		391	0.0040
		393	0.2016
		395	0.1512
21	डावल	93	0.0288
		98	0.0576
		97	0.1800
		96	0.0648
		102	0.0072
		103	0.1080
		109	0.2232
		113	0.1880
		117	0.1080
		114	0.1224
		115	0.0072
		122	0.3096
		119	0.0144
		120	0.0072
		121	0.1872
22	सालरी	1010	0.0360
		1007	0.2376
		1008	0.0020
		1009	0.0072
		1002	0.1512
		1000	0.0864
		997	0.0144
		995	0.0432

1	2	3	4
22	सालरी (जारी....)	994	0.2448
		853	0.0072
		854	0.0040
		991	0.2088
		990	0.1008
		989	0.0432
		858	0.1512
		930	0.0144
		954	0.0432
		955	0.2088
		956	0.0072
		957	0.0288
		958	0.0576
		963	0.1008
		960	0.0072
		964	0.0504
		930	0.0288
		925	0.0648
		937	0.0144
		924	0.0936
		921	0.0792
		920	0.0720
		918	0.1728
		1077	0.0216
23	सेमली कल्याण	266	0.0360
		268	0.1872
		255	0.6336
		257	0.0360
		269	0.0216
		276/419	0.0720
		253	0.1080
		251	0.0936
		250	0.1584
		248	0.0040
		246	0.1008
		247	0.1440
		239	0.2952
		237	0.1656
		234	0.0288
		329	0.1080
		330	0.0040
		331	0.1728
		332	0.0360
		224	0.0792
		227	0.1224
		228	0.0648
		230	0.0360
		174	0.0144
		190	0.0144
		189	0.0144
		188	0.1296
		176	0.1224
		177	0.0504
		178	0.1296

[फा. सं. आर-31015/84/2004-ओ.आर-I]

हरीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd May, 2005

S. O. 1705.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Manglya (Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh, an extension pipeline to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi should be laid by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Deepak Nandi, Competent Authority, Mumbai-Manglya Pipeline Extension Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, B-105, Indravihar, Talwandi, Kota-324005 (Rajasthan).

SCHEDULE

TEHSIL : PIDAWA		DISTRICT : JHALAWAR	STATE : RAJASTHAN
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1	SARKHEDI	977	0.0648
		952	0.1224
		953	0.0072
		976	0.2232
		975	0.2376
		973	0.1944
		966	0.1584
		669	0.1368
		667	0.0792
		555	0.0216
		556	0.2664
		559	0.0720
		560	0.1008
		561	0.1440
		563	0.0864
		564	0.0360
		591	0.0144
		592	0.0648
		593	0.1224
		511	0.0288
		508	0.0020
		510	0.1440
		470	0.2376
		452	0.2016
		441	0.1944
		442	0.0360
		443	0.0936
		444	0.1440
		445	0.2592
		446	0.0040
		432	0.0576
2	RAMPURIYA	672	0.0288
		671	0.0504
		670	0.0072
		679	0.0432
		681	0.2232
		683	0.1440
		686	0.1440
		687	0.0072
		689	0.3672
		669	0.0360
		690	0.0432
		691	0.0072

1	2	3	4
2	RAMPURIYA (Contd.....)	668	0.0360
		667	0.0216
		666	0.1512
		646	0.1800
		644	0.1152
		643	0.1224
		641	0.2088
		597	0.0144
		542	0.2232
		544	0.0144
		545	0.0576
		547	0.0360
		548	0.0288
		549	0.0072
		550	0.0504
		551	0.0432
		552	0.0504
		573	0.0648
		190	0.0288
		179	0.0144
		185	0.1440
		189	0.1080
		187	0.1224
		227	0.0360
		221	0.0072
		228	0.1080
		229	0.1728
		230	0.0040
		231	0.0288
		232	0.0792
		245	0.2232
		247	0.1800
		248	0.1440
		121	0.0720
		120	0.0504
		119	0.3528
		118	0.0720
		115	0.2808
		111	0.1008
		110	0.0288
		81	0.0720
		85	0.1440
		82	0.1008
		84	0.0040
		83	0.0288
3	RAMTI	172	0.0504
		173	0.1224
		171	0.2880
		169	0.0144
		147	0.2880
		142/540	0.0072
		140	0.2520
		139	0.1080
		138	0.0360
		137	0.1440
		134	0.1440
		135	0.0144
		130	0.0144
		93	0.1080
		96	0.1440
		97	0.2016
		98	0.0648
		99	0.1512
		76	0.0360
		73	0.0144
		51	0.1584
		67	0.5472
		64	0.0216

1	2	3	4
3	RAMTI (Contd.....)	59	0.2880
4	SHERPUR	653	0.0288
		652	0.1944
		626	0.0072
		627	0.2592
		628	0.2016
		629	0.2016
		621	0.2304
		620	0.0216
		604	0.2592
		603	0.0864
		602	0.2232
		601	0.0720
		594	0.0432
		594	0.0144
		338	1.6632
		337	0.0288
		336	0.2664
		332	0.0648
		331	0.1584
5	DAULATPURA	349	0.0432
		342	0.0720
		348	0.1080
		347	0.1296
		349	0.6552
		350	0.0040
		384	0.0072
		354	0.2376
		357	0.3312
		360	0.0144
		304	0.2376
		527/302	0.1224
		524/302	0.2376
		521/301	0.0864
		522/301	0.2160
		525/301	0.2520
		268	0.2448
		267	0.0040
		266	0.0144
		264	0.1872
		263	0.1008
		260	0.1440
		258	0.2376
		257	0.1440
		256	0.1512
6	DHARONIYA	1717	0.8208
		1718	0.3744
		1734	0.0216
		1790/1945	0.1728
		1790/2009	0.0216
		1791	0.0864
		1789	0.0216
		1773	0.1440
		1776	0.0864
		1777	0.1080
		1779	0.1440
		1780	0.1440
		1781	0.0072
		1782	0.0864
		1783	0.1656
		1784	0.0216
		1767	0.0144
		1807	0.0216
		1809	0.1872
		1856	0.0072
		1820	0.0936
		1819	0.0040
		1821	0.0864

1	2	3	4
6	DHARONIYA (Contd.....)	1822	0.0864
		1847	0.0864
		1846	0.0040
		1848	0.0576
		1872	0.0792
		1839	0.1224
		1838	0.0936
		1837	0.0792
		1835	0.1368
		1833	0.0360
7	NIMAHEDA	166	0.1296
		167	0.0504
		168	0.0432
		186	0.2088
		185	0.0720
		187	0.2304
		196	0.0432
		195	0.0792
		194	0.1440
		199	0.0216
		199/245	0.0864
		193	0.0288
		200	0.1224
		201	0.0720
		447	0.0720
		448/561	0.0576
		448/562	0.0504
		448/563	0.0504
		448/564	0.0720
		545	0.0144
		542	0.2160
		543	0.0040
		452	0.0144
		526	1.5192
8	KACHRA KHEDI	661/700	0.0936
		661/701	0.0288
		661/705	0.0288
		661	0.6120
		654	0.0360
		650	0.0792
		649	0.0288
		645	0.1368
		644	0.0504
		642	0.1584
		638	0.0864
		639	0.0216
		437	0.1080
		630	0.1512
		631	0.0216
		629	0.0144
		521	0.0036
		522	0.0072
		523	0.0576
		520	0.0072
		524	0.0864
		525	0.1080
		526	0.0072
		528	0.0720
		529	0.0144
		533	0.0792
		538	0.1512
		536	0.0144
		537	0.0144
		539	0.0360
		603	0.0648
		604	0.0936
		601	0.0792
		600	0.0648

1	2	3	4
8	KACHRA KHEDI (Contd.....)	599	0.0792
		599/729	0.1080
		598	0.0216
		604	0.0288
		597	0.2664
9	FATEHGARH	581/1109	0.0216
		581	0.0576
		580	0.0216
		525/1082	0.1584
		515	0.0288
		517	0.0792
		518	0.1008
		519	0.2304
		524	0.0720
		521	0.1224
		522	0.0144
		523/1107	0.0360
		545	0.1368
		523/1108	0.0360
		523	0.0216
		506	0.1368
		546	0.0288
		547	0.0288
		497/1173	0.0072
		497	0.0576
		490/1104	0.0020
		490	0.0288
		489	0.0648
		488	0.0288
		487	0.0072
		486	0.0720
		485	0.0020
		481	0.0288
		478	0.0936
		479	0.0144
		475	0.0288
		474	0.0504
		473	0.0216
		472	0.0144
		470	0.0576
		471	0.0144
		468	0.0144
		463	0.0144
		466	0.0072
		465	0.0288
		459	0.0576
		455/1172	0.1728
		454/1171	0.0432
		446	0.0216
		757	0.0576
		758	0.1008
		422	0.0144
		759	0.0216
		444	0.0020
		428	0.0720
		427	0.0936
		422/1105	0.0144
		424	0.0648
		423	0.0288
		421	0.0648
		420	0.0360
		419	0.0360
		417	0.0432
		418	0.0072
		413	0.0216
		411	0.0020
		412	0.0432
		409	0.0216

1	2	3	4
9	FATEHGARH (Contd.....)	408	0.0288
		405/1100	0.0040
		405	0.0288
		404	0.1080
		400	0.0288
		399	0.0432
		403	0.0072
		385	0.0360
		384	0.1872
		383	0.0144
		380	0.0792
		379	0.0504
		823/1122	0.1224
		823	0.1584
		824	0.0072
		825	0.1080
		927	0.3816
		926	0.1368
		923	0.2664
		922	0.0360
		921	0.0864
		920	0.0792
		901	0.1440
		902	0.1512
		912	0.0288
10	KHIJARPUR	6	0.1800
		7	0.0720
		9	0.2664
		28	0.0864
		29	0.1008
		30	0.0936
		31	0.1944
		33	0.0792
		35	0.2592
		36	0.0576
		79	0.0576
		99	0.0072
		102	0.2736
		78	0.1296
		115	0.1080
		116	0.0936
		125	0.0648
		128	0.0216
		129	0.1296
		124	0.0072
		123	0.0040
		144	0.1296
		145	0.0288
		159	0.0144
		158	0.0792
		160	0.0288
		186	0.0144
		187	0.0432
		185	0.0040
		179	0.0040
		190	0.0864
		192	0.0360
		193	0.0144
		194	0.0020
		196	0.0504
		195	0.0144
		199	0.0576
		200	0.0432
		396	0.0936
		395	0.1152
		397	0.0864
		394	0.1152
		458	0.0144

1	2	3	4
10	KHIJARPUR (Contd.....)	398	0.3096
		455	0.0020
		399	0.0020
		401	0.0216
		402	0.0360
		421	0.0576
		422	0.0432
		427	0.1944
		428	0.0432
		429	0.0144
		430	0.0040
		197	0.0288
11	BANOR	927	0.0144
		917	0.1296
		918	0.0144
		919	0.0360
		920	0.0144
		921	0.2160
		943	0.0216
		942	0.1584
		941	0.1080
		940	0.1152
		939	0.0936
		946	0.0360
		950	0.1296
		949	0.0648
		956	0.1296
		957	0.0144
		959	0.0288
		958	0.0072
		984	0.1008
		955	0.1440
		960	0.1224
		983	0.0648
		982	0.0040
12	ASONDIYA	2	0.2376
		3	0.0144
		4	0.0216
		5	0.1440
		5/407	0.0864
		13/409	0.1944
		36	0.1440
		35	0.0144
		34	0.0864
		37	0.0144
		33	0.0864
		15	0.0144
		20	0.4104
		96	0.0144
		99	0.1800
		102	0.1296
		101	0.0792
		103	0.1728
		106	0.0936
		108	0.0936
		107	0.0072
		121	0.0216
		120	0.0020
		122	0.1584
		131	0.1152
		130	0.3024
		129	0.0072
		128	0.0576
		161	0.0216
13	KOTRI KHURD	13	0.0216
		15	0.0288
		14	0.0360
		18	0.1080

1	2	3	4
13	KOTRI KHURD (Contd.....)	19	0.0072
		26	0.1944
		25	0.1368
		27	0.0072
		32	0.1944
		33	0.1944
		37	0.0144
		93	0.1872
		98	0.0504
		99	0.1008
		103	0.2592
		89	0.1152
		88	0.0144
		87	0.2808
		82	0.2304
		81	0.2448
		71	0.0216
		70	0.2736
14	SEMLI BHAWANI	251	0.0216
		253	0.2232
		259	0.1152
		258	0.0504
		257	0.0648
		260	0.0020
		256	0.2088
		247	0.1008
		246	0.0432
		243	0.0020
		266	0.0288
		305	0.0720
		306	0.1656
		319	0.1368
		320	0.2448
		323	0.0020
		322	0.1512
		321	0.0072
		324	0.0144
		422	0.2736
		419	0.0216
		420	0.3528
		421	0.0576
		407	0.4104
		456	0.1080
		455/474	0.0072
		406	0.0144
		396	0.0216
		395	0.2088
		393	0.0576
		397	0.1368
15	BORBANDH	361	0.0144
		362	0.1368
		373	0.0144
16	DIWAL KHEDA	301	0.0072
		302	0.1008
		303	0.0792
		317	0.2664
		318	0.1368
		320	0.0144
		369	0.0144
		368	0.0144
		370	0.2160
		371	0.1728
		388	0.1080
		390	0.1728
		391	0.0216
		389	0.0072
		395	0.2520
		396	0.0144

1	2	3	4
16	DIWAL KHEDA (Contd.....)	343	0.0040
		399	0.1728
		495	0.0072
		546	0.1368
		566	0.1080
		564	0.2016
		569	0.0072
		570	0.1440
		700	0.0216
		870	0.2808
		869	0.2088
		861	0.0144
		864	0.1224
		863	0.1584
17	MUNDLA	856	0.0720
		855	0.1296
		858	0.0072
		859	0.1008
		865	0.1152
		861	0.0040
		864	0.0936
		866	0.1224
		867	0.0936
		795	0.2304
		803	0.2016
		789	0.0040
		792	0.0020
		791	0.1368
		790	0.1368
		771	0.2880
		772	0.1584
		774	0.0504
		775	0.0072
		770	0.0216
		649	0.0144
		651	0.4608
		650	0.0020
		653	0.0216
		654	0.0720
		656	0.1728
		657	0.0216
		658	0.0792
		759	0.0072
		760	0.0144
		661	0.0040
		176	0.0576
		667	0.0288
		668	0.0288
		669	0.0566
		670	0.1728
		671	0.0144
		537	0.0040
		535	0.1008
		542	0.0020
		534	0.0720
		523	0.0144
		533	0.1512
		531	0.1440
		528	0.0040
		529	0.0040
		530	0.0072
		312	0.0144
		313	0.0144
		314	0.0144
		315	0.0504
		316	0.0216
		317	0.0288
		319	0.0288

1	2	3	4
17	MUNDLA (Contd.....)	320	0.0288
		321	0.0144
		322	0.0144
		323	0.0936
		324	0.0288
		340	0.1296
		300	0.0020
		339	0.0040
		341	0.0720
		359	0.0216
		358	0.0648
		360	0.0144
		357	0.0360
		354	0.0020
		368	0.0792
		367	0.0144
		371	0.0576
		370	0.0144
		372	0.0720
		378	0.0072
		377	0.1080
		376	0.0360
		375	0.0216
		389	0.1512
		393	0.0072
		388	0.0144
18	KALYANPURA	36	0.0648
		35	0.0936
		37/89	0.1008
		44	0.0216
		77	0.4032
		76	0.1296
		75	0.0288
		74	0.1152
		48	0.0020
		49	0.0072
		57	0.1512
		51	0.0216
		52	0.0216
		53	0.0504
		54	0.0576
		55	0.0040
		56	0.0576
		28	0.0648
		59	0.1080
		60	0.0864
		43	0.0288
19	BAJRANGPURA	59	0.0360
		57	0.0576
		58	0.2160
		56	0.0504
		54	0.1152
		6	0.0216
		7	0.0504
		8	0.0360
		9	0.1224
		10	0.0576
		11	0.0576
		12	0.0792
		45	0.2160
		44	0.0360
		43	0.1800
		42	0.0288
		22	0.0144
		29	0.1008
		28	0.0504
20	RAGHUNATHPURA	246	0.0072
		247	0.0288

1	2	3	4
20	RAGHUNATHPURA (Contd.....)	248	0.0144
		249	0.1296
		250	0.0072
		251	0.1296
		234	0.1152
		230	0.1656
		231	0.0040
		232	0.2160
		289	0.0792
		233	0.0864
		192	0.2088
		193	0.1656
		191	0.0144
		189	0.0144
		239	0.0216
		184	0.0040
		127	0.1368
		126	0.0288
		125	0.1368
		129	0.0144
		131	0.0040
		130	0.0040
		150	0.1440
		149	0.2232
		146	0.1368
		147	0.0792
		145	0.0288
		144	0.0144
		361	0.0216
		363	0.0504
		364	0.0936
		367	0.0040
		365	0.0288
		366	0.1368
		354	0.0576
		369	0.0864
		370	0.1584
		387	0.1440
		386	0.0072
		388	0.1296
		389	0.1728
		392	0.2304
		391	0.0040
		393	0.2016
		395	0.1512
21	DAWAL	93	0.0288
		98	0.0576
		97	0.1800
		96	0.0648
		102	0.0072
		103	0.1080
		109	0.2232
		113	0.1880
		117	0.1080
		114	0.1224
		115	0.0072
		122	0.3096
		119	0.0144
		120	0.0072
		121	0.1872
22	SALRI	1010	0.0360
		1007	0.2376
		1008	0.0020
		1009	0.0072
		1002	0.1512
		1000	0.0864
		997	0.0144
		995	0.0432

1	2	3	4
22	SALRI (Contd.....)	994	0.2448
		853	0.0072
		854	0.0040
		991	0.2088
		990	0.1008
		989	0.0432
		858	0.1512
		930	0.0144
		954	0.0432
		955	0.2088
		956	0.0072
		957	0.0288
		958	0.0576
		963	0.1008
		960	0.0072
		964	0.0504
		930	0.0288
		925	0.0648
		937	0.0144
		924	0.0936
		921	0.0792
		920	0.0720
		918	0.1728
		1077	0.0216
23	SEMLI KALYAN	266	0.0360
		268	0.1872
		255	0.6336
		257	0.0360
		269	0.0216
		276/419	0.0720
		253	0.1080
		251	0.0936
		250	0.1584
		248	0.0040
		246	0.1008
		247	0.1440
		239	0.2952
		237	0.1656
		234	0.0288
		329	0.1080
		330	0.0040
		331	0.1728
		332	0.0360
		224	0.0792
		227	0.1224
		228	0.0648
		230	0.0360
		174	0.0144
		190	0.0144
		189	0.0144
		188	0.1296
		176	0.1224
		177	0.0504
		178	0.1296

[No. R-31015/84/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 2005

का. आ. 1706.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के का. आ. **3217 दिनांक 16.12.2004** द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर, ब्यावर से चित्तौड़गढ़ तक पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए "सिद्धपुर-सांगानेर पाइपलाइन से चित्तौड़गढ़ तक ब्रान्च लाईन" के कार्यान्वयन हेतु एक शाखा पाइपलाइन बिछाने के लिये उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान राज्य की भूमि अधिसूचित की थी।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को दिनांक **10.01.2005** तक उपलब्ध करा दी गई थी ।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी, राजस्थान, ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
रामपुरा	1484	0	00	20
	1482	0	11	00
	1490	0	06	70
	1489	0	07	40
	1491	0	00	20
	1498	0	02	40
	1497	0	02	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1493	0	09	00
	1496	0	02	30
	1495	0	10	00
	1461	0	02	40
	1462	0	14	40
	1464	0	02	90
	1457	0	00	50
	1412	0	02	80
	1465	0	09	70
	1413	0	02	70
	1414	0	03	80
	1415	0	02	70
	1416	0	10	30
	1429	0	01	60
	1433	0	01	00
	1432	0	13	50
	1437	0	02	30
	1428	0	00	20
	1436	0	08	10
	1711मिन	0	07	70
	1711/3412	0	02	10
	1710	0	00	20
	1704	0	12	60
	1703	0	07	10
	1702	0	07	50
	2353	0	05	20
	2351	0	01	40
	2350	0	04	30
	2349	0	10	00
	2342	0	15	80
	2331	0	15	20
	2328	0	10	50
	2400	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	2390	0	00	40
	2403	0	00	30
	2404	0	04	50
	2327	0	03	90
	2323	0	00	40
	2322	0	04	30
	2321	0	05	80
	2318	0	08	30
	2317	0	05	30
	2302	0	08	60
	2301	0	07	30
	2299	0	10	80
	2298	0	05	60
	2293	0	09	90
	2292	0	05	60
	2294	0	00	20
	2264	0	11	90
	2267	0	03	80
	2268	0	04	20
	2269	0	30	00
	2270	0	07	20
	2271	0	11	80
	2254	0	05	40
	2253	0	13	20
	2273	0	02	70
	2218	0	04	90
	2207	0	03	30
	2208	0	06	80
	2209	0	00	20
	2220	0	12	80
	2205	0	00	90
	2206	0	07	30
	2176	0	08	30

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	2167	0	05	70
	2145	0	12	60
	2146/3394	0	12	40
	2140	0	00	20
	2147	0	09	80
	2148	0	16	20
	2149	0	02	00
	2150	0	05	90
अखेगढ़	890	0	00	50
	893	0	13	10
	895	0	00	20
	894	0	02	30
	907	0	06	00
	892	0	00	60
	908	0	05	70
	906	0	00	20
	909	0	02	40
	919	0	02	70
	920	0	06	30
	922	0	00	20
	937	0	02	30
	921	0	09	00
	938	0	00	20
	933	0	07	70
	932	0	00	70
	936	0	00	20
	930	0	09	20
	1026	0	01	50
	1036	0	06	70
	1035	0	01	20
	1037	0	04	20
	1038	0	00	20
	1057	0	00	20

तहसील : आसींन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1049	0	08	30
	1056	0	00	70
	1050	0	00	60
	1048	0	11	20
	1047	0	11	90
	1046	0	00	70
	1069	0	11	80
	1084	0	11	40
	1085	0	05	20
	1086	0	04	20
	1080	0	00	20
	1079	0	00	40
	1087	0	04	40
	1088	0	06	20
	1091	0	02	70
	1090	0	00	50
	1089	0	07	40
मोटरास	28	0	06	50
	24	0	00	20
	25	0	07	00
	23	0	08	60
	21	0	13	70
	35	0	03	70
	40	0	12	90
	60	0	11	80
	62	0	00	30
	61	0	03	60
	1231	0	00	20
	1229	0	09	90
	1230	0	07	20
	1291	0	14	90
	1276	0	00	40
	1290	0	08	60

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1289	0	07	50
	1288	0	13	30
	1319	0	02	20
	1286	0	02	40
	1320	0	09	50
	1337	0	06	70
	1335	0	02	30
	1339	0	00	90
	1338	0	00	20
	1418	0	00	80
	1346	0	10	80
	1347	0	06	70
	1348	0	10	70
	1363	0	00	20
	1396	0	01	10
	1362	0	18	70
	1395	0	08	00
	1394	0	04	80
	1393	0	05	10
	1385	0	02	20
	1386	0	07	90
	1387	0	00	20
	1388	0	08	10
	1617	0	07	10
	1616	0	10	60
	1618	0	03	90
	1631	0	06	00
	1653	0	00	80
	3136/1653	0	10	00
	1652	0	07	20
	3175/1654	0	00	20
	2235	0	00	20
	2234	0	11	50

तहसील : आसींद	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	2232	0	07	20
	2180	0	00	30
	2182	0	09	20
	2183	0	09	50
	2185	0	01	30
	2190	0	00	80
	2186	0	07	90
	2187	0	07	20
	2172	0	05	20
	2171	0	11	60
	2169	0	01	40
	2158	0	01	90
	2159	0	06	60
	3251/2159	0	02	30
	2167	0	00	20
	2161	0	08	30
	2166	0	04	50
	2163	0	00	30
	2164	0	04	20
	2165	0	07	00
	2138	0	03	90
	2139	0	06	10
	2140	0	03	90
	2141	0	01	40
संग्रामगढ़	58	0	04	70
	59	0	11	60
	62	0	03	70
	63	0	06	30
	64	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	64/2037	0	06	00
	68	0	00	20
	68/1	0	03	40
	68/2040	0	04	40
	67/2039	0	04	50
	67	0	08	50
	70	0	02	40
	187/2011	0	06	20
	187/2011/2109	0	06	90
	191	0	27	00
	192	0	12	10
	196	0	02	30
	172	0	28	10
	174	0	02	90
	173	0	41	10
	262	0	19	60
	270	0	04	20
	271	0	18	10
	323	0	02	60
	324	0	20	50
	322	0	04	40
	325	0	13	00
	327	0	00	20
	329	0	16	80
	330	0	09	80
	331	0	10	70
	339	0	02	10
	338	0	19	20
	357	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	332	0	00	20
	337	0	11	80
	335	0	11	60
	445	0	10	50
	440	0	14	10
	438	0	14	30
	435	0	40	00
	433	0	10	30
	675	0	08	00
	678	0	00	60
	678/1987	0	14	90
	677	0	56	70
भैरुखेड़ा	19	0	06	30
	73	0	07	30
	74	0	00	30
	92	0	11	70
	93	0	00	20
	91	0	06	00
	90	0	00	30
	94	0	08	00
	88	0	02	50
	104	0	07	40
	106	0	05	60
	100	0	06	10
	99	0	00	20
	111	0	02	40
	112	0	00	60
	114	0	13	90
	116	0	05	70

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	141	0	08	90
	143	0	00	80
	142	0	10	10
	185	0	00	80
	186	0	11	80
	184मिन	0	15	20
	184/270	0	01	90
	182	0	00	20
	189	0	13	50
	191	0	04	70
	190	0	06	10
	205	0	10	90
	209	0	00	30
	200	0	01	80
	211	0	09	30
	210	0	00	20
गजसिंहपुरा	62	0	09	40
	61	0	03	80
	63	0	04	20
	64	0	06	20
	80	0	01	50
	81	0	03	40
	79	0	01	40
	78	0	07	70
	83	0	10	70
	77	0	07	40
शम्भूगढ़	231	0	00	30
	235	0	02	40
	236	0	05	20

तहसील : आसींद	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	237	0	09	70
	250	0	02	40
	239	0	09	30
	240	0	09	50
	242	0	04	10
	243	0	02	10
	203	0	00	20
	204	0	10	60
	412	0	02	00
	413	0	13	10
	409	0	00	20
	408	0	03	60
	414	0	12	60
	417	0	01	00
	419	0	09	40
	423	0	01	10
	425	0	08	70
	424	0	04	00
	453	0	12	10
	449	0	01	90
	450	0	00	20
	451	0	09	20
	529	0	15	90
	530	0	11	70
	531	0	01	10
	532	0	01	10
	571	0	00	70
	569	0	11	70
	556	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	557	0	10	60
	558	0	07	10
	553	0	06	90
	552	0	11	40
	551	0	01	80
	548	0	01	20
	550	0	00	40
	549	0	03	20
	762	0	05	30
	761	0	07	90
	760	0	01	40
	696	0	07	00
	697	0	06	50
	698	0	11	60
	699	0	02	40
	703	0	00	30
	701	0	06	90
	702	0	05	80
	708	0	04	00
	1101	0	00	30
	1100	0	02	60
	1099	0	04	30
	1098	0	08	70
	1096	0	06	80
	1095	0	01	10
	1108	0	00	20
	1113	0	04	50
	1112	0	02	80
	1093	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1111	0	01	10
	1110	0	00	20
	1114	0	00	90
	1115	0	02	20
	1116	0	03	80
	1119	0	09	60
	1118	0	00	60
	1120	0	01	30
	1121	0	04	50
	1122	0	06	70
	1123	0	01	00
	1079	0	02	20
	1078	0	00	20
	1070	0	10	20
	1069	0	06	20
	1068	0	07	00
	1067	0	03	50
	1066	0	03	40
	1203	0	00	20
	1201	0	02	40
	1202	0	02	70
	1200	0	18	50
	1199	0	06	70
	1180	0	00	50
	1197	0	00	20
	1181	0	10	00
	1182	0	08	10
	1183	0	11	00
	1187	0	13	40

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1186/2935	0	01	10
	1186	0	05	10
	2600	0	06	90
	2599	0	19	10
	2530	0	14	50
	2529	0	08	40
	2528	0	13	80
	2516	0	02	00
	2484/2943	0	20	90
	2515	0	00	20
	2484/2942	0	10	00
बरसनी	224	0	06	50
	1061	0	18	20
	1062	0	31	90
	1079	0	16	20
	1078	0	02	00
	1088	0	04	20
	1087	0	00	20
	1089	0	05	80
	4747	0	11	60
	4748	0	02	60
	4756	0	02	90
	4817	0	05	10
	4816	0	15	20
	4815	0	12	10
	4820	0	11	40
	4821	0	09	60
	4833	0	15	30
	4835	0	02	60

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	4836	0	00	20
	4834	0	05	90
	4832	0	03	10
	4842	0	04	50
	4841	0	02	60
	4843	0	16	70
	4862	0	01	40
	4861	0	06	50
	4964	0	01	70
	4863	0	00	20
	4963	0	04	00
	4962	0	01	50
	4961	0	05	20
	4960	0	06	00
	4959	0	13	00
	4882	0	01	10
	4955	0	08	40
	4898	0	02	80
	4899	0	07	60
	4900	0	07	80
	4903	0	00	30
	4902	0	07	60
	4930	0	05	40
	4929	0	03	20
	4928	0	02	80
	4913	0	05	40
	4924	0	03	60
	4918	0	04	40
	4917	0	04	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	4923	0	00	20
	4919	0	00	20
	4920	0	05	60
	4921	0	05	30
	5212	0	06	00
	5213	0	01	70
कोलीखेड़ा	291	0	10	50
	294	0	16	70
	296	0	10	80
आमेसर	3230	0	02	30
	3231	0	06	20
	3232	0	06	70
	3233	0	11	60
	3234	0	06	30
	3243	0	16	80
	3247	0	08	70
	3249	0	12	40
	3251	0	06	50
	3253	0	10	80
	3252	0	04	80
	3190	0	10	80
	3187	0	02	90
	3186	0	01	50
	3184	0	00	20
	3185	0	13	60
	3182	0	02	40
	3183	0	03	10
	3209	0	03	30
	3202	0	01	80

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	3201	0	00	70
	3200	0	09	80
	370	0	13	10
	371	0	07	20
	404/4947	0	11	90
	404/4934	0	00	50
	818/4933	0	05	60
	879	0	05	00
	880	0	07	40
	882	0	00	90
	896	0	06	50
	899	0	00	50
	895	0	08	00
	894	0	09	70
	905	0	10	50
	930	0	03	70
	929	0	03	20
	927	0	05	60
	928	0	01	80
	925	0	00	70
	924	0	04	90
	922	0	09	10
	921	0	03	20
	1595	0	19	10
	1596	0	05	10
	1588	0	04	80
	1607	0	07	40
	1608	0	05	30
	1606	0	01	10

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1609	0	10	40
	1634	0	10	50
	1633	0	01	80
	1632	0	10	20
	1630	0	00	20
	1631	0	02	10
	1638	0	02	20
	1639	0	07	30
	1626	0	00	20
	1640	0	06	20
	1641	0	11	30
	1642	0	09	90
	1643	0	08	10
	1988	0	05	40
	1987	0	00	30
	1986	0	03	60
	1959	0	03	90
	1950/4890	0	03	00
	1950	0	05	80
	1949	0	04	50
	1951	0	02	90
	1945	0	04	60
	1944	0	07	20
	1943	0	09	30
	1941	0	02	00
	1942	0	00	70
माताजी का खेड़ा	995	0	16	40
जबरकिया	247	0	12	60
	248	0	00	30

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	256	0	10	80
	296	0	07	60
	295	0	04	90
	292	0	02	00
	294	0	06	20
	293	0	10	40
	413	0	11	40
	416	0	00	60
	414	0	10	70
	594	0	14	10
	591	0	00	50
	590	0	09	00
	588	0	01	90
	589	0	00	30
	585	0	10	90
	583	0	03	60
	775	0	08	30
	772	0	12	80
	764	0	02	50
	765	0	01	00
	766	0	10	80
	763	0	00	80
	767	0	00	20
	761	0	03	60
	762	0	02	40

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	759	0	00	20
	760	0	05	60
	758	0	05	40
	757	0	05	10
	756	0	02	00
	755	0	00	20
	836	0	06	80
	837	0	10	10
	841	0	11	10
	842	0	01	00
	743	0	01	80
	1021	0	14	40
	1026	0	05	30
	1024	0	11	40
	1023	0	10	00
	1022	0	14	80
	1264	0	04	00
	1265	0	06	90
	1270	0	00	50
	1266	0	01	80
	1267	0	02	20
	1268	0	06	30
	1240	0	05	70
	1239	0	02	80
	1238	0	01	30
	1236	0	01	30
	1241	0	02	70
	1235	0	02	20
	1234	0	01	70

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1242	0	01	30
	1243	0	06	00
	1233	0	01	10
	1227	0	01	20
	1228	0	02	10
	1229	0	08	80
	1226	0	02	90
	1369	0	00	40
	1471	0	04	10
	1472	0	09	80
	1468	0	14	00
	1467	0	01	00
	1514	0	00	20
	1515	0	07	80
	1516	0	11	40
	1517	0	09	30
	1519	0	15	20
	1520	0	08	10
	1519/1531	0	00	20
	1520/1532	0	23	70
	1521	0	00	20
	1526	0	08	50
	1525	0	00	20
	1527	0	78	60
	1511	0	01	00
पालड़ी	765	0	04	20
	764	0	08	70
	767	0	00	50
	766	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	763	0	07	60
	769	0	05	90
	770	0	01	10
	782	0	05	70
	781	0	00	30
	790	0	08	20
	791	0	01	80
	794	0	08	70
	793	0	00	20
	792	0	00	20
	795	0	07	30
	817	0	02	70
	816	0	08	10
	815	0	08	30
	814	0	04	60
	813	0	04	50
	812	0	04	40
	811	0	03	60
	810	0	10	90
	808	0	03	60
	807	0	10	50
	806	0	13	80
सरेरी	130	0	10	40
	128	0	07	10
	127	0	22	40
	146	0	12	40
	145	0	06	70
	147	0	29	80
	148	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	149	0	26	20
	150	0	26	00
	257	0	00	30
	5317/257	0	03	20
	171	0	16	60
	254	0	06	90
	253	0	16	30
	174	0	14	70
	175	0	04	80
	250	0	32	40
	249	0	05	90
	248	0	03	70
	237	0	07	20
	241	0	00	70
	239	0	11	40
	234	0	01	20
	5307/233	0	07	30
	229	0	14	40
	228	0	48	80
	1687	0	15	80
	1693	0	00	20
	1694	0	09	90
	1697	0	02	20
	1695	0	06	40
	1700	0	07	60
	1701	0	17	10
	1714	0	14	40
	1711	0	00	20
	1715	0	00	20

तहसील : आसींद	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1716	0	02	00
	1713	0	03	00
	1712	0	00	40
	1717	0	09	90
	1718	0	07	60
	1668	0	00	20
	1667	0	08	20
	1666	0	05	30
	1665	0	11	30
	1662	0	00	30
	1663	0	07	10
	1664	0	00	30
	1661	0	08	70
	1660	0	02	10
	1659	0	05	90
	1656	0	01	10
	1654	0	08	00
	1655	0	04	90
	1649	0	19	00
	1648	0	01	10
	1627	0	01	70
	1628	0	01	60
	1629	0	11	30
	1630	0	00	20
	1631	0	10	90
	1626	0	01	80
	1449	0	00	20
	1448	0	15	00
	1447	0	01	30

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1446	0	10	60
	1452	0	00	50
	1445	0	15	60
	1436	0	11	00
	1435	0	03	10
	1416	0	11	10
	1417	0	01	10
	1419	0	00	90
	1403	0	07	80
	1402	0	02	50
	1317	0	06	80
	1318	0	10	80
	1307	0	01	30
	1319	0	02	80
	1306	0	00	30
	1305	0	17	80
	1280	0	06	40
	1281	0	01	40
	1277	0	07	70
	1276	0	00	80
	1278	0	00	20
	4261	0	09	00
	5250/4259	0	00	70
	4260	0	04	30
	4265	0	05	90
	4251	0	02	00
	4250	0	02	30
	4252	0	01	40
	4249	0	14	10

तहसील : आसींद	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	4248	0	01	20
	4345	0	08	00
	4346	0	01	10
	4344	0	00	20
	4351	0	07	20
	4350	0	02	20
	4352	0	00	20
	4353	0	07	60
	4355	0	01	60
	4360	0	00	80
	4354	0	08	90
	4359	0	05	70
	4391	0	00	30
	4382	0	16	50
	4390	0	00	20
	4389	0	00	40
	4436	0	00	20
	4434	0	12	80
	4417	0	01	20
	4419	0	04	20
	4420	0	00	90
	4421	0	01	60
	4432	0	02	30
	4422	0	04	80
	4431	0	04	70
	4429	0	04	50
	4430	0	01	10
	4428	0	00	30
	4490	0	00	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	4488	0	00	60
	4487	0	00	70
	4489	0	17	00
	4666	0	06	00
	4667	0	02	90
	4686	0	01	90
	4664	0	08	00
	4688	0	04	60
	4687	0	02	00
	4689	0	03	80
	4690	0	02	10
	4691	0	02	80
	4718	0	00	80
	4719	0	00	20
	4717	0	06	70
	4715	0	03	20
	4716	0	04	50
	4790	0	05	00
	4788	0	00	20
	4794	0	05	20
	4795	0	02	90
	4796	0	03	50
	4840	0	08	50
	4839	0	05	00
	4846	0	05	60
कोरनास	1528	0	11	20
	1527	0	00	20
	1600	0	07	50
	1602	0	04	20

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1606	0	02	50
	1605	0	11	10
	1609	0	04	80
	1610	0	02	10
	1617	0	10	40
	1618	0	08	60
	1619	0	00	20
	1644	0	03	80
	1645	0	08	30
	1657	0	08	60
	1669	0	08	70
	1658	0	01	40
	1667	0	10	30
	1668	0	00	20
	1681	0	07	00
	1682	0	02	00
	1705	0	06	90
	1707	0	00	20
	1706	0	06	70
	1700	0	10	70
	1717	0	00	20
	1699	0	04	40
	1698	0	04	30
	1697	0	09	50
	1696	0	00	30
	1740	0	28	30
	1756	0	07	70
	1755	0	07	50
	1767	0	04	50

तहसील : आसीन्द	जिला : भीलवाड़ा	राज्य : राजस्थान		
गांव का नाम	खसरा सख्या	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
	1766	0	01	00
	1768	0	08	70
	1774	0	06	20
	1775	0	01	70
	1773	0	08	60
	1780	0	00	60
	1781	0	14	60
	1794	0	04	90
	1792	0	00	20
	1789	0	03	60
	1793	0	26	60

[फा. स. आर-25011/31/2004-ओ.आर-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th May, 2005

S. O. 1706.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. number 3217 dated 16.12.2004 issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in **Tehsil : Asind, District : Bhilwara** in the State of Rajasthan, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products in the State of Rajasthan from Beawar to Chittaurgarh in respect of "Branch Pipeline to Chittaurgarh from Sidhpur – Sanganer Pipeline" by the Indian Oil Corporation Limited

And whereas, copy of the said notification was made available to the general public on 10.01.2005

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this Notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : ASIND	**District : BHILWARA**	**State : RAJASTHAN**		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
Rampura	1484	0	00	20
	1482	0	11	00
	1490	0	06	70
	1489	0	07	40
	1491	0	00	20
	1498	0	02	40
	1497	0	02	20
	1493	0	09	00
	1496	0	02	30
	1495	0	10	00
	1461	0	02	40
	1462	0	14	40
	1464	0	02	90
	1457	0	00	50
	1412	0	02	80
	1465	0	09	70
	1413	0	02	70
	1414	0	03	80
	1415	0	02	70
	1416	0	10	30
	1429	0	01	60
	1433	0	01	00
	1432	0	13	50
	1437	0	02	30
	1428	0	00	20
	1436	0	08	10
	1711Min	0	07	70

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1711/3412	0	02	10
	1710	0	00	20
	1704	0	12	60
	1703	0	07	10
	1702	0	07	50
	2353	0	05	20
	2351	0	01	40
	2350	0	04	30
	2349	0	10	00
	2342	0	15	80
	2331	0	15	20
	2328	0	10	50
	2400	0	00	20
	2390	0	00	40
	2403	0	00	30
	2404	0	04	50
	2327	0	03	90
	2323	0	00	40
	2322	0	04	30
	2321	0	05	80
	2318	0	08	30
	2317	0	05	30
	2302	0	08	60
	2301	0	07	30
	2299	0	10	80
	2298	0	05	60
	2293	0	09	90
	2292	0	05	60
	2294	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	2264	0	11	90
	2267	0	03	80
	2268	0	04	20
	2269	0	30	00
	2270	0	07	20
	2271	0	11	80
	2254	0	05	40
	2253	0	13	20
	2273	0	02	70
	2218	0	04	90
	2207	0	03	30
	2208	0	06	80
	2209	0	00	20
	2220	0	12	80
	2205	0	00	90
	2206	0	07	30
	2176	0	08	30
	2167	0	05	70
	2145	0	12	60
	2146/3394	0	12	40
	2140	0	00	20
	2147	0	09	80
	2148	0	16	20
	2149	0	02	00
	2150	0	05	90
Akhegarh	890	0	00	50
	893	0	13	10
	895	0	00	20
	894	0	02	30

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	907	0	06	00
	892	0	00	60
	908	0	05	70
	906	0	00	20
	909	0	02	40
	919	0	02	70
	920	0	06	30
	922	0	00	20
	937	0	02	30
	921	0	09	00
	938	0	00	20
	933	0	07	70
	932	0	00	70
	936	0	00	20
	930	0	09	20
	1026	0	01	50
	1036	0	06	70
	1035	0	01	20
	1037	0	04	20
	1038	0	00	20
	1057	0	00	20
	1049	0	08	30
	1056	0	00	70
	1050	0	00	60
	1048	0	11	20
	1047	0	11	90
	1046	0	00	70
	1069	0	11	80
	1084	0	11	40

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1085	0	05	20
	1086	0	04	20
	1080	0	00	20
	1079	0	00	40
	1087	0	04	40
	1088	0	06	20
	1091	0	02	70
	1090	0	00	50
	1089	0	07	40
Motras	28	0	06	50
	24	0	00	20
	25	0	07	00
	23	0	08	60
	21	0	13	70
	35	0	03	70
	40	0	12	90
	60	0	11	80
	62	0	00	30
	61	0	03	60
	1231	0	00	20
	1229	0	09	90
	1230	0	07	20
	1291	0	14	90
	1276	0	00	40
	1290	0	08	60
	1289	0	07	50
	1288	0	13	30
	1319	0	02	20
	1286	0	02	40

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1320	0	09	50
	1337	0	06	70
	1335	0	02	30
	1339	0	00	90
	1338	0	00	20
	1418	0	00	80
	1346	0	10	80
	1347	0	06	70
	1348	0	10	70
	1363	0	00	20
	1396	0	01	10
	1362	0	18	70
	1395	0	08	00
	1394	0	04	80
	1393	0	05	10
	1385	0	02	20
	1386	0	07	90
	1387	0	00	20
	1388	0	08	10
	1617	0	07	10
	1616	0	10	60
	1618	0	03	90
	1631	0	06	00
	1653	0	00	80
	3136/1653	0	10	00
	1652	0	07	20
	3175/1654	0	00	20
	2235	0	00	20
	2234	0	11	50

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	2232	0	07	20
	2180	0	00	30
	2182	0	09	20
	2183	0	09	50
	2185	0	01	30
	2190	0	00	80
	2186	0	07	90
	2187	0	07	20
	2172	0	05	20
	2171	0	11	60
	2169	0	01	40
	2158	0	01	90
	2159	0	06	60
	3251/2159	0	02	30
	2167	0	00	20
	2161	0	08	30
	2166	0	04	50
	2163	0	00	30
	2164	0	04	20
	2165	0	07	00
	2138	0	03	90
	2139	0	06	10
	2140	0	03	90
	2141	0	01	40
Sangramgarh	58	0	04	70
	59	0	11	60
	62	0	03	70
	63	0	06	30
	64	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	64/2037	0	06	00
	68	0	00	20
	68/1	0	03	40
	68/2040	0	04	40
	67/2039	0	04	50
	67	0	08	50
	70	0	02	40
	187/2011	0	06	20
	187/2011/2109	0	06	90
	191	0	27	00
	192	0	12	10
	196	0	02	30
	172	0	28	10
	174	0	02	90
	173	0	41	10
	262	0	19	60
	270	0	04	20
	271	0	18	10
	323	0	02	60
	324	0	20	50
	322	0	04	40
	325	0	13	00
	327	0	00	20
	329	0	16	80
	330	0	09	80
	331	0	10	70
	339	0	02	10
	338	0	19	20
	357	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	332	0	00	20
	337	0	11	80
	335	0	11	60
	445	0	10	50
	440	0	14	10
	438	0	14	30
	435	0	40	00
	433	0	10	30
	675	0	08	00
	678	0	00	60
	678/1987	0	14	90
	677	0	56	70
Bhairukhera	19	0	06	30
	73	0	07	30
	74	0	00	30
	92	0	11	70
	93	0	00	20
	91	0	06	00
	90	0	00	30
	94	0	08	00
	88	0	02	50
	104	0	07	40
	106	0	05	60
	100	0	06	10
	99	0	00	20
	111	0	02	40
	112	0	00	60
	114	0	13	90
	116	0	05	70

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	141	0	08	90
	143	0	00	80
	142	0	10	10
	185	0	00	80
	186	0	11	80
	184Min	0	15	20
	184/270	0	01	90
	.182	0	00	20
	189	0	13	50
	191	0	04	70
	190	0	06	10
	205	0	10	90
	209	0	00	30
	200	0	01	80
	211	0	09	30
	210	0	00	20
Gajsinghpura	62	0	09	40
	61	0	03	80
	63	0	04	20
	64	0	06	20
	80	0	01	50
	81	0	03	40
	79	0	01	40
	78	0	07	70
	83	0	10	70
	77	0	07	40
Shambhugarh	231	0	00	30
	235	0	02	40
	236	0	05	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	237	0	09	70
	250	0	02	40
	239	0	09	30
	240	0	09	50
	242	0	04	10
	243	0	02	10
	203	0	00	20
	204	0	10	60
	412	0	02	00
	413	0	13	10
	409	0	00	20
	408	0	03	60
	414	0	12	60
	417	0	01	00
	419	0	09	40
	423	0	01	10
	425	0	08	70
	424	0	04	00
	453	0	12	10
	449	0	01	90
	450	0	00	20
	451	0	09	20
	529	0	15	90
	530	0	11	70
	531	0	01	10
	532	0	01	10
	571	0	00	70
	569	0	11	70
	556	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	557	0	10	60
	558	0	07	10
	553	0	06	90
	552	0	11	40
	551	0	01	80
	548	0	01	20
	550	0	00	40
	549	0	03	20
	762	0	05	30
	761	0	07	90
	760	0	01	40
	696	0	07	00
	697	0	06	50
	698	0	11	60
	699	0	02	40
	703	0	00	30
	701	0	06	90
	702	0	05	80
	708	0	04	00
	1101	0	00	30
	1100	0	02	60
	1099	0	04	30
	1098	0	08	70
	1096	0	06	80
	1095	0	01	10
	1108	0	00	20
	1113	0	04	50
	1112	0	02	80
	1093	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1111	0	01	10
	1110	0	00	20
	1114	0	00	90
	1115	0	02	20
	1116	0	03	80
	1119	0	09	60
	1118	0	00	60
	1120	0	01	30
	1121	0	04	50
	1122	0	06	70
	1123	0	01	00
	1079	0	02	20
	1078	0	00	20
	1070	0	10	20
	1069	0	06	20
	1068	0	07	00
	1067	0	03	50
	1066	0	03	40
	1203	0	00	20
	1201	0	02	40
	1202	0	02	70
	1200	0	18	50
	1199	0	06	70
	1180	0	00	50
	1197	0	00	20
	1181	0	10	00
	1182	0	08	10
	1183	0	11	00
	1187	0	13	40

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1186/2935	0	01	10
	1186	0	05	10
	2600	0	06	90
	2599	0	19	10
	2530	0	14	50
	2529	0	08	40
	2528	0	13	80
	2516	0	02	00
	2484/2943	0	20	90
	2515	0	00	20
	2484/2942	0	10	00
Barsani	224	0	06	50
	1061	0	18	20
	1062	0	31	90
	1079	0	16	20
	1078	0	02	00
	1088	0	04	20
	1087	0	00	20
	1089	0	05	80
	4747	0	11	60
	4748	0	02	60
	4756	0	02	90
	4817	0	05	10
	4816	0	15	20
	4815	0	12	10
	4820	0	11	40
	4821	0	09	60
	4833	0	15	30
	4835	0	02	60

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	4836	0	00	20
	4834	0	05	90
	4832	0	03	10
	4842	0	04	50
	4841	0	02	60
	4843	0	16	70
	4862	0	01	40
	4861	0	06	50
	4964	0	01	70
	4863	0	00	20
	4963	0	04	00
	4962	0	01	50
	4961	0	05	20
	4960	0	06	00
	4959	0	13	00
	4882	0	01	10
	4955	0	08	40
	4898	0	02	80
	4899	0	07	60
	4900	0	07	80
	4903	0	00	30
	4902	0	07	60
	4930	0	05	40
	4929	0	03	20
	4928	0	02	80
	4913	0	05	40
	4924	0	03	60
	4918	0	04	40
	4917	0	04	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	4923	0	00	20
	4919	0	00	20
	4920	0	05	60
	4921	0	05	30
	5212	0	06	00
	5213	0	01	70
Kolikhera	291	0	10	50
	294	0	16	70
	296	0	10	80
Amesar	3230	0	02	30
	3231	0	06	20
	3232	0	06	70
	3233	0	11	60
	3234	0	06	30
	3243	0	16	80
	3247	0	08	70
	3249	0	12	40
	3251	0	06	50
	3253	0	10	80
	3252	0	04	80
	3190	0	10	80
	3187	0	02	90
	3186	0	01	50
	3184	0	00	20
	3185	0	13	60
	3182	0	02	40
	3183	0	03	10
	3209	0	03	30
	3202	0	01	80

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	3201	0	00	70
	3200	0	09	80
	370	0	13	10
	371	0	07	20
	404/4947	0	11	90
	404/4934	0	00	50
	818/4933	0	05	60
	879	0	05	00
	880	0	07	40
	882	0	00	90
	896	0	06	50
	899	0	00	50
	895	0	08	00
	894	0	09	70
	905	0	10	50
	930	0	03	70
	929	0	03	20
	927	0	05	60
	928	0	01	80
	925	0	00	70
	924	0	04	90
	922	0	09	10
	921	0	03	20
	1595	0	19	10
	1596	0	05	10
	1588	0	04	80
	1607	0	07	40
	1608	0	05	30
	1606	0	01	10

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1609	0	10	40
	1634	0	10	50
	1633	0	01	80
	1632	0	10	20
	1630	0	00	20
	1631	0	02	10
	1638	0	02	20
	1639	0	07	30
	1626	0	00	20
	1640	0	06	20
	1641	0	11	30
	1642	0	09	90
	1643	0	08	10
	1988	0	05	40
	1987	0	00	30
	1986	0	03	60
	1959	0	03	90
	1950/4890	0	03	00
	1950	0	05	80
	1949	0	04	50
	1951	0	02	90
	1945	0	04	60
	1944	0	07	20
	1943	0	09	30
	1941	0	02	00
	1942	0	00	70
Mataji Ka Khera	995	0	16	40
Jabrakiya	247	0	12	60
	248	0	00	30

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	256	0	10	80
	296	0	07	60
	295	0	04	90
	292	0	02	00
	294	0	06	20
	293	0	10	40
	413	0	11	40
	416	0	00	60
	414	0	10	70
	594	0	14	10
	591	0	00	50
	590	0	09	00
	588	0	01	90
	589	0	00	30
	585	0	10	90
	583	0	03	60
	775	0	08	30
	772	0	12	80
	764	0	02	50
	765	0	01	00
	766	0	10	80
	763	0	00	80
	767	0	00	20
	761	0	03	60
	762	0	02	40

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	759	0	00	20
	760	0	05	60
	758	0	05	40
	757	0	05	10
	756	0	02	00
	755	0	00	20
	836	0	06	80
	837	0	10	10
	841	0	11	10
	842	0	01	00
	743	0	01	80
	1021	0	14	40
	1026	0	05	30
	1024	0	11	40
	1023	0	10	00
	1022	0	14	80
	1264	0	04	00
	1265	0	06	90
	1270	0	00	50
	1266	0	01	80
	1267	0	02	20
	1268	0	06	30
	1240	0	05	70
	1239	0	02	80
	1238	0	01	30
	1236	0	01	30
	1241	0	02	70
	1235	0	02	20
	1234	0	01	70

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1242	0	01	30
	1243	0	06	00
	1233	0	01	10
	1227	0	01	20
	1228	0	02	10
	1229	0	08	80
	1226	0	02	90
	1369	0	00	40
	1471	0	04	10
	1472	0	09	80
	1468	0	14	00
	1467	0	01	00
	1514	0	00	20
	1515	0	07	80
	1516	0	11	40
	1517	0	09	30
	1519	0	15	20
	1520	0	08	10
	1519/1531	0	00	20
	1520/1532	0	23	70
	1521	0	00	20
	1526	0	08	50
	1525	0	00	20
	1527	0	78	60
	1511	0	01	00
Palri	765	0	04	20
	764	0	08	70
	767	0	00	50
	766	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	763	0	07	60
	769	0	05	90
	770	0	01	10
	782	0	05	70
	781	0	00	30
	790	0	08	20
	791	0	01	80
	794	0	08	70
	793	0	00	20
	792	0	00	20
	795	0	07	30
	817	0	02	70
	816	0	08	10
	815	0	08	30
	814	0	04	60
	813	0	04	50
	812	0	04	40
	811	0	03	60
	810	0	10	90
	808	0	03	60
	807	0	10	50
	806	0	13	80
Sareri	130	0	10	40
	128	0	07	10
	127	0	22	40
	146	0	12	40
	145	0	06	70
	147	0	29	80
	148	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	149	0	26	20
	150	0	26	00
	257	0	00	30
	5317/257	0	03	20
	171	0	16	60
	254	0	06	90
	253	0	16	30
	174	0	14	70
	175	0	04	80
	250	0	32	40
	249	0	05	90
	248	0	03	70
	237	0	07	20
	241	0	00	70
	239	0	11	40
	234	0	01	20
	5307/233	0	07	30
	229	0	14	40
	228	0	48	80
	1687	0	15	80
	1693	0	00	20
	1694	0	09	90
	1697	0	02	20
	1695	0	06	40
	1700	0	07	60
	1701	0	17	10
	1714	0	14	40
	1711	0	00	20
	1715	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1716	0	02	00
	1713	0	03	00
	1712	0	00	40
	1717	0	09	90
	1718	0	07	60
	1668	0	00	20
	1667	0	08	20
	1666	0	05	30
	1665	0	11	30
	1662	0	00	30
	1663	0	07	10
	1664	0	00	30
	1661	0	08	70
	1660	0	02	10
	1659	0	05	90
	1656	0	01	10
	1654	0	08	00
	1655	0	04	90
	1649	0	19	00
	1648	0	01	10
	1627	0	01	70
	1628	0	01	60
	1629	0	11	30
	1630	0	00	20
	1631	0	10	90
	1626	0	01	80
	1449	0	00	20
	1448	0	15	00
	1447	0	01	30

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1446	0	10	60
	1452	0	00	50
	1445	0	15	60
	1436	0	11	00
	1435	0	03	10
	1416	0	11	10
	1417	0	01	10
	1419	0	00	90
	1403	0	07	80
	1402	0	02	50
	1317	0	06	80
	1318	0	10	80
	1307	0	01	30
	1319	0	02	80
	1306	0	00	30
	1305	0	17	80
	1280	0	06	40
	1281	0	01	40
	1277	0	07	70
	1276	0	00	80
	1278	0	00	20
	4261	0	09	00
	5250/4259	0	00	70
	4260	0	04	30
	4265	0	05	90
	4251	0	02	00
	4250	0	02	30
	4252	0	01	40
	4249	0	14	10

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	4248	0	01	20
	4345	0	08	00
	4346	0	01	10
	4344	0	00	20
	4351	0	07	20
	4350	0	02	20
	4352	0	00	20
	4353	0	07	60
	4355	0	01	60
	4360	0	00	80
	4354	0	08	90
	4359	0	05	70
	4391	0	00	30
	4382	0	16	50
	4390	0	00	20
	4389	0	00	40
	4436	0	00	20
	4434	0	12	80
	4417	0	01	20
	4419	0	04	20
	4420	0	00	90
	4421	0	01	60
	4432	0	02	30
	4422	0	04	80
	4431	0	04	70
	4429	0	04	50
	4430	0	01	10
	4428	0	00	30
	4490	0	00	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	4488	0	00	60
	4487	0	00	70
	4489	0	17	00
	4666	0	06	00
	4667	0	02	90
	4686	0	01	90
	4664	0	08	00
	4688	0	04	60
	4687	0	02	00
	4689	0	03	80
	4690	0	02	10
	4691	0	02	80
	4718	0	00	80
	4719	0	00	20
	4717	0	06	70
	4715	0	03	20
	4716	0	04	50
	4790	0	05	00
	4788	0	00	20
	4794	0	05	20
	4795	0	02	90
	4796	0	03	50
	4840	0	08	50
	4839	0	05	00
	4846	0	05	60
Kornas	1528	0	11	20
	1527	0	00	20
	1600	0	07	50
	1602	0	04	20

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1606	0	02	50
	1605	0	11	10
	1609	0	04	80
	1610	0	02	10
	1617	0	10	40
	1618	0	08	60
	1619	0	00	20
	1644	0	03	80
	1645	0	08	30
	1657	0	08	60
	1669	0	08	70
	1658	0	01	40
	1667	0	10	30
	1668	0	00	20
	1681	0	07	00
	1682	0	02	00
	1705	0	06	90
	1707	0	00	20
	1706	0	06	70
	1700	0	10	70
	1717	0	00	20
	1699	0	04	40
	1698	0	04	30
	1697	0	09	50
	1696	0	00	30
	1740	0	28	30
	1756	0	07	70
	1755	0	07	50
	1767	0	04	50

Tehsil : ASIND	District : BHILWARA	State : RAJASTHAN		
Name of the Village	Khasara No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
	1766	0	01	00
	1768	0	08	70
	1774	0	06	20
	1775	0	01	70
	1773	0	08	60
	1780	0	00	60
	1781	0	14	60
	1794	0	04	90
	1792	0	00	20
	1789	0	03	60
	1793	0	26	60

[No. R-25011/31/2004-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 2005

का. आ. 1707.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी (पुणे) से पकनी (सोलापुर) तक हज़ारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एस. एन. कुन्देतकर, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेगा सेंटर, मागरपट्टा, एम व एन विंग, हादापसर-411 028 (पुणे जिला), महाराष्ट्र राज्य को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : खानापुर		जिला : सांगली		राज्य : महासष्ट्र		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल	
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोलवणी		1062		00	26	00
			1130		00	01	26
			1150		00	01	12
			1547		00	00	30
			1523		00	06	94
			100		00	14	25
			101		00	01	25
			99		00	11	04
			95		00	18	00
			296		00	06	10
			313		00	03	41
				कुल	**00**	**89**	**67**
2	अलसुंद		224		00	13	47
			2192		00	01	75
				कुल	**00**	**15**	**22**
3	तांदुलवाडी		120		00	11	00
			112	8	00	00	60
			112	7	00	01	75
			112	5	00	01	00
			112	9	00	00	30
			212		00	00	60
			220		00	01	20
				कुल	**00**	**16**	**45**

[फा. सं. आर-31015/28/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th May, 2005

S. O. 1707.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni (Pune) to Pakni (Solapur) via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.N. Kundetkar, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mega Center, Magarpatta – M&N Wing, Hadapsar – 411 028, Pune District , Maharashtra.

SCHEDULE

Taluka : KHANAPUR		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BHALAVANI		1082		00	26	00
			1130		00	01	26
			1150		00	01	12
			1547		00	00	30
			1523		00	06	94
			100		00	14	25
			101		00	01	25
			99		00	11	04
			95		00	18	00
			296		00	06	10
			313		00	03	41
				Total	**00**	**89**	**67**
2	ALSUND		224		00	13	47
			2192		00	01	75
				Total	**00**	**15**	**22**
3	TANDULVADI		120		00	11	00
			112	8	00	00	60
			112	7	00	01	75
			112	5	00	01	00
			112	9	00	00	30
			212		00	00	60
			220		00	01	20
				Total	**00**	**16**	**45**

[No. R-31015/28/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 मई, 2005

का. आ. 1708.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी (पुणे) से पकनी (सोलापुर) तक हज़ारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेगा सेंटर, मगरपट्टा, एम व एन विंग, हादापसर-411 028 (पुणे जिला), महाराष्ट्र राज्य को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : हवेली **जिला : पुणे** **राज्य : महाराष्ट्र**

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कदमवाकवस्ती		803		00	00	59
			767		00	00	20
			833		00	00	20
			849		00	01	93
			763		00	00	20
			615		00	02	21
			605		00	05	23
			599		00	01	21
				कुल	00	11	77

तालुका : हवेली		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल	
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	लोनी कालभोर		1747	25	00	26	10
			1791		00	01	90
			1699		00	01	80
			1696		00	00	86
			1694		00	00	80
			1527		00	02	35
			1526		00	05	44
			1518		00	03	47
			1517		00	00	36
			1512		00	07	54
			1503		00	02	55
			1492		00	04	92
			1467		00	02	54
			1465		00	01	38
			1459		00	02	04
			1419		00	02	24
			1170		00	03	88
				कुल	**00**	**70**	**17**
3	आलंदी म्हातोबाची		1120		00	04	23
			1094		00	15	36
			1090		00	02	62
			1065		00	01	60
			1055		00	01	80
				कुल	**00**	**25**	**61**

[फा. सं. आर-31015/24/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 4th May, 2005

S. O. 1708.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni (Pune) to Pakni (Solapur) via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mega Center, Magarpatta – M&N Wing, Hadapsar – 411 028, Pune District, Maharashtra.

SCHEDULE

Taluka : HAVELI		District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KADAM WAKWASTI		803		00	00	59
			767		00	00	20
			833		00	00	20
			849		00	01	93
			763		00	00	20
			615		00	02	21
			605		00	05	23
			599		00	01	21
				Total	00	11	77
2	LONI KALBHOR		1747	25	00	26	10
			1791		00	01	90
			1699		00	01	80
			1696		00	00	86
			1694		00	00	80
			1527		00	02	35
			1526		00	05	44
			1518		00	03	47
			1517		00	00	36
			1512		00	07	54
			1503		00	02	55
			1492		00	04	92
			1467		00	02	54
			1465		00	01	38

Taluka : HAVELI		District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
			1459		00	02	04
			1419		00	02	24
			1170		00	03	88
				Total	**00**	**70**	**17**
3	ALANDI		1120		00	04	23
	(MHATOBACHI)		1094		00	15	36
			1090		00	02	62
3	ALANDI		1065		00	01	60
	(MHATOBACHI) (Contd.)		1055		00	01	80
				Total	**00**	**25**	**61**

[No. R-31015/24/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2005

का. आ. 1709.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी (पुणे) से पकनी (सोलापुर) तक हज़ारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एस. एन. कुन्देतकर, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेगा सेंटर, मागरपट्टा, एम व एन विंग, हादापसर-411 028 (पुणे जिला), महाराष्ट्र राज्य को लिखित रुप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : कवठे महांकाल		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल	
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिसंगी		471		00	02	23
			484		00	01	19
			489		00	00	85
			500	ब	00	02	50
			639		00	00	30
			669		00	05	43
			667		00	01	17
			665		00	11	27
			कुल		00	24	94
2	घाटनांद्रे		78		00	00	20
			183		00	01	27
			191		00	00	77
			248		00	00	42
			257		00	01	09
			283		00	01	54
			598		00	01	80
			595		00	04	06
			599		00	00	20
			594		00	00	40
			817		00	23	25
			823		00	07	83
			कुल		00	42	83

[फा. सं. आर-31015/30/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2005

S. O. 1709.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni (Pune) to Pakni (Solapur) via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.N. Kundetkar, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mega Center, Magarpatta – M&N Wing, Hadapsar – 411 028, Pune District , Maharashtra.

SCHEDULE

Taluka : KAVTHE MAHANKAL		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area	
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TISANGI		471		00	02	23
			484		00	01	19
			489		00	00	85
			500	B	00	02	50
			639		00	00	30
			669		00	05	43
			667		00	01	17
			665		00	11	27
				Total	00	24	94
2	GHATNANDRE		78		00	00	20
			183		00	01	27
			191		00	00	77
			248		00	00	42
			257		00	01	09
			283		00	01	54
			598		00	01	80
			595		00	04	06
			599		00	00	20
			594		00	00	40
			817		00	23	25
			823		00	07	83
				Total	00	42	83

[No. R-31015/30/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2005

का. आ. 1710.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुन्द्रा (गुजरात) से दिल्ली तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री राम करण शर्मा, सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मकान संख्या -1418, सेक्टर - 6, बहादुरगढ़, जिला - झज्जर - 124507 (हरियाणा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसुची

तहसीलः बहादुरगढ़	जिलाः झज्जर		राज्यः हरियाणा			
गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	मुसतिल संख्या	खसरा/ किला संख्या	श्रेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1. बादली	72	4	17	00	00	98
			23	00	01	53
		12	3/2	00	01	78
		13	16	00	00	39
		20	5/1	00	01	44
			7/1	00	00	98
			7/2	00	02	12
			12	00	00	69
			13	00	00	61
		35	6	00	00	45
			14	00	03	95
			23	00	01	78
		39	16	00	00	64
		40	2	00	01	03
			11	00	00	84
		61	4	00	00	98
			13	00	00	61
		68	16	00	00	45
		96	4	00	00	81
			8	00	01	02
		97	16	00	00	25
		104	22	00	02	33
		136	1	00	09	76

तहसीलः बहादुरगढ़	जिलाः झज्जर		राज्यः हरियाणा			
गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	मुसतिल संख्या	खसरा/ किला संख्या	श्रेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
2. मोहमदपुर माजरा	88	8	15/2	00	02	02
		15	3	00	02	58
			9	00	01	06
			20	00	01	60
			21	00	01	19
		19	1	00	00	27
		32	5	00	00	55
			6	00	00	90
3. गोयला कलां	58	63	2	00	03	17
			9	00	00	27
		74	21	00	03	56
	58		107 (रास्ता)	00	00	90
		77	1/1	00	09	54
			1/2	00	01	26
			10	00	07	77
4. बुर्पानियां	59	10	25	00	02	88
		19	15/2	00	01	34
		42	220	00	04	35
			11	00	00	96
			20	00	00	62
			21	00	01	91
		59	6	00	00	51
			15	00	00	57
			17	00	01	01
			23/1	00	00	39
		66	3	00	09	07
			4/1	00	01	50
			8	00	11	60
			12	00	00	78
			13	00	10	16
			18/1	00	01	36
			19	00	10	22
			22	00	11	60
		88	1	00	01	75
			10/1	00	05	92
			10/2	00	01	63
		89	16	00	02	62
			25/2	00	05	28

तहसील: बहादुरगढ़	जिला: झज्जर		राज्य: हरियाणा			
गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	मुमतिल संख्या	खसरा/ किला संख्या	श्रेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
4. बुपनियां (जारी...)		96	23	00	00	58
		121	21	00	00	46
		127	15	00	00	52
			25/1	00	00	56
		128	1	00	00	40
			26	00	00	74
		152	18	00	02	09
			23	00	01	27
		159	8/2	00	00	41
	59	159	22/1	00	01	62
		182	15	00	00	71
		185	4	00	00	93
5. डाबोदा खुर्द	49	36	4/1	00	02	07
			4/2/3	00	00	25
			7	00	02	89
			14	00	01	59
		67	8/1	00	03	09
			8/2	00	00	25
			12/1	00	01	20
			13/1/1	00	01	68
			20/2	00	00	55
			21	00	08	14
		78	1	00	00	30
		79	5	00	08	52
			6	00	07	65
			7	00	04	57
			14	00	07	45
			18	00	06	10
			21	00	00	85
		107	10	00	00	65
6. महब्दीपुर	50	11	2	00	00	63
			12/2	00	01	72
		27	15	00	01	66
			16	00	02	15
			25	00	02	33
		34	4	00	01	95
			17/2	00	00	90

तहसीलः बहादुरगढ़	जिलाः झज्जर			राज्यः हरियाणा		
गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	मुसतिल संख्या	खसरा/ किला संख्या	श्रेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
7. जाखोदा	41	14	10	00	02	74
		15	5/2	00	00	89
			6/1	00	02	85
			15	00	11	15
			25	00	01	26
		18	5	00	01	72
			17	00	01	39
		37	3	00	02	48
	41	37	12	00	01	15
8. आसोदा टोडरान	28		826	00	06	89
			830	00	04	68
			831	00	01	80
			836	00	02	79
			838	00	04	99

[फा. सं. आर-31015/48/2004-ओ.आर-II]
हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2005

S. O. 1710.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Mundra (Gujarat) to Delhi, a pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule, may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Ram Karan Sharma, Competent Authority, Mundra - Delhi Petroleum Product Pipeline, Hindustan Petroleum Corporation Limited, H. No. 1418, Sector – 6, Bahadurgarh - 124507, District – Jhajjar (Haryana).

SCHEDULE

Tehsil :BAHADURGARH		District : JHAJJAR		State : HARYANA		
Name of Village	Hadbast No.	Mustil No.	Khasara / Killa No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
1. BADLI	72	4	17	00	00	98
			23	00	01	53
		12	3/2	00	01	78
		13	16	00	00	39
		20	5/1	00	01	44
			7/1	00	00	98
			7/2	00	02	12
			12	00	00	69
			13	00	00	61
		35	6	00	00	45
			14	00	03	95
			23	00	01	78
		39	16	00	00	64
		40	2	00	01	03
			11	00	00	84
		61	4	00	00	98
			13	00	00	61
		68	16	00	00	45
		96	4	00	00	81
			8	00	01	02
		97	16	00	00	25
		104	22	00	02	33
		136	1	00	09	76
2. MOHAMAD PUR MAJRA	88	8	15/2	00	02	02
		15	3	00	02	58
			9	00	01	06
			20	00	01	60
			21	00	01	19
		19	1	00	00	27
		32	5	00	00	55
			6	00	00	90
3. GOYALA KALAN	58	63	2	00	03	17
			9	00	00	27
		74	21	00	03	56

Tehsil :BAHADURGARH		District : JHAJJAR		State : HARYANA	
Name of Village	Hadbast No.	Mustil No.	Khasara / Killa No.	Area	
				Hectare	Are	Square Metre
3. GOYALA KALAN	58		107 (Path)	00	00	90
(Cont...)		77	1/1	00	09	54
			1/2	00	01	26
			10	00	07	77
4. BHUPANIA	59	10	25	00	02	88
		19	15/2	00	01	34
		42	220	00	04	35
			11	00	00	96
			20	00	00	62
			21	00	01	91
		59	6	00	00	51
			15	00	00	57
			17	00	01	01
			23/1	00	00	39
		66	3	00	09	07
			4/1	00	01	50
			8	00	11	60
			12	00	00	78
			13	00	10	16
			18/1	00	01	36
			19	00	10	22
			22	00	11	60
		88	1	00	01	75
			10/1	00	05	92
			10/2	00	01	63
		89	16	00	02	62
			25/2	00	05	28
		96	23	00	00	58
		121	21	00	00	46
		127	15	00	00	52
			25/1	00	00	56
		128	1	00	00	40
			26	00	00	74
		152	18	00	02	09
			23	00	01	27
		159	8/2	00	00	41
	59	159	22/1	00	01	62
		182	15	00	00	71
		185	4	00	00	93

Tehsil :BAHADURGARH		District : JHAJJAR		State : HARYANA		
Name of Village	Hadbast No.	Mustil No.	Khasara / Killa No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
5. DABODA KHURD	49	36	4/1	00	02	07
			4/2/3	00	00	25
			7	00	02	89
			14	00	01	59
		67	8/1	00	03	09
			8/2	00	00	25
			12/1	00	01	20
			13/1/1	00	01	68
			20/2	00	00	55
			21	00	08	14
		78	1	00	00	30
		79	5	00	08	52
			6	00	07	65
			7	00	04	57
			14	00	07	45
			18	00	06	10
			21	00	00	85
		107	10	00	00	65
6. MEHINDIPUR	50	11	2	00	00	33
			12/2	00	01	72
		27	15	00	01	66
			16	00	02	15
			25	00	02	33
		34	4	00	01	95
			17/2	00	00	90
7. JAKHODA	41	14	10	00	02	74
		15	5/2	00	00	89
			6/1	00	02	85
			15	00	11	15
			25	00	01	26
		18	5	00	01	72
			17	00	01	39
		37	3	00	02	48
	41	37	12	00	01	15
8. ASUDHA TODRAN	28		826	00	06	89
			830	00	04	68
			831	00	01	80
			836	00	02	79
			838	00	04	99

[No. R-31015/48/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7अप्रैल, 2005

का.आ. 1711.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सैन्ट्रल बैंक आफॅ इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अलाप्पुझा के पंचाट [संदर्भ संख्या 8/98(c)] को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/346/97-आई आर (बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th April, 2005

S.O. 1711.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award [Ref. No. 8/98(c)] of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Alappuzha as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 07-04-2005.

[No. L-12012/346/97-IR (B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL : ALAPPUZHA

(Dated this the 2nd day of March, 2005)

PRESENT :

Shri K. Kanakachandran,
Industrial Tribunal

I. D. No. 8/98(C)

BETWEEN :

The Regional Manager,
Central Bank of India,
P.B. No. 98, Gopal Building,
Thyvila Road,
Thiruvananthapuram-695001

AND

The workmen of the above concern
Sri Suresh Kumar S,
T.C. No. 5/1119, Peroorkada P.O.,
Thiruvananthapuram-695 001.

REPRESENTATIONS :

Sri. V.V. Sidharthan, Advocate, Ernakulam	: For Management
Sri H.B. Shenoy & Ashok B. Shenoy, Advocates, 'Vatsal', Krishnaswamy Road, Cochin-35.	: For workman

AWARD

1. On the reference made by the Government of India, by their order dated 24-4-98 on the issue of denial of employment to S. Suresh Kumar from 6-6-97, an award was passed by this Tribunal on 19-7-2000 after taking elaborate evidence. The relief to the workman was molded by this tribunal in para 9 of award. It reads :

> "In the light of the above discussion it can only be held the workman was eligible for absorption in the earliest vacancies of Peon in any of the Branches in the Trivandrum region of the management bank. Without sufficient reason, he was not considered for absorption. From the records made available in this case and also from various circulars issued by the management bank themselves, it is clear that the workman was eligible to be absorbed without any test or interview in any of the earliest vacancies which arose either 1993 or later. Such an entitlement cannot be denied him forever. Therefore it is directed that the management shall appoint him forthwith in any of the vacancies now available or keep him as supernumerary in any of the Branches. The seniority position in his case should be reckoned from the date on which the person next to him in age was absorbed as regular peon with reference to the first qualification mentioned in Clause 3.1 of the Circular dated 12-3-1991. However, the workman will not be entitled for back wages for the period upto 30-6-2000."

2. The award of this Tribunal and the directives contained therein were challenged by both management Bank and the workman. While the management grievance was against the direction for absorption of the workman in service in the next available vacancy with retrospective effect, the grievance of the workman was against the denial of monetary benefit to him for the period up to 30-6-2000. Both sides approached the High Court of Kerala by filing writ petitions. In the writ petition filed by the management O.P. No. 30570/00, the learned Single Judge interfered on the award of this

Tribunal and quashed the same by holding the view that while granting relief, this Tribunal exceeded the jurisdiction by going beyond the scope of the reference. However the judgment of the Single Judge was taken in appeal by the workman by filing writ appeal WA No. 1563/04. By a judgment dated 7-9-2004 the Division Bench of the High Court presided over by then Chief Justice reversed the judgment of the Learned Single Judge by holding a contrary view on the issue of jurisdiction and powers exercised by this Tribunal. It was held in the writ appeal judgment that this Tribunal would have the power to issue such a direction for regularization or absorption and it could not be held as without jurisdiction. However on the findings entered into by this Tribunal on the merit of the entitlement of the workman, a different view was taken by the Division Bench and that was mainly with reference to a passage contained in the written statement filed by the management on their specific denial on the claim put forward by the workman on his continuous service particularly contained in para 12 of the written statement. It was observed by the Division Bench as follows :

"4. As regards the findings of the Industrial Tribunal, the same are based on an alleged admission made by the management. The Tribunal, in the impugned award, had specifically stated that the assertion of the workman that he had completed 240 days of service during the years 1986 and 1987, had not been disputed by the management. This is not correct. we have perused the written statement filed by the management before the Tribunal and in paragraph 12 thereof, the management has specifically denied the fact that the workman had completed 240 days during any period so as to become entitled to claim absorption in the regular service of the Bank. Since the Tribunal too has proceeded on a wrong basis, the findings recorded by it in the impugned award will also have to be set aside which we hereby do. It is true that the Tribunal had also placed reliance on the communication Ext. W5 to hold that the workman had become eligible to seek absorption in terms of the aforesaid circular. Since we are remitting the case back to the Industrial Tribunal, we are not expressing any opinion in this regard and it will be open to the Industrial Tribunal to look into the said document while recording its finding afresh."

4. In the light of the above observation of the High Court in the writ appeal judgment, the parties were permitted to adduce fresh evidence in support of their respective contentions.

5. On the side of management an additional witness was examined before this Tribunal as MW2 after the remand from the High Court. Through him a statement showing the service particulars concerning the workman was also brought in evidence. According to MW2, the details therein were collected from the records available in the branches of the management bank.

6. The main ground on which the Division Bench of the High Court remanded the dispute for fresh consideration was that this Tribunal wrongly assumed the position that the management Bank had not specifically controverted the assertion of the workman that he had to his credit more than 240 days of continuous service in between 1-1-1982 to 31-12-90 particularly in the years 1986 and 1987 and in fact in para 12 of their written statement, they had disputed such contention raised. On the above matter this Tribunal had not made any such remark based on the written statement filed by the management before this Tribunal. What this Tribunal referred was the statement filed by the management Bank before Conciliation Officers in response to the earlier complaint filed by the workman. In this connection it is useful to extract a portion from paragraph 8 of the award of this Tribunal.

> "8. In the claim submitted by the workman to the Assistant Labour Commissioner (Central), it is specifically asserted that he was having more than 240 days of service during the years 1986 and 1987. This assertion is not disputed by the management in their reply to the claim. Without furnishing any detail regarding the exact number of days the workman had worked in the Branches under the management bank, only in a general way it is contended that he worked only for a short period on daily wages. In paragraph 6 it is only stated that the workman did not satisfy the eligibility conditions stipulated in the circular."

7. In this connection it is relevant to Ext. W1 complaint submitted by the workman before the management. The number of days he worked during various periods are stated in detail :

"1985—210,
1986—251,
1987—246,
1988—255,
1989—191,
1990—221."

8. About the above particulars furnished what the management stated in Ext. W1 reply is only this.

"The provisions of HO Circular referred to are not applicable to Suresh Kumar as he does not satisfy the eligibility conditions stipulated in it."

9. With reference to the above answering by the management to the complaint of the workman, this Tribunal held earlier that there was no clear-cut refuting by the management. The eligibility conditions were prescribed by the Head Office of the management bank themselves as per their Ext. W3 series circulars, particularly the circular dated 18-2-91. In those circulars, various eligibility conditions are prescribed and one of the conditions is that temporary employees who have worked for 240 days in any continuous period of 12 months after 1-1-1982 upto 31-12-90 should be considered for permanent recruitment as a condition precedent. Based on the above provision in the circular, the workman asserted that he had to his credit more than 240 days of continuous service during three years 1986, 87 and 88. That assertion is not disputed by the management with the facts and figures available with them except a general way in response to the complaint before Labour Officials. According to the workman he did not have any documentary evidence as his own, because, for the work done by him on all working days, he would be paid daily wages and for such payments made to him he would give vouchers to the bank and the payments to him would be recorded by the management in their own daily wage payment register. Since the custodian of all the records is the management bank themselves, the workman filed a petition for causing production of those documents by the management. But they failed to produce the ledgers and relevant documents relating to the period in which the workman claimed to have worked for more than 240 days in a year. When the management failed to produce the necessary documents, the workman had placed his trump card. Ext. W5 will support his claim and that was letter of recommendation sent by the Branch Manage. conceding the position that the workman would come within the eligibility category. About that document, now the management had taken up the contention that the Branch Manager who sent that letter had no business to send such a letter making recommendations.

10. Ext. W3 series circulars would highlight the mode of absorption or regularization process of sub-staff who would satisfy the eligibility conditions. Central Office of the management bank had been issuing various guidelines and direction to the Regional Offices and Zonal Offices through those circulars to collect the required particulars from the branches in which eligible condidates were working. Moreover, the contention raised by the learned counsel for the management on the competency of the Branch Managers in sending letters like Ext. W5 is of no basis when we peruse the Circular dated 18-2-1981. That circular is issued from the Regional Office at Cochin to all the Branch Managers of Cochin and Trivandrum regions. It directed the branches to send bio data of those persons who would come under the eligible categories in duplicate. It should be remembered that each case would be considered only on the basis of particulars furnished from each branch. No individual application from any candidate would be entertained. The Branch Managers should also desist from forwarding any individual application.

11. In view of the above circular issued from the Regional Office, it can be seen that all the Branch Managers are bound to send particulars of the eligible candidates. The Branch Managers were prevented from procuring any individual applications of the eligible candidates. Definitely, only in accordance with the instructions contained in Ext. W3 circulars, Ext. W5 communication was sent by the Branch Manager to the regional office. Sending of Ext. W5 was admitted by WW2 who forwarded the details concerning the workman to the Regional office. Though an attempt was made by the very same Branch Manager (WW2) to back out from the responsibility for sending Ext. W5, that is of no use when we look at the specific directive contained in the Circular of the management dated 18-2-1991. It can only be concluded that WW2 acted only within the parameters specified in the Ext. W3 series circulars.

12. After the remand of this dispute for fresh consideration, as noted earlier, the management adduced additional evidence by examining a Senior Manager now working in the Trivandrum region. He had brought in evidence Ext. M2 which is a statement prepared by himself and the Regional Manager. Regarding the details of service particulars furnished by the workman (through Ext. W2), MW2 had deposed that the contend of it were not correct. Regarding Ext. W5 what is deposed by him was that the same was not received in the Regional Office. However he has admitted that during that time he was working in the Kottayam Branch and not in the Regional Office. On the question whether if no eligible candidates were available for recruitment or absorption, the Branch Manager was bound to send any "nil report", MW2 expressed some kind of ignorance. He has stated that after perusing the records obtained from the Branch, he prepared Ext. M2. However he admitted that none of the original of the documents he relied on for prepairing Ext. M2 are not available now, because, those were not traceable. To another question whether the payments made to the workman for the days he worked could be ascertainable from the miscellaneous account maintained in the branch, MW2 deposed in affirmative. However he added that the original of those miscellaneous accounts are not now available. It is also deposed by him that such records were maintained usually only for five years. In view of the above position, the only viable alternative is to rely on Ext. W5 communication which was admittedly sent by WW2 to the regional office

in response to the directive from the Regional or Zonal Office of the Bank though he disputed the contends of it before this Tribunal. Possibly such a twist now might be due to the pressure exerted on him to defeat somehow the case of the workman in these adjudication proceeding. In the absence of any cogent evidence from the side of the management, it is only appropriate to reach a conclusion on the eligibility of the workman by fully relying on Ext. W5 communication which was sent by the Manager of the Branch in which the workman was working. In fact he was duty bound to send such details in response to the circular issued from the Regional Office of the management on 18-12-1991. In this context it is to be noted that Ext. W4 dated 19-10-1993 which was sent from the same branch to the Cochin Regional Office also contains similar particulars and that was sent subsequent to the sending of Ext. W5. In that Ext. W4, bio-datas of some other workmen were also forwarded. That was sent after two months from the date of sending of Ext. W5. In both Ext. W4 and W5, specific recommendations were made by the Branch Manager regarding the eligibility of the persons for absorption or appointment in regular service. In view of this position, there is no reason to ignore Ext. W5 alone. Moreover, in the writ Appeal judgment it was specifically stated that the Tribunal is within right to look into the admissibility of Ext. W5 communication. Such a direction was disagreeing with the findings arrived by the learned Single Judge on the admissibility of Ext. W5.

13. In the result an award is passed holding that the workman is entitled for absorption without any test or interview in any of the earliest vacancies which arose either in 1993 or later as he had satisfied the eligibility conditions. Therefore it is directed that the management should give him the posting with retrospective effect as was ordered earlier. If no vacancies were available as on that date, a supernumerary post shall be created for his appointment. The workman will be entitled for monetary benefits from the date of passing of this award.

(Dated this the 2nd day of March, 2005)

Sd/-

K. KANAKACHANDRAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

I. D. No. 8/1998 (C)

Witnesses examined on the side of the Management :

MW1 : Surendran Nair

MW2 : Muthuswamy T.S.

Witnesses examined on the side of the workman :

WW1 : Suresh Kumar

WW2 : K. Sreenivasan

[Joint Trial with I.D. No. 9/98(C)]

Exhibits marked on the side of the Management :

M1 : Extract copy of daily wage book from 2/92 to 6/93 maintained by the management Bank.

M2 : Statement showing number of days of engagement of the workman on daily basis at different branches of the management bank during the years 1985 to 1997.

Exhibits marked on the side of the workman :

W1 : letter dated 4-9-97 sent by the management bank to the Assistant Labour Commissioner (Central), Trivandrum.

W2 : Copy of the letter dated 18-9-97 sent by the workman to the Assistant Labour Commissioner (Central), Trivandrum.

W3 (series 5 Nos.) : Copy of circular dated 13-3-90; 18-9-90, 18-2-91, 12-3-91 & 20-9-93 issued by the Management Bank.

W4 : Copy of letter dated 19-10-93 sent by the Management Trivandrum branch to Cochin Regional Office.

W5 : Copy of letter dated 23-8-93 sent by the Management Trivandrum branch to Trivandrum Regional Office.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

का.आ. 1712.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 54/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/239/98-आई आर (बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2005

S.O. 1712.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 54/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the the employers in relation to the Management of Punjab National Bank and their workman, which was received by the Central Government on 7-4-2005.

[No. L-12012/239/98-IR (B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT/LOK ADALAT SARVODYA NAGAR, KANPUR

INDUSTRIAL DISPUTE No. 54 OF 1999

In the matter of dispute between :—

Sri Prakash Narayan
House No 334/14,
Ram Nagar, Lucknow Road,
Hardoi

AND

Punjab National Bank
The Regional Manager
PNB 156, Civil Lines,
Bareilly.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, *vide* its Notification No. L-12012/239/98/I.R. (B-II) dated 9-3-99, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> "Whether the action of the management of Punjab National Bank in dismissing the workman Sri Prakash Narayan, Head Cashier vide order dated 10-7-97 was legal and justified? If not what relief is the workman entitled to?"

2. In the instant case, after exchange of pleadings between the parties, the concerned workman was debarred from adducing his evidence in support of his case as the workman could not make his presence on the date of hearing of the case when the case was taken up. The management beside filing of documentary evidence has also lead oral evidence in support of their case, through its Senior Manager Sri B. S. Gupta. On the date of evidence of the none was present from the side of workman to cross examine the management witness. Hence the evidence of the management remains uncontroverted and under these circumstances the tribunal has no hesitation in believing the evidence lead by the management in support of their case. Moreover as per settled principle of law if a party raising claim fails to adduce evidence in support of his case, his claim must fail. Since in the instant case, workman has claimed that the action of the management in dismissing him from the services of the bank was neither legal nor justified. Under these circumstances it was incumbent upon the workman to have lead evidence in support of his claim. Workman having failed to adduce evidence in support of his case is not held entitled to any relief pursuant to the present reference made to this tribunal.

3. Accordingly it is held that the workman is not entitled for any relief for want of evidence in support of his case and the reference is decided against the workman and in favour of the management.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

का.आ. 1713.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 67/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/49/2000-आई आर (बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2005

S.O. 1713.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 67/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 07-04-2005.

[No. L-12012/49/2000-IR (B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT/LOK ADALAT SARVODAYA NAGAR, KANPUR

INDUSTRIAL DISPUTE No. 67 OF 2000

In the matter of dispute between :—

Sri Ram Phal S/o Sri Durjan
Village Itaura
Post Ahitganj Jagir,
Mainpuri,
Uttar Pardesh

AND

Bank of India
The Regional Manager BOI,
Ist floor, Jiwan Prakash
LIC Building, Sanjay Palace,
Agra-202001

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/49/2000/IR (B-II) dated 19-7-2000, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> "Whether the claim of Sri Ram Phal that he has been working as Badlisafai Karamchari for the bank for the last ten years and that and on retirement of Smt. Maya Devi part time Safai Karamchari he worked against the vacancy since 1-1-94 is true? If so whether the action of the management of BOI in terminating his services w.e.f. 23-6-99 and appointing another part time Safai Karamchari is justified ? If not, to what relief the disputant Sri Ram Phal is entitled to ?"

2. In the instant case after exchange of pleadings between the parties, the case was taken up for evidence of the parties. But unfortunately both the contesting parties failed to adduce their respective evidence in support of their claim. Therefore, virtually the present case is a case of no evidence. It is settled principle of law that party raising dispute first to lead evidence in support of his case and in case he fails to lead evidence in support of his case, his claim must fail and he cannot be held entitled to claim any relief. Needless to mention that on failure to put appearance on the date fixed parties were debarred from adducing their respective evidence by the tribunal.

3. In the facts and circumstances stated above, the tribunal is left with no other option but to hold that the claimant of the present dispute is not entitled for any relief for want of evidence. Reference is answered accordingly against the workman and in favour of the management.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

का.आ. 1714.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 6/1999) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 07-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/40/98-आई आर(बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th April, 2005

S.O. 1714.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 6/1999) of the Central Government Industiral Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 07-04-2005.

[No. L-12012/40/98-IR(B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT/LOK ADALAT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR
INDUSTRIAL DISPUTE No. 6 OF 1999

In the matter of dispute between :

Naresh Chandra Batham
C/o B.P. Saxena
426, Block II Basant Vihar,
Kanpur.

AND

Bank of India
Regional Manager,
Bank of India
15/54-B, Civil Lines,
Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-12012/40/98-IR(B-II) dated 30-12-98, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

> "Whether the action of the management of Bank of India in terminating the services of Shri Naresh Chandra Batham w.e.f. 13-4-96 is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled ?"

2. In the instant case after exchange of pleadings between the parties, the case was taken up for evidence of the parties. But unfortunately both the contesting parties failed to adduce their respective evidence in support of their claim. Therefore, virtually the present case is a case of no evidence. It is settled principle of law that party raising dispute first to lead evidence in support of his case, and in case he fails to lead evidence in support of his case, his

case, his claim must fail and he cannot be held entitled to claim any relief. Needless to mention that on failure to put appearance on the date fixed parties were debarred from adducing their respective evidence by the tribunal.

3. In the facts and circumstances stated above, the tribunal is left with no other option but to hold that the claimant of the present dispute is not entitled for any relief for want of evidence. Reference is answered accordingly against the workman and in favour of the management.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली 8 अप्रैल, 2005

का.आ. 1715.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कॉपर लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 19/89) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 08-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/52/84-आई आर (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 1715.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 19/89) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Hindustran Copper Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 08-04-2005.

[No. L-43012/52/84-IR(M)]

B.M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 19/89

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 43012/52/84 डी. III (बी) दि. 23-1-89

श्री अर्जुन राम ढाका मार्फत राष्ट्रीय खेतड़ी ताम्बा प्रोजैक्ट मज़दूर संघ, झुंझनू।

—प्रार्थी

बनाम

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर।

—अप्रार्थी

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह नैन

अप्रार्थी की ओर से : श्री संजय राहड़

दिनांक अवार्ड : 24-2-2005

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :

> "Whether the action of the management of Hindusthan Copper Ltd., Khetri Copper Complex, Khetrinagar in terminating Shri Arjun Ram Dhaka, Mining Mate w.e.f. 21-4-84 is justified? If not, what relief is the workman entitled to?"

2. श्रमिक के क्लेम का आधार यह है कि उसको विपक्षी कम्पनी द्वारा 30-1-73 को खनिज श्रमिक के पद पर नियोजित किया गया था व उस समय "बी" फार्म में जन्म पत्री के आधार पर उसकी जन्म तिथि 16-7-1930 दर्ज की गई थी जो सही है व मूल जन्म पत्री भी उसने नियोजक को प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त श्रमिक ने भारतीय सेना में नौकरी की थी जहां से डिस्चार्ज प्रमाण पत्र में उसकी आयु 21-4-1926 बताई गई थी व संयुक्त निदेशक (खान) सुरक्षा अजमेर द्वारा सेवा के आधार पर उसे आयु संबंधी जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसमें उसकी जन्म तिथि 7-5-1925 दर्ज की गई थी। श्रमिक का कथन है कि दोनों जन्म तिथियों में उसकी वैधानिक जन्म तिथि 16-7-30 है व उसी के अनुसार उसे नियोजक द्वारा सेवा निवृत किया जाना था किन्तु नियोजक ने धोखे से एक खाली कागज़ पर हस्ताक्षर करवाकर सेना के डिस्चार्च प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्म तिथि में संशोधन कर दिया व उसे 21-4-26 को जन्म तिथि के आधार पर 21-4-84 को सेवा निवृत कर दिया जो नियोजक की कार्यवाही अवैधानिक व अन्यायोचित है। श्रमिक का यह भी कथन है कि "बी" फार्म में प्रारंभ से जो उसकी जन्म तिथि दर्ज की हुई थी उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया गया व 5-7-83 को उसने जन्म तिथि बदलने बाबत आवेदन कार्मिक अधिकारी को प्रस्तुत किया जो स्वीकार नहीं किया गया। श्रमिक का यह भी कथन है कि सेवा निवृत्ति के लिए "बी" फार्म में दर्ज जन्म तिथि अंतिम रूप से नियमानुसार मान्य है व अन्य श्रमिकों के मामले में भी उसी को आधार मानते हुए कार्यवाही की गई है।

3. नियोजक ने अपने जवाब में एक प्रारंभिक आपत्ति यह ली है कि चूंकि श्रमिक को 21-4-84 को मान्य रूप से सेवा निवृत कर दिया गया है इसलिए उसके व विपक्षी के बीच नियोजित व नियोजक का संबंध नहीं रहा इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा जो विवाद निर्देशित किया गया है वह पोषणीय नहीं है। तथ्यों के संबंध में यह भी अभिकथित किया गया है कि यह प्रकट होता है कि "बी" फार्म में श्रमिक की जन्म तिथि गलत दर्ज कर दी गई थी व श्रमिक ने जो सूचना आयु बाबत दी थी उसमें उसकी जन्म तिथि 7-5-1925 अंकित थी व बाद में सेवा निवृत्ति से कुछ समय पूर्व 1983 में श्रमिक ने सेना का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसकी जन्म तिथि 22-2-1926 दर्ज थी व उसे सही मानते हुए श्रमिक को 21-4-84 को सेवा निवृत किया गया। उनका यह भी कथन है कि 22-1-83 को श्रमिक ने स्वेच्छा से अपनी जन्म तिथि 22-4-1926 दर्ज करने का अनुरोध किया था, इस कार्यवाही में उसके साथ कोई भी धोखा नियोजक द्वारा नहीं किया गया है। "बी" फार्म के संबंध में यह बताया गया है कि सामान्यत: उसमें जो जन्म तिथि दर्ज होती है वह सही मानी जाती है किन्तु यदि उपयुक्त कारण से उसमें संशोधन किया जाता है तो उसी के अनुसार किसी भी श्रमिक को सेवा निवृत्त किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि "बी" फार्म ऐसा प्रलेख नहीं है कि जो उपयुक्त आधार पर संशेधित न किया जा सके।

4. मौखिक साक्ष्य में श्रमिक की ओर से उसका स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व इसके अलावा नियोजक की ओर से एक गवाह श्री डी. एन. शर्मा उप प्रबन्धक (कार्मिक) का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। श्रमिक ने प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-7 प्रलेख प्रस्तुत किये थे। नियोजक की ओर से तत्समय कोई प्रालेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर इस अधिकरण ने 31-1-95 को अवार्ड पारित किया कि श्रमिक अर्जुन राम ढाका को 21-4-84 को सेवा निवृत्त करने को कार्यवाही उचित व वैधानिक नहीं है व उसके स्थान पर श्रमिक को 15-7-88 को सेवा निवृत्त करना चाहिये था। परिणामस्वरूप श्रमिक 21-4-84 से 15-7-88 के बीच की अवधि का बकाया वेतन व अन्य लाभ उसी अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है जैसा कि वह सेवा में रहते हुए प्राप्त करता।

5. इस अधिकरण के अवार्ड दिनांक 31-1-95 को अप्रार्थी नियोजक ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष एस. बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 757/96 प्रस्तुत कर चुनौती दी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12-11-03 के द्वारा इस रिट को स्वीकार करते हुए इस अधिकरण के अवार्ड दिनांक 31-1-95 को अपास्त कर दिया और मामला पुन: सुनवाई हेतु इस अधिकरण के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रेषित किया कि अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों पर विचार करते हुए पक्षकारों को सुनकर पुन: अवार्ड पारित किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों पर अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 12-8-2004 को इस अधिकरण के समक्ष पेश करने पर रैफरैंस पुन: नम्बर पर दर्ज किया गया और अप्रार्थी ने 25-8-2004 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति अधिकारण के समक्ष पेश की। काफी तलाश के पश्चात् भी पूर्व में दर्ज पत्रावली जो अत्याधिक पुरानी होने से अधिकरण के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हुई जिसपर पक्षकारों को पत्रावली को पुनर्निर्मित करने के लिए दस्तावेज पेश करने के आदेश दिये गये जिसपर पक्षकारों ने उपलब्ध दस्तावेज अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये और पत्रावली को पुन: निर्मित किया गया।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रार्थी ने अपने कब्जे के दस्तावेज में मात्र एक दस्तावेज प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र दिनांक 22-1-83 को इस अधिकरण के समक्ष दिनांक 6-1-2005 को प्रस्तुत किया और इसे साबित करने के लिए श्री पी. के. सनवाल का शपथ पत्र पेश किया जिससे प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की। खण्डन में प्रार्थी ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिससे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की। दोनों पक्षों के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. इस अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 31-1-95 में साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि प्रार्थी की सेवाभिलेख जो अप्रार्थी के कब्जे व शक्ति में है, जिसे पेश नहीं किया गया है, उसमें प्रार्थी की जन्म तिथि 16-7-30 दर्ज की हुई है। यह भी निर्धारित किया गया कि अप्रार्थी द्वारा जारी स्थाई आदेशों के नियम 7 (सी) के अन्तर्गत सेवाभिलेख के अन्तर्गत एक बार जो जन्म तिथि दर्ज कर दी गई है उसमें परिवर्तन का प्रावधान नहीं है लेकिन यदि उचित कारण हो तो जन्म तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है और तत्समय आई साक्ष्य से यह साबित नहीं माना कि अप्रार्थी के पास सेवाअभिलेख में जन्म तिथि परिवर्तित करने का कोई उचित कारण था। उसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त अवार्ड को अपास्त करने के पश्चात् अप्रार्थी को उसके कब्जे व शक्तियों के जितने भी दस्तावेज हैं, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है लेकिन अप्रार्थी ने मात्र एक प्रार्थना पत्र जो कि श्रमिक अर्जुन राम ढाका के द्वारा हस्ताक्षरित बताया गया है, को प्रस्तुत कर प्रदर्श कराया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 22-1-83 का है जो अंग्रेजी में है इस पर ए से बी हस्ताक्षर हिन्दी में हैं जिसमें अंकित किया गया है कि श्रमिक पूर्व में सेना से 17-5-47 को डिस्चार्ज किया गया था और डिस्चार्ज के समय उसकी आयु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के अनुसार 21 वर्ष 25 दिन थी जिससे उसकी जन्म तिथि 22-4-26 होती है, उसके सेवाभिलेख में उक्त जन्म तिथि अंकित की जाये और इस आधार पर श्रमिक की जन्म तिथि 22-4-26 दर्ज कर उसको सेवानिवृत्त किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में नियोजक की ओर से उनके यहां यह प्रार्थना पत्र कब पेश हुआ, किसने पेश किया और इस पर क्या कार्यवाही हुई, कुछ भी अंकित नहीं है, न नियोजक की ओर से किसी के कोई हस्ताक्षर हैं। प्रार्थना पत्र से यह

भी पता नहीं चलता कि नियोजक के पास यह किस प्रकार आया। इसको साबित करने के लिए अप्रार्थी ने श्री पी. के. सनवाल का शपथ पत्र पेश किया है लेकिन सेवा से जो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र श्रमिक का था न तो नियोजक ने उसे पेश किया न ही श्रमिक के सेवाभिलेख को पेश किया जिससे स्थिति स्पष्ट होती, न ही इस प्रार्थना पत्र की बाबत की गई कार्यवाही की कोई टिप्पणी व इस संबंध में की गई कार्यवाही का अभिलेख पेश किया। श्री पी. के. सनवाल ने अपनी जिरह में स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसने जो दस्तावेज देखा है उसके अनुसार नियुक्ति के समय श्रमिक ने जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था, जन्म तिथि उनके यहां स्थाई आदेशों के आधार पर तय की जाती है, श्रमिक का मेडीकल करवाया गया या नहीं, पता नहीं श्रमिक की व्यक्तिगत पत्रावली तैयार की जाती है तो जो पर्सनल विभाग में आज भी संस्थान में विद्यमान है। पत्र प्रदर्श आर-1 दिनांक 22-1-83 वैसे तो जनरल मैनेजर या उनके पी. ए. को जाना चाहिये था परन्तु इस पत्र से ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, प्रोपर चैनल के आधार पर विभाग के माध्यम से जनरल मैनेजर के पास पहुंचना चाहिये तथा अग्रिम कॉपी भी दी जा सकती है जो फॉरवर्डिंग लैटर लगा कर कार्यवाही की जा सकती है। इस पत्र पर ऐसी कार्यवाही हुई या नहीं, उसे पता नहीं। इस पत्र के मुद्दे पर क्या कार्यवाही हुई है वह दस्तावेज़ उसने पेश नहीं किया। जबकि खण्डन में श्रमिक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसके खाली कागज़ पर हस्ताक्षर करवाये गये थे और बाद में यह पत्र टाईप करवा लिया होगा, उसने इस प्रकार का कोई पत्र नहीं दिया। इस पत्र पर ए से बी हस्ताक्षर उसके हैं, उससे जिरह भी की गई है जिसमें इसके विपरीत उसने कुछ नहीं कहा। ऐसी सूरत में चूंकि नियोजक की ओर से उसके कब्ज़े में श्रमिक का सेवाभिलेख था, इस पत्र के साथ सेवा का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी दिया जाना अंकित है, यह भी नियोजक के कब्ज़े में था, और इस पत्र पर जो कार्यवाही की गई, क्या प्रक्रिया पद्धति अपनाई गई, इस संबंध में भी दस्तावेज़ नियोजक के कब्ज़े में हैं जो नियोजक द्वारा पेश नहीं किये गये हैं और उनको नियोजक ने जानबूझ कर पेश नहीं किया है। ऐसी सूरत में जैसा कि गोपाल कृष्णा जी केतकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ व अन्य ए. आई. आर. 1968 (एस.सी.) 1413 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को जिस पक्षकार के कब्ज़े में दस्तावेज़ हैं और वह पेश नहीं कर रहा है तो उसके विपरीत उपधारणा की जानी चाहिये। उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अप्रार्थी नियोजक के विपरीत उपधारणा की जाती है और पत्र प्रदर्श आर. 1 दिनांक 22-1-83 पर मात्र श्रमिक के हस्ताक्षर होने ही माना जाता है, इस पर क्या कार्यवाही हुई यह स्पष्ट नहीं है और इस पत्र के आधार पर सेवा अभिलेख में परिवर्तन किया जाना कतई न्यायौचित नहीं है। वैसे भी स्थाई आदेशों के अन्तर्गत नियम 7 (सी) के यह प्रावधान है कि सेवा अभिलेख में एक बार जो तिथि अंकित कर दी गई है वह श्रमिक की प्रार्थना पर परिवर्तित नहीं की जायेगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरजू प्रसाद बनाम जनरल मैनेजर व अन्य एफ.एल.आर. 1981 (43) एस.सी. 408 में यह प्रतिपादित किया है कि जन्म तिथि में परिवर्तन से पूर्व श्रमिक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। बिना सुनवाई के अवसर दिये जन्म तिथि में परिवर्तन कर सेवा निवृत्त करने का आदेश गलत है। जन्म तिथि में किये गये ऐसे परिवर्तन व सेवा निवृत्ति आदेश को अपास्त किया जाना चाहिये। इसी सरधाराम लाल बनाम एडीशनल कमिश्नर एफ.एल.आर. 1992 (64) इलाहाबाद 1155 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि याची के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, उसके अपनी आयु के संबंध में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य पेश नहीं की, उसने जन्म तिथि के बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और विवाद उठाने पर उसे सिविल सर्जन के पास भेजा गया तब सिविल सर्जन के अनुसार बताई गई तिथि अंकित कर दी गई लेकिन याची को सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र के अभाव में सेवाभिलेख में सेवा के समय जन्म तिथि जो अंकित की गई है, वही उसकी सही जन्म तिथि मानी जायेगी और समस्त परियोजन हेतु सेवाभिलेख की जन्म तिथि ही मान्य रहेगी।

8. उक्त सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए चूंकि सेवाभिलेख में जन्म तिथि 16-7-30 अंकित की गई है और उसमें परिवर्तन का कोई आधार व श्रमिक को सुनवाई का अवसर देकर परिवर्तन करना नियोजक ने प्रमाणित नहीं किया है, ऐसी सूरत में श्रमिक की जन्म तिथि जो सेवाभिलेख में प्रविष्टि के समय 16-7-30 दर्ज़ की गई थी, वही मानी जायेगी और नियोजक द्वारा उसमें किये गये परिवर्तन को उचित नहीं माना जा सकता।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"नियोजक हिन्दुस्तान कॉपर लि. खेतड़ी कॉपर कॉम्पलैक्स खेतड़ी नगर द्वारा श्रमिक अर्जुन राम ढाका को दिनांक 21-4-84 को सेवा निवृत्त करने की कार्यवाही उचित व वैधानिक नहीं है व उसके स्थान पर श्रमिक को दिनांक 15-7-88 को सेवा निवृत्त किया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप श्रमिक 21-4-84 से 15-7-88 के बीच की अवधि का बकाया वेतन व अन्य लाभ इसी अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है जैसा कि वह सेवा में रहते हुए प्राप्त करता।"

10. अवार्ड आज दिनांक 24-2-2005 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी.एल. हिस्सारिया, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का०आ० 1716.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 05/318) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/29/89-डी. II (ए)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 1716.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 05/318) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab and Sindh Bank and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-2005.

[No. L-12012/29/89-D.II(A)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 82/89

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल. 12012/29/89-डी-2 (ए) दिनांक 18-8-89

————

श्री कैलाश कुमार सैन द्वारा सहायक महासचिव, राजस्थान बैंक एम्पलाईज़ यूनियन, आदर्श नगर, जयपुर।

———प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बी-23, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।

———अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्नारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम. एफ. बेग

अप्रार्थी की ओर से : श्री पी. एस. रत्नू

दिनांक अवार्ड : 23-2-2005

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :

> "Whether the action of the management of Punjab and Sindh Bank in terminating the services of Shri Kailash Kumar Sain and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under section 25-H of the ID Act is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. प्रार्थी यूनियन ने स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश किया है जिसके अनुसार केन्द्र सरकार ने जो विवाद अधिकरण के समक्ष भेजा है वह संबंधित श्रमिक कैलाश चंद सैन को अवैध सेवा मुक्ति एवं उसे सेवा से पृथक करने के बाद नये श्रमिकों को भर्ती करते समय प्रार्थी श्रमिक को 25 एच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) के तहत पुनः नियुक्ति नहीं देने के संबंध में है। यूनियन के कथानुसार प्रार्थी श्रमिक को नियुक्ति पीओन के पद पर दिनांक 28-2-83 को अप्रार्थी के अधीन हुई थी, उसकी सेवाएं 288 दिन कार्य लेने के बाद 17-6-86 को समाप्त कर दी गई जो अवैध व अनुचित है, अप्रार्थी के यहां कार्य समाप्त नहीं हुआ है अतः सेवा मुक्ति अनुचित है। श्रमिक को सेवामुक्त करने से पूर्व वरिष्ठता सूची नहीं बनाई, न ही शास्त्री अवार्ड के पैरा 507(1) की अनुपालना की गई। इसके अनुसार अंत में आने वाले श्रमिक को पहले हटाना चाहिये किन्तु इस सिद्धान्त को दरकिनार कर श्रमिक से कनिष्ठ श्रमिक से पहले ही प्रार्थी श्रमिक को सेवा पृथक कर दिया जो अनुचित है, श्रमिक जिनकी छंटनी की गई है उनका रजिस्टर नहीं रखा गया, सेवा समाप्त करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस अथवा नोटिस पे अप्रार्थी ने नहीं दी, न ही कोई छंटनी का मुआवजा उसे दिया गया, इस प्रकार शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(5) का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी ने धारा 25-एच व जी अधिनियम के साथ-साथ औद्योगिक विवाद नियम के नियम 77-78 तथा शास्त्री अवार्ड के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। चूंकि श्रमिक को रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था अतः उसे स्थाई किया जाना चाहिए था और नियुक्ति तिथि से समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए था जो नहीं दिया जाकर उसे अनुचित तरीके से सेवा से पृथक किया गया है जो अनुचित है और श्रमिक को पुनः सेवा में समस्त वेतन व लाभ सहित श्रमिक को बहाल किये जाने का अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की गई है।

3. अप्रार्थी बैंक ने क्लेम का जवाब पेश कर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि प्रार्थी श्रमिक को क्लेमेण्ट की विशिष्ट अवधियों के लिए कार्य पर रखा था जिसे किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। उसने कभी भी 240 दिन कार्य नहीं किया, बैंक में नियमित रोज़गार का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता। स्थाई कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने अथवा अवकाश पर रहने की वजह से अवकाश रिक्तियों पर अस्थाई रूप से की गई थी, ये विशिष्ट अवधि के लिए की गई थी और अवधि समाप्त होने के साथ ही श्रमिक का कार्य भी समाप्त हो जाता था। प्रकरण बहुत देरी से उठाया गया है, इन आधारों पर प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

4. गुणावगुण पर अप्रार्थी का जवाब है कि प्रार्थी श्रमिक को 28-2-83 को एक विशिष्ठ अवधि के लिए पूर्ण रूप से अस्थाई स्थिति में रखा गया था, जिसका उसे पूरा ज्ञान था। समय समय पर विशिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर उसकी सेवाएं भी स्वत: ही समाप्त हो गईं, श्रमिक को कभी भी स्थाई नियुक्ति नहीं दी गई ऐसे श्रमिक को सेवा में नियमित होने का कोई अधिकार नहीं होता। अप्रार्थी ने जवाब के पैरा 6 में प्रार्थी श्रमिक द्वारा बैंक को विभिन्न कार्यालयों में जितनी अवधि तक कार्य किया उसका विवरण प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वर्ष 1983 में अलग-अलग कार्यालयों में अलग-अलग अवधियों में कुल 151 दिन, वर्ष 1984 में 20 दिन व वर्ष 1985 में 86 दिन कार्य किया जाना बताया है। जब जब जहां जहां आकस्मिक आवश्यकता पड़ी वहीं श्रमिक को रख लिया गया और उस अवधि की समाप्ति के बाद श्रमिक की सेवाएं स्वत: ही समाप्त हो गईं। अप्रार्थी बैंक द्वारा किसी प्रकार के प्रावधानों अथवा शास्त्री अवार्ड के पैराज का उल्लंघन नहीं किया गया है। नियमित नियुक्तियां बैंक की सुनियोजित प्रक्रिया के अधीन की जाती थी। प्रार्थी श्रमिक ने कभी भी एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया अत: धारा 25-एफ अधिनियम इस प्रकरण पर लागू नहीं होता। प्रार्थी श्रमिक की सेवा स्वयं निश्चित अवधि पर समाप्त होने के कारण छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है अत: क्लेम खारिज किये जाने की प्रार्थना अप्रार्थी द्वारा की गई है।

5. प्रार्थी संघ की ओर से महेश मिश्रा व कैलाश कुमार सैन के शपथ पत्र पेश हुए हैं जिनसे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अप्रार्थी की ओर से बलविन्दर सिंह का शपथ पत्र पेश हुआ है जिससे प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है तथा नेमीचंद एवं बाबू लाल लोढ़िया के बयान कराये है। दस्तावेजी साक्ष्य में अप्रार्थी ने बाबू लाल लोढ़िया की नियुक्ति पत्र एवं नेमीचंद का नियुक्ति पत्र क्रमश: प्रदर्श एम-1 व एम-2 को प्रदर्श कराया है। खण्डन में कैलाश कुमार सैन ने पुन: अपना शपथ पत्र पेश किया है जिससे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने पुन: जिरह की है।

6. दोनो पक्षों के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने लिखित बहस भी पेश की है जिसका भी अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि कैलाश कुमार को अप्रार्थी बैंक के यहां चपरासी के पद पर प्रथम नियुक्ति 28-2-83 को हुई थी और उसकी सेवा 17-6-86 को समाप्त की। अप्रार्थी का यह कथन है कि उसे एवजी में रखा था, कोई विशिष्ट अवधियां नहीं बताने के कारण मानने योग्य नहीं है और श्रमिक की नियुक्ति धारा 2(00) (बीबी) अधिनियम की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए अवधि समाप्ति के साथ उसकी सेवा समाप्त नहीं हुई और उसकी सेवा समाप्ति छंटनी की परिभाषा में आती है तथा धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू होते हैं। श्रमिक को हटाने के बाद नई नियुक्ति दी गई है जिसमें बाबू लाल एवं नेमीचंद को रखा गया है जिनके नियुक्ति पत्र प्रदर्श एम-1 व एम-2 हैं और इससे पूर्व श्रमिक कैलाश कुमार को नोटिस नहीं दिया गया है जबकि श्रमिक कैलाश कुमार को उनसे पहले रखा जाना चाहिये था इसलिए धारा 25 एच अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और श्रमिक कैलाश कुमार पुन: नियुक्ति पाने का अधिकारी है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम एस. सत्यम 1996 II एल. एल. जे. 820 (एस. सी.) का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है।

8. इसके प्रतिकूल अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का कथन है कि श्रमिक कैलाश कुमार ने किसी भी वर्ष में 240 दिन तक कार्य नहीं किया। स्थाई कर्मचारियों के अवकाश पर जाने के कारण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके स्थान पर श्रमिक को निश्चित अवधि के लिए समय-समय पर अस्थाई दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी गई थी और चूंकि श्रमिक ने कभी भी 240 दिन तक किसी भी वर्ष में काम नहीं किया इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम व 25-जी एवं 25-एच अधिनियम भी इस मामले में लागू नहीं होता। श्रमिक को हटाने के बाद कोई अस्थाई नियुक्ति नहीं दी गई है। बाबू लाल व नेमीचंद की नियुक्ति छ: माह की परिवीक्षा काल के लिए स्थाई पद के लिए नियमित नियुक्ति दी गई है और नियमित कर्मचारी तथा दैनिक कर्मचारी की तुलना नहीं की जा सकती। श्रमिक के मामले में चूंकि उसे निश्चित अवधि के लिए रखा गया था और 18-8-84 के बाद हटाया गया है जिस समय 2(00) (बी बी) अधिनियम लागू हो गया था और इस कारण श्रमिक कैलाश कुमार सैन को हटाना छंटनी की तारीफ में नहीं आता है, धारा 25-एच अधिनियम किसी भी प्रकार लागू नहीं होता और श्रमिक कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. गैरीसन इंजीनिर एम. ई. एस. बनाम सी. आई. टी. 1993 II एल. एल. जे 876 (राज.)
2. युनियन बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आर. एल. आर. 2002 (1) (राज.) 320
3. राम चन्द्र यादव बनाम आर. एस. आरश्टी. सी 1990 (60) एफ एल. आर. 287 (राज.)
4. राजबीर सिंह बनाम लेबर कोर्ट आर. एल. आर. 1995 (1) (राज.) 518
5. छगन लाल सेठी बनाम राजस्थान राज्य 1996 (1) एल. एल. एन 222 (राज.)
6. राजीव कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1995 (2) डब्ल्यू. एल. एन. 534

9. मैंने उक्त तर्कों के परिपेक्ष में पत्रावली का भली-भांति अवलोकन किया, तर्कों पर गंभीरता से विचार किया, प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा।

10. रैफरेंस मात्र धारा 25-एच अधिनियम का है। इसके अन्तर्गत प्रार्थी को अपने क्लेम में यह बताना चाहिये था कि उसके मामले में धारा-25 एच अधिनियम लागू होता है और श्रमिक की छंटनी के पश्चात् अन्य श्रमिकों को कितने कितने को, कब कब रखा गया तथा कितनी अवधि तक रखा गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है उसमें यह तो कहा गया है कि अन्य को अस्थाई तौर पर रखा गया परन्तु किसी का नाम व अवधि नहीं बताई गई है। यहां तक प्रार्थी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें महेश मिश्रा ने सिर्फ यह कहा है कि वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई, न ही प्रकाशित की गई। पीओन के पद

पर नई नियुक्ति दी गई है लेकिन किसी का नाम नहीं बताया। जिरह में उसने कहा है कि श्रमिक कैलाश कुमार बीच बीच में अनुपस्थित नहीं रहा, बैंक ने हटा दिया होगा। उसने कभी 30 दिन या 50 दिन काम किया है। 28-9-85 के बाद काम नहीं करने का पता नहीं। 1984 में बाबू लाल को पीओन रखा था। यह बात भी उसने केवल जिरह में कही है, कब रखा और कितनी अवधि तक रखा यह कुछ नहीं कहा।

11. इसी तरह श्रमिक कैलाश कुमार ने भी अपने शपथ पत्र में सिर्फ यह कहा है कि उसकी सेवा 17-6-86 को समाप्त की, उससे पूर्व कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई, उसकी सेवा पुस्तिका नहीं बनाई। वरिष्ठता को ध्यान में रखे बिना उसे सेवा पृथक कर दिया और उसके बाद नई नियुक्ति दी गई लेकिन किसको दी गई, कब दी गई कितनी अवधि तक दी गई, इस बारे में कुछ नहीं बताया, न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश किया । अप्रार्थी की ओर से बाबू लाल तथा नेमीचंद के बयान कराये गये हैं जिन्होंने अपना नियुक्ति पत्र प्रदर्श एम-1 व एम-2 पेश किये हैं जो परिवीक्षा पर रखे गये हैं जिसका तात्पर्य यही है कि ये नियमित नियुक्तियां दी गई हैं, अस्थाई तौर पर नहीं दी गई और नियमित व अस्थाई कर्मचारी की तुलना नहीं की जा सकती। बलविन्द्र सिंह ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट कहा है कि श्रमिक कैलाश कुमार को निश्चित अवधि के लिए अन्य स्थाई व्यक्तियों के छुट्टी जाने पर एवजी में रखा गया था जिसके लिए कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है। अन्य जो स्थाई नियुक्ति नेमीचंद व बाबू लाल को दी गई है वे नियमित नियुक्तियां निश्चित प्रक्रिया एवं साक्षात्कार लेने के उपरान्त की गई हैं। जिरह में इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है।

12. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है वह सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम एस. सत्यम के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं वे भिन्न तथ्यों पर आधारित हैं जबकि हस्तगत मामले में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रोद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं और प्रार्थी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है :

> "पंजाब एंव सिन्ध बैंक के प्रबन्धतंत्र की श्री कैलाश कुमार सैन श्रमिक के विरुद्ध की गई सेवा मुक्ति को कार्यवाही एवं धारा 25-एच. औ. वि. अधिनियम के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों के नियोजन के समय श्रमिक को कन्सीडर नहीं किये जाने की कार्यवाही उचित एवं वैध है। प्रार्थी श्रमिक कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

14. अवार्ड आज दिनांक 23-2-2005 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का.आ. 1717.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 46/87) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-3(20)/86-कॉन II/डी III (बी)-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 1717.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 46/87) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan State Mines and Minerals Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 08-04-2005.

[No. L-3(20)/86-Con II/D III (B)IR(M]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 46/87

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 3(20)/86-कॉन II/डी III बी दिनांक 17-6-1987

———

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स कर्मचारी संघ, उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., उदयपुर।
2. मैसर्स इस्टर्न इंजीनियरिंग इन्टरप्राईजेज, उदयपुर 221, मोती मगरी स्कीम, पार्क के सामने, उदयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम. एफ. बेग एवं डॉ विक्रम सिंह नैन

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से : श्री वी. पी. अग्रवाल

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से : श्री मनोज कुमार शर्मा

दिनांक अवार्ड : 17-2-2005

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया है :

"क्या मैसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज, उदयपुर, ठेकेदार, मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., (राजस्थान सरकार का उपक्रम) उदयपुर के प्रबंधतंत्र को अपनी राकफास्फेट खान के 137 कर्मकारों को छंटनी करने की कार्यवाई उचित एवं वैध है ? यदि नहीं तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

क्र. सं.	नाम	कैटेगरी/ पद	भर्ती की तिथि
1	2	3	4
1.	सर्वश्री के. सी. सरकारिया	शांवल आपरेटर	24-5-81
2.	पी. के बालन	,,	12-7-81
3.	एस. एस. नायर	,,	19-8-81
4.	अमर सिंह	,,	1-4-83
5.	मोहम्मद तस्लीम	सीनियर मैकेनिक	20-5-81
6.	बी. पी. गुप्ता	,,	24-5-81
7.	महेन्द्र सिंह	,,	6-8-81
8.	वी. एम. जोय	,,	23-9-81
9.	कुन्दन लाल	डोज़र आपरेटर	23-5-81
10.	राजेन्द्र प्रताप सिंह	,,	8-9-81
11.	बनारसी सिंह	,,	13-9-81/1-4
12.	रमजान बेग	आटो फिटर	6-10-81
13.	सलीम खां	,,	1-4-82
14.	एस. शशीधरन	फिटर	11-6-81
15.	एम. प्रकाशन	,,	11-6-81
16.	पी. के. मधुसुदन	,,	1-8-82
17.	अब्दु [illegible]री	जूनियर फिटर	24-5-81
18.	मो. सरफद्दीन	,,	12-7-81
19.	के. सुरेन्द्रन	जूनियर फिटर	12-7-81
20.	अब्दुल अजीज	,,	8-9-81
21.	मोहम्मद हनीफ	,,	18-11-81
22.	जुगल किशोर	कम्प्रेसर ऑपरेटर	20-5-81
23.	भंवर सिंह	,,	22-8-81
24.	कल्लूराम रावत	,,	5-9-81
25.	नरेन्द्र डांगी	कम्प्रेसर ऑपरेटर	6-9-81
26.	राजेन्द्र आहिरो	,,	6-9-81
27.	आर. के. गुप्ता	,,	8-9-81
28.	धनेश्वर आहिरि	,,	18-9-81
29.	आर. के. मिश्रा	ड्रिल आपरेटर	12-7-81
30.	हरि गोस्वामी	,,	12-7-81
31.	कल्लू राम गौड़	,,	4-8-81
32.	फकीर मोहम्मद	,,	8-9-81
33.	जगदीश प्रसाद	,,	20-10-81
34.	मोहन लाल मीणा	,,	5-9-81
35.	पन्ना बेरा	जैक हैमर	5-9-81
36.	लालू राम	,,	18-9-81
37.	नानु राम	,,	29-9-81
38.	सदरुद्दीन खां	हैल्पर	24-5-81
39.	एम. अशोकन	,,	6-9-81
40.	हरबन्स सिंह	,,	6-8-81
41.	के. सोमन पिल्लाई	,,	6-8-81
42.	वी. जे. थोमस कुट्टी	,,	7-8-81
43.	एच. के. मिश्रा	,,	18-8-81
44.	विनय सिंह राजपूत	,,	25-8-81
45.	शंकर दायमा	,,	6-9-81
46.	सोहन लाल ओथ	,,	8-9-81
47.	मदन लाल आहिरि	,,	18-9-81
48.	शशी धरन पिल्लाई	,,	20-9-81
49.	जोर्ज कुट्टी	,,	20-9-81
50.	पन्ना लाल मीणा	,,	20-9-81
51.	डी. मोहन	,,	20-9-81
52.	ख्याली लाल जोशी	,,	20-9-81
53.	शंकर लाल कटारा	,,	20-9-81
54.	लालूराम मीणा	,,	20-10-81
55.	के. के. नायर	,,	25-10-81
56.	बालिस्टर	,,	1-3-82
57.	उमेश सिंह	,,	1-7-82
58.	गोवर्धन सिंह	,,	10-8-83

1	2	3	4
59.	मोहन राम	हैल्पर	8-9-93
60.	गोपाल सिंह	क्लर्क	12-11-83
61.	अजीत सिंह	,,	13-4-84
62.	महेन्द्र सिंह	,,	22-8-84
63.	कन्नु जोशी	,,	8-10-84
64.	रोड़ सिंह पंवार	फोरमैन	20-10-81
65.	मांगी लाल गुर्जर	,,	4-9-83
66.	कैलाश धीबाई	सुपरवाईज़र	1-3-84
67.	हरिराम रावत	जूनियर सुपरवाईज़र	20-10-83
68.	मांगी लाल टेलर	,,	23-9-81
69.	मांगू सिंह	,,	5-9-81
70.	दलीचन्द	,,	20-9-81
71.	साका	,,	1-7-82
72.	बेरा	,,	1-7-82
73.	मोती	,,	1-9-82
74.	रामू	,,	1-9-82
75.	चेन्ना	,,	1-9-82
76.	शंकर	,,	1-9-82
77.	तोला मोती	,,	3-5-83
78.	कन्ना	,,	3-5-83
79.	लिम्बा	,,	3-5-83
80.	कर्मा	,,	3-5-83
81.	नाथू	,,	3-5-83
82.	के. वी. वान्डो	,,	3-5-83
83.	मेघराज	,,	20-5-83
84.	बाबूदीन	,,	20-5-83
85.	किशन पाल	,,	20-5-83
86.	सांवर लाल	,,	20-5-83
87.	राजेन्द्र रावत	,,	21-5-83
88.	राजेन्द्र सिंह	,,	22-5-83
89.	महेन्द्र यादव	,,	28-5-83
90.	एम. के. गुप्ता	,,	29-9-83
91.	रन्जीत सिंह	,,	28-10-83
92.	मो. अब्रार	,,	28-10-83
93.	शिव बहादुर	मजदूर,	6-11-83
94.	लक्ष्मण सिंह	,,	20- -84
95.	मोहन लाल	,,	6-4-84
96.	मेघ सिंह	,,	1-7-84
97.	शंकर सिंह	,,	13-7-84
98.	पी.बी. सुन्द्रेन	वैल्डर	20-9-81
99.	एस.एम. नाथानी	,,	10-10-82
100.	एस.एस. नायर	,,	24-1-84
101.	अब्दुल रहमान	टर्नर	1-6-83
102.	गोपाल सिंह	चौकीदार	1- -82
103.	पूरा	,,	27- -
104.	पाल सिंह	,,	1-11-84
105.	यशपाल सिंह	ट्रिप काउन्टर	21-9-83
106.	चान्द किशोर	,,	13-9-83
107.	मदन वशिष्ठ	,,	11-10-83
108.	भूपेन्द्र सिंह	,,	5-11-83
109.	पी. वी. जेकब	ट्रिप ड्राईवर	24-5-81
110.	हरेन्द्र सिंह	,,	19-6-81
111.	थन्काचन	,,	8-7-81
112.	शिवदासन	,,	12-7-81
113.	तारकेश्वर सिंह	,,	9-8-81
114.	गुलाब रावत	,,	18-8-81
115.	जवान सिंह	,,	22-5-81
116.	सफी मोहम्मद	,,	25-8-81
117.	दिनेश बाजपाई	,,	4-9-81
118.	केरिंग लाल	,,	15-9-81
119.	नर्वे सिंह	,,	18-9-81
120.	प्रताप सिंह	,,	18-9-81
121.	शमशुद्दीन	,,	18-9-81
122.	ओमकार सिंह	,,	20-9-81
123.	मनोहर लाल रावत	,,	20-9-81
124.	शंकर लाल आहिरि	,,	20-9-81
125.	डी.टी. दास	,,	10-10-81
126.	भंवर दास	,,	20-10-81

1	2	3	4
127.	उमा शंकर	ट्रिप ड्राईवर	20-1-81
128.	दौलत सिंह	,,	1-12-81
129.	सीताराम साधु	,,	1-12-81
130.	किशन दास	,,	1-12-81
131.	जवाद खां	,,	6-7-82
132.	प्रभु लाल	,,	20-5-83
133.	उदय लाल	,,	20-5-83
134.	माजिद बेग	,,	9-7-84
135.	श्री रामलाल आहिरि	ट्रैक्टर ड्राईवर	10-1-82
136.	रविन्द्र प्रकाश	,,	24-5-83
137.	मुखतियार खां	ऑटो इलैक्ट्रिशियन	13-11-84

2. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स कर्मचारी संघ उदयपुर (जिसे आगे प्रार्थी संघ संबोधित किया जा रहा है) ने उक्त विवाद के संबंध में अपना वाद प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रार्थी संघ एक रजिस्टर्ड संघ है और झामर कोटरा खदानों पर कार्य करने वाले श्रमिक इस संघ के सदस्य हैं। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि० एक राजकीय उद्योग है जिसे आगे अप्रार्थी सं. 1 लिखा जा रहा है और ये झामर कोटरा खानों के मुख्य नियोजक हैं। मैसर्स इस्टर्न इंजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज़ एक साझेदारी फर्म है (जिसे आगे अप्रार्थी सं. 2 लिखा जा रहा है), एक ठेकेदार है जिन्हें अप्रार्थी सं. 1 ने खानों से उत्पादित माल को हटाने व खानों के खदान का कार्य ठेके पर दे रखा है। विपक्षी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के ठेके पर लिये हुए कार्य को सम्पन्न कराने हेतु 250 श्रमिकों को वर्ष 1981 में नियोजित किया था। अप्रार्थी सं. 1 ने मान्यता प्राप्त यूनियन रॉक फास्फेट मज़दूर संघ से 19-5-81 को एक समझौता किया था जिसमें यह तय किया था कि अप्रार्थी सं. 2 का कार्य समाप्त हो जाने पर उनके यहां कार्य करने वाले श्रमिकों को अप्रार्थी सं. 1 अपने यहां नियोजन में प्राथमिकता देंगे। अप्रार्थी सं. 2 ने ठेके का कार्य समाप्त होना बताते हुए कुछ श्रमिकों की छंटनी की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा था और उक्त पत्र के विचाराधीन होते हुए उसी दौरान समस्त 137 श्रमिकों की सेवाएं अनुचित व अवैध तरीके से समाप्त कर दी। इसके लिए मान्यताप्राप्त यूनियन को भी विश्वास में नहीं लिया और 5 कर्मचारियों जो उनके विश्वास पात्र थे, के साथ 26-7-85 को समझौता कर लिया जो श्रमिकों के हितों के विपरीत एवं बदनियतिपूर्ण व अनफेयर लेबर प्रेक्टिस में आता है, संघ की ओर से औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर छंटनी रोकने की मांग की गई किन्तु सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा कोई कार्यवाही नहों की गई और अप्रार्थी सं. 2 ने समस्त 137 श्रमिकों की दिनांक 30-7-85 से सेवा से छंटनी कर दी। उक्त छंटनी को अवैध बताते हुए प्रार्थी संघ ने आधार दिये हैं कि जुलाई 1985 में अप्रार्थी सं. 2 के ठेके का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, उस कार्य को 100 नये श्रमिकों को नियुक्ति कर चलाया जा रहा है, पांच श्रमिकों के साथ जो समझौता किया गया है वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, समझौता न तो सभी श्रमिकों को पढ़ कर सुनाया न उन्हें बुलाकर स्वीकृति ली गई, श्रमिकों को ग्रेच्युटी के हक से वंचित करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 ने बदनियतिपूर्वक श्रमिकों की छंटनी की है, छंटनी का कोई उचित कारण नहीं था, श्रमिकों ने छंटनी को न तो स्वेच्छा से स्वीकार किया है न ही स्वेच्छा से सेवाओं को त्याग दिया है, इस छंटनी के कारण श्रमिकों को दिनांक 19-5-81 के समझौते के लाभ से भी वंचित कर दिया गया है, संघ को समाप्त करने की नियत से छंटनी की गई है, अत: उक्त छंटनी को अवैध व अनुचित घोषित करने व सभी श्रमिकगण को समस्त पिछले वेतन व लाभ सहित सेवा में नियोजित करने का अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की गई है।

3. उपरोक्त क्लेम का अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 के संस्थान झामरकोटरा में रॉक फास्फेट मज़दूर संघ एकमात्र श्रमिकों का संगठन है जो संस्थान में मान्यताप्राप्त है। प्रार्थी संघ बहुसंख्यक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अप्रार्थी सं. 1 राज्य सरकार का संस्थान है और झामरकोटरा की खानें इन्हीं के पास हैं, इस तथ्य को जवाब में स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 की खानों से उत्पादित ऊपरी सस्तर को हटाने का ठेका दिया हुआ है यह कार्य हमेशा नहीं होता, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा किये गये काम के आधार पर भुगतान किया जाता है इस संबंध में कोई संविदा नहीं है, मशीनें, व्यक्ति आदि सब उन्हीं के द्वारा लगाये जाते हैं जिसका अप्रार्थी सं. 1 से कोई संबंध नहीं होता। श्रमिकों की संख्या अप्रार्थी सं. 2 के पास ही होती है वे अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिक लगाते हैं। 19-5-81 को कोई समझौता अप्रार्थी सं. 1 व मान्यताप्राप्त संघ के मध्य नहीं हुआ। मान्यताप्राप्त संघ ने रीकेटेगराईज़ेशन के लिए मांग रखी थी इसी संबंध में प्रबन्धकों के प्रतिनिधि व यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर वार्ता होती रहती थी। दिनांक 19-5-81 की वार्ता भी इसी संबंध में हुई थी जिसके मिनट्स बनाये गये थे पर कोई द्वि-त्रीपक्षीय समझौता इस संबंध में नहीं हुआ। कम्पनी ने यह बात मानी थी कि यदि कोई श्रमिक बेरोज़गार हो जायेगा तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी न कि नियुक्ति देने की बात कही गई थी। अप्रार्थी सं. 1 के यहां एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार नई भर्ती की जाती है जो चयन समिति द्वारा की जाती है। 19-5-81 के मिनट्स का असर उसी परिस्थिति में हो सकता था जब ठेका समाप्त हो जाता किन्तु चूंकि ठेका चालू है, इसका कोई लाभ प्रार्थी अथवा अप्रार्थी सं. 1, 2 को नहीं मिल सकता। 26-7-81 को कोई समझौता न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। 26-7-85 का समझौता त्रिपक्षीय था और पांच कर्मचारी श्रमिकों के प्रतिनिधि थे। उक्त समझौते की वैधता का कोई रैफरैंस नहीं है अत: न्यायालय इस बिन्दु पर विचार नहीं कर सकता। अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध कोई औद्योगिक विवाद नहीं बनता है। अप्रार्थी सं. 1 को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है। छंटनी के कारण अप्रार्थी सं. 1 के पास नहीं हैं। नये श्रमिकों की जो भर्ती अप्रार्थी सं. 2 के यहां की गई बताई है उसके कोई नाम या विवरण वाद में नहीं दिये गये हैं। प्राथमिकता का प्रश्न ठेका समाप्त होने के बाद पैदा होता है, अत: छंटनी से प्रभावित श्रमिकों के विषय में विपक्षी सं. 1 की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

4. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में कुछ वैधानिक आपत्तियां भी उठाई हैं कि यह मामला ठेकेदार व उसके श्रमिकों के बीच है अत: ऐसे मामलों में कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के अन्तर्गत मामला आता है, औद्योगिक

विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता। समुचित सरकार द्वारा भेजे गये रैफरैंस में अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दर्शाये गये श्रमिकों के नियोजक अप्रार्थी सं. 1 नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 के यहां ठेके का कार्य करता है और जिनका कार्य वह करता है उसका भुगतान कर दिया जाता है। नियोजक व ठेकेदार दोनों ही पक्ष क्रमश: पंजीकृत व लाइसैन्स प्राप्त हैं इसलिए अप्रार्थी सं. 1 की कोई ज़िम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। अगर अप्रार्थी सं. 2 ने कोई गैर कानूनी छंटनी की है तो उसके लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार है न कि अप्रार्थी सं. 1 जो सूची केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिकों को भेजी गई है उसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि कितने श्रमिकों ने कितने दिन तक कार्य किया है इसके बिना प्रार्थीगण कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह समस्त अभिलेख अप्रार्थी सं. 2 के यहां है, इसलिए अप्रार्थी सं.1 किसी भी प्रकार से उक्त छंटनी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है न ही इन श्रमिकों का नियोजक है, अत: प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रार्थी संघ के क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी सं. 2 को अप्रार्थी सं. 1 की खानों से उत्पादित सस्तर को हटाने का ठेका दिया गया जिसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। अप्रार्थी सं. 2 के कार्य की प्रकृति को देखते हुए रॉक फास्फेट मज़दूर संघ जो अप्रार्थी सं. 1 के श्रमिकों की मान्यता प्राप्त यूनियन थी, के साथ अप्रार्थी सं. 2 ने द्विपक्षीय समझौता किया जो 26-5-81 को किया गया, जिससे स्पष्ट है कि श्रमिकगण को संविदा पर एक निश्चित अवधि के लिए रखा गया था। इसके बाद कार्य की अवधि एवं प्रकृति को देखते हुए आगे भी कई समझौते किये गये जिनके अनुसार संविदा का एवं ठेके का कार्य 30 सितम्बर, 1985 तक समाप्त होना था। इसी बीच श्रमिकगण की ओर से स्वैच्छिक सेवा निवृति का सामूहिक प्रार्थना पत्र कुछ शर्तों के साथ प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 को आभास हुआ कि छंटनी किये जाने की पूर्व अनुमति के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर श्रमिकगण ने दोनों पक्षों के बीच सहमति से, श्रमिकगण द्वारा चाहे गये लाभ अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दिये जाने की स्वीकृति पर, समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) के समक्ष प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये और इस प्रकार सहमति से समझौता स्वैच्छिक सेवा निवृति के संबंध में समझौता अधिकारी केन्द्रीय के समक्ष हुआ। उक्त समझौते को मान्यताप्राप्त यूनियन एवं 137 उपरोक्त श्रमिकों ने समर्थ स्वीकार करते हुए श्रमिकगण के नौ प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किये। इन्हीं नौ श्रमिकगण में से पांच श्रमिकगण प्रतिनिधि के रूप में यूनियन में चुने गये जिन्होंने 26-7-85 के समझौते पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी सं. 2 का कथन है कि प्रस्तुत रैफरैंस में प्रार्थी संघ की यही आपत्ति है कि 26-7-85 के समझौते पर 5 श्रमिकगण के हस्ताक्षर हैं बाकी प्रतिनिधियों के नहीं। जबकि उक्त समझौते की जो शर्तें हैं उस पर प्रार्थी संघ को कोई आपत्ति नहीं है। श्रमिकगण की नियुक्ति औद्योगक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (००)(बीबी) के अन्तर्गत आती है जिसमें निश्चित अवधि समाप्त होने पर सेवा स्वत: ही समाप्त हो जाती है। अत: प्रस्तुत रैफरैंस का कोई महत्व नहीं है, न ही यह औद्योगिक विवाद की तारीफ में आता है। समझौता वार्ता की कार्यवाही से सही स्थिति अधिकरण के समक्ष स्पष्ट हो जाती है। किसी प्रकार का कोई पक्षपात अथवा अनुचित श्रम व्यवहार की नीति अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नहीं अपनाई गई है। समझौता दिनांक 26-7-85 द्वारा श्रमिकगण के कार्य की संविदा समाप्त हो गई और उन्होंने अपने समस्त लाभ प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी सं. 2 ने किसी श्रमिक की कोई छंटनी नहीं की है न ही उन्हें आगे नियोजन में रखने को बाध्य है, इसके लिए उन्हें अप्रार्थी सं. 1 को अप्रोच करनी चाहिये। कुछ श्रमिकगण अप्रार्थी सं. 1 के यहां कार्य भी कर रहे हैं। समझौते की वैधता को यूनियन इस रैफरैंस में चुनौती नहीं दे सकती। श्रमिकगण के इस आरोप को गलत बताया है कि जबर्दस्ती उनसे किसी कागज़ों पर हस्ताक्षर कराये गये हों। उनका यह भी जवाब में कथन है कि प्रारंभिक आपत्तियों का निर्णय पहले किया जाये और अंत में अप्रार्थी सं. 2 का जवाब है कि यूनियन को कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है अत: क्लेम खारिज किया जाये।

6. प्रार्थी यूनियन ने अप्रार्थी सं. 1 के जवाब का जवाबुलजवाब पेश किया है कि यह सही है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को कार्य का ठेका दिया था और जब ठेका समाप्त नहीं हुआ जो उन्हें कार्य से हटाया नहीं जाना चाहिये था। चूंकि वे कार्य अप्रार्थी सं. 1 का ही करते हैं ऐसे में अप्रार्थी सं. 1 का संबंध श्रमिकों से है। अब प्रार्थी यूनियन को जानकारी मिली है कि अब अप्रार्थी सं. 1 ने ठेका समाप्त कर दिया है ऐसे में अप्रार्थी सं. 1 को इन श्रमिकगण को समझौते के अनुसार नियोजन देना चाहिये। विपक्षी सं. 1 को छंटनी के संबंध में समस्त जानकारी है और उन्हीं को भारत सरकार ने पक्षकार भी बनाया है, अत: उनकी श्रमिकों के संबंध में पूरी जिम्मेदारी है। समझौते के आधार पर पर्यावसान की बात को प्रार्थी संघ ने गलत बताते हुए कहा है कि ठेके का कार्य सितम्बर 1985 में समाप्त होना कहा गया है जबकि ठेका समाप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्तियों को भी इन्कार करते हुए क्लेम स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

7. अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी प्रार्थी संघ ने जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सं. 1 के कार्य का विपक्षी सं. 2 को दिया गया ठेका मई 1981 से अगस्त 1991 तक लगातार चलता रहा है। ठेके की अवधि बढ़ाये जाने का उद्देश्य श्रमिकों को नियोजन में रखना था जिस दायित्व को अप्रार्थी सं. 2 ने पूरा नहीं किया और 137 श्रमिकों की अवैध छंटनी कर दी। श्रमिकों ने स्वेच्छा से सेवाएं त्यागने के प्रार्थना पत्र नहीं दिये। समझौता दिनांक 26-7-85 कानून के विपरीत होने से प्रभावहीन है। छंटनी किये गये श्रमिकों ने उन पांच श्रमिकों को जिनके साथ उक्त समझौता किया गया को प्रतिनिधि नहीं बनाया बल्कि उन पांच श्रमिकों का चुनाव अप्रार्थी सं. 2 के अनुसार 1983 में हुआ था और प्रस्तुत विवाद 1985 का है। प्रार्थी संघ द्वारा उठाया गया विवाद सेवा मुक्ति का विवाद होने से औद्योगिक विवाद की तारीफ में आता है। अन्य समस्त तथ्यों को गलत बताते हुए प्रार्थी संघ की प्रार्थना है कि उनका क्लेम स्वीकार किया जाकर समस्त श्रमिकों को पिछले वेतन व लाभ सहित सेवा में बहाल किये जाने का अवार्ड पारित किया जावे।

8. उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर इस अधिकरण द्वारा निम्नलिखित विवाद बिन्दु कायम किये गये :

1. क्या विवादग्रस्त श्रमिकों की नियुक्ति राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर के यहां उनके अधीन एवं नियंत्रण में उन्हीं के कार्य एवं उत्पादन के लिए की गई थी ?

2. क्या राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लि. उदयपुर ही श्रमिकों के मुख्य नियोजक थे ?

3. क्या विवादग्रस्त श्रमिकों को सेवा मुक्ति करने से पूर्व सरकार से अनुमति ली गई तथा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की पालना नहीं की गई ?

4. क्या प्रार्थी संघ ईस्टर्न इंजीनियरिंग एन्टरप्राईजेज के श्रमिकों का एक संघ है और उसे ईस्टर्न इंजीनियरिंग के श्रमिकों की ओर से वाद उठाने का अधिकार प्राप्त है ?

5. क्या दिनांक 19-5-81 को यूनियन व विपक्षी सं. 1 के बीच समझौता किया अगर ऐसा है तो उसका विवाद पर क्या असर है ?

6. क्या 26-5-81 का समझौता किया गया अगर ऐसा है तो इसका क्या प्रभाव है ?

7. क्या विपक्षी सं. 2 ने श्रमिकों को निश्चित समय के लिए सेवा में लिया था और यह सेवा की शर्त थी ?

8. क्या श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है और उनकी कोई छंटनी नहीं की गई है ?

9. क्या निर्देश में दर्शाए गये श्रमिकों विपक्षी सं. 1 के श्रमिक हैं और वह किसी प्राकर की सुविधा या अन्य पारितोष पाने के अधिकारी हैं ?

10. क्या विपक्षी सं. 1 की, यदि रूदि श्रमिक विपक्षी सं. 2 के श्रमिक पाये जायें, तो कोई जिम्मेदारी है ?

11. क्या प्रार्थी यूनियन को समझौते की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है ?

12. क्या ठेकेदार विपक्षी सं. 2 द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आता है ? ऐसा विवाद धारा 10 औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत चलने योग्य है ?

9. प्रार्थी संघ की ओर से सर्वश्री मोहन सिंह खमेशरा, प्रार्थी संघ के अध्यक्ष के साथ-साथ श्रमिक नाथू, चेना, रमज़ान बेग, ओंकार सिंह, तंगचन पी.के. अब्दुल रहमान, मोती, शंकर, फकीर मोहम्मद, बलिस्तर, मेरा, केरिंग लाल, दौलत सिंह, दलीचंद, लक्ष्मण सिंह के शपथ पत्र पेश किये गये हैं जिनसे अप्राथीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है। इसके अलावा सर्वश्री सक्का, उमेश सिंह, कालूराम, हनीफ मोहम्मद, लिम्बा, मांगीलाल, उदय लाल, मनोहर लाल, भूपेन्द्र सिंह, तोला व लालू राम के शपथ पत्र भी पेश हुए हैं परन्तु ये श्रमिकगण जिरह के लिए उपस्थित नहीं हुए जिनसे अप्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधिगण को जिरह का अवसर नहीं मिला इसलिए इनके शपथ पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिन श्रमिकगण के शपथ पत्र पेश हुए हैं उनके कुछ अतिरिक्त शपथ पत्र भी पेश हुए हैं जिनसे जिरह भी की गई है जो साक्ष्य में ग्राह्य है या नहीं, इस बात पर अंतिम निर्णय के समय विचार किये जाने की शर्त के साथ पेश करने की व जिरह की स्वीकृति दी गई है।

10. अप्रार्थीगण की ओर से के.सी. बोले, आर. के. मेहता एवं सज्जनसिंह शकतावत एवं एल. एल. चण्डालिया के शपथ पत्र पेश हुए हैं जिनसे के.सी. बोले के अलावा अन्य तीनों साक्षियों से जिरह की गई है। श्री के. सी. बोले से जिरह नहीं हुई इसलिए उसके शपथ पत्र पर गौर नहीं किया जा सकता।

11. मैंने उभय पक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

12. मेरे समक्ष अप्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधिगण ने सर्वप्रथम यह विधिक तर्क दिया है कि केन्द्रीय सरकार ने जो रैफरैंस न्याय निर्णय हेतु अधिकरण को प्रेषित किया है, उस रैफरैंस में मात्र 137 श्रमिकों की छंटनी करने की कार्यवाही के उचित एवं वैद्य होने का न्याय निर्णय चाहा है, छंटनी की कोई तिथि अंकित नहीं की गई है। चूंकि रैफरेंस में छंटनी की तिथि अंकित नहीं है इसलिए यह अधिकरण यह निर्णय नहीं दे सकता कि कौन सी तिथि को छंटनी के बारे में निर्णय दिया जाना है। अपने क्लेम में प्रार्थी संघ ने छंटनी की तिथि 30-7-85 अंकित की है लेकिन जो साक्ष्य पेश की गई उसमें श्रमिकगण ने अधिकांशत: छंटनी की तिथि 30-7-85 बताई है लेकिन फकीर मोहम्मद ने शपथ पत्र में 31 जुलाई, 1985 छंटनी की तिथि अंकित की है। इस तरह श्रमिकों के शपथ पत्रों के अनुसार भी छंटनी की तिथि विविध हो जाती है और जब कोई तिथि ही रैफरैंस में अंकित नहीं है तब अधिकरण इस रैफरैंस पर न्याय निर्णय नहीं कर सकता। अपने तर्क के समर्थन में अप्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधिगण ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. एम. कॉनरीअल उदयपुर **बनाम** छोटा लाल व अन्य डब्ल्यू.एल.सी. 2003 (राज.)(यू.सी.) 127

2. महावीर कन्डक्टर **बनाम** नन्द किशोर, डब्ल्यू.एल.सी. 2003 (राज.)(यू.सी.) 424

13. इसके प्रतिकूल प्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान प्रतिनिधिगण ने यह तर्क दिया है कि यह सही है कि समुचित सरकार द्वारा भेजे गये रैफरैंस में छंटनी की तिथि अंकित नहीं है परन्तु श्रमिक द्वारा प्रस्तुत क्लेम एवं शपथ पत्रों में छंटनी की तिथि 30-7-85 अंकित की गई है और इसी तिथि को की गई छंटनी पर न्याय निर्णय किया जाना है। रैफरैंस में तकनीकी त्रुटि के आधार पर उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने शेषराव भादूजी हटवार बनाम पी.ओ. लेबर कोर्ट व अन्य 1992 I एल. एल. जे. 672 (बॉम्बे) का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है।

14. मैंने दोनों पक्षों के इस तर्क पर गंभीरता से विचार किया, प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा।

15. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है उनमें एम. कारनॉल, उदयपुर **बनाम** छोटा लाल व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि निर्देशन जिसमें छंटनी की तिथि अंकित नहीं है, अवैध है और यदि रैफरैंस स्वयं में अवैध हो तो पक्षकारों को समुचित सरकार को इसे सुधारने के लिए कार्यवाही कराने का विकल्प है, अधिकरण स्वयं इसमें सुधार नहीं कर सकता जो

ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 537 मदन पाल सिंह बनाम यू.पी. स्टेट को निर्दिष्ट करते हुए सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसी तरह महावीर कन्डक्टर बनाम नन्द किशोर में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "निर्देश में सेवाओं के पर्यवसान की तिथि का उल्लेख नहीं है, इन परिस्थितियों में श्रम न्यायालय श्रमिकों के कथनानुसार पर्यवसान की तिथि को स्वीकार कर निर्देश की शर्तों में सुधार, संशोधन या उपान्तरण करने हेतु सक्षम नहीं है। अधिकरण द्वारा दिये गये अधिनिर्णय बिना अधिकारिता के हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार चूंकि इस अधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित किये गये निर्देश में छंटनी की तिथि अंकित नहीं है इसलिए इस अधिकरण को यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उस निर्देश में छंटनी की तिथि में कोई संशोधन या उपान्तरण या अंकन कर सके।

16. प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जो प्रोद्धरण शेषराव भादूजी हटवार का प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय बॉम्बे उच्च नयायालय ने पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद को निर्णित किये जाने के लिए लिखा है, जिसके तथ्य भिन्न हैं, इससे प्रार्थीगण को कोई लाभ नहीं पहुंचता क्योंकि दोनों ही प्रोद्धरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि जहां छंटनी की तिथि रैफरैंस में अंकित नहीं है वहां इस अधिकरण को किसी प्रकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाता है। ऐसी सूरत में छंटनी की तिथि निर्देश में नहीं होने के कारण किस छंटनी पर विचार किया जाना है यह अधिकरण तय नहीं कर सकता। ऐसे में पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे समुचित सरकार के यहां से प्रेषित रैफरैंस में यदि संशोधन कराना चाहें तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। संशोधित रैफरैंस आने पर ही उस पर विचार किया जा सकता है। बिना तिथि अंकित किये किसी भी छंटनी की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता।

17. प्रकरण में उपरोक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाकर आज दिनांक 17-2-2005 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

पी.एल. हिस्सारिया, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

का०आ० 1718.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० हिन्दुस्तान जिंक लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 36/91) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 08-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/68/90-आई. आर.(विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 2005

S.O. 1718.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.36/91) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Hindustan Zinc Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 08-04-2005.

[No. L-29012/68/90-IR(M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी.आई. टी. 36/91

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 29012/68/90/आई. आर./विविध दि. 15-7-91

डालचंद पिता श्री गहरीलाल नागदा, कर्मचारी सं० 35720, राजपुरा दरीबा माइन्स, हाल गांव बाघपुरा तहसील झड़ौल (फलासिया) जिला उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

वरिष्ठ प्रबन्धक (खान) राजपुरा दरीबा खान, हिन्दुस्तान जिंक लि०, राजपुरा दरीबा खान, पोस्ट दरीबा 313211 तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज कुमार शर्मा

दिनांक 11-3-2005

अवार्ड :

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने उपरोक्त अधिसूचना के जरिये निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of Rajpura Dariba Mines of M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur in discharging Shri Dal Chand S/o Shri Gahrilal Nagda ex. labourer w.e.f. 12-5-1990 is just and legal? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. प्रार्थी श्रमिक डालचंद ने इस विवाद पर अपना क्लेम पेश किया है जिसके अनुसार उसकी नियुक्ति 11-5-88 को साक्षात्कार लेने के बाद अप्रार्थी के यहां श्रमिक के पद पर हुई, उसे तीन माह के लिए परिवीक्षाधीन रखा और उसका कार्य संतोषप्रद पाया गया। 11-5-90 तक उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई। सेवा में आने के समय वह अविवाहित था इस कारण भविष्य निधि में अपने पिता को नोमीनी बनाया था। उसके पश्चात् प्रार्थी की शादी हो गई और अपनी पत्नी को नोमीनी बनाने के लिए वह श्री कोठारी की सलाह पर

29-3-90 को पर्सनल विभाग में इस कार्यवाही हेतु गया, वहां से बाहर आने पर उसे अपनी साईकिल की सीट की स्प्रिंग टूटने का ध्यान आने पर वैल्डिंग विभाग में श्री शंकरलाल के पास साईकिल ठीक कराने गया जहां से वैल्ड कराकर वह वापस आ रहा था तो मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मचारी बी.डी. यादव खड़े थे, उसने साईकिल रोकनी चाही परन्तु ब्रेक नहीं लगने से साईकिल का अगला पहिया श्री यादव के पांव पर लग गया, इस कारण यादव ने हैंडिल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और सिक्योरिटी रूम में ले जाकर उससे बुरी तरह से मारपीट की। उसने सुध आने पर देखा कि वहां के. एस. राजपुरोहित व संजय शर्मा खड़े थे जिन्होंने यादव से कहा कि इसका सारा नाटक ठीक कर दो और राजपुरोहित ने प्रार्थी के पेट पर लगे बैल्ट को खोला तथा टेबल पर रखे पैकेट को उसके बनियान में पेट पर रखा और जोर से दबाया और छोड़ दिया जिससे पैकेट धरती पर गिर पड़ा जिसमें तीन अलग-अलग साईज़ के बेयरिंग थे और उसके पास से बेयरिंग बरामद होना कहा व चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे खान परिसर में घुमाया तथा फोटोग्राफर की दुकान में ले जाकर फोटो खिंचवाई और चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस षड्यंत्र का पता न चले इस कारण मौका देखकर सुरक्षाकर्मियों ने मोटर साईकिल पर आ रहे फोटोग्राफर को टक्कर मार दी जिससे वह मर गया। प्रार्थी के विरुद्ध बेयरिंग चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे निलंबित कर दिया तथा आरोप पत्र दे दिया और उस आरोप पत्र में जांच अधिकारी ने जांच कार्यवाही कर 11-4-90 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर 12-5-90 से प्रार्थी को सेवामुक्त कर दिया। जांच अधिकारी ने सही जांच नहीं की, एकतरफा जांच करके तमाम कार्यवाही की। उसको सेवा पृथक करने का आदेश पूर्णत: गलत है। इसलिए उसे जिस दिन से सेवा पृथक किया है उसी दिन से पुन: सेवा में लिया जाकर और अनवरत सेवा काल मानते हुए पिछला पूरा वेतन व देनदारियां दिलाई जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक की ओर से प्रार्थी के क्लेम का जवाब दा. पेश किया गया है जिसके अनुसार उसे 11-5-88 से बदली श्रमिक के बतौर कार्य पर रखना कहा है, उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर तीन मा. के लिये की गई थी, उसका कार्य व्यवहार ठीक नहीं होने से उसे दुराचरण के कारण सेवा मुक्त किया गया था परन्तु उसके निवेदन पर प्रबन्धन ने दया दिखाकर उसे पुन: नियुक्ति दी, इस तथ्य को प्रार्थी ने अपने क्लेम में छुपाया है। प्रार्थी को सुरक्षाकर्मियों ने बेयरिंग ले जाते हुए गेट पर रंगे हाथों पकड़ा है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उसे चोरी का सही आरोप पत्र दिया गया है जिस आरोप पत्र में उसने बेयरिंग अपने पास होना स्वीकार किया परन्तु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना बताया और बाद में मनगढ़न्त झूठी कहानी भी बनाई है जो किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं है। फोटोग्राफर की कहानी भी बनावटी है जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी को चोरी के आरोप में दुराचरण का दोषी मानकर सेवा पृथक का दण्डादेश दिया गया है जो दुराचरण का आरोप सिद्ध होने पर दिया गया है। प्रार्थी कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। उसका वाद खारिज किया जावे।

4. इस अधिकरण ने घरेलू जांच की शुद्धता पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 15-1-98 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध की गई घरेलू जांच को शुद्ध एवं उचित होना माना है, अत: दोनों पक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण की मामले के गुणावगुण पर अंतिम बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि यद्यपि घरेलू जांच को अधिकरण ने शुद्ध माना है लेकिन घरेलू जांच के दौरान जो भी साक्ष्य जांच अधिकारी के समक्ष आई है वह विश्वसनीय नहीं है और इस साक्ष्य से प्रार्थी के विरुद्ध चोरी का कोई मामला साबित नहीं होता। उसे चोरी के आरोप में झूठा फंसाया गया है। वास्तविक मामला जैसा कि उसने अपने क्लेम में पेश किया है साईकिल नहीं रोकने से सुरक्षाकर्मी के पांव पर पहिया लग जाने से वह नाराज़ हो गया और मारपीट कर उससे झूठी बरामदगी बेयरिंग की बताते हुए चोरी का आरोप लगाया गया है जो एक मामूली घटना है और इस दुराचरण के आरोप को अगर साबित मान भी लिया जावे तो भी धारा 11-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) के अन्तर्गत अधिकरण को असीमित शक्तियां हैं और इन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध पारित दण्डादेश को कम किया जा सकता है और उसे पुन: नियोजित कर पूर्व के वेतन सहित समस्त लाभ दिलाया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. एयर लंका लि० बनाम जौन विलियम नाथन व अन्य, 1991 I एल.एल.जे. 291 (मद्रास)
2. एच.एम.टी. लि० बनाम मोहम्मद उस्मान 1984 II एल.एल. जे. 386 (एस.सी.)
3. ए.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम ऐडीशनल लेबर कोर्ट, हैदराबाद 1984 I, एल.एल.जे. 128
4. शंकर लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1996 लैब. आई. सी. 2118 (राज.)

6. इसके प्रतिकूल अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि प्रार्थी से सुरक्षाकर्मियों ने मुख्य दरवाज़े पर बेयरिंग बरामद किये हैं जो चोरी करके ले जा रहा था, उसे रंगे हाथों पकड़ा है जिसकी बरामदगी बताई है, बेयरिंग्स को भी, जो बरामद हुए, उन्हें अधिकरण के समक्ष पेश कर दिखाया है और इस पर प्रार्थी श्रमिक को चोरी के गंभीर दुराचरण के आरोप का आरोप पत्र दिया गया है जिसका प्रार्थी ने जवाब पेश किया है जिसमें उसने कहा है कि जब वह स्प्रिंग वैल्ड कराकर अपने घर जा रहा था तो कैन्टीन के पास एक व्यक्ति उसे मिला और उसे बेयरिंग पकड़ाये तथा कहा कि इसे मेन गेट पर पहुंचा दो, वह उस व्यक्ति को शकल से जानता है, उसने सहज रूप से बेयरिंग को मेन गेट पर पहुंचाया जहां सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जब आरोप पत्र के जवाब में ही उसने बेयरिंग उससे स्वयं से बरामद होना स्वीकार किया है, उसके बाद में उसने एक नई कहानी बनाई है और मारपीट कर उससे झूठी बरामदगी बताई है जो कहानी विश्वसनीय नहीं है। अधिकरण ने जांच को पूर्णतया शुद्ध एवं उचित घोषित किया है, जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच का समस्त रिकार्ड अधिकरण के समक्ष पेश हुआ है। जांच रिपोर्ट पूर्णतया विधिक साक्ष्य पर आधारित है जिस साक्ष्य से प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध चोरी के गंभीर दुराचरण का आरोप साबित है और ऐसे

दुराचरण के आरोप साबित होने पर उसे सेवा पृथक की जो सज़ा दी गई है वह पूर्णतया नियोजित है, इसमें अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि जब श्रमिक ने नियोजक का विश्वास खो दिया है तो वह पुनः नियोजन पाने का अधिकारी नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. हिन्दुस्तान जिंक लि० बनाम मोहन लाल एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 3053/97 निर्णय दिनांक 14-8-2001 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की प्रति पेश की है।

2. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० बनाम एम. चन्द्रशेखर रेड्डी 2005 एल.एल.आर. 258

3. जनथा बाज़ार (साऊथ कैनारा सैन्ट्रल कोआपरेटिव होलसेल स्टोर्स लि०) बनाम दी सैक्रेट्री, सहकारी नौकारारा संघा 2000 एल.एल.आर. 1271 (एस.सी.)।

7. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया। मेरे समक्ष अभिलेख पर आई समस्त रिकार्ड का भलीभांति अवलोकन किया।

8. इस अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 15-1-98 के द्वारा प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध की गई घरेलू जांच को पूर्णतया शुद्ध व उचित एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप माना है। अब मात्र यह देखना है कि क्या अभिलेख से जो जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य आई है उससे जांच अधिकारी ने चोरी का आरोप प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध साबित माना है वह सही तौर पर माना है अथवा मनमाने तौर पर माना है। प्रार्थी श्रमिक से तीन बेयरिंग चोरी कर ले जाते बरामद होने का आरोप लगाया गया। इस आरोप पत्र का प्रार्थी श्रमिक ने जो जवाब दिया है उसमें स्वयं से बरामदगी होना माना है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ये तीनों बेयरिंग उसे दिया जाना कहा है। इस तथ्य को भी बाद में उसने इन्कार कर दिया और जांच अधिकारी के समक्ष जो साक्ष्य आई है उसमें अपने पास से बरामदगी के तथ्य को स्पष्ट तौर पर इन्कार कर दिया और उससे झूठी बरामदगी होने के तथ्य को बताया है। इसके लिए उसने अपने बयान के साथ एक साक्षी मोहन लाल को पेश किया है परन्तु वह प्रार्थी श्रमिक द्वारा बताई गई कथित कहानी को साबित करने में सफल नहीं रहा है। आरोप को साबित करने का भार नियोजक पर था और नियोजक ने जांच अधिकारी के समक्ष पी.एस. सोलंकी, बी.डी. यादव, के.एस. राजपुरोहित, संजय शर्मा, भीम सिंह, शंकर लाल और आर.के. पोखरणा के बयान कराये हैं तथा प्रदर्श एम-1 से एम-6 तक 6 दस्तावेज़ प्रदर्श कराये हैं। मैंने प्रार्थी श्रमिक एवं उसके साथी मोहन लाल के बयान के साथ प्रबन्धन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सात साक्षियों के पूरे बयान, जिरह एवं सभी दस्तावेज़ों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया है। इनमें श्री बी.डी. यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसने मुख्य दरवाज़े से श्रमिक के कब्ज़े से तीनों बेयरिंग एक बैग में बरामद किये थे जो उसकी पैन्ट में छिपाये हुए थे। प्रार्थी श्रमिक के विद्वान प्रतिनिधि ने यह तर्क दिया है कि इस साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पैकेट पैन्ट की बैल्ट के नीचे नहीं आ सकता। मैं विद्वान प्रतिनिधि के इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि पैकेट को अच्छी तरह से पैन्ट के नीचे छिपाया होना साक्षी ने कहा है जो जिरह की कसौटी पर खरा उतरा है और इस तथ्य को प्रार्थी ने जवाब में स्वीकार किया है, यद्यपि बाद में इससे इन्कार किया है किन्तु इन्कारी का जो स्पष्टीकरण दिया है वह विश्वसनीय नहीं है। यादव के अलावा श्री राजपुरोहित ने भी अपने बयान में कहा है कि आरक्षी ने श्रमिक से बेयरिंग बरामद किये थे जिसको उसके सामने ज़ब्त किया गया था। इसी तरह से संजय शर्मा ने भी अपने बयान में घटना की पुष्टि की है और कहा है कि श्रमिक डालचंद के पेट पर बेयरिंग छिपाने का काला-काला सा निशान बन गया था जो उसने देखा था और बेयरिंग उससे बरामद हुए थे। भीमसिंह घटना के बाद का गवाह है इसलिए उसके कथन पर विश्वास न भी किया जाये तब भी डी.डी. यादव के बयान से प्रार्थी श्रमिक के पास से बेयरिंग बरामद होना पूर्णतया साबित होता है जिसका खण्डन श्रमिक अपने एवं अपने साक्षी मोहन लाल के बयान से नहीं कर सका है और जांच अधिकारी ने प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध चोरी के गंभीर आरोप, जो दुराचरण की तारीफ में आता है, का साबित होना सही तौर पर माना है।

9. अब प्रश्न यह रहता है कि जब दुराचरण का आरोप साबित है तो क्या इन परिस्थितियों में धारा 11-ए अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये दण्डादेश में हस्तक्षेप करना उचित है या नहीं ? जैसा कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रोद्धरणों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब श्रमिक ने नियोजक का विश्वास खो दिया है और उसके विरुद्ध दुराचरण का आरोप साबित हुआ है, तो इन परिस्थितियों में अधिकरण को श्रमिक के लिए कोई नरमी नहीं अपनाई जानी चाहिये व दण्डादेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रोद्धरण में जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, इसके प्रतिकूल माननीय उच्चतम न्यायालय का कोई प्रोद्धरण इन्हीं परिस्थितियों का प्रार्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रोद्धरणों को मैंने आदर सहित पढ़ा है जो भिन्न तथ्यों पर आधारित हैं जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त से श्रमिक को कोई लाभ नहीं पहुंचता और श्रमिक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

> "हिन्दुस्तान जिंक लि० की राजपुरा दरीबा खान के प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी श्रमिक श्री डाल चंद के विरुद्ध दिनांक 12-9-90 से सेवा पृथक करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है । प्रार्थी श्रमिक किसी राहत का अधिकारी नहीं है।"

11. अवार्ड आज दिनांक 11-3-2005 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का.आ. 1719.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा०को०को०लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 71/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-20012/105/2002-आई. आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. 1719.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 71/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-2005.

[No. L-20012/105/2002-IR (C-1)]

S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10 (1)(d) (2A) of I.D. Act.

Reference No. 71 of 2002.

PARTIES : Employers in relation to the management of South Balihari Colliery under P.B. Area of M/S. BCCL.

AND

Their Workmen.

PRESENT : Shri S.P. Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers	:	Shri D.K. Verma, Advocate.
For the Workmen	:	None.
State : Jharkhand.		Industry : Coal.

Dated, the 29th March, 2005.

AWARD

By Order No. L-20012/105/2002-IR (C-I) dated 15-7-2002 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-sec. (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

> क्या रा.को.म. संघ की भा.को.को.लि., पी.बी. क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से माँग कि सर्वश्री भोला सिंह, स्लाम मियां, राधा बाउरी, बिरजु राम, सुधीर बाउरी तथा अमला प्रसाद को "टींडल जमादार" के पद पर पदोन्नत किया जाए, उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि हाँ तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं तथा किस तारीख से ?"

2. In this case none is appearing on behalf of the workmen since 20-11-2002, though several adjournments were given. Thereafter registered notice was also sent, even to-day none is present on behalf of the workman to take any step. Therefore, it appears that neither the sponsoring union nor the concerned workman is interested to proceed with the case.

3. In such circumstances, I render a 'No Dispute' Award in the present reference case.

S. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का.आ. 1720.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा०को०को०लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 50/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-20012/285/2002-आई. आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. 1720.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 50/2003) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-2005.

[No. L-20012/285/2002-IR (C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10 (1)(d) (2A) of I.D. Act.

Reference No. 50 of 2003.

PARTIES : Employers in relation to the management of North Tisra Colliery of M/s. BCC. Ltd.

AND

Their Workmen.

Present : Shri S. Prasad, Presiding Officer

Appearances :

For the Employers : Shri D.K. Verma, Advocate

For the Workmen : Shri S.C. Gour, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal.

Dated, the 23rd March, 2005

AWARD

By Order No. L-20012/285/2002-IR (C-I) dated 23-6-2003 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-sec. (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the demand of Koyla Inspat Mazdoor Panchayat from the management of North Tisra Colliery of M/s. BCCL for regularisation of Sri Ramdin Pasi in Excavation Grade-D is legal and justified? If so, what relief the workman concerned is entitled to and from which date?"

2. In this reference case both the parties have filed their respective written statements. Thereafter, though several adjournments were given, neither the sponsoring union nor the concerned workman appeared to take any step. Thereafter on 21-3-2005. Shri S.C. Gour, Advocate, appearing on behalf of the concerned workman, submitted that neither the sponsoring union nor the concerned workman is interested to proceed with the case further. Therefore, he prayed for passing of 'No Dispute' Award in this case.

3. Accordingly, I render a 'No Dispute' Award in this reference case.

S. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का.आ. 1721.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 104/88) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-20012/84/88-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. 1721.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 104/88) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of E.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-05.

[No. L-20012/84/88-IR (C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10 (1)(d) of I.D. Act.

Reference No. 104 of 1988

Parties : Employers in relation to the management of Hariajam Colliery of M/S. E.C. Ltd.

AND

Their Workmen

Present : Shri S. Prasad, Presiding Officer

Appearances :

For the Employers : Shri B.M. Prasad, Advocate

For the Workmen : Shri D.K. Verma, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, the 22rd March, 2005

AWARD

By Order No. L-20012/84/88-D-3(A) dated 9-8-1988 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Hariajam Colliery of M/s. E.C. Ltd. in dismissing Sri Mahabir Bhuia, Loader/Stacker from 20-11-1986 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The sponsoring union has filed its written statement from which it appears that the concerned

workman, Mahabir Bhuia, who was a permanent Loader/Stacker working at Hariajam Colliery of M/S. E.C. Ltd. was dismissed from service w.e.f. 20-11-1986.

3. According to the sponsoring union the concerned workman was unable to report for duty from 15-1-85 as he was sick. He reported the matter to the management and requested for grant of sick leave, but the management did not respond. The concerned workman after recovery from his illness reported to the management in June, 1986 with medical certificate with a request for allowing him to resume work, but it was told that his case has been referred to Area Office for instruction. Ultimately on 20-11-86 he was informed that he was dismissed from service of the colliery. According to the sponsoring union, before dismissal no chargesheet was received by the concerned workman nor he was informed about the domestic enquiry and he was illegally dismissed from service.

4. The management of M/s. E.C. Ltd. has also filed its written statement alleging that the concerned workman remained absent from duty without information, then ultimately he was issued a chargesheet on 30-12-85 and was sent to his own address as he was not traceable in the colliery or in its vicinity. A copy of the chargesheet was also displayed on the Notice Board, but the concerned workman failed to submit any explanation. Then the concerned workman was noticed by letter dated 16-1-86 to be present before the Enquiry Officer on 28-1-86 which was sent by Regd. post A.D. and the copy of the same was displayed on the Notice Board of the colliery, but the concerned workman failed to appear before the Enquiry Officer. Thereafter another letter was issued on 4-2-86 directing him to appear before the Enquiry, Officer on 15-2-86, yet he did not appear in the enquiry, then the enquiry was held ex-parte and on the ground of absence for a very long time he was held guilty of the charge and ultimately dismissed from service.

5. According to the management, they have got their dispensary in every colliery and they have got Central Hospital at Dhanbad for free treatment of its workmen, but the concerned workman neither reported for his treatment in the colliery dispensary nor in the Central Hospital, Dhanbad. Therefore for a long absence the concerned workman was dismissed from service.

6. The issue regarding domestic enquiry being fair and proper was taken up as preliminary issue and by order dated 5-8-91 it has been held that the domestic enquiry was not fair and proper. Thereafter the management was directed to produce evidence on merit. The management has examined MW-2, D.P. Sinha, on merit, who was Attendance Clerk at the relevant time. He said that the concerned workman was absenting from duty from 25-1-85 and did not return back to duty. Thereafter he was issued with a chargesheet 30-12-85 and was ultimately dismissed from service. He has clearly stated that the concerned never informed about his absence. Further he has admitted that after closure of the enquiry the concerned workman had come to join his duty, but was not allowed.

7. The concerned workman has not examined himself nor has produced any document to show that he informed the management about his illness or had applied for any sort of leave.

8. Therefore, from the materials on record it appears that the concerned workman was absenting for a very long time, but MW-2 has admitted that he is an illeterate workman. The record shows that the concerned workman was probably suffering from T.B. It appears that due to his illeteracy he did not inform the management and when he recovered he reported for duty. Therefore, in case of such illeterate workmen it cannot be expected that they will go on informing the management in writing about his illness. Further more for absence from duty dismissal from service is harsh punishment and in catena of cases it has been held that dismissal for unauthorised absence is very harsh punishment. Further it is apparent that before dismissal letter was issued to the concerned workman he had reported for duty in the month of June, 1986, but the management did not allow him because by that time domestic enquiry was concluded and report was submitted.

Therefore, considering all the aspects of the case, in my opinion, the dismissal from service appears to be a harsh punishment and therefore the action of the management cannot be justified. However, considering the circumstances of the case the concerned workman can be ordered to be reinstated in service but in the circumstances of the case without back wages.

9. In the result, I render the following award—

That the action of the management in dismissing the concerned workman w.e.f. 20-11-1986 is not justified and the concerned workman is entitled for reinstatement without back wages. The management is directed to reinstate him within 30 days from the date of publication of the award.

S. PRASAD, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का. आ. 1722. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एअर इंडिया लि० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय, मुम्बई-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 40/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-11012/99/2000-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. 1722.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 40/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court Mumbai-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Air India Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 8-4-05.

[No. L-11012/99/2000-IR (C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, AT MUMBAI

PRESENT:

B. I. KAZI, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT-2/40 OF 2001

Employers in relation to the Management of

The Managing Director,
Air India Ltd.,
Air India Building,
Nariman Point,
Mumbai-400021.

AND

Their Workman

Mr. R. N. Patil,
Mental Hospital,
Regional Manorugnalay,
Near Supervisor Bungalow,
Dharamveer Nagar,
Thane (West).

APPEARANCES:

For the Employers : M/s M.V. Kini & Co. Advocates

For the Workmen : In person

Dated, the 21st February, 2005

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, by its Order No. L-11012/99/2000(C-1) dated 18-10-2000 originally referred the following industrial dispute for adjudication to Central Govt. Industrial Tribunal No. 1, Mumbai and Thereafter vide Orders No. L-11012/99/2000-IR(C-1) dated 26-3-2001 withdrawn the proceedings from Central Govt. Industrial Tribunal No. 1, Mumbai and transferred the same to this Tribunal with a direction to proceed from the stage at which they are transferred to this Tribunal :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Air India Ltd., Mumbai in dismissing the services of Mr. R. N. Patil, w.e.f. 20-1-2000 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

At the time of transfer, the matter was at the stage of filing statement of claim by workman.

2. On receipt of the proceedings from Central Govt. Industrial Tribunal No. 1, Mumbai, notices were issued to both the parties. Pursuant to the notice, workman Shri R. N. Patil filed statement of claim (Ex. 12) and the same was resisted by the employer M/s. Air India Ltd. vide written statement (Ex.14). The workman filed rejoinder (Ex. 15). On the rival pleadings of the parties my Ld. Predecessor framed issues (Ex. 16). Thereafter the matter was fixed for evidence. During the pendency of the matter for evidence of workman, the workman filed application (Ex. 32) stating that the management Air India Ltd. is ready to take him again in their company as workman. He further states that the management had told him to close the above case mentioning that he is taking the case back without any pressure from the employer. The workman states that he is not interested in back wages. The workman states that he is taking the case back from his personal point.

3. Since the workman Shri R. N. Patil do not wish to proceed the reference will have to be disposed of and hence the order.

ORDER

Reference stands disposed for non-prosecution.

B. I. KAZI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

का. आ. 1723.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अजमेर के पंचाट (संदर्भ संख्या 05/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-41012/42/1997-आई.आर.(बी-1)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 05/1998) of the Industrial Tribunal/Labour Court, Ajmer now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Railway and their workman, which was received by the Central Government on 11-4-05.

[No. L-41012/42/1997-IR (B-1)]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

न्यायालय श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर (राज.)

पीठाधीन अधिकारी : श्री जी. एस. शेखावत, आरएचजेएस

प्रकरण संख्या-सी.एल.सी.आर. 05/1998

(रेफरेंश नं. एल. 41012/42/97 आई आर. दिल्ली दिनांक 17-3-98)

मंडल सचिव, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद् 1623/35, गुलाबबाड़ी, रेलवे क्रासिंग के पास, नाका मदार, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. उप मुख्य यांत्रिक अभियंता (लोको) कारखाना, पश्चिम रेलवे, अजमेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित : श्री किशन गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी

: श्री वी. डी. भार्गव, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी

दिनांक 23 मार्च, 2005

अवार्ड

केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित विवाद निम्नानुसार है :—

"क्या वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कारखाना) पश्चिम रेलवे, अजमेर के पत्र दि. 22-12-94 के द्वारा श्री रामकिशन गुर्जर की बिना भविष्य को प्रभावित करते हुए आगामी वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए प्रतिबंध किया जाना उचित व वैध है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत का अधिकारी है ?"

नोटिस के उपरांत उभयपक्ष उपस्थित आये। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत क्लेम के विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थी रामकिशन गुर्जर प्रधान लिपिक के पद पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कैरिज कारखाना, पश्चिम रेलवे अजमेर के अधीन कार्यरत है। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कारखाना) अजमेर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध ज्ञापन ई. डब्ल्यू 308 एम. आर./आर. 94-158 दिनांक 27-7-94 के अंतर्गत एक आरोप पत्र जारी किया जिस पर प्रार्थी ने दि. 8-8-94 को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप-पत्र से संबंधित प्रलेखों का निरीक्षण करवाने की प्रार्थना की किंतु इस प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये ही अनुशासनिक प्राधिकारी ने आदेश दि. 22-12-94 के द्वारा बिना भविष्य को प्रभावित करते हुए प्रार्थी की आगामी वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी। अनुशासनिक प्राधिकारी का उक्त आदेश नियम विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। रेलवे बोर्ड के पत्र दि. 12-6-78 के अनुसार अपचारी द्वारा प्रलेखों के निरीक्षण की मांग करने पर जांच अधिकारी को उचित समय में निवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सूचना आरोपित कामगार को दी जानी चाहिए तथा उसके पश्चात् दस दिन की अवधि में उत्तर प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी ने इसकी पालना नहीं की। प्रार्थी को नियंत्रक शॉप अधीक्षक तथा नियंत्रक अधिकारी उपमुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कैरिज कारखाना) थे। अतः वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कारखाना) द्वारा आरोप-पत्र जारी किया जाना नियम विरुद्ध था। इस प्रकार प्रार्थी के अनुशासनिक अधिकारी सही नहीं है। अंत में वेतन वृद्धि रोकने के उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

प्रतिपक्षी ने उत्तर में अंकित किया है कि आरोप के विवरण के अनुसार प्रार्थी को शाप अधीक्षक, फाउंड्री (बी) ने पी.सी.डी.ओ. अकाउंटैंट का कार्य करने के लिए दि. 30-5-93 रविवार को बुक किया था किन्तु प्रार्थी उक्त दिवस को कर्तव्य पर उपस्थित नही हुआ जिसकी पुष्टि आर.पी.एफ. लोको गेट पर रखे चाबी रजिस्टर से होती है कि उक्त दिवस को ढलाई घर पर शॉप का कार्यालय ही नहीं खोला गया। प्रार्थी का उक्त कृत्य आदेशों की अवहेलना करना, प्रशासन को धोखा देना, रेल सेवा आरक्षण नियम 1966 के नियम 3(1) उपनियम 1, 2, 3 का गंभीर उल्लघंन है। इसके उपरांत भी प्रार्थी ने 30-5-93 की एवज में दि. 18-6-93 को एवजी अवकाश प्राप्त कर लिया जो उक्त नियम के अतर्गत गंभीर अपचार है। छोटी शस्ति के प्रकरण में प्रलेख दिखाने का प्रावधान नही है लेकिन सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। उक्त प्रतिवेदन का निर्णय किये जाने से पहले ही प्रार्थी ने दूसरा प्रतिवेदन 11-8-94 को प्रस्तुत कर दिया जिसका उत्तर प्रार्थी को प्रेषित कर दिया गया। आरोप के संबंध में प्रार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नही दिया प्रार्थी को बचाव का पूरा मौका दिया गया था। अंत में अंकित किया है कि दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील और रिव्यु भी निरस्त हो चुकी है। अंत में क्लेम निरस्त करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने क्लेम की संतुष्टि में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षण करवाया है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डब. 1 से प्रदर्श डब. 3 तक प्रलेख की प्रतियां प्रदर्शित करवाकर प्रस्तुत की है। प्रतिपक्षी ने हीरालाल मीणा मुख्य कार्यालय अधीक्षक का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपरीक्षण करवाया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श एम-1 से एम-7 प्रलेखों की प्रतियां प्रदर्शित करवाकर प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष का श्रवण किया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया।

प्रार्थी ने अपने क्लेम में अनुशासनिक के सक्षम नहीं होने की आपत्ति उठायी थी किन्तु अपने शपथ पत्र में इस संबंध में कोई कथन अंकित नहीं किया, इस बिन्दु पर प्रार्थी के अभिभावक ने बहस भी नहीं की।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि प्रार्थी ने प्रलेख निरीक्षण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र 8-8-94 को अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत किया था जो स्वीकृत तथ्य है। उनका तर्क है कि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी जबकि ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना देने के दस दिन के अंदर प्रार्थी को अपना उत्तर और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार उनका तर्क है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसके विपरीत प्रतिपक्षी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के तीन दिन पश्चात् ही 11-8-94 को एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिसका उत्तर प्रार्थी को दिया जा चुका है किन्तु फिर भी प्रार्थी ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अंत में उनका तर्क है कि 96 सुप्रीम टुडे 511 के दृष्टांत के अनुसार प्रार्थी किसी प्रकार से प्रिज्युडिस नहीं हुआ अत: यह जांच और दंड दिया जाना दूषित नही है।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर विचार लिया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी को ज्ञापन आरोप पत्र और उसका विवरण पत्र 27-7-94 को जारी हुआ जो प्रार्थी को 5-8-94 को प्राप्त हुआ। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त जांच में प्रार्थी पर 30-5-93 को रविवार के दिन उसे बुक करने पर भी अनुपस्थित रहकर उसकी एवज में 18-6-93 को एवजी अवकाश का उपभोग कर लेने का आरोप लगाया गया है। उक्त ज्ञापन के प्राप्त होने के तीन दिन पश्चात् ही प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रदर्श डब्ल्यू-1 अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया यह स्वीकृत तथ्य है। यह प्रार्थना पत्र अनिर्णीत रहा यह भी स्वीकृत तथ्य है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने आर पी एफ/लोको गेट का चाबी रजिस्टर एवं एस. एस/एफ.डी वाई या अन्य प्राधिकारी के द्वारा की गई शिकयतें एवं प्रार्थी की निष्ठा को चुनौती देने वाले अन्य प्रलेखों का निरीक्षण करवाने की प्रार्थना की गई है। निरीक्षण के पश्चात् ही ज्ञापन का उत्तर और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह भी अंकित किया है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना को अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक ई (डी.एण्ड ए) 77 आर जी 6—20 दि. 12-6-78 महत्वपूर्ण है। जिसका सार निम्न प्रकार है:—

"इट इज रियटरेटेड देट दी टाईम लिमिट आफ टेन डेज प्रेस्क्राईब्ड इन दी स्टेण्डर्ड फार्म आफ मेमोरेंडम आफ चार्जशीट फोर माइनर पेनेल्टीज शूड बी स्ट्रक्टली अडयेर्ड टू वेयर दी चार्जड आफिशियल मेक्स ए रिक्वेस्ट फोर पेरेजल आफ एनी डोक्युमेंट दी डिसिपिलनरी आथिरिटी शूड विधिन ए रिजनेबल टाईम" शे विधिन फाईव डैज आफ दी रिसीट आफ दी रिक्वेस्ट आईदर एक्सेप्ट दी रिक्वेस्ट आर रिजेक्ट दी सेम वेयर इन्सेक्शन आफ दी डाक्यूमेंट इज अलाउड बाई दी डिसिपिलनरी आथिरिटी, फाइव डेज टाईम मे बि गिविन फोर दी पर्पज एंड दे चार्जड एम्पलायी शुड बी आक्सक्ड टू सबमिट हीज रिप्रेजेंटेशन, इफ एनी, विधिन 10 डेज आफ दी कम्पलीशन आफ दी इंस्पेक्शन डाक्यूमेंट हाउजऐवर वेयर इंस्पेक्शन आफ डाक्यूमेंट नोट एग्रीड टू दी एम्पलोयी मे बी इनफोर्मड आफ दी सेम इन राईटिंग एंड आस्क टू सबमिट हीज रिप्रेजेंटेशन विधिन 10 डैज फ्रोम दी डेट एंड देयर आफ्टर फाइनल डिसीजन आफ दी सेम मे बि टेकन"?

इस प्रकार रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र से यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अपचारी के प्रलेख निरीक्षण के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना के पश्चात् 10 दिन में अपचारी को ज्ञापन के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। प्रस्तुत जांच में भी अनुशासनिक अधिकारी ने प्रलेख निरीक्षण के उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी थी। प्रार्थी के विरूद्ध, बुक करने के बाद भी 30-5-93 को रविवार को काम पर उपस्थित नहीं होने और उसके बदले में 18-6-93 को एवजी अवकाश उपभोग करने का आरोप लगाया है। आरोप में ही यह उल्लेख है कि इसकी पुष्टि आर पी एफ लोको गेट पर रखी चाबी रजिस्टर से हुई है कि दि. 30-5-93 को ढलाई घर शाप का कार्यालय नहीं खोला गया। इस प्रकार लोको गेट का चाबी रजिस्टर इस जांच में महत्वपूर्ण प्रलेख था जिसको प्रार्थी निरीक्षण करना चाहता था किन्तु प्रार्थी को उक्त रजिस्टर का निरीक्षण नहीं करने दिया गया और न ही प्रार्थना पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी बिना प्रलेखों के निरीक्षण के अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था। इस प्रकार प्रार्थी को अपने बचाव का समुचित अवसर नहीं मिला। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का भी उल्लंघन है। इस प्रकार उसके प्रलेख निरीक्षण के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नही देने से प्रार्थी अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सका और निश्चित रूप से वह प्रिज्युडिस हुआ है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने रेलवे बोर्ड के पत्र दि. 12-6-78 द्वारा जारी निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। अत: मेरे मत में प्रार्थी को अनुशानिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया उक्त दंड अवैध एवं अनुचित है।

आदेश

फलत: प्रस्तुत विवाद का उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (कारखाना) पश्चिम रेलवे अजमेर के पत्र दि. 22-12-94 के द्वारा श्री रामकिशन गुर्जर की असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए रोकी गयी वेतन वृद्धि का आदेश अनुचित एवं अवैध है। अत: उक्त आदेश अपास्त किया जाता है।

अवार्ड आज दि. 23-3-05 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अवार्ड की प्रति नियमानुसार केन्द्र सरकार को वास्ते गजट में प्रकाशन प्रेषित की जावे।

जी. एस. शेखावत, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

का. आ. 1724.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तरी रेलवे के

प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय II, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 46/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-41012/121/1997-आई.आर.(बी-I)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1724.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. ID No. 46/98) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court II, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 11-4-05.

[No. L-41012/121/1997-IR (B-1)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI

R. N. RAI, Presiding Officer

I. D. No. 46/98

In the Matter of :—

Sh. Gurswaroop Joshi,
C/o Bhartiya Railway Karamchari Union,
5/38, Ajmal Khan Road, Karol Bagh,
New Delhi-110005.

Versus

The Divisional Railway Manager,
Northern Railway, Estate Entry Road,
New Delhi-110001.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-41012/121/97-IR (B.I.) Central Government dtd. 23-02-1998 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :—

"Whether the action of the management of Northen Railway in denying the pay scale of Rs. 1400-2300 w.e.f. 25-03-1988 as also the consequential promotions in the grade of Rs. 1600-2660 and 2000-3200 to Sh. Gurswroop Joshi is just and fair ? If not, what releif the concened workman is entitled to."

The union has filed statement of claim on behalf of the workman. In the statement of claim, it has been stated that the workman is a retired Travelling Ticket Examiner, and retired as such from the office of Divisional Chief Ticket Inspector, Delhi Jn. Railway Station of Delhi Division over N. Rly., on 28-02-1995 in pay scale Rs. 1400-2300 at basic pay of Rs. 2150 + 20 Spl. Pay and total of his monthly wages came to Rs. 4500 inclusive of all allowances. That the workman was classified as 'Continuous' worker with 8 hours fixed duty roster and one day's weekly rest/off which a supervisor is not allowed. Workman was not declared supervisor by any competent authority. He himself performed routine clerical duty of checking railway passengers if they were travelling with proper tickets and had no control or supervision over the work of any other employee as none worked under him so he was a workman in terms of Section 2(s) of Industrial Disputes Act, 1947, and continues to be such workman for the purpose of this Industrial dispute as the same arises out of the terms of his employment and relates back to service period.

That the workman while in service had to undergo heart surgery at Railway Hospital Perambur, Chennai where from he was sent back to Northern Railway Central Hospital, New Delhi. He was subsequently declared permanently unfit medically for his original post of Assistant Station Master in pay scale of Rs. 1400-2300 by Medical Superintendent, Northern Railway, Delhi, under his certificate dtd. 6-1-1988 (copy Annx-W-I) and he was recommended suitable alternative employment of sedentary nature. That despite this medical recommendation and the provision of Rules on the subject, workman was not given alternative job in suitable post in pay scale of Rs. 1400-2300 but was given lower grade post in lower pay scale of Rs. 1200-2040 and workman had to accept the same under protest and compulsion of loosing the job and resumed it on 25-03-1988 for the sake of livli hood of entire family. At any rate this forced acceptance cannot operate against statutory provisions on the subject which provide for suitable alternative job.

That the admitted facts are that the workman was holding the permanent post of Assistant Station Master in pay scale of Rs. 1400-2300 when he fell ill on 28-04-1987 and sent to Railway Hospital at Perambur, Chennai, for heart operation after which he was returned back to Central Hospital, Northern Railway, New Delhi. Thereafter the workman was declared permanently medically unfit for his original post of Assistant Station Master by Medical Superintendent, Northern Railway, Delhi, under medical certificate dtd. 6-1-1988 (Annx-W-1) but was recommeded alternative suitable employment with sedentary nature of job. But workman was given alternative job of Senior Ticket Collector in lower pay scale of Rs. 1200-2040, by the Senior

Divisional Officer, Northern Railway, New Delhi, under his letter number 729-E/22/205-E/P-2 dt. 22-03-1988 (Photo copy Annx-W-2). At this post was not suitable, being in lower pay scale of Rs. 1200—2040, workman accepted it under protest, otherwise he would have lost his job/employment by being discharged from service. So the workman resumed this lower grade on 25-03-1988 which fact of acceptance did not operate as an estoppel being against statute as the law is well establishment that there can be no estoppel against statute.

That this act of the management is not only unjustified and unfair but is even against departmental statutory Rules and law of the land but even in contravention of Articles 14 and 16 of Constitution of India in as much as the management has given higher grades to his juniors in similar/same circumstances.

It was never the case of the management that at the time of workman's absorption in alternative lower post on 25-03-1988, there was no vacancy in pay scale of Rs. 1400—2300 equivalent to one held by workman at that time. Juniors to workman were given equivalent grade alternative posts under similar circumstances but workman was discriminated against. Juniors to workman, due to this discrimination by management, got higher pay scales Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200 but the workman was illegally denied the same, The management denied pay scales Rs. 1400—2300, 1600—2660 and Rs. 2000—3200 on irrelevant grounds of no vacancy, minimum period of service in grade. Management did not give due consideration to the fact that acceptance by the workman of alternative post was under protest and compulsion as non acceptance would have resulted in his discharge from service causing loss of source of his livelihood. It is against the principles of natural justice. The workman was not given an opportunity to show that there was suitable vacancy in the post in Cash Office in which the workman was in fact posted for period of 3 months from 1-11-1987 in the equivalent grade of Rs. 1400—2300. It is against the principles of stepping up of pay as Shri O.P. Arora who was also holding a similar post of Assistant Station Master like workman, was recommended light duty for one year by the Medical Board on 4-1-1979 and was, therefore, absorbed in alternative post of Ticket Collector in grade of Rs. 330—560 in equivalent grade. (Copy of letter dt. 14-08-1981. Annx-W-4) and was further given the post of H.T.T.E. in grade of Rs. 425—640 on 5-1-1983 and even higher posts were given to him as of T.T.I. and C.T.I. grade of Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200 from 1-1-1984 and 20-10-1987 respectively, but the workman was illegally deprived of these higher posts and grades.

The management has filed written statement. In the written statement, it has been stated that the applicant was appointed as Asstt. Station Master Gr. Rs. 80—170 on 3-3-1958 on Western Railway. He was transferred to Delhi Division at his own request in Gr. Rs. 330—560 and resumed his duty as ASM on 20-1-1973. He was promoted against the up gradation from 1-1-1984 in Gr. Rs. 425—640 (RS.) The applicant was permanently medically unfit for the duties of this original post on 6-1-1988. He was placed on leave and called to appear before the Adjudging Committee who found him fit for the post of TCR Gr. Rs. 950—1500 (RPS).

On the request of the applicant the adjudging committee considered his request sympathetically and adjudged him for the post of Sr. TCR Gr. Rs. 1200—2040 and the applicant clearly accepted the offer of Sr. TCR Gr. Rs. 1200—2040 under clear signature dt. 22-3-1988. By this way his emoluments were protected. He expressed his sincere thanks to Northern Railway for protecting his salary and offering a suitable job to him and further requested to consider him in Gr. Rs. 1400—2300, since the post of Hd. TCR in a selection post and it is filled up by written test followed by viva voce test, he could not be promoted as Hd. TCR before 24-07-1993.

It is submitted that the applicant was declared permanently medically unfit for the duties of his original post on 06-01-1988. He was placed on leave and called to appear before the Adjudging Committee who found him fit for the post of TCR Gr. Rs. 950—1500 (RPS). On the request of the applicant the committee considered his request sympathetically and adjudged him forthe post of Sr. TCR Gr. Rs. 1200—2040. The applicant clearly accepted the offer of Sr. TCR under his clear signature dt. 22-03-1988. By this way his emolument were protected. He expressed his sincere thanks to Northen Railsway for protecting his salary and offering a suitable job to him vide his application dt. 25-10-1988. (Copy annexed as Annexure R-1). It is submitted that the applicant accepted the post of Sr. TCR and continuously worked on the same post. The post HTCR is a selection post and he has to pass the selection on his turn. He was promoted as HDTCR Gr. 1400—2300 on 24-07-1993 and was not due promotion in next higher grade Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200 because his promotion was not due as per his seniority assigned. No junior to him have been promoted in Gr. Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200. That the case of the applicant has no relevancy with that of S/Sh. Vijay Kumar Trikha, Sh. O. P. Gupta, and Sh. Jagdish Meena who were medically decategorised from the category of Guard which relates to running staff categoty in whose case different rules and instructions are adhered to at the time of their alternative appointment (copy of PS.No. 10598 in Annexure R-II).

That the applicant's promotion was not due in next higher grade Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200 as per his seniority assigned and no junior to him has been promoted. it is submitted that the contents of para 4 of the above reply be read as part and parcel of this reply. It is submitted that the case of Sh. O.P. Arora has been examined. He was absorbed as HDTEE Gr. Rs. 425—640 on 5-1-1983 and joined as such on 6-1-1983. Later on he was promoted to the rank of ITT and CTI Grade Rs. 1600—2660 and 2000—3200

respectively w.e.f 1-1-1984 and 20-10-1987 on adhoc basis. it is further submitted that prior to 5-1-1983 while he was working as ASM, he was recommended light duty for a period of one year by the Medical Board on 4-1-1979. Therefore he was posted as Ticket Collctor Gr. Rs. 330—360 temporarily on 30-5-1979. He was again examined by the Medical Board on 10-06-1980 and he was declared fit for his original job of ASM and thereafter posted in his original category as ASM.

The workman applicant has filed rejoinder. In his rejoinder he has reiterated the averments of his claim statement and has denied most of the paras of the written statement.

Evidence of both the parties has been taken.

Heard arguments from both the sides and perused the papers on the record.

It was submitted from the side of the workman that he was holding permanent post of Assistant Station Master in Pay Scale of Rs. 1400—2300. When he fell ill on 28-04-1987 he was sent to Railway Hospital. he was declared permanently medically unfit for his original post of Assistant Station Master by Medical Superintendent, Northern Railway, Delhi under medical certificate dated 6-1-1988. The Sr. Divisional Officer. Northern Railway, gave him alternative job of Sr. T.C. in lesser pay Scale of Rs. 1200—2040. He accepted it under protest. He was given lower post in contravention of Article 14 and Article 16 of the Constitution of India in as much as the management has given higher grades to his juniors in similar/same circumstances. Juniors to the workman were given equivalent grade, alternative posts under similar circumstances but discrimination was made with the workman applicant. Acceptance of the alternative post was under protest. It was against the principles of natural justice. He should be posted on the post where he can get equivalent pay prior to his being handicapped. It was submitted from the side of the management that on the request of the applicant the adjudging committee considered the request sympathetically and adjudged him fit for the post of Sr. TCR, Grade Rs. 1200—2040 and appl at clearly accepted under his clear signature dated 22-3-1988. In this way his emoluments were protected. He was called to appear before the adjudging committee and his request was considered sympathetically and he was given the aforesaid post. He worked continuously.

It was further submitted that the post HTCR is a selection post and he has to pass the selection on his turn. He was promoted in the Scale of Rs. 1400—2300 on 24-7-1993 and there was no due promotion in the next higher Grade. No junior to him has been given Pay Scale of Rs. 1600—2660 and Rs. 2000—3200. His case has no relevancy with the case of Shri Vijay Kumar and Shri O.P. Gupta and Shri C. Jagdish Mina. They were medically decategorised from the category of Guard, which relates to the running staff category. Different rules and instructions are adhered to at the time of their alternative appointment.

It was further submitted that he was placed at the basic pay of Rs. 2040 whereas he was drawing pay of Rs. 2150/- so he was posted at a little less pay. There was a loss of Rs. 200 per month, no doubt but he was selected by the selection committee and the entire discretion vests in the selection committee. He has filed this case after retirement after 10 years as such there is delay and laches on his part. According to the Railway Rules for medically unfit employees there may be variance of wages from 20-30%. As per the rules the management will try to adjust the Pay Scale of the handicapped employee equivalent to the pay he was already drawing but in any case he should not get lesser amount than 25% of his entire emoluments. In the instant case the workman applicant was getting Rs. 200 less emoluments before being handicapped. The deduction is not above 20% and he is to be adjusted between 20-30% so it cannot be said that the selection committee has not considered his case sympathetically. The selection committee has posted him at the Pay Scale of 1400—2300 and he is placed at Rs. 2040 basic pay while he was previously drawing Rs. 2150 so it cannot be said that there is any anomly in considering his case. The cases of the other workmen cited are not applicable in the present facts and circumstances of the case as they belong to running staff and there is separate rules for them so no injustice has been caused to the workman applicant in placing him in the Pay Scale of Rs. 1400—2300 at the time of his posting. The workman applicant is not entitled to get any releif as prayed for. Delay and laches also go against him.

The reference is replied thus :—

The action of the management of Northern Railway in denying the Pay Scale of Rs. 1400—2300 w.e.f. 25-3-1988 as also the consequential promotions in Grade of Rs. 1600—2660 and 2000—3200 to Shri Guruswaroop Joshi is just and fair. The workman applicant does not deserve to get any releif as prayed for. No order as to costs.

The Award is given accordingly.

Date : 4-4-2005.

Let requisite copies of the Award be sent to the Ministry of Labour for necessary action at their end.

Date : 4-4-2005.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

का.आ. 1725.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक आफ राजस्थान लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जोधपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 24/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12025/2/2000-आई.आर.(बी-I)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.24/2001) of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jodhpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers inrelation to the Management of The Bank of Rajasthan Ltd. and their workman, which was received by. the Central Government on 11-04-2005.

[No. L-12025/2/2000-IR (B-I)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री के.के. गुप्ता, आर.एच.जे.एस.

ओ. वि. (केन्द्रीय) संख्या :—24/2001

श्री जगदीश पुरोहित पुत्र श्री देवकिशन पुरोहित निवासी मालीपाड़ा जैसलमेर।

....प्रार्थी

बनाम

1. दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. एम.आई. रोड़, केन्द्रीय कार्यालय, जयपुर
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. क्षेत्रीय कार्यालय चौपासनी रोड़, जोधपुर।
3. शाखा प्रबन्धक, दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. जेसलमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थिति

(1) प्रार्थी प्रतिनिधि श्री विनोद पुरोहित उप.

(2) अप्रार्थीगण प्रतिनिधि श्री पी. के. भंसाली उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 24-1-2005

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी अधिसूचना क्रमॉक एल-12025/2/2000-आई.आर. (बी. I) दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 से निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायालय को प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of Bank of Rajasthan Ltd., in terminating the services of Shri Jagdish Purohit, Part time Pass-book writer by oral order with effect from 5-2-97 is justified ? If not, to what relief he is entitled and from which date ?"

प्रार्थी ने अपना मॉग-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 3 के मातहत पासबुक राईटर के पद पर 180 दिन के लिए 6-8-96 से 1-2-97 की अवधि के लिए पार्ट टाईम नियुक्ति 583.33 मय नियमानुसार महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के आधार पर प्रदान की जिसके क्रम में 2-3-1997 को लिखित आदेश भी जारी किया गया, नियुक्ति के समय प्रार्थी ने बी.ए. पार्ट प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। प्रार्थी ने 180 दिवस, की अवधि 6-8-96 से 1-2-97 के बाद भी अप्रार्थी सं. 3 बैंक शाखा में कार्य किया, अक्समात् ही चार दिन पश्चात् 5-2-97 को कार्योपरान्त अप्रार्थी सं. 3 ने मौखिक आदेश से प्रार्थी की सेवाओं को मनमाने तौर पर समाप्त कर दिया जब कि अप्रार्थी के अधीन पद व कार्य दोनों ही निरन्तर जारी थे लेकिन प्रार्थी को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को मनमाने तौर पर सेवापृथक् कर दिया जो ओ. वि. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा किये गये कार्यों के एवज में 184 दिन की अवधि का बोनस का भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी को सेवापृथक करने के पश्चात् अप्रार्थी द्वारा अन्य बैंक शाखाओं में कई कर्मचारियों को नियुक्तियां प्रदान की गई लेकिन प्रार्थी को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, प्रार्थी से कम अवधि तक अप्रार्थी बैंक में मदनमोहन अग्रवाल ने कार्य किया उसे बैंक ने प्राथमिकता प्रदान करते हुए पुन: ड्यूटी पर ले लिया अप्रार्थी का उक्त कृत्य धारा 25-एच के प्रावधानों के विपरीत है। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत 3-8-98 को नोटिस भी प्रेषित किया लेकिन इसके बावजूद भी कोई राहत प्रार्थी को प्रदान नहीं की गई। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी 25-एच के प्रावधानों के अनुरूप बैंक में प्राथमिकता के आधार पर पुन: सेवा में नियोजित होने का कानूनन अधिकारी है अत: अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि बैंक में भविष्य में पद रिक्त होने पर प्रार्थी को कन्सीडर कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर पुन: नियुक्ति प्रदान करावें, प्रार्थी की सेवा समाप्ति के पश्चात् अप्रार्थी के अधीन नियुक्त किये गये अन्य कर्मचारी की नियुक्ति तिथि के प्रभाव से प्रार्थी को पुन: सेवा में नियोजित कराते हुए सभी अनुगामी लाभ प्रदान किये जावें।

अप्रार्थी की ओर से मांग-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रारम्भिक आपत्तियों में कहा गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति 6 माह की निश्चित कार्य अवधि हेतु अप्रार्थी बैंक की जैसलमेर शाखा में अस्थाई पार्टटाईम पासबुक राईटर के रूप में की गई थी इस पद के लिए यह

आवश्यक था कि वह व्यक्ति या तो नियमित अध्ययनरत् छात्र हो अथवा वह सेवानिवृति हो, यह नियमित अध्ययनरत् छात्रों के लिये एक कल्याणकारी योजना थी, प्रार्थी की 6 माह की निश्चित अवधि (180 दिन अथवा 184 दिन) के लिए ही दिनांक 5-8-1996 से नियुक्ति की गई थी, प्रार्थी, अप्रार्थी बैंक का कर्मचारी नहीं था यह मात्र अस्थाई पार्टटाईम श्रमिक ही था इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच कर्मचारी व नियोजक का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ, भारत सरकार द्वारा प्रेषित विवाद, पोषणीय नहीं है। बैंक में नियुक्ति एक निश्चित प्रक्रिया व नियमानुसार ही साक्षात्कार के पश्चात् की जा सकती है। प्रार्थी को एक निश्चित अवधि 180 दिन अथवा 184 दिन के लिए रखा था जो समाप्त होने पर वह स्वत: ही अस्थाई पार्ट टाईम पास-बुक राईटर के पद से कार्यमुक्त हो गया। प्रार्थी ने प्रति कार्य दिवस, पर मध्यान्ह 3 बजे से सांय 5 बजे तक अर्थात् मात्र दो घंटे की अवधि के लिए ही पार्टटाईम पास-बुक राईटर के रूप में कार्य किया था, निश्चित सेवा अवधि के समाप्त होने के बाद अप्रार्थी बैंक की जैसलमेर शाखा में अस्थाई पार्टटाईम पास-बुक राईटर का कोई पद अथवा कार्य नहीं था अत: बाद में अन्य किसी को नियुक्ति नहीं दी गई, अधिकरण के समक्ष 25-एच ओ. वि. अधिनियम का कोई रेफरेन्स नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी बैंक में 240 दिन अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए अस्थाई पार्टटाईम पास-बुक राईटर के पद पर कार्य नहीं किया इस कारण ओ. वि. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आगे जवाब में कहा गया कि प्रार्थी अस्थाई पार्टटाईम पास-बुक राईटर के पद पर 6 माह की निश्चित अवधि के लिए 6-8-96 को नियुक्त किया तब अध्ययनरत् विद्यार्थी था, अप्रार्थी बैंक कभी भी प्रार्थी का नियोजक नहीं रहा, प्रार्थी ने अस्थाई पार्टटाईम पास-बुक राईटर के रूप में अप्रार्थी बैंक में प्रति कार्यदिवस पर दो घन्टा प्रतिदिन 3 बजे मध्यान्ह से 5 बजे सांयकाल तक कार्य किया जिसका भुगतान प्रार्थी को किया गया, प्रार्थी की नियुक्ति निश्चित अवधि 6 माह (180 दिन अथवा 184 दिन) की समाप्ति पर स्वत: ही समाप्त हो गई, प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी बैंक की जैसलमेर शाखा में 5-2-97 के कार्य उपरान्त मौखिक आदेश से सेवा समाप्त कर दी पूर्ण रूप से गलत है, प्रार्थी को देय पारिश्रमिक जो 6-8-96 से 31-8-96 की अवधि के लिए था अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी को भुगतानकर दिया गया, प्रार्थी, अप्रार्थी बैंक की सेवा में पुन: नियोजन पाने का अधिकारी नहीं है, प्रार्थी व अप्रार्थी बैंक में कभी भी एम्पलोइ व एम्पलोयर का सम्बन्ध नहीं रहा। प्रार्थी ने जिस मदनमोहन अग्रवाल का उल्लेख किया है वह बैंक का स्थाई कर्मचारी 30-10-1993 से है, प्रार्थी ने अपने विवाद में यह नहीं कहा है कि उसे अप्रार्थी बैंक द्वारा उसकी सेवा से छंटनी कर दी गई थी और इस कारण धारा 25-एफ व 25-जी के प्रावधान प्रार्थी पर लागू होते हैं जब प्रार्थी द्वारा 25-एफ व 25-जी का कोई विवाद उठाया ही नहीं गया है तब धारा 25-एच के प्रावधान इस प्रकरण में विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुसार किसी भी अवस्था में लागू नहीं हो सकते। प्रार्थी, अप्रार्थी बैंक में, किसी भी प्रकार के किसी भी आधार पर किसी भी पद पर नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी, अप्रार्थी बैंक की स्थायी सेवा में नहीं था और न ही अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थी की सेवा से छंटनी ही की गई थी इस कारण इस आधार पर प्रार्थी द्वारा जो धारा 25-एच के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना चाही गई है वह प्रार्थना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का मांग-पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थी की ओर से स्वयं का शपथ-पत्र मांग-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई तथा अप्रार्थी की ओर से शिवगिरी स्वामी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई। दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न दस्तोवजात की फोटो स्टेट प्रतियां पेश की गई।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी का यह तर्क है कि 6-8-96 ये 1-2-97 तक प्रार्थी को पास-बुक राईटर पार्टटाईम के पद पर 180 दिन के लिए नियुक्त किया, उसके बाद भी उसने चार दिन और काम किया और उसे बिना नोटिस व मुआवजा दिये अवैध तरीके से हटा दिया उससे कनिष्ठ मदनमोहन अग्रवाल को नियुक्ति दे दी गई अत: उसे पुन: सेवा में नियुक्त किया जावे।

अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी को छ: मास के लिए रखा था, छ: माह के अन्दर 184 दिन काम किया। उसे पार्टटाईम पास-बुक राईटर की नियुक्ति तभी करते हैं जब पास-बुक एकत्रित हो जाती है, यह अस्थाई कार्य है व अस्थाई पद है, कार्य समाप्ति पर उसकी सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाती हैं। विद्यार्थियों और रिटायर्ड व्यक्तियों को लगाते हैं ताकि उनकी सहायता हो सके और एक सप्ताह में 12 घण्टे कुल कार्य लिया जाता है। प्रार्थी ने 240 दिन तक कार्य नहीं किया है अत: धारा 25-एफ का उल्लंघन नहीं हुआ है। मदनमोहन अग्रवाल स्थाई कर्मचारी 30-10-1993 से है, प्रार्थी 1996 में लगा था इसलिये मदनमोहन प्रार्थी से कनिष्ठ नहीं था। उनका यह भी कहना है कि पास-बुक राईटर का काम बैंक में समाप्त हो चुका है, बैंक कम्पयुटराईज्ड हो चुके हैं।

प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि 6-8-96 से 5-2-97 को छ: माह पूरे होते है, प्रदर्श-4 की शर्त नम्बर-1 (एक) पढ़ ली थी, बोनस की राशि बैंक में 27-5-2002 को जमा करायी, तारीख याद नहीं, 27-5-2002 को बोनस की राशि ले ली।

अप्रार्थी की ओर से बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में फोटो कापियां प्रस्तुत हुई है। 23-5-2002 का प्रार्थी को भुगतान का वाउचर व प्रार्थी के बैंक खाते में जमा होने का 27-5-2002 के खाते की फोटो कॉपी प्रस्तुत हुई है। प्रार्थी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि बोनस का बैंकर्स चैक उसे मिल गया, पे-स्लिप मेरे हाथ की भरी हुई है वे मेरी दस्तखती है। जब कि प्रार्थी ने अपने शपथ-पत्र के पैरा नम्बर-5 में यह अंकित किया है कि 184 दिन की बोनस की अवधि का भुगतान नहीं किया है, यह शपथ-पत्र प्रार्थी ने 12-12-2002 को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उसने जिरह में इस संबंध में यह कहा है कि बोनस राशि मिल गई यह बात शपथ-पत्र तैयार कराते समय वकील साहब को बताई या नहीं शायद भूल गया होगा। इससे जाहिर होता है कि प्रार्थी ने जानबुझकर झूठा शपथ-पत्र इस संबंध में दिया है, प्रार्थी एक पढ़ा-लिखा है वह बी.ए. पास है, उसने अपने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र में यह कहा है कि उच्च माध्यमिक (व्यवसायिक) परीक्षा 1993 में पास की व बी.ए. 1999 में किया।

अप्रार्थी के शपथगृहता शिवगिरी स्वामी ने जिरह में कहा है कि 5-2-97 तक प्रार्थी ने काम किया, छः माह बाद जरूरत खत्म हो गई, समझौते के आधार पर लगाया था, मदनमोहन पार्ट टाईम नहीं था परमानेन्ट था।

यह स्वीकृत तथ्य है कि जब प्रार्थी ने बैंक में पार्ट टाईम पास-बुक राईटर के रूप में छः माह तक सेवाएं दी उस समय वह विद्यार्थी था अतः अप्रार्थी का यह कथन कि पार्ट टाईम पास-बुक राईटर विद्यार्थियों व सेवानिवृत व्यक्तियों को लगाया जाता है की पुष्टि होती है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त 2003 डब्ल्यू.एल.एन. 690 भीमराज बनाम उत्तीरय राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में यह कहा गया है कि निश्चित कार्य अवधि के लिए नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति-पत्र में लिखा अतः अपने आप में इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करता है कि वह निश्चित अवधि की नियुक्ति थी, ट्रिब्युनल इस संबंध में वास्तव में किस प्रकार की नियुक्ति थी, निर्णय कर सकता है। प्रार्थी की ओर से 1999 (81) एफ.एल.आर. 746 समिस्ता दुबे बनाम सिटी बोर्ड ईटावा का विनिश्चय पेश किया। इसमें यू.पी. इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2(जेड) व 2(के) महिला टाईपिस्ट क्लर्क सिटी बोर्ड में सैक्शन 2 (जेड) के प्रावधनों के अन्तर्गत श्रमिक है। इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

अप्रार्थी की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी को पास-बुक लिखने के लिए पार्ट टाइम पास-बुक राईटर के रूप में नियुक्त किया गया एवं प्रार्थी ने 180 दिन के बाद भी 4 दिन काम कर लिया है तब भी उसके 240 दिन पूरे नहीं होते हैं और पास-बुक राईटर का काम लगातार प्रकृति का नहीं है। जब पास-बुकें एकत्रित हो जाती हैं तभी कार्य करने के लिए रखते हैं। अब स्थिति यह है कि बैंक कम्प्यूटराईज्ड हो चुके हैं और पास-बुक राईटर का काम कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है इसलिये पास-बुक राईटर का पद अब बैंक में विद्यमान नहीं है अप्रार्थी की ओर से आर.एल.डब्ल्यू. 2002(4) एस.सी. पेज 511 मै. हरियाणा स्टेट एफ्.सी.सी.डब्ल्यू. स्टोर लि. बनाम राम निवास का विनश्चिय पेश किया जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ओओ) एवं 25(एच) छंटनी कर्मकार को विशेष कार्य एवं नियम समय के लिए व्यवस्थापकों द्वारा नियुक्त किया गया-विशेष कार्य के समापन एवं नियत समय के पूर्ण होने पर कर्मकार को सेवा से हटाने की कार्यवाही को छंटनी नहीं माना जा सकता। धारा 25(च) लागू नहीं होगी। अप्रार्थी की ओर से आर.एल.आर. 2004 (3) पेज 289 डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर बनाम बापु लाल व अन्य का विनिश्चय पेश किया यह नियमितिकरण करने के सम्बन्ध में है, यहां नियमितीकरण का मामला नहीं है।

प्रदर्श-4 नियुक्ति-पत्र के अवलोकन से प्रार्थी को 6-8-96 से 1-2-97 तक 180 दिन के लिए नियुक्ति दी गई और प्रार्थी ने 5-2-97 तक कुल 184 दिन कार्य किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी ने 240 दिन तक लगातार कार्य नहीं किया है। किन्तु स्थिति स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में लगातार 240 कार्य दिवस नहीं होते हैं तब धारा 25-बी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25-एफ आकृषित नहीं होती है और इस सेवामुक्ति को धारा 25-एफ के प्रावधानों के अर्न्तगत छंटनी नहीं कहा जा सकता। इस तरह के तथ्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टान्तों में नहीं है अतः उसे कोई सहायता नहीं पहुंचाते हैं। प्रार्थी ने चूंकि पिछले एक वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया है इसलिये उसकी सेवामुक्ति को भी 25-एफ के अर्न्तगत छंटनी नहीं माना जायेगा।

प्रार्थी का यह कथन है कि मदन मोहन अग्रवाल को बैंक ने स्थाई नियुक्ति दे दी, अप्रार्थी की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मदनमोहन अग्रवाल प्रार्थी से पूर्व 1993 से ही कार्यरत है। प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में अन्य ऐसा कोई नाम नहीं बताया है जो 96 के बाद में पास-बुक राईटर के रूप में रखा गया हो और उसे प्रार्थी के स्थान पर नियमित नियुक्ति दे दी गई हो। उसने तो यह भी नहीं बताया है कि जैसलमेर शाखा में उसको हटाने के बाद यदि पास-बुक राईटर का काम शेष था तो अन्य किसी को रखा, प्रार्थी यह बताने में कतई असफल रहा है कि उसके हटाने के पश्चात् किसी अन्य को बैंक में उसके स्थान पर रखा गया हो।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर जब प्रार्थी ने 240 दिन लगातार कार्य नहीं किया तो इस सेवा-मुक्ति को 25-एफ आई.डी. एक्ट के प्रावधानों के अर्न्तगत छंटनी नहीं कहा जा सकता और प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, प्रार्थी यह बताने में भी कतई असफल रहा है कि उसके बाद किसी अन्य कनिष्ठ को पास-बुक राईटर के रूप में रखा गया हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी से कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रार्थी जगदीश पुरोहित पार्ट टाईम पास-बुक राईटर द्वारा अप्रार्थी बैंक ऑफ राजस्थान लि. के अधीन लगातार 240 दिन कार्य नहीं किया अतः प्रार्थी की 5-2-97 से की गई सेवामुक्ति को धारा 25-एफ आई.डी. एक्ट के प्रावधानों के अर्न्तगत छंटनी नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इस अधिनिर्णय को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जावे।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 24-1-2005 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

हस्ता./-

के.के. गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 12अप्रैल, 2005

का.आ. 1726.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 21/90) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/58/88-डी.आई.(बी)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1726.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 21/90) of the Central Industrial Tribunal Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Mewar Anchalik Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 11-04-2005.

[No. L-12011/58/88-DI (B)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, JAIPUR

Case No. C.I.T. 21/90

Ref. : Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi Order No. L-12011/58/88-DI(B) 24-5-89

Grameen Bank Employees Union
C/o The General Secretary,
Above Akar & Co.,
Acharyon Ki Haveli,
Kishan Pole Bazar Jaipur. ....Applicant

Vs.

Mewar Anchalik Gramin Bank,
Udaipur,
C/o The Chairman,
14, Alkapuri, Rani Road,
Udaipur (Rajasthan) ....Non-Applicant

PRESENT :

Presiding Officer : Shri P.L. Hissaria, RHJS

For the Applicant : Shri R.C. Jain

For the non-applicant : Shri Man Singh Gupta

Date of Award : 16-3-2005

AWARD

1. The Central Government, Labour Ministry, New Delhi *vide* its above order sent the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Mewar Anchlik Gramin Bank Udaipur in (1) not regularising the services of its messangers in proper wage scales as adopted by the State Govt.; (2) Not paying arrears of conveyance expenses both sides—to and fro—Railway Station/Bus Stand for the period prior to 16-8-88: (3) not granting loans for purchase of second hand vehicles; and (4) recovering training expenses from the staff on their resigning from services is just and legal ? If not, what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The applicant union has filed statement of claim according to which it is stated that the respondent Bank started functioning since, 1984, there are permanent vacancies of messangers who perform the permanent nature of work and the bank has 59 branches in all and messangers are 66 in number working in various branches including head office of the bank. The management has not issued any appointment letter to these messangers giving terms and conditions of service in violation of principles of natural justice, also these messangers are not being paid the wages as per scales and instead they are arbitrarily engaged them as daily wages at the rate of 6/-, 8/- and 10.50 per day. That the Govt. of India vide its Order/Circular No. F. 7(4)/84-RRB dated 8th October, 1984 issued instructions regarding creation of posts of messangers in RRBs, this circular has since been modified by National Bank for Agriculture and Rural Development vide Circular dated 7th May, 1987. Despite clear instructions and orders, the management has not been implementing the instructions and this action of the management deserves to be declared illegal and the workmen be declared to entitled wages with retrospective effect.

3. The next matter is regarding not making payment of arrears of conveyance expenses both sides—to and fro—Railway Station/Bus Stand for the period perior to 16-8-88. The union submits that the employees working in the Regional Rural Banks, are entitled to these expenses as per Rules, framed by the Govt. of India known as R.B.B. Act, 1976 and according to Rule No. 17 of this Act. The mangement is denying the arrears of allowances which action is not just and legal hence deserves to be illegal.

4. The third issue/demand of the union is of not granting loans for purchase of second hand vehicles. It is stated by the union that in this connection the conditions of service in regard to granting loans, are governed by the State Govt. and Finance Department of State Government vide order dated 2-2-87 has issued guidelines in regard to grant of loans for purchasing conveyance to Govt. servants. The management is also denying to extend this facility to its workmen, which action of the management be declared illegal and workmen be declared to entitle this facility according to State Government order as above.

5. The last and fourth issue of the claim is of recovering training expenses from the staff on their resigning from service. The Union stated that the non-applicant bank is recovering amount of training from its workmen which ranges between Rs. 3,000/- to 20,000/- according to the training course in total service tenure. The applicant union submits that the recovery of any amount from the dues of employees who resigns from

service is without any reules and terms and conditions of appointment, is also against the principles of natural justice and violation of Rules. There is no such Rule in any industry for recovering training expenses when the employee resigns from service, hence the action of the management be declared as illegal and proper directions be issued to the non-applicant.

6. The non-applicant bank has filed its reply to the statement of claim and raised some preliminary objections as the reference has not been espoused by the recognised union, claimant has no locus standi to file the instant claim, reference is bad in law as no notice has been served by the applicant to the bank before referring the matter for adjudication. On mertis the non-applicant has stated that bank was paying wages to the 66 daily rated workers @ 14/-. After receiving the copy of NABARD letter dated 7-5-87, as it was a policy matter, the bank put up the matter in its Board meeting dated 11-7-88 and Board gave consent for regularisation of daily rated workers according to the instructions of NABARD, Government of India. Bank issued a cicular dated 25-8-88 and called upon options from daily waged worker to opt either for 50% pay of full time regular messenger or daily wage rate. Screening Committee constituted by the Board took interview of 25 daily wages workers on 19-9-88, total 5 posts of full time regular messengers were created and three posts were reserved for general category and one post was reserved for SC and one for ST, appointment letter was issued to three candidates in compliance of Board's decision. In compliance of Board's decisions, also Bank has regularised 42 daily rated workers as the part time regular messenger w.e.f. 1-12-88, two daily rated workers do not having required qualification of VIIIth standard and five other workers having IXth standard qualification have also been regularised. In this way the management has taken all steps to regularise the daily rated workers.

7. Regarding demand No. 2, the management's reply is that keeping in view the fact that travelling allowance is not a source of profit to receipient, the bank has paid the actual expenses limited to Rs. 10 to Rs. 13 to specified categories of staff from duty point and vice versa. After receiving clarification from the Government of Rajasthan fixed milage allowance @ 20/- or 26/- started giving w.e.f. 16-8-88 hence the claim in this regard has been denied by the non-applicant.

8. Demand No. 3 of the union has also been denied and it has replied by the bank that conveyance loan scheme is framed by the bank according to the State Government Conveyance Advance Rules, 1970 and according to Rule No. 14 of said Rules first loan can be granted to new vehicles and second/third loan can be granted to old vehicles, thus the scheme of the bank of conveyance loan include both the provisions.

9. In reply to demand No. 4 of the union, the non-applicant bank pleaded that the bank is recovering training expenses from officers or employees who resign from bank's service according to Mewar Anchalik Gramin Bank Staff Service Regulations 1983 and thus is legal. It is prayed by the non-applicant that statement of claim of the workmen may be dismissed in the interest of justice.

10. Both the parties have not led any evidence either in support of the claim or in rebuttal as the case may be. I have heard the learned representatives of both the parties and gone through the file.

11. The learned representative for the applicant argued that he does not press Demand No. 3 and 4 referred to in this reference. As far as demand No. 1 and 2 are concerned, both the demands have been accepted by the National Tribunal which has been confirmed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No. 132 of 1984 G.S. Kaushik *Vs.* Union of India with Civil Writ Petition No. 7149-50 of 1982 Rakesh Kumar Gautam *Vs.* Union of India. He has also argued that the Hon'ble Rajasthan High Court has also decided in Marudhar Khetriya Gramin Bank *Vs.* Mahaveer Singh in D.B. Civil Appeal (W) No. 70/2002 decided on April 21st, 2003 and followed the award passed by the National Tribunal.

12. The learned representative for the opponent has agreed with the argument of learned representative of the applicant.

13. In view of the arguments and in the circumstances when there is an award of the National Tribunal on the same matter, there is no need to pass a separate award on the matter because Demand No. 1 and 2 of the claim have been accepted by the National Tribunal in its Award. Therefore, in view of that award the reference is disposed of accordingly and the following award is passed :

> "The action of the management of Mewar Achalik Gramin Bank, Udaipur in not giving beneft to the workmen regarding Demand No. 1 and 2 of the claim is not just and legal and award of the National Tribunal will be effective for these two demands. Rest of the two demands i.e. No. 3 and 4 are not just and legal and for that workmen are not entitled to get any relief."

14. Copy of the Award be sent to the Central Government for publication as per the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.

15. Pronounced this the 16th day of March, 2005 in the open Court.

P. L. HISSARIA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

का.आ. 1727.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 70/90) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/12/86-डी. IV(ए)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1727.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.70/90) of the Central Industrial Tribunal or Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of The Bank of Rajasthan Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 11-4-2005.

[No. L-12011/12/86-D. IV(A)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण,
जयपुर

केस नं० सी०आई टी० 70/90

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एल. 12011/12/86-डी(ए)दिनांक 19-8-87

राजस्थान बैंक एम्पलाईज़ यूनियन, ... प्रार्थी
परवाना भवन,
माधौबाग, जोधपुर

बनाम

दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ...अप्रार्थी
सी-71, सरोजनी मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी :—श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री आलोक फतहपुरिया

दिनांक अवार्ड : 16-2-2005

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :

"क्या बैंक ऑफ राजस्थान लि०, जयपुर के प्रबन्धतंत्र को निम्नलिखित कर्मकारों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही वैध व उचित है :

क्रम सं.	नाम व पदनाम	शाखा	सेवा समाप्ति की तारीख
1.	श्री दिनेश गांधी, क्लर्क	एच.सी. रोड, जोधपुर	10-12-80
2.	श्री रामधन अग्रवाल, क्लर्क	-यथोक्त-	24-10-75
3.	श्री गोविन्द प्रकाश गोयल पो. बुक राईटर	मन्दोर्स रोड, जोधपुर	31-3-85
4.	रामकिशोर सिंघल, क्लर्क	-यथोक्त-	8-1-81
5.	योगेश कुमार सोगोनो क्लर्क	गणेश मण्डी, जोधपुर	1-7-85

यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

2. उक्त रैफरैंस के संबंध में केंन्द्र सरकार का पत्र दिनांक 8-10-90 इस अधिकरण में प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रार्थी संघ ने रैफरैंस की पुष्टि में अपना वाद पेश किया है कि श्रमिक दिनेश गांधी को लिपिक के रूप में अप्रर्थी बैंक की हाई कोर्ट रोड शाखा, जोधपुर में दिनांक 23-9-80 को नियुक्त किया गया दिनांक 10-12-80 को 79 दिन की सेवा करने के पश्चात् उसे सेवा से अलग कर दिया। श्री रामधन अग्रवाल, क्लर्क को लिपिक के रुप में हाई कोर्ट रोड, शाखा जोधपुर में दिनांक 10-2-75 को नियुक्त किया तथा 23-2-75 को सेवा से अलग कर दिया, पुन: उनको 26-2-75 को रखा 2-3-75 को सेवा से अलग कर दिया, फिर 7-3-75 को नियुक्त किया व 18-3-75 को हटा दिया, उसके बाद दिनांक 21-3-75 को पुन: नियुक्त किया और 25-3-75 को हटा दिया और 1-8-75 को फिर नियुक्त कर 20-8-75 को हटाया। इस प्रकार श्री अग्रवाल ने बैंक में 58 दिन कार्य किया है और उन्हें हटाने के बाद बैंक ने अन्य कर्मचारियों को श्रमिक की जगह नियुक्त किया। श्री गोविन्द प्रकाश गोयल, पास बुक राईटर को अंशकालीन पास बुक राईटर के रूप में अप्रार्थी को मण्डौर शाखा, जोधपुर में दिनांक 3-10-84 को नियुक्त किया गया और 31-3-85 को 180 दिन की सेवा करने को पश्चात् बैंक सेवा से अलग कर उनके स्थान पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया। श्री रामकिशोर सिंघल को दिनांक 8-12-80 को अप्रार्थी की मण्डौर शाखा, जोधपुर में नियुक्त किया व 7-1-81 को हटा दिया और बार-बार पुन: नियुक्त कर अंत में 8-1-81 को हटाया और इस अवधि में श्रमिक ने कुल 80 दिन कार्य किया और फिर उसके स्थान पर अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर

दिया। श्री योगेश कुमार सोमानी, क्लर्क को 6-12-84 को घासमण्डी रोड़, शाखा में नियुक्त कर दिनांक 12-1-85 को हटा दिया और पुन: नियुक्त करते हुए अंत में 1-7-85 तक नौकरी करवा कर सेवा से अलग कर दिया। उक्त अवधि में श्रमिक ने कुल 80 दिन कार्य किया उसके बाद अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। प्रार्थी संघ का कथन है कि उक्त सभी श्रमिकों को नौकरी से निकालने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया जो शास्त्री अवार्ड की धारा 522 (4) के विपरीत है। इन श्रमिकों को निकालने के बाद उनकी जगह नये कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई इससे पहले श्रमिकगण को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, न ही नोटिस समय 14 दिन का भुगतान दिया गया इस प्राकर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 25-जी व 25-एच का उल्लंघन किया गया है साथ ही औद्योगिक विवाद नियम 76, 77 व 78 का भी उल्लंघन किया गया है। अत: प्रार्थी संघ की प्रार्थना है कि उक्त पांचों श्रमिकों की सेवाएं गैर-कानूनी तरीके से समाप्त की गई हैं अत: उन्हें नौकरी से निकालने की तारीख से पूरे वेतन सहित पुन: सेवा में बहाल किया जाये। कर्मचारीगण जो कार्य कर रहे थे वह स्थाई प्रकृति का था, अत: उनका क्लेम स्वीकार किया जाये।

3. अप्रार्थी बैंक की ओर से वाद का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रारम्भिक आपत्तियां उठाई गई हैं कि यह विवाद औद्योगिक विवाद नहीं हैं क्योंकि अप्रार्थी के कर्मचारियों ने उक्त विवाद उठाने हेतु: यूनियन या व्यक्ति विशेष को अधिकृत नहीं किया है। अधिनियम की धारा 2(ए) के अन्तर्गत केवल डिस्चार्ज डिसमिसल, अथवा छंटनी का ही विवाद उठाया जा सकता है जबकि उपरोक्त श्रमिकगण को न तो डिसमिसल किया गया न ही रिटरैंच अथवा डिसमिस किया गया बल्कि उनकी सेवा एक निश्चित अवधि के लिए आवश्यक एवं आकस्मिक कार्य हेतु नियुक्त करने के पश्चात् स्वत: ही समाप्त हो गई, अत: यह औद्योगिक विवाद की तारीफ में नहीं आता। प्रार्थी संघ द्वारा मामला बहुत ही देरी से उठाया है। स्थाई नियुक्ति हेतु वर्ष 1986 में सूचना प्रकाशित की गई उसके अधार पर इन श्रमिकों का चयन नहीं होना प्रमाणित करता है कि ये श्रमिक स्थाई पद पर नियोजित होने के योग्य नहीं हैं। स्थाई नियुक्ति हेतु बैंक में नियमानुसार प्रक्रिया है जिसके आधार पर ही नियमित नियुक्तियां की जाती हैं। रैफरैंस टर्मीनेशन का किया गया है जबकि श्रमिकगण की सेवाएं निश्चित अवधि पूरी होने के बाद स्वत: ही समाप्त हो गई। अत: रैफरेंस निरस्तनीय है। इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन एवं बैंक कर्मचारियों के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आकस्मिक कार्य हेतु या कार्य की अधिकता होने पर किसी व्यक्ति को अस्थाई रूप से अल्प अवधि के लिये नियुक्त करने का बैंक को अधिकार है। इन श्रमिकगण पर धारा 25-एफ अधिनियम लागू नहीं होती ऐसे में धारा 25-एच का उल्लंघन सिद्ध नहीं होती है।

4. गुणावगुण पर अप्रार्थी का जवाब है कि श्रमिक रामधन अग्रवाल अप्रार्थी के रिकार्ड के अनुसार 14-8-75 के पश्चात् कभी भी बैंक के नियोजन में नहीं रहा। अप्रार्थी ने कभी भी किसी कर्मचारी को सेवा मुक्त अथवा सेवा से पृथक नहीं किया बल्कि उनकी सेवाएं नियोजक की तयशुदा शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के समाप्त होने पर स्वत: समाप्त हुई हैं अत: यह प्रकरण औद्योगिक विवाद की तारीफ में नहीं आता। अप्रार्थी ने कभी भी शास्त्री अवार्ड के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया।

बैंक द्वारा किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि श्रमिकगण की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं बल्कि निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद स्वत: ही समाप्त हो गई हैं। धारा 25 एच के प्रावधान तभी लागू होते हैं जबकि धारा 15-एफ के अन्तर्गत प्रकरण आता हो किसी भी श्रमिक ने 240 दिन सेवा नहीं की इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते अत: धारा 25(एच) अधिनियम इनके प्रकरण पर लगू नहीं होती। अप्रार्थी ने किसी प्राकर के प्रावधानों का कोई उल्लंघनों नहीं की है और श्रमिकगण कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं।

5. प्रार्थी संघ ने अप्रार्थी के जवाब का जवाबुल जवाब पेश किया है कि सभी श्रमिकगण यूनियन के सदस्य हैं और नियमानुसार विवाद उठाया गया है, अप्रार्थी द्वारा श्रमिकगण की सेवा मुक्ति की गई है अत: प्रकरण औद्योगिक विवाद की तारीफ में आता है, केवल मात्र एक श्रमिक ने 1975 में अप्रार्थी के यहां सेवा की है, अन्य के मामले वर्ष 80, 81 व 85 के हैं और भारत सरकार ने विवाद रैफरैंस के जरिये 1987 में ही अधिकरण में भेज दिया था लेकिन अधिकरण में न पहुंचने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी अत: भारत सरकार का यूनियन द्वारा पुन: ध्यान आकर्षित करने पर 1990 में इसकी प्रतिलिपि पुन: अधिकरण को भेजी गई तब प्रकरण रजिस्टर किया गया अत: यूनियन के स्तर पर कोई देरी नहीं हुई है बल्कि 1985 में ही यूनियन ने विवाद उठा लिया था। स्थाई प्रकृति के कार्य पर आकस्मिक नियुक्ति कर और उसे हटाकर पुन: नई नियुक्ति नहीं की जा सकती, इन श्रमिकगण के स्थान पर अप्रार्थी बैंक ने नई नियुक्तियां की हैं जिनका समस्त रिकार्ड बैंक के पास है, अत: धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू होते हैं। अत: प्रार्थी संघ ने क्लेम स्वीकार किये जाने व तदनुसार श्रमिकगण को लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

6. जिन पांच श्रमिकगण का विवाद केन्द्र सरकार द्वारा रैफर किया गया है उनमें गाविन्द प्रकाश गोयल व योगेश कुमार सोमानी ने अपने विवाद की पुष्टि में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, न ही उनकी तरफ से प्रार्थी यूनियन ने किसी प्रकार की साक्ष्य पेश की है। दिनेश चंद गांधी की ओर से स्वयं दिनेश चंद गांधी का शपथ पत्र पेश किया गया है जिससे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है, प्रार्थी श्रमिक की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। श्रमिक रामधन अग्रवाल ने मात्र स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है। राम किशोर सिंघल श्रमिक ने भी मात्र अपना शपथ पत्र पेश किया है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे भी अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की हैं। अप्रार्थी बैंक की ओर से तेज सिंह कावड़िया एवं भरत सिंह पंवार के शपथ-पत्र पेश किये गये हैं तथा प्रदर्श एम-1 से एम-11 तक 11 दस्तावेज प्रदर्श कराये गये हैं। इन दोनों साक्षियों से प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है।

7. मैंने दोनों पक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

8. जहां तक श्रमिक गोविन्द प्रकाश गोयल एवं योगेश कुमार सोमानी का संबंध है, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अपने वाद की पुष्टि में नहीं आने से वे अपने क्लेम को किसी तरह से साबित नहीं कर सके हैं अत: इन दोनों श्रमिकगण के लिए कोई विवाद साबित नहीं होने के कारण 'नो डिस्प्यूट अवार्ड' पारित किया जाता है।

9. जहां तक शेष तीनों श्रमिकों का प्रश्न है, इनके लिए विवाद केवल यह रैफर हुआ है कि क्या उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से उनको सेवा मुक्त करना वैध या उचित है ? इनमें दिनेश चंद गांधी ने जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें उसने कहा है कि उसकी नियुक्ति विपक्षी बैंक में 23-9-80 को की गई थी, कोई नियुक्ति आदेश नहीं दिया, अस्थाई नियुक्ति थी, 10-12-80 से मौखिक आदेश से ही सेवा मुक्त कर दिया। प्रार्थी ने इसके लिए जो क्लेम पेश किया है उसमें भी कुल 79 दिन की सेवा करने के बाद सेवा से अलग करने की बात लिखी है। इस तरह इस श्रमिक का 240 दिन का कार्य पूरा नहीं हुआ और इस कारण धारा 25-एफ अधिनियम इस श्रमिक के लिए लागू नहीं होती। इस तथ्य को प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने भी स्वीकार किया है। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का एकमात्र तर्क यह है कि इन तीनों ही श्रमिकगण ने 240 दिन की सेवा पूरी नहीं की परन्तु इनकी सेवा समाप्त करने के पश्चात् अन्य श्रमिकों को अस्थाई नियुक्ति दी गई है और इन श्रमिकों को पुन: सेवा में लेने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए धारा 25-एच अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है जो अपने आप में पूर्ण प्रावधान है और धारा 25-एफ अधिनियम पर निर्भर नहीं है। इसलिए तीनों श्रमिकों को बिना नोटिस दिये अन्य श्रमिकों को नौकरी पर रखा गया है। और अन्य श्रमिकों ने जितने दिन कार्य किया है उतने दिन का वेतन तीनों श्रमिकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने सूर्य प्रकाश शर्मा बनाम राजस्थान टैक्सट बोर्ड, जयपुर 1991 (2) आर.एल.आर. 691 (राज.) का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है।

10. इसके प्रतिकूल विद्वान प्रतिनिधि अप्रार्थी का तर्क है कि केन्द्रीय सरकार ने धारा 25-एच अधिनियम का कोई रैफरैंस अधीकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जो रैफरैंस प्रस्तुत हुआ है वह मात्र सेवा मुक्ति की वैधता व औचित्यता का है जो धारा 25-एफ अधिनियम का है और धारा 25-एफ अधिनियम के प्रावधान, चूंकि तीनों ही श्रमिकगण ने 240 दिन कार्य नहीं किया है, इसलिए लागू नहीं होते, इस कारण इन तीनों श्रमिकों की सेवा समाप्ति जो निश्चित अवधि के लिए पूर्णत: अस्थाई तौर पर किसी अन्य के छुट्टी पर जाने के कारण की गई थी, पूर्णत: उचित व वैध है। अत: प्रार्थी श्रमिकगण कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है। उनका एक तर्क यह भी है कि दिनेश गांधी, रामधन अग्रवाल व रामकिशोर सिंघल की सेवा समाप्ति तिथि क्रमश: 10-12-80, 24-10-75 व 8-1-81 बताई गई और सात वर्ष तक जिसमें रामधन के मामले में 12 वर्ष तक इस सेवा मुक्ति के पश्चात् उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार ने मृतप्राय: वाद को पुनर्जीवित किया है और मात्र 7 व 12 वर्ष की देरी होने के कारण से प्रार्थीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

11. मैंने इस संबंध में दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया। मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई साक्ष्य का अवलोकन किया।

12. दिनेश गांधी ने 79 दिन तक काम करना कहा है, जिरह में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श एम-1 व एम-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसको किसी के स्थान पर रखा हो तो पता नहीं, अपनी सेवा मुक्ति के बाद राम किशोर सिंघल, ज्योति तथा चन्द्र मूंदड़ा को अस्थाई पद पर लगाना कहा है लेकिन उन्हें कब नियुक्त किया गया, कब हटाया गया, उन्होंने कितने दिन कार्य किया और उनको कितना वेतन दिया गया, इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

13. इस तरह रामधन अग्रवाल ने अपने शपथ पत्र में स्वयं को 80-85 दिन कार्य करना कहा है, उसकी सेवा मुक्ति के पश्चात् प्रमोद अग्रवाल, दिनेश गांधी, दिनेश पंवार, निर्मल भण्डारी, ज्योति, चन्द्रा मूंदड़ा, राम किशोर सिंघल को नियुक्त करना कहा है। परन्तु उसने भी न तो इनमें से किसी के नाम क्लेम में अंकित किये हैं, न ही इस बाबत कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है कि इनकी नियुक्ति कब कब की गई, कितने दिन इन्होंने कार्य किया और उनको कितना वेतन दिया गया। जिरह में उसने प्रदर्श एम-3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उसे सेवा से हटाये जाने के बाद उसने कभी कोई नौकरी का आवेदन बैंक में नहीं किया।

14. इसी तरह राम किशोर सिंघल ने अपने शपथ पत्र में मात्र 80 दिन काम करना कहा है और इसके बाद किसको रखा गया इस संबंध में न तो क्लेम में कोई नाम बताया है न ही अपनी साक्ष्य में कहा है। जिरह में प्रदर्श एम-4 व 5 एवं 6 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है और उसे हटाये जाने के बाद कभी बैंक में आवेदन नहीं करना और परीक्षा नहीं देना कहा है।

15. इस तीनों ही श्रमिकगण का प्रथम तो धारा 25-एच अधिनियम की बाबत केन्द्र सरकार द्वारा कोई विवाद ही प्रेपित नहीं किया गया है जिसके लिए न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक हो। द्वितीय इन्होंने यह साक्ष्य भी पेश नहीं की कि उनके बाद किन-किन व्यक्तियों को कितने दिन बैंक में रखा गया और उन्हें कितना वेतन दिया गया जिससे यह न्याय निर्णय किया जा सके कि यदि उनके बाद किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बिना श्रमिकगण को नोटिस दिये रखा गया है और वेतन दिया गया है तो उतना वेतन इन श्रमिकगण को दिलाया जा सके। परन्तु साक्ष्य के अभाव में यह कतई संभव नहीं है।

16. जहां तक विवाद की देरी का प्रश्न है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रामधन अग्रवाल ने 12 वर्ष पश्चात्, दिनेश चन्द्र गांधी ने सात वर्ष पश्चात् व राम किशोर ने छ: वर्ष पश्चात् विवाद उठाया है और इस देरी का कोई भी कारण नहीं बताया है। इस कारण भी वे कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं।

17. अप्रार्थी नियोजक की ओर से तेज सिंह कावड़िया पेश हुए हैं जिन्होंने राम किशोर सिंघल के लिए कहा है कि उनका नियुक्ति पत्र प्रदर्श 5 है जो मानसिंह गहलोत के अवकाश पर जाने के कारण उन्हें रखा था, उनका घोषणा पत्र प्रदर्श 7 है। अवकाश के कारण जो प्रबन्ध

का आदेश किया गया था वह प्रदर्श-6 है। जिरह में उसने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है। इसी प्रकार भरत सिंह पंवार ने दिनेश चंद गांधी का नियुक्ति पत्र प्रदर्श एम-1 व एम-2 होना कहा है जो दिनेश चंद गांधी ने भी स्वीकार किया है, जो नियुक्ति पत्र अन्य कर्मचारी के अवकाश पर रहने के कारण दिया गया है। राम धन अग्रवाल का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-3 होना कहा है व अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर जाने के कारण उसे नियुक्ति देना कहा है जिसके पत्र क्रमशः प्रदर्श-8 लगायत 11 हैं और जिरह में उसने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है। इस तथ्य को साबित करने का भार प्रार्थी संघ पर था कि इन श्रमिकों को हटाये जाने के बाद अन्य श्रमिकगण की नियुक्ति की गई जिनके लिए इन श्रमिकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और अन्य श्रमिकों ने कितनी अवधि तक काम किया तथा उन्हें कितना वेतन दिया गया जो ये श्रमिकगण प्राप्त कर सकते। परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य इन श्रमिकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी सूरत में ये तीनों श्रमिकगण भी अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"बैंक ऑफ राजस्थान के प्रबन्धतंत्र, जयपुर द्वारा पांचों श्रमिकगण सर्वश्री दिनेश गांधी, रामधन अग्रवाल, गोविन्द प्रकाश गोयल, राम किशोर सिंघल, योगेश कुमार सोमानी को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है। श्रमिकगण कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं।"

19. अवार्ड आज दिनांक 16-2-2005 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2005

का.आ. 1728.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय II, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 34/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/134/1998-आई. आर. (बी-I)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2005

S.O. 1728.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 34/99) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Standard Chartered Bank and their workman, which was received by the Central Government on 11-04-2005.

[No. L-12012/134/1998-IR (B-I)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT-II,

RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE NEW DELHI

R. N. RAI, Presiding Officer

I.D. No. 34/99

IN THE MATTER OF :—

Ms. Nirupama Rajoo,
House No. 142/5, Moti Bazar, Mand,
Himachal Pradesh,
Distt. Mandi (H.P.) 175001.

VERSUS

Standard Chartered Bank,
The Sr. Manager (Personnel),
17, Parliament Street,
New Delhi-110001.

AWARD

1. The Ministry of Labours, by its letter No. L-12012/134/98/IR(B-I) Central Government dt. 06-01-1999 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :—

"Whether Ms. Nirupama Rajoo was a workman under the meaning of Industrial Disputes Act, 1947 ? If yes, whether the action of the management of Standard Chartered Bank, New Delhi in terminating Ms. Nirupama Rajoo from service w.e.f. 01-07-1997 is just and legal, if not what relief the concerned workman is entitled to, and from what date?"

The claimant has filed claim petition. It has been stated that the petitioner was employed as workman and was allowed wages like similarly situate employees but she was not on the post of Manager, Supervisor or Officer. Her case is covered under bipartite and tripartite settlements entered into between the Bank Employees Union and the Bank. She did not enjoy the power of Supervisor. She is not an Officer as has been alleged by the management. The work and conduct of the petitioner has been satisfactory and she got appreciation letter from Ms. Shalini, Sr. Manager, Quality Services, Bangalore. She is a workman under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Her services were terminated w.e.f. 01-07-1997

without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 so she is entitled to be reinstated. She joined the service on 22-02-1995 but her services were terminated on 01-07-1997.

It was submitted from the side of the management that she was Gazetted Officer and her case is not covered under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. She was employed as Officer Customer Services and she was in Grade Band-8. The Band duty performed by the petitioner were not manual, un-skilled, skilled, technical, operaitonal or clerical in nature so her case is not covered under Section 2(s) of the Industrial Dispute Act, 1947. The termination of her services is neither illegal nor unjust. She was an Officer and she was drawing salary more than Rs. 1,600/- per month so she cannot be termed as workman.

The workman applicant has filed rejoinder. In her rejoinder she has denied most of the paras of the reply and asserted that she was not an Officer and she is a workman. The workman applicant is not turning up for a long time. She is not available for cross-examination since 2000. It was argued from the side of the management that she is in Australia for 7-8 years and she is not coming up for cross-examination so her cross-examination was closed. The workman applicant has signed on declaration according to that declaration she was appointed as an Officer Customer Services so she is not workman and the case is not covered by Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. She has not given any evidence in support of her claim statement. She is not able to get any relief as prayed for.

The reference is replied thus"—

Ms. Nirupama Rajoo was not a workman under the meaning of Industrial Disputes Act, 1947 and the action of the management of Standard Chartered Bank, New Delhi in terminating Ms. Nirupama Rajoo from the services w.e.f. 1-7-1997 is just, fair and legal. The workman applicant is not entitled to get any relief as prayed for.

The Award is given accordingly.

Date : 06-04-2005. R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1729.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० ऑल इण्डिया स्टोन कं. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद नं. 2 के पंचाट (संदर्भ संख्या 23/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/49/2002-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1729.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 23/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. All India Stone Co. and their workman, which was received by the Central Government on 13-04-2005.

[No. L-29012/49/2002-IR (M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

SHRI B. BISWAS, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act. 1947

REFERENCE NO. 23 OF 2003

PARTIES : Employers in relation to the management of the M/s. All India Stone Co. at Sindhipara and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None

On behalf of the employers : None

State : Jharkhand Industry : Stone Mine

Dated, Dhanbad, the 29th March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-29012/49/2002 IR(M) dated, the 21st February, 2003.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. All India Stone Co., Pakur in terminating the services of Muzaffar Seheikh and paying less than

the amount entitled under Sec. 25-F of I.D. Act, is legal or justified ? If not, to what relief he is entitled?"

2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared. None also appeared on behalf of the management. Record shows that consecutive notices were issued to the parties but inspite of issuance of notices they failed to turn up before this Tribunal. Gesture of the parties if is taken into consideration will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. Under the circumstances, this Tribunal also finds no ground to adjourn the case suo moto for days together only for causing appearance of the parties. Hence, the case is closed.

Accordingly a 'No dispute' Award is passed in this reference presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1730.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० तोराई माईन्स के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद नं. 2 के पंचाट (संदर्भ संख्या 30/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/52/2003-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1730.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 30/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Dhanbad No. 2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Torai Mines and their workmen, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-29011/52/2003-IR (M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

SHRI B. BISWAS, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 30 of 2004

PARTIES : Employer in relation to the management of M/s. Torai Mines, at Saharkol PO & Distt. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : None

State : Jharkhand Industry : Stone Mines

Dated, Dhanbad, the 29th March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-29011/52/200-IR(M) dated the 19th January, 2004.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s Torai Mines, Pakur in terminating the services of Sh. Hafizul Sheikh and Zakir Akli Sheikh without complying the provision of Section 25-F of I.D. Act, is legal or justified ? If not, to what relief the above workmen are entitled ?"

2. In this reference neither the concerned workman nor their authorised representative appeared. None also appeared on behalf of the management. Record shows that consecutive notices were issued to the parties but in spite of issuance of notices to them they failed to turn up before this Tribunal. Gesture of the parties if is taken into consideration will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. Under the circumstances, this Tribunal also finds no ground to adjourn the case suo moto for days together for causing appearance of the parties. Hence, the case is closed. Accordingly a 'No dispute' Award is passed in this reference presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1731.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पायराईट्स फोसफेट्स एंड केमिकल्स लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद नं. 1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 184/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29012/87/99-आई.आर.(विविध)]

बी. एम. डे विड, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1731.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 184/99) of the Central Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court, Dhanbad No. 1 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-29012/87/99-IR (M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD

In the matter of a reference U/S. 10 (1)(d)(2A) of I.D. Act.

Refelence No. 184 of 1999

AND

THEIR WORKMEN

PARTIES: Employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd. and their workmen

PRESENT:

SHRI S. PRASAD, Presiding Officer

APPEARANCES:

For the Employers	:	Shri G. Prasad, Advocate.
For the Workmen	:	None
State : Bihar		Industry : Chemical.

Dated, the 7th April, 2005

AWARD

By Order No. L-29012/87/99-IR(M) dated 17-11-1999 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-sec. (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd. in terminating the services of S/Shri Laxman Choudhary and nine others is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

2. In this case since 7-1-2003 none is apearing on behalf of the workmen for taking further step, though adjournments were given. It therefore appears that neither the concerned workmen nor the sponsoring union are interested to proceed with the case further.

In such circumstances, I render a 'No Dispute' Award in the present reference case.

S. PRASAD, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1732.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पायराईट्स फोसफेट्स एंड केमिकल्स लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद नं. 1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 7/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-29011/45/99-आई.आर.(विविध)]

बी. एम. डे विड, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1732.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 7/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad No. 1 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-29011/45/99-IR (M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD

In the matter of a reference U/S. 10 (1)(d)(2A) of I.D. Act.

Reference No. 7 of 2000.

PARTIES: Employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd.and their workmen

PRESENT:

SHRI S. PRASAD, Presiding Officer

APPEARANCES:

For the employers	:	Shri G. Prasad, Advocates.
For the workmen	:	None
State : Bihar	:	Industry : Chemicals.

Dated, the 7th April, 2005

AWARD

By Order No. L-29011/45/99/IR(M) dated 14-12-1999 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-sec. (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

> "Whether the action of the management of M/s. Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd. Amjhore, Rohtas, in terminating the services of S/Shri Rabindra Paswan, Jai Mangal Singh, Antu Ram, Shiv Kumar and Sadruddin Ansari is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

2. In this case since 6-8-2003 none is appearing on behalf of the workmen for taking further step, though adjournments were given. It is therefore appears that neither the concerned workmen nor the sponsoring union are interested to proceed with the case further.

In such circumstances, I render a 'No Dispute' Award in the present reference case.

S. PRASAD, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1733.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 48/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/282/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1733.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 48/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1 Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-0205.

[No. L-40012/282/2002-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 48 of 2002

Shri Vikramjit son of Shri Shiv Lal, House No. 692, V. Burail, Chandigarh

Applicant

Versus

The Principal General Manager, Telecom, Sector-18A, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the workman	:	Shri O. P. Singh
For the management	:	Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/282/2000/IR (DU) dated 25th of February, 2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of Department of Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Vikramjit Singh son of Shri Shiv Lal w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1734.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 282/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/225/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1734.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 282/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1 Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/225/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 282 of 2002

Tanved Ali C/o Shri R. K. Sharma, House No. 372, Sector 20.A, Chandigarh

Applicant

Versus

(1) The Chief General Manager, Telecom Punjab Circle Sector 34, Chandigarh

(2) The Principal General Manager, Telecom., Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/225/2000/IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of Chief General Manager, Telecom, Punjab Circle, Chandigarh and the Principal General Manager, Telecom, Chandigarh District, in ordering disengagement/termination of services of Shri Tanved Ali, a workman engaged through contractor M/s Gupta w.e.f. 27-2-1999 is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1735.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 285/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/229/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1735.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 285/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1 Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/229/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 285 of 2000

Raheemdeen C/o Shri R. K. Sharma House No. 372, Sector-20 A, Chandigarh

Applicant

Versus

(1) The Chief General Manager, Telecom Punjab Circle Sector 34, Chandigarh

(2) The Principal General Manager, Telecom., Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the Management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/229/2000/IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Chief General Manager, Telecom, Punjab Circle, Chandigarh and the Principal General Manager, Telecom, Chandigarh District, in ordering disengagement/termination of services of Shri Raheemdeen a workman engaged through contractor M/s Gupta w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1736.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 286/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/232/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1736.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 286/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1 Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/232/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 286 of 2000

Amrik Singh C/o Shri R. K. Sharma House No. 372, Sector-20 A, Chandigarh

Applicant

Versus

(1) The Chief General Manager, Telecom Punjab Circle Sector-34, Chandigarh

(2) The Principal General Manager, Telecom, Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/232/2000/IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Chief General Manager, Telecom, Punjab Circle, Chandigarh and the Principal

General Manager, Telecom, Chandigarh District, in ordering disengagement/termination of services of Shri Amrik Singh a workman engaged through contractor M/s Gupta w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1737.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 287/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/164/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1737.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 287/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/164/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, CHANDIGARH

Case No. I.D. 287 of 2002

Jitender Pal Gaur C/o Shri R. K. Sharma House No. 372, Sector 20.A, Chandigarh

Applicant

Versus

(1) the Chief General Manager, Telecom Punjab Circle Sector-34, Chandigarh

(2) The Principal General Manager, Telecom., Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/164/2000/IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Chief General Manager, Telecom, Punjab Circle, Chandigarh and the Principal General Manager, Telecom, Chandigarh District, in ordering disengagement/termination of services of Shri Jatinder Pal Gaur a workman engaged through contractor M/s Gaur w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1738.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 299/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/187/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1738.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 299/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. 1, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/187/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1, CHANDIGARH

Case No. I.D. 299 of 2000

Kuldip Singh son of Shri Sardara Singh Village Jhampur, P.O. Tira, Teh. Kharar, Ropar

Applicant

Versus

(1) the Chief General Manager, Telecom Punjab Circle Sector 34, Chandigarh

(2) The Principal General Manager, Telecom., Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/187/2000/IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of Department of Telecom Chandigarh in terminating the services of Shri Kuldip Singh son of Shri Sardara Singh w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR,, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1739.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 301/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/189/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1739.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 301/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/189/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 301 of 2000

Ravinder Singh son of Shri Kulwant Singh, Village Manaulli Tehsil Mohali, Ropar

Applicant

Versus

The General Manager, Telecom, Sector-18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. *vide* notification No. L-40012/189/2000/IR (DU) daated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Ravinder Singh son of Shri Kulwant Singh is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1740.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 333/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-05 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/264/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1740.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 333/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. 1, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/264/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 333 of 2000

Smt. Trishla Devi, House No. 1558, Burail Sector-45, Chandigarh. Applicant

Versus

1. The General Manager, Telecom, Sector-18, Chandigarh.

Respondent

REPRESENTATIVE:

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Govt., Ministry of Labour *vide* Notification No. L-40012/264/2000/IR (DU) daated 29th of August, 2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Chandigarh in terminating the services of Smt. Trishla Devi is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The representative of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the representative of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1741.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध

में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 373/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/304/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1741.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 373/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/304/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH

Case No. I.D. 373/2000

Jaswinder Singh son of Shri Jagdish Chand, House No. 2193/1, Pipliwala Town Manimajra, Chandigarh.

Applicant

Versus

1. The Chief General Manager, Telecom, Punjab Circle, Sector, 34, Chandigarh.

2. The Principal General Manager, Telecom, Sector-18, Chandigarh. Respondent

REPRESENTATIVE:

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G. C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Govt. Ministry of Labour *vide* notification No. L-40012/304/2000/IR (DU) dated 25th of September, 2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Department of Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Jaswinder Singh son of Shri Jadish Chand w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of A/R of workman recorded on SA. The representative of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the representative of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1742.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नं. I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/263/2001-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1742.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 10/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/263/2001-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH

Case No. I.D. 10 of 2002

Ram Naresh son of Sh. Sipahi Mazhi, House No. 879, Rajeev Colony, Sector-17, Panchkulla, (Haryana)

Applicant

Versus

The Principal General Manager, Telecom, Telephone Department, Sector-18A, Chandigarh

Respondent

REPRESENTATIVE:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G. C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Govt. *vide* notification No. L-40012/263/2001/IR (DU) dated 1st of January, 2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Department of Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Ram Naresh son of Sh. Sipahi Mazhi, Asstt. Line man w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If so to what relief the workman is entitled?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of A/R of workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objections the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR,, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1743.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. I चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 46/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/298/2001-आईआर (डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O.1743.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 46/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 1 Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/298/2001-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 46 of 2002

Prem singh House No. 18/11, Sector-42-B, Chandigarh.

Applicant

Versus

The Principal General Manager, Telecom, Telephone Deptt. Sector-18-A, Chandigarh

Respondent

REPRESENTATIVE:

For the Workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G. C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

The Central Govt. *vide* notification No. L-40012/298/2001/IR (DU) dated 5th of February, 2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Prem Singh, Peon, w.e.f. 27-2-1999 is just and legal? If so to what relief the workman is entitled?"

1. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of A/R of workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announed

18-2-2005

RAJESH KUMAR,, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1744.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 330/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/261/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1744.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 330/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-05.

[No. L-40012/261/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 330/2000

Kuldip Singh son of Amar Nath, VPO Teuuar Teh. Kharar, District Ropar

Applicant

Versus

The General Manager, Telecom, Sector, 18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. vide notification No. L-40012/261/2000/IR (DU) dated 29-8-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Kuldip Singh son of Shri Amar Nath is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as with draw on 3-3-2005. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1745.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 329/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/266/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1745.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 329/2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/266/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 329/2000

Gurvinder Singh son of Shri Gian Singh, V.P.O. Daun, Tehsil Mohali, Ropar

Applicant

Versus

The General Manager, Telecom, Sector, 18, Chandigarh.

Respondent

APPEARANCES:

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. vide notification No. L-40012/266/2000/ IR (DU) dated 29-8-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Gurinder Singh son of Shri Gian Singh is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as with drawn on 3-3-2005. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1746.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 302/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/190/2000-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1746.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 302/ 2000) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court No. I, Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/190/2000-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 302/2000

Dinesh Kumar House No. 18/12, Attawa, Sector-42-B, Chandigarh.

Applicant

Versus

The General Manager, Telecom, Sector, 18, Chandigarh.

Respondent

Appearances

For the workman : Shri O. P. Singh

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 18-2-2005

Central Govt. vide notification No. L-40012/190/2000/ IR (DU) dated 31-7-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Chandigarh in terminating the services of Shri Dinesh Kumar is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. On the request of both the parties, case taken up in Lok Adalat for settlement/disposal. Statement of the authorised representative of the workman recorded on S.A. The rep. of the workman made a statement to withdraw the present reference in Lok Adalat as the case has been settled. In view of the statement of the workman and management having no objection, the reference is returned to the Central Govt. as withdrawn on 3-3-2005. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

18-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1747.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं. I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 4/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[स० एल-40011/31/2003-आई.आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1747.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 4/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. I Chandigarh now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40011/31/2003-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 4 of 2004

Raj Kumar son of Shri Jhanda Ram Village Khichian, Gurdaspur.

.....Applicant

Versus

1. The General Manager, Telecom, BSNL, Pathankot.

2. The sub Divisional Officer (Telecom), BSNL Gurdaspur.

.....Respondent

APPEARANCES:

For the workman : None

For the management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 15-2-2005

Central Govt. vide Notification No. L-40011/31/2003/IR (DU) dated 30-12-2003 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of BSNL Gurdaspur in terminating the services of Shri Raj Kumar son of Shri Jhanda Ram instead of regularising/granting temporary status is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. Case repeatedly called. None has put appearance on belalf of the workman despite registered notice and acknowledgement also received back and he has signed the same in token of the receipt of the notice. It appears that workman is not interested to persue with the present reference. In view of the above, the present reference is returned to the Central Govt. for want of prosecution. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced

15-2-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का. आ. 1748—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. I, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 9/98) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/67/96-आईआर(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1748 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 9/98) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. I, Dhanbad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Post and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-40012/67/96-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10 (1) (d) (2A) of I.D. Act.

Reference No. 9 of 1998

Parties: Employers in relation to the management of Sr. Supdt. of Post Offices, Samastipur.

AND

Their Workman.

PRESENT:

SHRI S. PRASAD, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers : None

For the workman : Shri B. N. Singh, Advocate

State : Bihar : Industry : Postal

Dated, the 1st April, 2005

AWARD

By Order No. L-40012/67/96-IR (DU) dated 9-3-1998 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Postal Department in retrenching Sh. Jagdeo Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. In this reference case Shri B. N. Singh, Advocate appearing on behalf of the workman submits that the concerned workman is not interested to proceed with the case, as such, he prays for passing a 'No Dispute' Award in this reference case.

3. In view of the submission made by Shri B. N. Singh, Advocate, for the workman, I render a 'No Dispute' Award in the present reference case.

S. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1749.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 5/96) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/42/94-आई.आर.(डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1749.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.5/96) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 13-04-2005.

[No. L-42011/42/94-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABLOUR COURT NEW DELHI

PRESIDING OFFICER : SHRI S.S. BAL

I.D. No. 5/96

In the metter of dispute between :

The General Secretary,
C.P.W.D. Mazdoor Union,
E-26, Old Quarters, Raja Bazar,
Baba Kharak Singh Marg,
New Delhi. ....Workman

Versus

The Director General Works,
Central Public Works Department,
Nirman Bhawan,
New Delhi. ...Management

APPEARANCES : Shri B.K. Prasad for the workman.
Shri B.K. Agnihotri A/R for management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42011/42/94-IR(DU) dated 27/28-12-95 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Director General of Works, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi in not regularising the services of thirteen workmen from the date of their engagement and in the respective category as shown in the statement of claim 14-10-93 is justified? If not, to what relief the workman are entitled?"

2. Brief facts of this case as culled from the claim statement and written statement are that the workmen namely Shri Virender Kumar and others 13 in number who are claimants herein as detailed in para No. 3 were working in different categories such as Carpenter, Plumber, Sewerman, Beldar etc. from the different dates with the respondent management when they raised dispute for regularisation of their services. It is further stated that the workmen are or were performing their duties as daily rated workmen continuously from respective dates as mentioned in the claim statement directly under the control of above management and payments were made to them directly the management of C.P.W.D. All the workmen working under the management in the above said different categories were getting equal pay for equal work in the pay scale of Rs. 950-1500/750-940 and that denial of equal pay for equal work to the workmen is/was discriminatory, unlawful. The Govt. of India has sanctioned 8982 posts for regularising daily rated workmen in compliance of orders of Supreme Court of India and the management have regularised many junior persons on the time scale but workmen herein were discriminated. After the orders of the Hon'ble Supreme Court they are entitled to be regularised and paid wages in the proper time scale and it is claimed that the workmen have completed 90 days of continuous service and thus attained the status of permanent workmen and the management has been denying the facilities to the workmen and thereby the discriminating them amongst the same employments which amounts to unfair labour practice and the non regularisation of the workman is unjustified as well as illegal and management failed to regularise them despite their request. Thus the workmen claim regularisation and confirmations from the date of their initial engagement in the pay scales mentioned in that application.

3. The management contested the case by filing written statement therein that the workmen-claimants at Sl. No. 2 and 3 were working as contractors and at Sl. No. 1 4 to 13 have never been engaged as such cannot claim any relief under the I.D. Act. It is stated that claimants No. 2 and 3 were given contract for maintenance of buildings on work order basis as such provisions of I.D. Act are not applicable and there is no violation of any provisions of law nor there is any discrimination and exploitation and adoption of any unfair labour practice and the allegation of discrimination exploitation and adopting unfair labour practice against the management are denied and further workmen are not entitled to any relief claimed.

4. Written statement was followed by rejoinder denying contents of written statement and reiterating those of the claim petition and thereafter case was posted for evidence of the management initially and management examined Shri I.R. Chawla Executive Engineer as MW1

and closed its evidence on 18-4-2000 and thereafter case was posted for evidence of the workman and workmen were given number of opportunities to adduce evidence on 11-7-2000, 5-9-2000, 14-11-2000 and 9-1-2001 when the workman could not file affidavit evidence. Hence evidence of workmen was closed by my learned predecessor and thereafter case was fixed for filing arguments the management filed its written submissions and Mr. Prasad A/R for the workman sought adjournment for filing written submissions and many opportunities were granted to him and ultimately case was fixed for today for filing written arguments and oen workman were given last opportunity on 1-6-04. It appears that due to oversight case has been fixed for filing affidavit on behalf of the management on 15-9-04 when none appeared for the workmen and Shri R.K. Agnihotri Advocate appeared for the management and case was fixed for 22-02-04 for argument. I have heard Shri B.K. Prasad Ld. A/R for the workman and Shri R.K. Agnihotri Advocate A/R for the management at length and perused the record with their assistance. It is apparent that the workman evidence was closed vide order dated 9-1-2001 as mentioned above after numerous hearings.

5. Claim of the workman is that they were engaged in different categories such as Carpenter, Plumber, Sewerman, Beldar etc. etc. with the management under the control of the management and they were thus employees of the management and they are entitled to regularisation and confirmation in the pay scale of Rs. 950-1500/750-940. They are to be confirmed as mentioned in the prayer clause of claim statement while the case of the management is that the workmen were not employees of the management and only claimants No. 2 and 3 were awarded contract of maintenance *vide* work order dated and other workmen claimants at Sl. No. 1 Shri Virender Kumar and at Sl. No. 4 to 13 in para 3 of the claim statement were working under the said contractor Peru Mal. The questions which need determination in this case is whether the workmen were employees of the management and whether they were entitled to regularisation and whether the action of the management is legal, justified or not and the onus to prove the questions lies on workman, it was duty of the workmen to prove that they were employees of the respondent and that they were entitled to regularisation/confirmations in the respective scale claimed. All the claimants have failed to prove the same and in the absence of any evidence on record I have no option but to hold that management is not under any obligation to regularise or confirm the claimant as claimed.

6. In view of the above discussions I am of the opinion that the action of the respondent the Director General of Works CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi in not regularising the services of thirteen workmen from the date of their engagement in respective categories as shown in the statement of claim dated 14-10-93 is justified. The reference is answered and award is passed accordingly.

DATED: 30-03-2005

S. S. BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1750.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कमांडिंग ऑफिसर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 159/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/9/99-आई.आर.(डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New-Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1750.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 159/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Commanding Officer and their workman, which was received by the Central Government on 13-4-2005.

[No. L-14012/9/99-IR (DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABLOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case No. I.D. 159 of 1999

Shri Paramjit Sigh son of
Shri Jagir Singh, Gaddaria (Shepherd),
V.P.O. Ranbirpura, Teh. &
District Patiala. Applicant

Versus

The Officer Commanding,
340 (Coy) A.S.C., C/o 56 A.P.O.

Respondent

APPEARANCES:

For the workman : None

For the management : Shri G. C. Babbar

AWARD

Passed on 14-3-2005

Central Govt. vide notification No. L-14012/9/99/IR (DU) dated 21-7-1999 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Commanding Officer, 340 COY, ASC (SUP) Type B, C/o 56 APO in terminating the services of Shri Paramjit Singh son

of Shri Jagir Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Case repeatedly called. None has put up appearance on behalf of the workman despite notice. It appears that workman is not interested to persue with the present reference. In view of the above and in view of the submission of the advocate for the management, the present reference is returned to the Central Govt. for want of prosecution. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced 14-3-2005 RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1751.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-2 के पंचाट (संदर्भ संख्या 90/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/2/98-आई.आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1751.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 90/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-2005.

[No. L-20012/2/98-IR (C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

B. Biswas, Presiding Officer

In the matter of Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 90/1999

PARTIES : Employer in relation to the management of Pindra Colliery of M/s C.C.L. and their Workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen : None

On behalf of the employer : Sri S. Jamal & Sri Sanjay Kr. Personnel Officers.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, 30th March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D.Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/2/98(CM-I) dated 29-1-1999.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Pindra Colliery of CCL, PO Topa, Distt. Hazaribagh in terminating Sri Suresh Munda, Ex-PR Worker from the services of CCL w.e.f. 8-9-94 is justified?"

2. The case of the concerned workman according to written statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :

The sponsoring union submitted that the concerned workman was terminated from his service all of a sudden without any notice and also without following any procedure of law. They further alleged that Project Officer was neither the appointing authority nor the Disciplinary Authority . Therefore the impugned order of termination is invalid and inoperative in the eye of law.

They submitted that application on account of illness and consequent availing of leave on medical ground does not constitute any misconduct and for which termination of service on that ground is absolutely illegal. Moreover neither any charge sheet was issued to the concerned workman nor any enquiry was held against him. No show-cause notice was also issued nor served upon the concerned workman and also no opportunity was given to him for making any submission on his part. They submitted further that the misconduct which the concerned workman committed on the ground of alleged absentism is not so serious an offence which could invite termination of his service. Accordingly, they alleged that management illegally arbtirarily and violating the principle of natural justice terminated the service of the concerned workman. They submitted that as the said order of termination was illegal the same should be required to be set aside and the concerned workman should be reinstated in service from the date of his termination with full back wages and other consequential relief.

3. Management on the contrary after filing written statement-cum-rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union assorted in the written statement.

They submitted that the concerned workman developed the habit of absenting from his duties unauthorisedly as per his own wishes without any

justifiable cause. They submitted that in the year 1992 the concerned workman remained himself absent from duty for 10 months and 15 days. Again w.e.f. 25-11-93 he started remaining himself absent from duty unauthorisedly and for which a charge sheet dated 29-4-94 was issued to him for committing misconduct on the ground of unauthorised absence as per provision of Standing Order applicable to the establishment. They submitted that concerned workman did not consider nacessary to submit any reply to the said charge sheet issued to him. As a result as per order of the Disciplinary Authority, Mr. R.R. Prasad, Senior Personnel Officer, Pindra Colliery was appointed as Enqairy Officer. After taking charge of the Enquiry Officer the said officer not only issued notice by registered post but also displayed the notice in the notice board for causing his appearance. As the concerned workman could not be traced out and as he deliberately avoided to attend the enquiry departmental enquiry was held against him by the Enquiry Officer exparte. The Enquiry Officer after completing enquiry submitted his report holding the concerned workman guilty to the charges brought against him.

They submitted that the enquiry Officer conducted domestic enquiry against the concerned workman, fairly properly and in accordance with the principle of natural justice. They also submitted that the Disciplinary Authority considering the report submitted by the Enquiry Officer and also considering all other aspects terminated him from service w.e.f. 8-9-94 and in doing so they neither committed any illegality nor took any arbitrary decision violating the principle of natural justice.

Accordingly, they submitted prayer to reject the claim of the sponsoring union for reinstatment of the concerned workman to his service.

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Pindra Colliery of CCL, PO Topa, Distt. Hazaribagh in terminating Sri Suresh Munda, Ex-PR Worker from the services of CCL w.e.f. 8-9-94 is justified?"

5. FINDING WITH REASONS

It transpires from the record that before taking up hearing of this case on merit it was taken into consideration if domestic enquiry conducted against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principle of natural justice.

It transpires from the record that the said preliminary issue on the point of domestic enquiry was disposed of in favour of the management vide order No. 19 dated 13-1-2005.

Now the point for consideration is whether the management have been able to substantiate the charge brought against the concerned workman and if so whether the concerned workman is entitled to get any relief in view of provision laid down u/s 11-A of the Industrial Dispute Act.

The charge sheet during evidence of M.W.I was marked as Exht M/z. From the charge sheet it transpires that the concerned workman was found absent from duty w.e.f. 25-11-93 without prior permission and sufficient reasons and as said unauthorised absent from duty constituted misconduct he was asked to submit his explanation why disciplinary action would not be taken against him.

It transpires from the record that the concerned workman did not submit any reply to the charge sheet issued against him. It further transpires that as the concerned workman did not submit any reply to the charge sheet Disciplinary Authority decided to hold domestic enquiry against him and accordingly appointed Mr. R.R. Prasad, Senior Personnel Manager as Enquiry Officer. It is seen from the evidence of M.W.I that after taking charge of the hearing of enquiry proceeding he not only issued notice to the concerned workman by registered post at his home address but also displayed the notice in the notice board. M.W.I during his evidence disclosed that as the concerned workman did not consider necessary to appear he took up hearing of the enquiry proceeding exparte and after completing the said enquiry submitted his report which during his evidence was marked as Exhibit M/9.

From the report it reveals that the concerned workman was in the habit of remaining himself absent from duty. It reveals from the report that in the year 1992 the concerned workman was on unauthorised absent continuously for a period of 11 months. However, he was allowed to resume his duty after a departmental enquiry and three S.P.R. were stopped as a token of punishment by the Area Management. The report shows that the concerned workman got his appointment on 30-3-91 and immediately after getting his appointment he grew up habit of remaining himself absent from duty. The report further shows that during 1993 the concerned workman worked for only 30 days in all and thereafter again started absenting from duty unauthorisedly. It therefore transpires that since his joining in the service on 30-3-91 his conduct appears to be very bad in the matter of attendance of his duties. During this short spell of service he was charge sheeted for committing misconducts on the ground of absentism and his three SPRA were stopped. It is seen that management allowed him to join his duty with a view to give him opportunity to mend his character but again ignoring the opportunity given to him he started remaining himself absent from duty and for which second charge sheet was issued to him.

It is the contention of the sponsoring union that the concerned workman went on authorised leave on medical ground for his treatment and for which they alleged that management illegally and arbitrarily issued charge sheet to him which is not tenable in the eye of law. In course of hearing inspite of getting ample opportunity the sponsoring union did not consider necessary to produce single scrap of medical paper in support of his treatment. On the contrary it is seen that he avoided to face domestic enquiry. After careful consideration of all the facts and circumstances I hold that the management in course of hearing have been able to substantiate the charge brought against him.

It transpires that the management is missed the concerned workman from his service considering the enquiry report submitted by the enquiry officer and also considering all other material aspects. The letter of termination during evidence of M.W.1 was marked as Exhibit M-10.

Now the point for consideration is if the concerned workman is entitled to get any relief U/s 11-A if the Industrial Dispute Act. Sec. II-A speaks as follows :

"Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may be its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require."

Therefore, according to the provision of this Section it is to be taken into consideration if the punishment imposed on the concerned workman was justified proportionate to the misconduct committed by him.

It transpires from the enquiry report that the concerned workman being a fresh appointee get his appointment under the management on 30-3-91. First charge sheet was issued to him for his unauthorised absence from duty w.e.f. 9-10-92. During that time he remained on unauthorised absent for a period of eleven months. Domestic enquiry was also held against him and as he was found guilty as punishment three S.P.R.A. were stopped though he was allowed to join his duty. It is seen that inspite of the said punishment he did not mend his habit and again started remaining himself absent from duty unauthorisedly.

In the instant case he avoided to face domestic enquiry and subsequently took the plea of his ailment which was the cause of his absent from duty. He also took the plea that for his treatment he went on authorised leave on medical ground but during hearing before this Tribunal he absolutely failed to justify the claim. Therefore, there is sufficient reason to believe that to get rid of the charge of misconduct which was brought against him by the management for his unauthorised absence he took such plea.

It is the contention of the sponsoring union that the management illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice terminated the concerned workman from his service but inspite of claiming so they have failed to justify the reasons in support of the allegation brought against the management.

On the contrary it has been exposed that within very short span of service the concerned workman was charge sheeted on two consecutive occasions for committing misconduct on the allegation of his remaining absent from duty unauthorisedly. It transpires clearly that he was awarded minor punishment for committing misconduct on the first occasion with expectation of mending his conduct in future. Instead of showing minimum diligence to his work as a duty bound workman he again started remaining himself absent from duty without taking any permission or giving any intimation to the management. There is sufficient reason to believe that he did not consider to maintain discipline in the place of his work and for which management was deprived to get any service from him. This act of the concerned workman appears to be highly degogatory to maintain disciple in the industry as his such activity not only hampered production but also indulged other workmen to follow his course. If all these aspects are considered carefully there is no scope to say that the termination order issued by the management was either injustified or was dispropotionate to the misconduct committed by him.

In view of the facts & circumstances discussed above, I therefore, hold that the concerned workman is not entitled to get any relief U/s II-A of the I.D. Act.

In the result the following award is rendered :

"That the action of the management of Pindra Colliery of CCL, PO Topa Distt. Hazaribagh in terminating Sri Suresh Munda, Ex-PR Worker from the services of CCL w.e.f. 8-9-94 was justified. Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief."

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का०आ० 1752.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 290/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/508/2000-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1752.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 290/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 12-4-2005.

[No. L-20012/508/2000-IR(C-I)]

S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947.

Reference No. 290/2001

PARTIES: Employer in relation to the management of Bhalgora Project under Kustore Area of M/s. BCCL and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workman : Ld. Advocate, Mr. H. Nath

On behalf of the management : Ld. Advocate, Mr. K.N. Singh

State: Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, 18th March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/508/2000-IR(C-I) dated, the 29th October, 2001.

SCHEDULE

"Whether the action of management of M/s BCCL Kustore Area for not paying the wages of Sundays, Holidays and overtime duty to Sri Ram Kishun Gupta, Shiv Kumar Prasad, Samsuddin Mian, Ram Kishun Yadav, Raka Paswan and Jagdish Yadav is justified, proper and legal ? If not to what relief is the workmen entitled ?"

2. The case of the concerned workmen according to written statement submitted by the sponsoring union on their behalf in brief is as follows :

The sponsoring union submitted that the concerned workmen are permanent fitters posted at Kustore Area under the management. They submitted that during the year 1997 being directed by the management the concerned workmen had to perform duties during Sundays and holidays but for performance of said duties management did not pay any wages which they are entitled to get. They disclosed that the concerned workmen submitted several representations to the management for payment of wages for the duties which they performed during Sundays and holidays but to no effect. As a result they raised an Industrial Dispute through sponsoring union before ALC(C) Dhanbad for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication.

Accordingly they submitted prayer to pass award directing the management to pay wages for the work done by the concerned workmen during Sundays and holidays.

Management on the contrary after filing written statement-cum-rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the written statement submitted on behalf of the concerned workmen.

They submitted that the concerned workmen are the employees of Kustore Area and posted in the Civil Department. They disclosed that Sunday is the week day of rest in Kustore Area and on Sundays and holidays only those employees are deputed to work whose services are essentially required. The concerned workmen were employed on some Sundays and holidays and for which they have already paid. Accordingly, they submitted that

the demand of the union is baseless and false and for which their claim is liable to be rejected :

3. **Points to be decided**

"Whether the action of management of M/s. BCCL Kustore Area for not paying the wages of Sundays, Holidays and over time duty to Sri Ram Kishun Gupta, Shiv Kumar Prasad, Samsuddin Mian, Ram Kishun Yadav, Raka Paswan and Jagdish Yadav is justIfied, proper and legal? If not, to what relief is the workmen entitled?"

4. **Finding with reasons**

It transpires from the record that neither the sponsoring union nor the management adduced any evidence with a view to substantiate their respective claim.

Accordingly, considering the facts disclosed in the pleadings of both sides let it be considered if the claim of the sponsoring union stands on cogent footing or not.

Considering the pleadings of both sides there is no dispute to hold that the concerned workmen are the permanent employees of Kustore Area.

It is the claim of the sponsoring union that in the year 1999 under directions of the management the concerned workmen performed their duties during Sundays and holidays but inspite of performing duties management refused to pay wages for the same. On the contrary, management admitting the fact of deployment of the concerned workmen to work during Sundays and holidays as their services were required essentially disclosed that they have paid wages to them for performance of said duties.

No cogent evidence is forth coming on the part of the sponsoring union refutting such claim of the management. Nature of the claim made by the sponsoring union speaks clearly that onus absolutely rests on them to establish that management did not pay any wages for the duties performed by the concerned workmen during Sundays and holidays. I find no hesitation to say that inspite of getting ample opportunity the sponsoring union have failed to substantiate their claim.

It is to be borne into mind that facts disclosed in the pleading can not be considered as substantive piece of evidence without its corroboration by cogent evidence. It is seen that the sponsoring union though got sufficient opportunity did not consider necessary to adduce any cogent evidence in support of their claim. In the circumstances just relying on the facts disclosed in the written statement I find no scope to uphold their contention. I find no hesitation to say that for the latches of their won the sponsoring union has lamentably failed to justify their claim and for which they are not entitled to get any relief.

In the result the following award is rendered :

"That the action of management of M/s. BCCL Kustore Area for not paying the wages of Sundays, Holidays and over time duty to Sri Ram Kishun Gupta, Shiv Kumar Prasad, Samsuddin Mian, Ram Kishun Yadav, Raka Paswan and Jagdish Yadav is justified, proper and legal. Consequently, the concerned workmen are not entitled to get any relief."

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का०आ० 1753.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 121/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/174/2003-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1753.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 121/2003) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-2005.

[No. L-20012/174/2003-IR(C-1)]

S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

(LOK ADALAT)

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 121 of 2003

PARTIES : Employer in relation to the management of C.V. Area of M/s. BCCL and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workman : Mr. N.G. Arun, Authorised Representative

On behalf of the employers : Mr. A. K. Sinha, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, 21st March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/174/2003 IR(C-I), dated, the 10th November, 2003.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Daahibari Colliery of M/s. BCCL in not regularising Sri Dhiren Chand Mahato as Magazine Clerk is fair and justified, If not, to what relief is the concerned workmen entitled and from what date?"

2. In response to appeal made by this Tribunal for disposing of this case through Lok Adalat management and representative of the workman filed a settlement petition for settling the dispute through Lok Adalat as per terms and conditions stated therein. Perused the petition of settlement. Terms and conditions incorporated in the said settlement petition appears to be fair, proper and in accordance with the principle of natural justice. Accordingly the same is accepted. In view of the facts and circumstances discussed above instant case is disposed through Lok Adalat as per settlement and an award is passed in terms of settlement entered into between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

FORM-H.

Memorandum of Settlement.

Short recital of the Case.

An I.D was raised by the secretary, RCMS Union on the matter of regularisation of Shri Dhiren Chandra Mahato, Explosives Carrier, Dahibari Colliery in clerical grade baing the job of Clerk performing by him in Magazine section, which ended in failure. The matter was referred to the Tribunal by the Ministry of Labour vide Reference No. 121 of 2003. Mean while the matter was also raised by the Union at D(p)'s level on 11-7-2003 and the Hqrs., after due discussion, agreed for giving him the post of Dumpman/Tripman in Clerical Grade III. Accordingly an approval has been received from the Hqrs., vide letter No. BCCL/PER/IR/04/2581 dated. 5/9-3-2004 of the G.M. (P&IR), wherein it has been communicated that the Competent Authority has approved for regularisation of Shri Dhiren Chandra Mahato, Explosives Carrier in the post of Tripman/Dumpman in Clerical Grade-III without any pay protection.

Accordingly, a settlement between the Union and the management is arrived at as under :—

1. That, Sri Dhiren Chandra Mahato, Explosives Carrier, Dahibari Colliery will be regularised as Dumpman/Tripman in Clerical Grade III subject to verification of his educational qualification and if the same is not found genuine, he will be reverted back to his original job of Explosives Carrier.

2. That, he will be posted at D.B.O.C.P.

3. That, he will not be given any pay protection, nor he will claim for any pay protection in future.

4. That, the above settlement will resolve the dispute in to at all level.

Representing Management.	Representing Party.
(1) Sri Baldev Bhattacharya, Chief General Manager, Chanch Victoria Area.	(1) Sri Chandan Singh. Area Secretary, RCMS, C/V Area,
(2) Sri A. Prabhakar, Dy. Chief Personnel Manager, Chanch Victoria Area.	(2) Sri Dhiren Chandra Mahato. (Workman concerned)

Witness : (A. Prasanna) Personnel Manager, Chanch Victoria Area.

Dated. April, 2004.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का०आ० 1754.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टिस्को के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 28/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/148/2003-आई.आर.(सी-1)]

एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1754.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 28/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tisco and their workman, which was received by the Central Government on 12-04-2005.

[No. L-20012/148/2003-IR(C-I)]

S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

B. BISWAS, Presiding Officer.

In the matter of an Industria Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE No. 28 OF 2004

PARTIES: Employers in relation to the management of Tisco and their workman

APPEARANCES:

On behalf of the workmen : None

On behalf of the employers : Mr. D.K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal Mine

Dated, Dhanbad, the 29th March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/148/2003 IR(C-I) dated, the 14th January, 2004.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Tisco in frequently changing the post and category of the workmen S/Sh. Suresh Singh and Aloke Chakraborty is just and fair? If not, to what relief are the said workmen entitled and from what date?"

2. In this reference neither the concerned workmen nor their representative appeared. Management, however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record that consecutive notices were issued to the workman side/sponsoring union but in spite of issuance of notices they failed to turn up before this Tribunal. Gesture of the workmen if is taken into consideration it will expose clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. Under such circumstances, this Tribunal also finds no ground to adjourn the case **suo moto** for days together only for cau- sing appearance of the workmen. Hence, the case is closed. Accordingly a 'No dispute' Award is passed in this reference presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का०आ० 1755.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को. लि., के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 62/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/110/2002-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1755.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 62/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-2005.

[No. L-20012/110/2002-IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT:

B. BISWAS, Presiding Officer.

In the matter of Industrial Dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 62/2002

PARTIES: Employer in relation to the management of Sijua Area of BCCL and their workman.

APPEARANCES:

On behalf of the workman : Mr. P.R. Shukla

On behalf of the employer : Mr. D.K. Verma

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, 21st March, 2005.

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No.L-20012/110/2002 IR(C-I) dated, 26-7-2002.

SCHEDULE

"Whether the demand of Janta Khan Mazdoor Sangh for regularisation of Suresh Dusadh as Dhowra Supervisor is just and proper ? If so, to what relief the workman is entitled and from which date ?"

2. The case of the concerned workman according to written statement submitted by the sponsoring union on his behalf in brief is as follows :

The sponsoring union submitted that the concerned workman is a permanent employee of Loyabad Coke Plant under Sijua Area. They submitted that management by order No. PD/Office Order/98 dated 7-5-98 authorised the concerned workman to supervise the works of sweepers of the area. They disclosed that though the said assignment was temporary he was allowed to continue the said assignment job continuously for more than six months which entitled him to get permanent status as per Standing Order applicable to the workman of the management. Accordingly, he submitted representation to the management for his regularisation as Dhowra Supervisor. They alleged that the management did not consider his such prayer taking the plea that he had not the requisite qualification for his regularisation as Dhowra Supervisor. Under this circumstances he raised an Industrial Dispute through his sponsoring union for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. The sponsoring union accordingly submitted prayer to pass award directing the management to regularise the concerned workman as Dhowra Supervisor for the date of his authorisation to work in the said post.

3. Management on the contrary after filing written statement-cum-rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the written statement submitted on behalf of the concerned workman.

The management submitted that the concerned workman is an Electrician and working as an Electrician in time rated category VI. They submitted that on temporary measure he was deployed to lookafter sanitation work of the Unit.

They submitted that Director Personnel of M/s. BCCL vide letter No. BCCL/GM/92/7867-18117 dt. 29-6-92/11-7-92 imposed strict ban on diverison of time rated and piece rated worker in the electrical job without express permission of the Head Quarter. It was also directed by the said order that the person so diverted, if any, should be reverted back to their original post.

They disclosed that the concerned workman is under Electrical and Mechanical Cadre and cadre of a workman can not be changed without express permission of the cadre controlling authority. They alleged that the sponsoring union demanded regularisation of the workman concerned in clerical cadre in utter violation of the cadre. Moreover, they submitted that the concerned workman does not possess requisite qualification as per cadre scheme for clerical cadre. Apart from this fact they disclosed that promotion/regularisation in clerical cadre is being made only on the recommendation of the Departmental Promotion Commttee, if vacancy exists.

They submitted that temporary deployment of a worker in a particular post does not create legal right to the workman to get regularisation in the said post ignoring the cadre scheme and qualification for the said post.

In view of the fact and circumstances stated above management submitted that the demand of the sponsoring union to regularise the concerned workman to that post of Dhowra Supervisor is a state demand and for which the same is liable to be rejected.

4. **POINTS TO BE DECIDED**

"Whether the demand of Janta Khan Mazdoor Sangh for regularisation of Suresh Dusadh as Dhowra Supervisor is just and proper ? If so, to what relief the workman is entitled and from which date ?"

5. **FINDING WITH REASONS**

It transpires from the record that inspite of giving several opportunities as the sponsoring union as well as the concerned workman ignored to take any step with a

view to substantiate the claim the instant case was taken up for ex parte hearing.

In course of exparte hearing management with a view to substantiate their claim examined one witness as MW I

M.W. I who is senior legal Inspector posted at Sijua Area during his evidence disclosed that the concerned workman is a time rated Electrician posted at Loyabad Coke Plant. He disclosed that promotion of Electrician is considered under Electrical and Mechanical Cadre. On the contrary this witness disclosed that the post of Dhowra Supervisor comes under clerical cadre and minimum qualification is matriculate. He submitted that the concerned workman never submitted any certificate to show that he was matriculate. It further transpires from his evidence that the post of electrician while comes under time rated category the post of clerk comes under monthly rated category. Concerned workman was an electrician of time rated category V and subsequently he was provided with the benefit of category VI under S.L.U. Disclosing all these facts this witness submit that the concerned workman in view of his prayer is not entitled to get any relief.

Considering the evidence of M.W.I and considering the facts disclosed in the written statement submitted by the sponsoring union on his berhalf there is no dispute to hold that the concerned workman by designation is an electrician and posted at Loyabad Coke Plant. Considering the facts and circumstances it transpires that for a temporary period by order of the Local management the concerned workman was allowed to work as Dhowra Supervisor.

It is the claim of the sponsoring union that though the concerned workman was allowed temporarily to work as Dhowra Supervisor he in that post worked continuously for more than six months and thereby accrued his eligibility to get his regularisation as Dhowra Supervisor. On the contrary from the contention of the management it has been exposed that the post of electrician is a time rated category and their promotion are considered as per Electrical and Mechanical Cadre which is absolutely different from clerical cadre. They submitted that to get posting promotion in clerical grade minimum qualification which is required is Matriculate and a workman is selected for the said post by way of interview/test while subsequent promotion is given on the basis of recommendations of Departmental Promotion Committee. Moreover the post of electrician comes under time category while the post of clerk comes on monthly basis under clerical cadre. Therefore, switching over of a workman from category post to clerical grade directly without any reocommendation by D.P.C. can not be acceded to as the Head Quarter by issuing circular have strictly prohibited the same.

It is further contention of the management that the concerned workman failed to show that he is matriculate. Therefore, from the very outset he is not eligible to claim his regularisation as Dhowra Supervisor is not maintainable in the eye of law. Moreover, his such demand has contravened the provision as laid down in J.B.C.C.I Circular in the matter of selection in clerical grade.

During hearing the sponsoring union inspite of getting ample scope have failed to produce any document to show that the concerned workman was Matriculate. Therefore, from the very outset he is to be considered not eligible to get his promotion in clerical grade until and unles any contrary is proved.

On the contrary it transpires clearly that he got his appointment as Electrician and posted in category V. Therefore, he was given with the benefits of category VI under SLU. It was the contention of the management that all through the concerned workman as Electrician drew his wages. They disclosed that absolutely as on temporary measure he was asked to work as Dhowra Supervisor automatically he is not eligible to get his regularisation as Dhowra Supervisor without having minimum qualification and also without the recommendation of DPC.

Therefore, onus absolutely was with the sponsoring union to show that without having requisite qualification and also without having his name recommended by D.P.C. he was very much entitled to get his regularisation as Dhowra Supervisor. It is seen that although as electrician he drew his wages as per category offered to him. No increminating material is forthcoming to show that during the said temporary period he was paid difference of wages for the duties performed by him as Dhowra Supervisor.

The order issued was absolutely temporary in nature which was subsequently recalled in view of order issued by the Head Quarter. Therefore, just on the basis of the order which was absolutely temporary in nature which was subsequently recalled, I think, did not accrue any right for his claiming the post of Dhowra Supervisor.

According in view of the facts & circumstances discussed above I hold that the sponsoring union have lamentably failed to substantiate their claim and for which the concerned workman is not eligible to get his posting as Dhowra Supervisor.

In the result the following award is rendered :

"That the demand of Janta Khan Mazdoor Sangh for regularisation of Suresh Dusadh as Dhowra Supervisor is not just and proper. Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief?".

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1756.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पवन हंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नई दिल्ली I, के पंचाट (संदर्भ संख्या 223/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/34/99-आई.आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1756.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 223/99) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court New Delhi-1 now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Pawan Hans and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-05.

[No. L-11012/34/99-IR(C-1)]

S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NEW DELHI

Shri S. S. Bal : PRESIDING OFFICER

I. D. NO. 223/99

In the matter of dispute between :

Sh. P. Saksena S/o Late Sh. Ram Prasad Saksena,
R/o B-104, Pocket B, Mayur Vihar,
Phase-II, Delhi-110091. .....Workman

Versus

The General Manager,
(Personal & H.R.D.),
Pawan Hans, Safdarjung Airport,
New Delhi-110001. ....Management

APPEARANCES:

Workman in person.

Shri J. Buther for manageinent.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour *vide* its Order No.L-11012/34/99-IR(C-I) dated 10-11-99 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the action of the Management of Pawan Hans in dismissing Shri P. Saksena, Sr. Aircraft Maintenance Engineer w.e.f. 30-11-90 is proper, legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The claim of the workman is that he was dismissed on 30-11-90 over on technical order (10-7-90) to which he had certain objections. The technical order was issued a fresh on 27-9-90 and that his dismissal caused dishonour and deprivation and injustice and hence he is entitled to Rs.4,00,000 as compensation.

3. The management contested the claim of the workman/claimant by filing written statement raising legal pleas by way of preliminary objections such as that the claimant is not a workman as defined in Section 2(s) of the I.D. Act, he being a Senior Aircraft Maintenance Engineer performed managerial and supervisory duties and as such claim is not maintainable; that this court has also no jurisdiction to entertain the claim and the dispute raised is also not an industrial dispute as defined in Section 2(k) of the I.D. Act and this court has got no jurisdiction. Even the reference is bad in law and reference is invalid and made without due application of mind by the appropriate authority and that he (claimant) has even failed to assial dismissal order dated 28/30-11-90 and is not legally entitled to compensation as claimed. The claim is vague and lacks in material particulars, and is frivolous vexations, unjustified and devoid of any merit & the claim also suffers from latches as there is delay and latches on the part of the claimant in initiating the proceedings. On merits it is submitted that the claimant was dismissed from service for proved misconduct *vide* order dated 29/30-11-90 at the time of dismissal claimant was holding senior post of Executive Level which is equivalent to Manager in the management company. His pay scale was 2050-80-2450-100-2750. As a Senior Aircraft Maintenance Engineer his duties were to assign, direct, control and supervise the work of Engineers/Technicians. He was to act independently and manage the problems. He was to inspect aircraft and also to impart training. He was to advise management on Technical aspects and manage the affairs concerning his department. Claimant was charge-sheeted vide charge-sheet dated 16-8-90 for committing misconduct. Enquiry was conducted and charges were proved in enquiry. Reasonable opportunities were given to the claimant and principles of Natural Justice were complied with therein and thereafter the punishment order aforesaid was passed. Claimant preferred an appeal which was decided *vide* order dated 20-4-92. In view of the above pleas the claim is sought to be dismissed.

4. Workman filed rejoinder wherein it was stated that his entry to Pawan Hans as Senior A.M.E was on grounds of current A.M.E. License which he had earned in Indian Airlines and performed duties of workman *vide*, S.O. 261 dated 15-3-58, Ministry of Labour and Employment and he filed copy of notification dated 15th March, 58 and in Pawan Hans he has enumerated his duties i.a Helicopter trade training under workman (b) Quality Control Office duties which were termed as A.M.E. experience, under the training establishment (Aviation Training School) as Librarian, incharge of training manuals duties being technical, clerical manual were workman duties and he issued instructions and performed duties of librarian and other instructional duties pertaining to tradesman. He was not an executive and as such his duties were not of an executive.

5. Thereafter, evidence was recorded. Workman was examined as WW1 while management examined Shri Sanjiv Aggarwal, Secretary to the respondent management as

MW1 and evidence was closed. Arguments were heard. Workman addressed arguments himself while Shri. J. Buther A/R for the management addressed arguments on behalf of the management.

6. I have bestowed my thoughtful considerations on the contentions raised on both sides and perused the record meticulously.

7. The case of the workman appears to be that he was dismissed on 30--11-90 vide order dated 30-11-90 and dismissal caused dishonour and injustice and that he as such claims Rs.4,00,000/- by way of compensation and prayed for passing an award in his favour. The following question arise for determination in this case:

1) Whether the claimant Sh. P. Saxena is the workman ?

2) Whether some industrial dispute has arisen ?

3) Whether the claimant is entitled to compensation as claimed ?

4) Whether the reference is bad in law ?

5) Whether the enquiry conducted against the workman before passing the punitive order of dismissal dated 30-11-90 was fair ?

8. I will treat issue No. 5 i.e. "whether the enquiry conduct against the workman before passing the punitive order of dismissal dated 30-11-90 was fair ?" as preliminary issue and take up the same for determinations first.

9. The workman has stated that he has been dismissed vide order dated 30-11-90 and claims compensation of Rs. 4,00,000/- but not claimed reinstatement. On the contrary management has claimed that the claimant workman was Charge-sheeted & was dismissed for misconduct as he refused to obey the orders dated 10-7-90 to go to Porbandar which amounted to misconduct. Ultimately enquiry was conducted and the impugned order giving punitive dismissal order dated 30-11-90 was passed after giving due opportunity to the workman. He was given fair opportunity during the course of enquiry. A look on the cross-examination of workman who was examined as WW1 shows that he was offered dismissal order by hand but he did not accept the same which was sent to him and received by him after a week through post. He also admitted that he was charge-sheeted on 16-8-90 and he did not file any reply to the charge-sheet and a departmental enquiry was conducted against him. He participated during the enquiry from the beginning till end and the enquiry officer was Shri. Patan V. K. Dhir. Dismissal order was passed by Shri G. P. Srivastava, General Manager Personnel and H.R.D. He filed an appeal against order of dismissal which was dismissed. He also filed review application which was also dismissed. He was employed in service on the post E-IV but he did not know the meaning of the word E-IV. He also stated that he never assigned any work to his subordinate. He supervised any work. He worked as Librarian in Aviation Training School which was his main job and he was not posted on any managerial post. He claimed himself to be a workman. From the above statement of the claimant in his cross-examination it is apparent that the workman was charge-sheeted and an enquiry was conducted against the he and he participated in the enquiry from start to finish. This shows that he has been awarded complete and fair opportunity during the course of the enquiry before the impugned order of dismissal was passed. The impugned order in my view does not appear to be bad in law and such the same is legal & Justified as the same has been passed after conducting proper enquiry as per procedure & giving complete opportunity of being heard to the workman.

10. The workman has claimed compensation of Rs. 4 lakhs. In my view the workman is not entitled to any compensation or compensation as claimed as the impugned order is legal & justified and passed after following due procedure of law in a proper enquiry conducted against the workman as mentioned above.

S.S.BAL Presiding Officer

Dated : 29-03-2005

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1757.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रॉयल नेपाल एअरलाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय कोलकाता के पंचाट (संदर्भ संख्या 03/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-04-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/36/2004-आई.आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1757.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No.03/2005) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court Kolkata now as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Royal Nepal Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 12-04-2005.

[No. L-11012/36/2004-IR (C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT KOLKATA

REFERENCE No. 03 OF 2005

PARTIES : Employers in relation to the management of Royal Nepal Airlines

AND

Their Workman

PRESENT :

MR. JUSTICE HRISHIKESH BANERJI.
Presiding Officer

APPEARANCE:

On behalf of the Management : Mrs. M. Sengupta, Offiicer-in-charge, Kolkata of Royal Nepal Airlines.

On behalf of the Workmen : Mr. R. Bhattacherya, Secretary of the Union.

State : West Bengal. Industry : Airlines.

Dated : 31-03-2005

AWARD

By Order No. L-11012/36/2004-IR (CM-1) dated 15-12-2004 the Central Government in exercise of its powers under Section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Royal Nepal Airlines in terminating the services of 11 workmen (as per list) is just, fair and legal ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

List of Workmen

1. Bidyut Dhar.
2. Montu Dey.
3. Tapan Das.
4. Dipan Das.
5. Rathin Bhattacharya.
6. Ashoke Das.
7. Narayan Kundu.
8. Dipak Das.
9. Bishu Dey.
10. Nandadulal Roy.
11. Biswanath Patra.

2. When the case is taken up today at the request of the parties, representative of the workmen files an application stating that the matter has been settled between the parties amicably and it is prayed that the matter be disposed of by passing a "No Dispute" Award. All the concerned workmen have also signed the application. Representative of the management has no objection.

3. Since the union which espoused the present reference states that the dispute under reference has been settled and prays for disposal of the reference by a "No Dispute" Award, I dispose of the present reference by passing a "No Dispute" Award. The application filed by the union in this regard is made part of the Award as Annexure—A.

HRISHIKESH BANERJI, Presiding Officer

Dated, Kolkata.

The 31st March, 2005.

ANNEXURE—A

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KOLKATA

20B, ABDUL HAMID STREET, 1ST FLOOR,

KOLKATA-700 069

In the matter of :

Reference No. 3 of 2005

-And-

In the matter of :

Royal Nepal Airlines

-And-

Their Workman

-And-

In the matter of :

(1) Sri Ashoke Das of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081

(2) Sri Bidyut Dhar of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081

(3) Sri Dipak Das of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081;

(4) Sri Narayan Kundu of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081

(5) Sri Nandadulal Roy of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081;

(6) Sri Rathin Bhattacharjee of 191, Kabi Nabin Sen Road, Dum Dum, Kazi Para, Kolkata-700 028

(7) Sri Bishu Dey of 1/5, Raghunathpur, P.O. Arjunpur, Uttarmath, P. S. Rajarhat, Kolkata-700 059

(8) Sri Montu Dey of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081

(9) Sri Bishwanath Patra, son of late Haru Patra of AC-24, Deshbandhunagar (Nort), Payarabagan, Arjunpur, Tegharia, Kolkata-700 059;

(10) Smt. Juthika Das wife of late Tapan Das of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081

(11) Sri Dipen Das, brother of late Dipan Das of 21/2 No. Gate, Motilal Colony, P.O. Rajbari Colony, Kolkata-700 081;

.....Applicants

Humble petition of the applicants abovenamed

Most Respectfully Sheweth

1. That the above reference case was started at the instance of the applicants abovenamed *through their union namely Royal Nepal Airlines Corporation Porters Union against non-payment of dues by the management of Royal*

Nepal Airlines Corporation (RNAC) thereby raising an industrial dispute under the Industrial Disputes Act.

2. That during the pendency of the above reference case the applicants herein and the RNAC have resolved all their disputes and amicably settled all their disputed matters which is the subject-matter of the instant reference case.

3. Th applicants submits that in that view of the matter the applicants herein do not want to proceed any firther with the above reference case as all their disputes with regard to their wages, claims etc. have been settled amicably with the RNAC.

The applicants, therefore, most humbly pray that the above reference case being Reference Case No. 03 of 2005 pending adjudication before this Learned Tribunal be disposed of by passing a No Dispute Award on the grounds stated hereinabove and be pleased further to pass such further order or orders which to Your Honour may deed fit and proper ;

And your applicants as in duty bound shall every pray. Rathin Bhattacharya

VERIFICATION

I, Rathin Bhattacharya, Secretary of Royal Nepal Airlines Corporation Porters Union and one of the applicants herein state that the stetements made herein are true to my knowledge and this petition is signed by all the applicants herein. A petition supported by an affidavit is also enclosed herewith for perusal of this learned Tribunal and to be kept in the records of the instant reference case. Rathin Bhattacharya.

Sd/-
(SRI ASHOKE DAS)
Sd/-
(SRI BIDYUT DHAR)
Sd/-
(SRI DIPAK DAS)
Sd/-
(SRI NARAYAN KUNDU)
Sd/-
(SRI NANDADULAL ROY)
Sd/-
(SRI RATHIN BHATTACHARYA)
Sd/-
(SRI BISHU DEY)
Sd/-
(SRI MONTU DEY)
Sd/-
(SRI BISHWANATH PATRA)
Sd/-
(SMT JUTHIKA DAS)
Sd/-
(SRI DIPEN DAS)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

का.आ. 1758.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई सी एल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय धनबाद-I, के पंचाट (संदर्भ संख्या 77/88) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/104/88-डी-3(ए)-आई.आर.(सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 13th April, 2005

S.O. 1758.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 77/88) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of E.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-05.

[No. L-20012/104/88 -D-3(A)-IR(C-1)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the mstter of a reference U/s. 10(1)(d) of the I.D. Act.

Reference No. 77 of 1988

Parties : Employers in relation to be management of Hariajam Colliery of Nirsa Area of M/s. E.C.L.

AND

Their Workmen

PRESENT:

Shri S. Prasad, Presiding Officer

APPEARANCES:

For the Employers : Shri B. M. Prasad, Advocate

For the Workmen : Shri D. K. Verma, Advocate

State : Jharkhand : Industry : Coal.

Dated, the 5th April, 2005

AWARD

By Order No. L-20012/104/88-D-3(A) IR(C-1) dated 6-7-1988 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Hariajam Colliery of Nirsa Area of M/s. Eastern

Coalfields Ltd. Post Nirsachatti, Dhanbad, in dismissing Sri Kalicharan Manjhi, Line Mazdoor w.e.f. 2-6-86 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. From the written statements filed by the parties it appears that the case of the sponsoring union is that Kalicharan Manjhi, Line Mazdoor, was a permanent workman of Hariajam Colliery, who was sick from 7-1-85 and was unable to report for duty. He informed the management of the colliery of his illness by a letter under registered post requesting for grant of sick leave. The management did not reply to that letter either allowing or rejecting his prayer for sick leave. The concerned workman, Kalicharan Manjhi after recovery from sickness reported for duty alongwith medical certificate, but the management did not allowing him to resume duty and ultimately by a letter dated 2-6-86 dismissed him from the services of the company with immediate effect.

The sponsoring union has further pleaded that the management has never served any chargesheet upon the concerned workman and without following the principles of natural justice the management held domestic enquiry and untimately dismissed the concerned workman, which is not justified.

3. The case of the management is that the concerned workman, Kalicharan Manjhi, employed as Line Mazdoor in Hariajam started absenting from duty w.e.f. 7-1-85 without information to the management or sufficient reason or without permission or satisfactory cause for a very long time. The the management issued a Chargesheet dated 30-12-85 and sent to the concerned workman under registered post, but the concerned workman failed to submit any explanation to the chargesheet. Therefore, the Dy. C.M.E./Agent of the colliery ordered for enquiry by letter dated 6-1-86. The enquiry was fixed on 29-1-86 and the letter was sent to the concerned workman by registered post to his home address, but he failed to attend the enquiry on that date. Another letter was sent informing him that enquiry will be held on 17-2-86 and was sent under registered post with A.D. but the concerned workman did not turn up, then the enquiry proceeded ex-parte. The concerned workman was held guilty and was ultimately dismissed from service.

4. The question of fairness and propriety of the domestic enquiry had been decided as preliminary issue and by order dated 5-8-91 the domestic enquiry has been held to be not fair and proper and the management was asked upon to adduce evidence on merit to justify its action.

The management has simply examined MW-2 on re-call and has not adduced any further evidence. MW-1-Dalip Kumar Singh was the Enquiry Officer and from his evidence as well as from the evidence of MW-2-D.P. Sinha, who was the management's representative in the domestic enquiry it appears that no chargesheet was served upon the concerned workman, therefore the concerned workman did not get an opportunity to reply to be chargesheet. Similarly the notice of enquiry was not served upon him, therefore he was unable to attend the domestic enquiry. It is further apparant that the management did not serve upon the copy of enquiry report to the concerned workman and he has been dismissed from service on account of being absented from duty. The concerned workman has deposed and has stated that in January, 1985 he was absenting from duty as he fell ill and he got a letter written by a co-villager and mailed it through the Post Office, but he did not get any reply from the mangement. He further stated that when he recovered from illness he went to resume duty with fithness certificate, but he was not allowed to resume duty. MW-2 has admitted that conernd workman is an illiterate workman. The management has not examined the Attendance Clerk, therefore the evidence of the workman that after recovery from illness he want to resume duty with medical certificate has not been controverted.

5. As per Certified Standing Orders of the Company remaining absent without permission, reason or sufficient cause is certainly a misconduct, but according to the concerned workman he fell ill and that is why he could not resume duty. He further said that he went to resume duty alongwith medical-fitness certificate, but he was not allowed to resume duty. Therefore, it cannot be said that the concerned workman was absenting from duty without reasonable cause or sufficient reason. Therefore, I find that the management has failed to prove that the concerned workman was guilty of misconduct for remaining absent without permission, without any reason or sufficient cause. Therefore, the management should have allowed the concerned workman to resume duty on production of medical fitness certificate and should have dealt with the period of absent as without wages.

6. Therefore, in my opinion, the concerned workman must be ordered to be resinstated in service, but since he was absent for pretty long time without information to the management, therefore, in my opinion, he should not be allowed to get back wages.

7. In the result, the following award is rendered—

That the action of the management in dismissing Kalicharan Manjhi, Line Mazdoor, w.e.f. 2-6-86 is not justified. The management is directed to reinstate him into service within 30 days from the date of publication of the award without back wages.

S. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

का.आ. 1759.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ईरिगेशन एण्ड पॉवर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. I, दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 128/98) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/84/97-आई.आर. (डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th April, 2005

S. O. 1759.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 128/98) of the Central Government Industrial Tribunal / Labour Court No. I, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Board of Irrigation and Power and their workman, which was received by the Central Government on 15-4-05.

[No. L-42012/84/97-IR(DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

SHRI S.S. BAL, Presiding Officer

I. D. No. 128/98

In the matter of dispute between :

Smt. Asha Sethi w/o Sh. K.B. Sethi,
C/o Pravin Sharma, Advocate,
A/56-A, Lajpat Nagar-II,
Central Market,
New Delhi-110 024 .....Workman

Versus

M/s Central Board of Irrigation and Power,
Malcha Marg, Chanakya Puri,
New Delhi .....Management

APPEARANCES : None for the workman.
Shri P.R. Chopra Advocate A/R for management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012/84/97-IR(DU) dated 28-5-1998 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"1. Whether the action of the management of Central Board of Irrigation & Power in reducing the salary Rs. 1380/- to 1200/- w.e.f. 1-1-93 is just, fair & legal? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Whether the action of the management of Central Board of Irrigation & Power in terminating the services of Smt. Asha Sethi, UDC w.e.f. 28-2-95 is just, fair & legal? If not, what relief the concerned workman is entitled to?"

2. Brief facts of the case as culled from the record are that workman was appointed as LDC-cum-typist with the management for three months which was extended and she was put on promotion for a period of two years. She remained in continuous service of the management up to 28-2-1995. She was promoted as Receptionist-cum-UDC in the scale of Rs. 1500-30-1560-40-2040 w.e.f. 1-1-1987 and lastly as U.D.C. w.e.f. 1-1-93 in which capacity she served up to 28-2-95 and as on 31-12-92 her basic pay was Rs. 1380/- She was further promoted and her pay on 1-1-93 was fixed as Rs. 1200/-. It is further stated that vide office order basic pay of the workman was reduced by Rs. 180/- illegally against which she made representation dated 18th February, 1993 but of no avail and vide office order No. 13182 dated 28-2-95 the workman was relieved of her services and a cheque towards one month's pay in lieu of notice and also her terminal gratuity was paid to her; that her performance throughout service during her tenure with management was satisfactory. She was not paid any retrenchment compensation at the time of her termination, that termination of her services amounts to retrenchment and is against the provisions contained in section 25-F, G and H of the I.D. Act, 1947. The workman remained in continuous services from 20-1-84 to 28-2-95. The action of the management in reducing her pay by Rs. 180/- is also against the provisions of I.D. Act and that termination of services is *malafide*, unjustified, vidictive and illegal. Workman gave notice dated 3-5-95 demanding reinstatement with back wages and another notice dated 24-10-95 was demanding a sum of Rs. 9029/- towards arrears of salary illegally deducted and other arrears etc. etc. but of no avail. That the management is an Industry as defined in I.D. Act, 1947. Workman has claimed reinstatement with continuity of service and full back wages and other accruing benefits and removal of anomaly of pay fixed and reinstatement in service in proper scale with continuity of service.

3. The claim has been contested by the management respondent by filing written statement raising preliminary objection that this court has no jurisdiction to decide the dispute between the parties as the respondent is a government organisation that the respondent Board is a Society and not a department nor an organ of the government and that respondent is not an industry and there is no industrial dispute and this court has no jurisdiction to decide any dispute between the parties. On merits it is admitted that the petitioner was appointed as temporary LDC-cum-typist with respondent w.e.f. 1-12-84 for a period of three months in the grade of Rs. 260-400. She worked as such till 31-12-86. Thereafter, she was appointed (and not promoted as alleged) as Receptionist-cum-UDC in the pay Scale of Rs. 1200-2040 w.e.f. 1-1-87. The said post was ex-cadre post. She was promoted from the post of LDC-cum-Typist from the post of UDC w.e.f. 1-1-83 vide office order dated 15-2-93 in the Grade of Rs. 1200-2040. She was at Sl. No. 15 in the seniority

list in the record of UDC. She was throughout a temporary employee of the respondent Board. It is further stated that her appointment and salary against the post of Receptionist cum UDC was ex-cadre post and has nothing to do with the salary when she was promoted to the post of UDC. Her pay was fixed at Rs. 1200 in the grade Rs. 1200—2040 as per rules. She was not entitled for fixation of his pay at a Rs. 1380 as claimed. It is further stated that during the month of September, 94 a decision was taken by the respondent board that as the work for claimant who was junior most UDC did not justify continuance of service. She should be declared surplus and relieved from the temporary employment and accordingly she was informed vide office order dt. 16-9-94 that she was likely to be declared surplus and was advised to apply for outside employment and that her applications were to be forwarded duly recommended. It was after above 5-1/2 months of the said decision that the claimant was relieved from the service of the respondent board on 18-2-95. On that day itself she was paid by cheques a sum of Rs. 3091 as one month salary in lieu of notice and (b) Rs. 13860 as terminal gratuity as per Fundamental Rules of Central Government which are applicable to the government and further cheque dated 1-3-95 she was paid Rs. 14109 towards leave encashment equivalent to 161 days emoluments and by another cheque dated 4-3-95 she was paid Rs. 61856.70p towards full and final settlement of Contributory Provident Fund. She received all these payments without demur and she also applied for an experience certificate which was issued and soon after termination of his service with respondent board claim has been in continuous employment with the Osvor Sr. Secondary School, E-Block, Vikas Puri, New Delhi and thus in view of the above submissions claim is sought to be dismissed.

4. Written Statement was followed by rejoinder where in contents of written statement were denied and those of claim statement were reiterated to be correct.

5. Thereafter, evidence of the parties was recorded. Workman filed her own affidavit in her evidence and examined herself as WW1 while the administrative Officer Shri S.P. Vats of the respondent Board was examined as MW1 on behalf of the management.

6. After close of evidence of both the parties arguments of both the parties were heard. Written submissions have been also filed on behalf of the respondent but none appeared on behalf of the workman at the time of addressing oral arguments. However, arguments were addressed by A/R of the management.

7. I have bestowed my thoughtful considerations on the question of law & facts involved in this case and perused the record meticulously.

8. The questions which arise for determination are :

(1) Whether respondent management is an industry or not?

(2) Whether the action of the management in reducing Salary of workman is fair, justified and legal?

9. I take up above question for determination one by one. Respondent has filed the memorandum of Association of the Central Board of Irrigation and Power which mentions that name of the Society is the Central Board of Irrigation and Power called the Board and that its objects for which board is established has been enumerated. To determine the question No. 1 above it would be appropriate to have a look on the meaning of Industry as per section 2(J) as of I.D. Act according to which the word 'Industry' means any Business, Trade, Undertaking, Manufacture, or calling of employers and includes any calling services employment in handicraft or industrial occupation or avocation of workmen. The respondent has also filed the memorandum of association wherein the name of the Society is mentioned as Central board of Irrigations and Power and its objects are incorporated in clause III as (a) to (v). A look on it shows that it is apparent that its objects are to pool technical knowledge and experience in the filed of irrigation and power and allied subjects and to utilise the same in the advancement of knowledge in evolving economies in the planning to initiate and develop and coordinate research on irrigation, electricity and allied subjects and to disseminate the results of such research. Thus from the perusal of object as enumerated in the memorandum it can be said that the respondent is not carrying any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and including any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen and to my mind the respondent board in view of its objects as enumerated in his clause III (a) to (v) of its memorandum of association cannot be termed as an Industry as defined in Section 2(j) of Industrial Dispute Act, 1947 and the disputes between its employee and the management cannot be said to be an industrial dispute and in view of this Court does not have the jurisdiction to entertain and determine the reference.

10. On merits it is stated that from the facts as enumerated in the written statement the applicant's services have been dispensed with by the respondent board because she was declared/found surplus and she was paid her one month salary and her all the due which fact is proved from the affidavit and statement of MW1. The action of the department in dispensing with or terminating services of the workman does not suffer from any illegality in view of the facts and circumstances of this case.

11. As regards reduction of pay it may be pointed out that the applicant was initially appointed as LDC and she was appointed as Receptionist-cum-UDC w.e.f. 20-1-84 and remained there till 31-12-86. She was appointed as Receptionist against an ex-cadre post in the pay scale

of Rs. 1200—2040 w.e.f. 1-1-97 and not promoted as claimed. She was promoted from the post of UDC-cum-Typist to the grade of 12/20.40 against the post of Receptionist- cum-UDC. Her pay was in the scale of Rs. 1200-2040 w.e.f. 1-1-87 and on 31-12-92 her basic pay was Rs. 1380 but the post of Receptionist-cum-UDC was an ex-cadre post. It was not a channel for promotion and while her channel of promotion was from LDC-cum -Typist to UDC and she was promoted as UDC vide office order dated 15-12-93 and her pay was fuxed at Rs. 1200 in the grade Rs. 1200—2040 as per rule so, to my mind she cannot claim salary at basic Pay of Rs. 1350 which was being paid to her while working against the post of Receptionist-cum-UDC which is different post other then promotional channel which is a different post than the promotional channel of the post of UDC wherein her pay was fixed at Rs. 1200. It is not a case of reduction of pay scale. Her promotion from the channel of LDC to UDC wherein pay was fixed at Rs. 1200 and her pay in the post of promotional post of UDC from LDC has been correctly fixed as Rs. 1200. She was appointed and officiated against the post of Receptionist-cum-UDC which is an ex-cadre post. It is not a case of reduction of pay as claimed by the petitioner/claimant. In view of the above discussions I am of the opinion that the action of the respondent Board in fixing the Basic Pay of the workman at Rs. 1200 as well as in terminating the services of the workman is just, fair and legal and does not suffer from any illegality. The award is given accordingly.

S. S. BAL, Presiding Officer

Dated : 28-3-2005.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2005

का.आ. 1760.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 81/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-4-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/176/2001-आई आर (बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 20th April, 2005

S.O. 1760.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 81/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/ Labour Court, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of UCO Bank and their workman, which was received by the Central Government on 12-4-2005.

[NO. L-12011/176/2001-IR(B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BRFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

CASE No. I. D. 81/2002

The General Secretary, UCO Bank Employees Union, Central Office, C/o UCO Bank G.T. Road, Jalandhar (Punjab).

...Applicant

Versus

UCO Bank, The Divisional Manager, UCO Bank, Zonal Office Sector-17, Chandigarh.

...Respondent

APPEARANCES:

For the Workman : None

For the Management : Shri N. K. Zakhmi.

AWARD

Passed on 2-3-05

Central Government vide notification No. L-12011/ 176/2001/IR(B-II) dated 22-4-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of UCO Bank in awarding in the punishment of bringing down to lower stage in the scale of pay by two stages and stoppage of two future increments with cumulative effect to Shri C. L. Mittal Special Assistant is legal and just? If not, what relief the concerned workman is entitled to and from what date?"

2. Case repeatedly called. None has put up appearance on behalf of the workman/union despite notice. On the last 8 dates no one is putting appearance. It appears that Union is not interested to pursue with the present reference. In view of the above, the present reference is returned to the Central Government for want of prosecution. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Announced 2-3-2005

RAJESH KUMAR, Presiding Officer.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.